GEO IAS
It's about quality

March 2024

GEO Daily

Daily Current Affairs

GEO IAS

SOURCES

THE HINDU | The Indian EXPRESS JOURNALISM OF COURAGE | pib | PIB | live mint | THE FINANCIAL EXPRESS | ET ECONOMIC TIMES.COM

Contents

सामान्य अध्ययन I 10

HISTORY, ART & CULTURE 10

1. पाकिस्तान का राष्ट्रीय दिवस समारोह दिल्ली में मनाया जाएगा- इंडियन एक्सप्रेस 10
2. इटली में 5000 साल पुराना ताम्रयुगीन कब्रिस्तान खोजा गया- टाइम्स ऑफ इंडिया 10
3. पीएम ने साबरमती गांधी आश्रम पुनर्विकास के लिए मास्टर प्लान लॉन्च किया- द हिंदू 11
4. वैकोम सत्याग्रह को 100 साल पुरे हुए - इंडियन एक्सप्रेस 11
5. त्रिपुरा की पारंपरिक आदिवासी पोशाक 'रिसा' को GI टैग मिला: त्रिपुरा सीएम - इंडियन एक्सप्रेस 12
6. जयपुर की सदियों पुरानी 'गुलाल गोटा' होली की परंपरा - इंडियन एक्सप्रेस 13
7. कम्बम घाटी:'दक्षिण भारत के ग्रेप्स सिटी- इंडियन एक्सप्रेस 13
8. वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड वॉच 2025 के नामांकन हेतु काज़ुवेली वाटरशेड क्षेत्र का प्रस्ताव रखा- द हिंदू 14
9. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 18 स्मारकों को संरक्षित सूची से बाहर करेगा -द हिंदू 14
10. मोहिनीअट्टम: कलामंडलम ने 'लैंगिक विभाजन' को समाप्त किया- द हिंदू 15

INDIAN SOCIETY 16

11. महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले केवल दो-तिहाई कानूनी अधिकार: विश्व बैंक - डाउन टू अर्थ 16
12. लिसु और सिंगफो समुदाय परिवारों में जन्म के क्रम को दर्शाते हैं- द हिंदू 16
13. लैंसेट रिपोर्ट: भारत में प्रजनन दर में गिरावट इंडियन एक्सप्रेस 17

GEOGRAPHY 18

14. अर्जेंटीना भारत की लिथियम खोज को बढ़ावा देगा- द हिंदू 18
15. पूर्ण सूर्य ग्रहण 2024: कहां और कब- फाइनेंशियल एक्सप्रेस 19
16. भारत महत्वपूर्ण खनिजों के लिए अब अफ्रीका से बातचीत करेगा - द हिंदू 19
17. अल नीनो प्रभाव के कारण मलावी में खाद्य संकट -द हिंदू 20
18. जलपाईगुड़ी जिले में नॉरवेस्ट तूफान से कई लोग घायल हुए- द हिंदू 20

सामान्य अध्ययन II 21

POLITY & GOVERNANCE 21

19. उच्च न्यायालयों के स्थगन आदेश स्वतः समाप्त नहीं होंगे: - द हिंदू/ छह महीने के बाद स्थगन आदेश स्वत: रद्द नहीं होंगे: सुप्रीम कोर्ट - इंडियन एक्सप्रेस 21
20. केंद्र ने मडिगा सदस्य के लिए अनुसूचित जाति में जगह सुनिश्चित की- द हिंदू 22
21. भारत में उदार लोकतंत्र में गिरावट: वी-डेम रिपोर्ट - द हिंदू 22

+91-9477560001, +91-9477560002, +91-9477560005
info@geoias.com
www.geoias.com
BRANCH: Delhi Kolkata, Raipur, Patna | Head office: 641, Ramlal Kapoor Marg, Mukherjee Nagar, Delhi, 110009

22. केवल संसद को ही खनिजों पर टैक्स लगाने का अधिकार है: सुप्रीम कोर्ट - इंडियन एक्सप्रेस 23

23. SBI ने चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड डेटा सौंपा- द हिंदू 23

24. कावेरी पैनल चार साल के बाद पुडुचेरी में बैठक करेगा - द हिंदू 24

25. सुप्रीम कोर्ट EC चयन पैनल में CJI को शामिल करने की याचिका पर सुनवाई करेगा- द हिंदू 25

26. समान नागरिक संहिता पर उत्तराखंड विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली - द हिंदू 27

27. कोविंद पैनल ने एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की- द हिंदू 28

28. मद्रास HC ने OPS को ADMK के प्रतीक, झंडे का उपयोग करने से रोका- द हिंदू 28

29. चुनावी बॉन्ड डेटा: पहले दो वर्षों में किसे कितना मिला - द हिंदू 29

30. जलवायु कार्यकर्ता वांगचुक ने सीमा मार्च का आहवान किया - द हिंदू 30

31. SC ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राशन कार्ड देने का निर्देश दिया- द हिंदू 31

32. सुप्रीम कोर्ट ने तथ्य जांच इकाई पर केंद्र के आदेश पर रोक लगाई -द हिंदू 31

33. प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया -द हिंदू 32

34. क्या हिरासत में रहते हुए भी केजरीवाल सीएम बने रह सकते हैं? - हिन्दू 32

35. शक्तियों के नियमित प्रयोग द्वारा प्रिवेंटिव डिटेंशन अवश्य होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट- इंडियन एक्सप्रेस 33

36. असाधारण मामलों में ही मीडिया रिपोर्टों पर रोक लगाएं - सुप्रीम कोर्ट -द हिंदू 34

37. POCSO अपराध के आरोपी बच्चे पर JJ एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए: केरल HC - द हिन्दू 34

38. सुप्रीम कोर्ट: PMLA से जुड़ी याचिका अदालत ने खारिज की- इकोनॉमिक टाइम्स 35

39. चुनाव आयोग का सीविजिल ऐप नागरिकों को सशक्त बनाएगा - पीआईबी 36

40. दिल्ली पुलिस ने UAPA मामले में न्यूज़क्लिक के ख़िलाफ़ आरोप पत्र दायर किया -द हिंदू 37

41. इलाहाबाद HC ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा अधिनियम को 'असंवैधानिक' बताया - द हिंदू 38

42. भारत में सबसे अधिक 'जीरो-फूड' बच्चे: JAMA नेटवर्क रिपोर्ट - द हिंदू 38

43. फ्रांस ने अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को शामिल किया - द हिंदू 39

44. विधि आयोग ने व्यापार रहस्यों की सुरक्षा के लिए नए कानून की सिफारिश की- इंडियन एक्सप्रेस 40

GOVERNMENT SCHEME 40

45. कैबिनेट ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दी - द हिंदू/ कैबिनेट ने 75 हजार करोड़ रुपये की छत सौर योजना को मंजूरी दी - इंडियन एक्सप्रेस 40

46. शिक्षा मंत्री ने SWAYAM Plus प्लेटफॉर्म लॉन्च किया - इंडियन एक्सप्रेस 41
47. प्रधानमंत्री ने सशक्त नारी - विकसित भारत कार्यक्रम में हिस्सा लिया - पीआईबी 42
48. प्रधानमंत्री ने पीएम-सूरज पोर्टल लॉन्च किया - द हिंदू 42
49. प्रधानमंत्री ने हजरतबल तीर्थ विकास परियोजना का उद्घाटन किया- पीआईबी 43
50. केंद्र ने साइबर अपराध, वित्तीय धोखाधड़ी की जांच हेतु DIP और Chakshu पोर्टल लॉन्च किए- पीआईबी 44
51. TDB और FNDR को इनोवेटिव एंटीबायोटिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हेतु 75 लाख रूपये का अनुदान- पीआईबी 44
52. केंद्रीय गृहमंत्री राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (NCD) लॉन्च करेंगे- पीआईबी 45
53. नीति आयोग ने 'वोकल फॉर लोकल' पहल का अनावरण किया- पीआईबी 46
54. केंद्र ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार की योजना का अनावरण किया- द हिंदू 46
INTERNATIONAL RELATION 47
55. भारत EFTA ब्लॉक के साथ व्यापार समझौता करने के लिए तैयार- इंडियन एक्सप्रेस 47
56. कई देशों ने VASP के दुरुपयोग को रोकने के लिए मानको को पूरी तरह से लागू नहीं किए: FATF - द हिंदू 47
57. ओपेक+ देशों ने कीमतें बढ़ाने के लिए तेल कटौती का विस्तार किया - द हिंदू 48
58. भारत और EFTA देशों के बीच प्रस्तावित FTA को जल्द ही औपचारिक रूप दिया जा सकता है – द हिंदू 48
59. भारत-अमेरिका त्रि-सेवा अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ शुरू -द हिंदू 49
60. राइट्स लिमिटेड IMEC कॉरिडोर के साथ विकास के अवसरों को लक्षित करेगा -द हिंदू 50
61. भारत अमेरिका के नेतृत्व वाले सहकारी कार्य कार्यक्रम में शामिल होगा -द हिंदू 51
62. IMF ने पाकिस्तान के साथ कर्मचारी स्तर पर समझौता किया- द हिंदू 52
63. SCO स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ- द प्रिंट 52
64. भारत ने पांच वर्षों में भूटान की सहायता को दोगुना करने का फैसला किया- द हिंदू 53
65. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गाजा में तत्काल युद्धविराम की मांग की -इंडियन एक्सप्रेस 54
66. पाकिस्तान भारत के साथ व्यापार संबंध फिर से शुरू करने के लिए तैयार -द हिन्दू 54
67. चीन श्रीलंका में सामरिक बंदरगाह, हवाईअड्डा विकसित करेगा-द हिंदू 55
68. भारत ने 4 यूरोपीय देशों के साथ 100 अरब डॉलर का मुक्त व्यापार समझौता किया - द हिंदू 56

69. भारत ने UN शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों को रिकॉर्ड करने के लिए डेटाबेस लॉन्च किया- बिजनेस स्टैंडर्ड 56

ECONOMY 57

70. संयुक्त राष्ट्र ने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 जारी की - इकोनॉमिक टाइम्स 57

71. पीएम ने कोलकाता में भारत की पहली अंडरवॉटर मेट्रो लाइन लॉन्च की- द हिंदू 58

72. केंद्रीय कैबिनेट ने सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली इकाइयों को मंजूरी दी - इंडियन एक्सप्रेस 59

73. RBI ने नियामक सैंडबॉक्स योजना से संबंधित मानदंडों में बदलाव किया - द इकोनॉमिक टाइम्स 60

74. जनवरी में पूंजीगत व्यय 40.5% कम हो गया - द हिंदू 61

75. RBI ने बैंकों को एकाधिक कार्ड नेटवर्क विकल्प प्रदान करने का निर्देश दिया-द हिंदू 61

76. गिग वर्कर सामाजिक सुरक्षा, विनियमन की कमी से पीड़ित- द हिंदू 62

77. जनवरी 2024 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 3.8 प्रतिशत बढ़ा- द प्रिंट 63

78. RBI इस साल कुछ NBFC को शीर्ष स्तर पर 'अपग्रेड' कर सकता है- द हिंदू 64

79. Paytm को थर्ड पार्टी एप्लिकेशन प्रदाता बनने हेतु NPCI की मंजूरी मिली- इंडियन एक्सप्रेस 65

80. रेलवे ने मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब विकसित करने की योजना बनाई - द हिंदू 66

81. ट्रेडमार्क नियमों के तहत 'पासिंग ऑफ' क्या है ?- इंडियन एक्सप्रेस 66

82. स्टार्ट-अप इकोसिस्टम के राजस्व की मांग में वृद्धि- फाइनेंशियल एक्सप्रेस 67

83. WTO में, भारत सीमा पार प्रेषण की लागत कम करने का प्रयास कर रहा है - द हिंदू 67

84. समावेशी विकास के साथ असमानता में कमी- द हिंदू 68

85. NAAC की मान्यता प्रणाली में बदलाव की आवश्यकता- इंडियन एक्सप्रेस 69

86. ILO और IHD ने भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 जारी की - द हिंदू 69

87. भारत के शुद्ध विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) प्रवाह में गिरावट'-द हिंदू 71

88. RBI ने AIF में निवेश करने वाले ऋणदाताओं हेतु मानदंडों में संशोधन किया - द हिंदू 71

89. GeM पोर्टल: FY24 में खरीद 4 ट्रिलियन रुपये के पार - इंडियन एक्सप्रेस 72

90. पूरे भारत के 60 से अधिक उत्पादों को भौगोलिक संकेत (GI) टैग मिला - द हिंदू 73

ENVIRONMENT 74

91. कॉल फॉर जस्टिस अध्ययन:5 राज्यों में FRA का कार्यान्वयन मिश्रित है -द हिंदू 74

92. पर्यावरण मंत्रालय ने तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की - द हिंदू/ मध्यप्रदेश तेंदुओं की संख्या में शीर्ष स्थान पर - इंडियन एक्सप्रेस 74

93. कैबिनेट ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA) की स्थापना को मंजूरी दी- पीआईबी/भारत बड़ी बिल्लियों की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय गठबंधन स्थापित करेगा - द हिंदू 75
94. पहले सर्वेक्षण के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की संख्या 718: पर्यावरण मंत्रालय - इंडियन एक्सप्रेस 76
95. UNEA-6: भौतिक संसाधनों का वैश्विक उत्पादन और खपत में 50 वर्षों में तीन गुना बढ़ी - डाउन टू अर्थ 76
96. UN ने खेतों और ग्रामीण इलाकों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की चेतावनी दी -द हिंदू 77
97. जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता: कार्बन कैप्चर क्या है? - इंडियन एक्सप्रेस 78
98. MNRE हाइड्रोजन भंडारण के लिए विशेष सिलेंडरों पर चर्चा करेगा- इंडियन एक्सप्रेस 79
99. SC ने पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य को गैर-अधिसूचित करने के असम सरकार के निर्णय रोका - द हिंदू 79
100. सौर ऊर्जा की शॉक्ले-क्विसर दक्षता सीमा - द हिंदू 80
101. UNEP रिपोर्ट: प्लास्टिक रसायन अनुमान से अधिक- द हिंदू 81
102. दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी: वैश्विक वायु गुणवत्ता रिपोर्ट-द हिंदू 82
103. दिल्ली की बायोमाइनिंग परियोजना 2024 की समय सीमा से चूकने की संभावना - द हिंदू 83
104. सुप्रीम कोर्ट ने बस्टर्ड संरक्षण को संतुलित करने हेतु पैनल का गठन किया-द हिंदू 84
105. पर्यावरण मंत्रालय ने बायोप्लास्टिक पर नियम सख्त किये -द हिंदू 84
106. कोडागु (बेंगलुरु) में भूजल स्तर में भारी गिरावट -द हिंदू 85
107. ऑस्ट्रेलिया की कार्बन क्रेडिट योजना वैश्विक स्तर पर विफल रही -हिन्दू 85
108. मोयार घाटी संरक्षण: जिप्स गिद्धों को प्राकृतिक आवास - इंडियन एक्सप्रेस 86
109. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड विलुप्त होने के कगार पर - द हिन्दू 87
110. CPCB ग्रीन फंड का 80% अप्रयुक्त: NGT -इंडियन एक्सप्रेस 87
SECURITY 88
111. रक्षा मंत्री डेफकनेक्ट 2024 का उद्घाटन करेंगे- पीआईबी 88
112. सरकार ने नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में AFSPA बढ़ाया - द हिंदू 89
113. "ग्रे जोन वॉरफेयर" अनौपचारिक युद्ध में नवीनतम: CDS- इंडियन एक्सप्रेस 90
114. भारतीय नौसेना मिनिकॉय द्वीप में INS जटायु को तैनात करेगी - पीआईबी 91
115. संयुक्त अभ्यास के लिए अमेरिकी तटरक्षक जहाज बर्थोल्फ पोर्ट ब्लेयर पहुंचा- इंडिया टुडे 91
116. प्रधानमंत्री ने असम को अरुणाचल से जोड़ने वाली सेला सुरंग का उद्घाटन किया- प्रिंट 92

117. भारत के पहले मानवयुक्त सबमर्सिबल मिशन, समुद्रयान हेतु मुख्य परीक्षण पूरा किया - द हिंदू . 93
118. अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास/कटलैस एक्सप्रेस 23 में INS त्रिकंद की भागीदारी- पीआईबी 93
119. वर्ष 2019-23 के बीच भारत दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक: SIPRI- द हिंदू 94
120. राजस्थान में सेना की पोखरण रेंज में युद्धाभ्यास 'भारत शक्ति' का आयोजन - द प्रिंट 94
SCIENCE & TECH 95
121. भारत के युवाओं में मोटापा बढ़ रहा है: लांसेट अध्ययन- इंडियन एक्सप्रेस 95
122. अंतर्राष्ट्रीय HPV जागरूकता दिवस- द हिंदू 95
123. Google भारतीय ऐप्स को अस्थायी रूप से बहाल करने पर सहमत- द हिंदू 96
124. एंथ्रोपिक का नया क्लाउड 3 AI मॉडल -द इंडियन एक्सप्रेस 96
125. नासा उपग्रह ने बादलों में अजीब छिद्रों को कैप्चर किया - टाइम्स ऑफ इंडिया 97
126. WHO ने डोलटेग्रेविर के प्रति बढ़ती HIV दवा प्रतिरोध पर प्रकाश डाला- डाउन टू अर्थ 97
127. याउंडे घोषणा: अफ्रीका में मलेरिया से होने वाली मौतों को समाप्त करने की प्रतिज्ञा- डाउन टू अर्थ 98
128. सरकार ने फार्मा कंपनियों के लिए मार्केटिंग कोड जारी किया- द हिंदू 99
129. सरकार ने अश्लील सामग्री स्ट्रीम करने के लिए OTT प्लेटफार्मों को ब्लॉक किया-द हिंदू 99
130. कर्नाटक सरकार ने रोडामाइन-B फूड कलर पर प्रतिबंध लगाया - द हिंदू 100
131. पीलीभीत में FMD रोग से दुधारू पशु प्रभावित - टाइम्स ऑफ इंडिया 100
132. पेट्रोलियम मंत्री ने इथेनॉल 100 ईंधन लॉन्च किया- पीआईबी 101
133. SAKH ऐप: गगनयान दल की सहायता के लिए बहुउद्देश्यीय ऐप - द हिंदू 101
134. डेंगू का टीका वर्ष 2026 के मध्य तक बाज़ार में आ सकता है: IIL - द हिंदू 102
135. एनवीडिया का प्रोजेक्ट GR00T क्या है -द हिंदू 102
136. MeitY/NIXI ने भाषानेट पोर्टल का सफलतापूर्वक अनावरण किया- पीआईबी 103
137. खगोलविदों ने कॉस्मिक कैन्नीबालिस्म तारों की खोज की - टाइम्स ऑफ इंडिया 103
138. केरल ने केंद्र की स्मार्ट मीटर योजना को खारिज किया - इंडियन एक्सप्रेस 104
139. ICCC: अनुकूलित समाधानों के लिए एकीकृत फार्म डेटा डैशबोर्ड -इंडियन एक्सप्रेस 104
140. भारत में 2015 से क्षय रोग (TB) के नए मामलों में 16% की गिरावट -द हिंदू 105
141. स्काईरूट ने विक्रम 1 अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के चरण-2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया- द हिन्दू 105
142. विदेश में साइबर फ्रॉड केंद्रों से 250 नागरिकों को बचाया: विदेश मंत्रालय- द हिंदू 106

एडिटोरियल, जिस्ट, एक्सप्लेनेर 107

143. मॉरीशस, मालदीव और भारत के आपसी राजनैतिक सम्बन्ध - इंडियन एक्सप्रेस 107

144. प्लास्टिक से हिमालयी राज्यों कों खतरा - द हिंदू 108

145. भारत के परमाणु कार्यक्रम की स्थिति- द हिंदू 108

146. खनिज तत्वों से सम्बंधित मामला - इंडियन एक्सप्रेस 109

147. भारत की न्याय व्यवस्था में महिलाओं की वर्तमान स्थिति - इंडियन एक्सप्रेस 110

148. भारत द्वारा अपनी श्रम शक्ति का न्यूनतम उपयोग- द हिंदू 110

149. भारत में गरीबी से सम्बंधित मामला - द प्रिंट 111

150. पश्चिमी घाट में एक जनजाति को जीवन रेखा की आवश्यकता - द हिंदू 112

151. रेडियोधर्मी अपशिष्ट कैसे उत्पन्न होता है - द हिंदू 112

152. भारत की अनुसंधान एवं विकास निधि से सम्बंधित मामला - द हिंदू 113

153. CAA और न्यायिक कार्यवाही की स्थिति -द हिंदू 114

154. चुनावों में जेनेरिक AI का प्रभाव - इंडियन एक्सप्रेस 114

155. नेपाल की राजनीतिक व्यवस्था से संबधित मामला - इंडियन एक्सप्रेस 115

156. IPCC रिपोर्ट में समानता की समस्या - इंडियन एक्सप्रेस 116

157. इंडो-पैसिफिक रणनीति- द हिंदू 116

158. भारत का सौर अपशिष्ट वर्ष 2030 तक 600 किलोटन तक पहुंचने की संभावना: CEEW अध्ययन - इंडियन एक्सप्रेस 117

159. वैश्विक जल संकट से सम्बंधित मामला - द हिंदू 117

160. ब्लैक कार्बन उत्सर्जन पर अंकुश लगाने की आवश्यकता -द हिंदू 118

161. चीन और ताइवान के बीच भू राजनैतिक संबंध - द हिन्दू 119

162. विश्व व्यापार संगठन (WTO) का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन -द हिंदू 119

163. भारत में इंटरनेट स्वतंत्रता से सम्बन्धित मामला - द हिंदू 120

164. केरल सरकार अपने विधेयकों पर राष्ट्रपति की मंजूरी रोकने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची-इंडियन एक्सप्रेस 120

165. सतत निर्माण सामग्री पारंपरिक निर्माण सामग्री के पर्यावरण के अनुकूल - द हिंदू 121

166. अंतरराष्ट्रीय परिवहन गलियारों के लिए भारत के प्रयास - द प्रिंट 122

फैक्ट फटाफट 124

1. वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम(VSHORADS) 124
2. बायोट्रिग 124
3. जूस जैकिंग 124
4. जीन थेरेपी 125
5. रोएन ओलमी 125
6. GRAPES-3 एक्सपेरिमेंट 125
7. ओबिलिस्क 125
8. जम्मू-कश्मीर में ओबीसी आरक्षण 126
9. व्योमित्र 126
10. हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल लक्ष्य "ABHYAS (अभ्यास)" 126
11. इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट (ICIMOD) 127
12. एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 127
13. राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड 127
14. सवेरा प्रोग्राम 128
15. PSiFI सिस्टम 128
16. अलास्कापोक्स 128
17. बोचासनवासी अक्षर पुरूषोत्तम स्वामीनारायण संस्था (BAPS) 128
18. स्वाति पोर्टल 129
19. गोल्ड नैनोकण 129
20. गोल्डन लैंगर्स 129
21. मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टार्गेटेबल री-एंट्री व्हीकल (MIRV) तकनीक 129
22. कृषि और ग्रामीण सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और बीमा (सारथी) पोर्टल 129
23. बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (BOT) मॉडल 130
24. जिरकोन मिसाइल 130
25. CAA, 2019 130
26. व्यायाम-सदा तनसीक 131
27. नॉनअल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस (NASH) 131

28. बायोट्रिग 131
29. स्टेट ऑफ द ज्यूडिशियरी रिपोर्ट 131
30. एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 132
31. राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड 132
32. पुन: प्रयोज्य लैंडिंग वाहन (RLV) LEX 02 132
33. मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया 132
34. मेमे कॉइन्स 132
35. अफानसी निकितिन सीमाउंट 133
36. खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 133
37. कोंडा रेड्डी जनजाति 133

महत्वपूर्ण समाचार लेख

सामान्य अध्ययन I

HISTORY, ART & CULTURE

1. पाकिस्तान का राष्ट्रीय दिवस समारोह दिल्ली में मनाया जाएगा- इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप और उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे
- लाहौर संकल्प
- पाकिस्तान

समाचार:
- **पाकिस्तान** ने इस साल फिर से **नई दिल्ली** में अपना **राष्ट्रीय दिवस समारोह आयोजित** करने का फैसला किया है, जो **23 मार्च** को मनाया जाता है, जिस दिन **वर्ष 1940** में **मुस्लिम लीग** द्वारा **लाहौर प्रस्ताव** अपनाया गया था।

लाहौर प्रस्ताव:
- इसे **22 मार्च** से **24 मार्च 1940** तक **लाहौर** में अपने **सामान्य सत्र** के दौरान **अखिल भारतीय मुस्लिम लीग** द्वारा अपनाया गया था, औपचारिक रूप से **भारत के मुसलमानों** के लिए एक **स्वतंत्र राज्य** का आह्वान किया गया था।
- प्रस्ताव में कहीं भी **'पाकिस्तान'** शब्द शामिल नहीं है।
- लाहौर प्रस्ताव की कई **भारतीय मुसलमानों** ने आलोचना की, जैसे **अबुल कलाम आज़ाद** और **हुसैन अहमद मदनी** के नेतृत्व वाले **देवबंद उलेमा**, जिन्होंने एकजुट भारत का समर्थन किया था।
- **भौगोलिक रूप** से **सन्निहित इकाइयों** को उन **क्षेत्रों** में **सीमांकित** किया जाता है जिन्हें इस प्रकार गठित किया जाना चाहिए, ऐसे **क्षेत्रीय पुनर्समायोजन** के साथ जो आवश्यक हो सकता है।
  - ये क्षेत्र जिनमें मुस्लिम संख्यात्मक रूप से बहुसंख्यक हैं जैसे भारत के उत्तर-पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र।
  - "**स्वतंत्र राज्यों**" के गठन के लिए समूहीकृत किया जाना चाहिए जिसमें **घटक इकाइयाँ स्वायत्त** और **संप्रभु** होंगी।
- **भारत** के अन्य हिस्सों में जहां **मुसलमान अल्पसंख्यक** हैं, उनके लिए **संविधान में विशेष रूप** से पर्याप्त, **प्रभावी** और **अनिवार्य सुरक्षा प्रदान** की जाएगी।
  - अन्य अल्पसंख्यकों के परामर्श से उनके धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और अन्य अधिकारों और हितों की सुरक्षा के लिए।

2. इटली में 5000 साल पुराना ताम्रयुगीन कब्रिस्तान खोजा गया- टाइम्स ऑफ इंडिया

प्रासंगिकता: भारतीय संस्कृति प्राचीन से आधुनिक काल तक कला रूपों, साहित्य और वास्तुकला के प्रमुख पहलुओं को कवर करेगी।

प्रीलिम्स टेकअवे
- ताम्रपाषाण
- ताम्र युग

समाचार:`
- **इटली** में पुरातत्वविदों ने **5,000 साल** पुराने **कब्रिस्तान** की उल्लेखनीय खोज की है जो **ताम्र युगीन सभ्यता** का था।

ताम्र युग:
- **ताम्र युग,** या **ताम्रपाषाण काल,** एक ऐसी अवधि है जो क्षेत्र के **आधार** पर **लगभग 5,000** से **2,000 साल** पहले तक फैली हुई है।
- यह **नवपाषाण काल** (**नव पाषाण युग**) से **कांस्य युग** तक का एक **संक्रमणकालीन चरण** था।
- इसकी विशेषता **धातु विज्ञान** का उद्भव है, विशेष रूप से **पत्थर** के **औजारों** के साथ **तांबे** का उपयोग।
- यह शिल्प विशेषज्ञता की शुरुआत, कृषि के विकास, लंबी दूरी के व्यापार और बढ़ी हुई सामाजिक-राजनीतिक जटिलता के साथ मेल खाता है।
- **किसान आम** तौर पर **भेड़-बकरी, मवेशी और सूअर** जैसे घरेलू जानवरों को पालते थे, जिनका आहार शिकार और **मछली पकड़ने** से पूरक होता था।

- **ताम्रपाषाणिक किसानों** द्वारा उगाई जाने वाली **फसलों** में **जौ, गेहूं और दालें** शामिल थीं।
- ताम्रपाषाण काल की एक मुख्य पहचान बहुरंगी चित्रित मिट्टी के बर्तन हैं।
- ताम्रपाषाणिक किसानों द्वारा बनाए गए घर पत्थर या मिट्टी की ईंटों से बनाए जाते थे।
- एक विशिष्ट पैटर्न आयताकार घरों की एक श्रृंखला का निर्माण है जो छोटे छोर पर साझा पार्टी की दीवारों द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
- एक अन्य पैटर्न, जो बड़ी बस्तियों में देखा जाता है, एक केंद्रीय आंगन के चारों ओर कमरों का एक सेट है, जो उसी प्रकार की सामाजिक व्यवस्था की सुविधा प्रदान कर सकता है।
- पुरातत्व में, नरसंहार, लड़ाई और योद्धा दफ़नाने के पहले संकेत ताम्र युग के उदय के साथ दिखाई देने लगते हैं।
- ताम्र युग के अंत तक, लोगों को पता चला कि तांबे में टिन मिलाकर, एक मजबूत और अधिक टिकाऊ धातु कांस्य बनाया जा सकता है, उस बिंदु से, कांस्य युग शुरू होता है।

3. पीएम ने साबरमती गांधी आश्रम पुनर्विकास के लिए मास्टर प्लान लॉन्च किया- द हिंदू

प्रासंगिकता: स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों के महत्वपूर्ण योगदानकर्ता/योगदान।

प्रीलिम्स टेकअवे
- दांडी मार्च
- असहयोग आन्दोलन

समाचार:
- **प्रधानमंत्री** ने ऐतिहासिक दांडी मार्च की वर्षगांठ पर **अहमदाबाद** में **साबरमती गांधी आश्रम पुनर्विकास** परियोजना के लिए एक **मास्टर प्लान लॉन्च** किया।

दांडी यात्रा (मार्च)
- **महात्मा गांधी** ने **मार्च-अप्रैल 1930** में एक महत्वपूर्ण **अहिंसक विरोध, दांडी मार्च** (जिसे नमक मार्च या नमक सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है) का नेतृत्व किया।
- इस **अधिनियम** ने **भारत** में **ब्रिटिश शासन** के खिलाफ एक **बड़े सविनय अवज्ञा आंदोलन** की शुरुआत की, जो **वर्ष 1931** तक जारी रहा।
- विरोध ने नमक उत्पादन और वितरण पर ब्रिटिश एकाधिकार को निशाना बनाया।
- कानूनों ने भारतीयों को अपना नमक बनाने या बेचने से रोक दिया, जिससे उन्हें महंगा, भारी कर वाला, अक्सर आयातित नमक खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा।
- इससे **गरीब बहुसंख्यक** लोग काफी प्रभावित हुए जो इसे वहन नहीं कर सकते थे।
- फरवरी 1930 में समाचार रिपोर्टों ने नमक कानूनों की अवहेलना करने की **गांधीजी** की योजना की घोषणा की।
- विरोध प्रदर्शन **12 मार्च** को शुरू होगा और **6 अप्रैल** को **गांधीजी** द्वारा प्रतीकात्मक रूप से नमक अधिनियम तोड़ने के साथ दांडी में समाप्त होगा।
- यह तारीख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह **वर्ष 1919** में स्थापित **राष्ट्रीय सप्ताह** की शुरुआत का प्रतीक है।
- गांधीजी ने अहिंसक सिद्धांतों के कड़ाई से पालन पर जोर देते हुए मार्च की सावधानीपूर्वक तैयारी की।
- उन्होंने अपने आश्रम से प्रतिभागियों को भर्ती किया, जो उनकी शिक्षाओं के प्रति अनुशासित प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे।
- टकराव से बचने के प्रयास में, गांधी ने वायसराय को पत्र लिखकर कर में कटौती और नमक कर को समाप्त करने सहित रियायतें मांगीं।
- हालाँकि, वायसराय ने इन मांगों को खारिज कर दिया, जिससे गांधी को मार्च के लिए आगे बढ़ना पड़ा।

4. वैकोम सत्याग्रह को 100 साल पुरे हुए - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: स्वतंत्रता संग्राम - इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न हिस्सों से महत्वपूर्ण योगदानकर्ता/योगदान।

प्रीलिम्स टेकअवे
- सत्याग्रह
- केपी केशव मेनन

समाचार:
- **त्रावणकोर रियासत** के एक **मंदिर शहर**, वै**कोम** में **30 मार्च, 1924** को एक **अहिंसक आंदोलन** की शुरुआत हुई, जो **मंदिर प्रवेश आंदोलनों** में पहला था, जो जल्द ही पूरे देश में फैल गया।
- बढ़ते **राष्ट्रवादी आंदोलन** के बीच, **सत्याग्रह** ने **त्रावणकोर राज्य** में विरोध के **गांधीवादी तरीकों** को सामने लाते हुए, **सामाजिक सुधार** को आगे बढ़ाया।

वाइकोम सत्याग्रह

- त्रावणकोर की रियासत में **सामंती, सैन्यवादी और प्रथा-ग्रस्त सरकार** की क्रूर व्यवस्था थी
  - कुछ सबसे कठोर, परिष्कृत और क्रूर सामाजिक मानदंड और रीति-रिवाज त्रावणकोर में देखे गए थे।
- **एझावा और पुलाया** जैसी **निम्न जातियों** को **प्रदूषण** फैलाने वाला माना जाता था और उन्हें **ऊंची जातियों** से दूर रखने के लिए कई नियम लागू थे।
- इनमें न केवल **मंदिर में प्रवेश** पर, बल्कि **मंदिरों के आसपास** की सड़कों पर चलने पर भी **प्रतिबंध** शामिल था।

नेताओं का योगदान:

- **वर्ष 1923** में, **माधवन** ने **अखिल भारतीय कांग्रेस समिति** की **काकीनाडा बैठक** में इस मुद्दे को एक प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया।
- इसके बाद, इसे **जनवरी 1924** में **केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी** द्वारा गठित **कांग्रेस अस्पृश्यता समिति** द्वारा उठाया गया।
- माधवन, **केपी केशव मेनन के केलप्पन** (जिन्हें केरल गांधी के नाम से भी जाना जाता है) को **वाइकोम सत्याग्रह आंदोलन** का **अग्रदूत** माना जाता है।

सत्याग्रह को प्रेरित करने वाले कारक

- **ईस्ट इंडिया कंपनी** द्वारा समर्थित **ईसाई मिशनरियों** ने अपनी पहुंच का विस्तार किया था और कई निचली **जातियों** ने **दमनकारी व्यवस्था** के **चंगुल** से बचने के लिए **ईसाई धर्म** अपना लिया था जो उन्हें बांधे हुए थी।
- इनमें से सबसे महत्वपूर्ण एक **आधुनिक शिक्षा प्रणाली** की शुरूआत थी जिसमें सभी **निम्न जातियों** के लिए भी **मुफ्त प्राथमिक शिक्षा** शामिल थी।
- **पूंजीवाद** की ताकतों और इन सुधारों ने **नए सामाजिक पदानुक्रम** बनाए जो हमेशा **पारंपरिक पदानुक्रमों** के अनुरूप नहीं थे।

5. त्रिपुरा की पारंपरिक आदिवासी पोशाक 'रिसा' को GI टैग मिला: त्रिपुरा सीएम - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: भारतीय संस्कृति में प्राचीन से लेकर आधुनिक काल तक कला रूपों, साहित्य और वास्तुकला के प्रमुख पहलुओं को शामिल किया जाएगा।

प्रीलिम्स टेकअवे
- रीसा पोशाक
- GI टैग

समाचार:

- **त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा** ने **अगरतला** में बताया कि **त्रिपुरा** की **पारंपरिक जनजातीय पोशाक** को भी **GI टैग** की मान्यता दी गई है।

रीसा पोशाक:

- यह ए**क हाथ** से **बुना हुआ** कपड़ा है जिसका **उपयोग महिलाओं** के **ऊपरी परिधान** के रूप में और **सम्मान व्यक्त** करने के लिए **हेडगियर, स्टोल** या **उपहार** के रूप में भी किया जाता है।
- इसे रंगीन डिज़ाइनों में बुना गया है और इसका महत्वपूर्ण सामाजिक और धार्मिक महत्व है।
- लगभग **12 से 14 वर्ष** की आयु की **त्रिपुरी किशोरियों** को सबसे पहले **रिसा सोरमानी** नामक एक कार्यक्रम में पहनने के लिए एक **रिसा** दिया जाता है।
- **धार्मिक प्रासंगिकता:** रिसा का उपयोग आदिवासी समुदायों द्वारा गरिया पूजा जैसे धार्मिक त्योहारों में किया जाता है, शादियों और त्योहारों के दौरान पुरुषों द्वारा पगड़ी, धोती के ऊपर कमरबंद, युवा लड़कियों और लड़कों द्वारा सिर पर स्कार्फ और सर्दियों के दौरान मफलर का उपयोग किया जाता है।
- इसे विशिष्ट प्राप्तकर्ताओं के सम्मान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।
- रिसा त्रिपुरा के लगभग सभी **19 भारतीय जनजातीय समुदायों** में आम है।
- पारंपरिक त्रिपुरी महिला पोशाक में **रिसा, रिग्नाई और रिकुतु** तीन भाग होते हैं ।
- रिसा एक हाथ से बुना हुआ कपड़ा है जिसका उपयोग महिलाओं के ऊपरी परिधान के रूप में किया जाता है।
- **रिगनाई** को मुख्य रूप से **निचले परिधान** के रूप में पहना जाता है और इसका **शाब्दिक** अर्थ **'पहनना'** है।
- **रितुकु** का उपयोग मुख्य रूप से एक **आवरण** के रूप में, या **'चुनरी'** या **भारतीय साड़ी** के **'पल्लू'** की तरह किया जाता है। इसका उपयोग **नवविवाहित त्रिपुरी महिलाओं** के **सिर** को **ढंकने** के लिए भी किया जाता है।

- ऐसा दावा किया जाता है कि संपूर्ण **त्रिपुरी पोशाक** की उत्पत्ति **माणिक्य राजाओं** के समय से भी पहले हुई थी, जिन्होंने **15वीं शताब्दी** से लेकर **500** से अधिक वर्षों तक **त्रिपुरा पर शासन** किया था।

6. जयपुर की सदियों पुरानी 'गुलाल गोटा' होली की परंपरा - इंडियन एक्सप्रेस

प्रीलिम्स टेकअवे
- भौगोलिक संकेत (GI) टैग
- जयपुर

प्रासंगिकता: भारतीय संस्कृति प्राचीन से आधुनिक काल तक कला रूपों, साहित्य और वास्तुकला के प्रमुख पहलुओं को कवर करेगी।

समाचार:
- **राजस्थान** के **जयपुर** के कुछ हिस्सों में, एक **पुरानी परंपरा** निभाई जाएगी जहां लगभग **400 साल पुरानी "गुलाल गोटा"** नामक एक अनोखे माध्यम से रंग फेंके जाएंगे।

गुलाल गोटा क्या है?
- **गुलाल गोटा लाख** से बनी एक **छोटी गेंद** होती है, जिसमें **सूखा गुलाल** भरा होता है।
- **स्थानीय कारीगरों** का कहना है कि **गुलाल गोटा** बनाने के लिए पहले **लाख** को **पानी** में **उबालकर** उसे लचीला बनाया जाता है।
- लाख एक **रालयुक्त पदार्थ** है जो कुछ **कीड़ों** द्वारा स्रावित होता है।
- इसका उपयोग **चूड़ियाँ बनाने** में भी किया जाता है।

जयपुर में गुलाल गोटे की परंपरा कैसे बन गई?
- **गुलाल गोटा** केवल **जयपुर** में **मुस्लिम लाख निर्माताओं**, जिन्हें **मनिहार** कहा जाता है, द्वारा बनाया जाता है।

जयपुर
- **जयपुर शहर** की स्थापना **वर्ष 1727** में हुई थी।
- इसके संस्थापक **सवाई जय सिंह द्वितीय,** कला के प्रशंसक थे
- **पूर्व शाही परिवार** को त्योहार के लिए अपने **महल** में **गुलाल गोटे** का ऑर्डर देने के लिए भी जाना जाता है।

इस कार्य का भविष्य कैसा है?
- परंपरा को बचाने के लिए, कुछ **गुलाल गोटा निर्माताओं** ने **भौगोलिक संकेत टैग** की मांग की है।
- **GI टैग** किसी उत्पाद के बारे में **जागरूकता** बढ़ाने और उसकी **स्थान-विशिष्ट विशिष्टता** को उजागर करने में मदद कर सकता है।
- यह मूल रचनाकारों को अपने उत्पादों को नकल से सुरक्षित रखने में भी मदद करता है।

7. कम्बम घाटी:'दक्षिण भारत के ग्रेप्स सिटी- इंडियन एक्सप्रेस

प्रीलिम्स टेकअवे
- कंबुम घाटी
- GI टैग

प्रासंगिकता: भारतीय संस्कृति प्राचीन से आधुनिक काल तक कला रूपों, साहित्य और वास्तुकला के प्रमुख पहलुओं को कवर करेगी।

समाचार:
- **दक्षिण भारत** का **कंबुम घाटी ग्रेप्स सिटी मस्कट हैम्बर्ग (पनीर थिराचाई)** की **खेती** के लिए बहुत लोकप्रिय है।
- उल्लेखनीय है कि **घाटी देश** में **पनीर थिराचाई उत्पादन** में **85%** तक का योगदान देती है।

पन्नीर ग्रेप: दक्षिण भारत से वर्ष भर मिलने वाला उपहार
- **पन्नीर ग्रेप** एक विशेष अंगूर की किस्म है जो मुख्य रूप से **तमिलनाडु** की **कंबुम घाटी** में उगाई जाती है।
- **सीमित फसल** के मौसम वाले अधिकांश **भारतीय अंगूरों** के विपरीत, **पन्नीर ग्रेप** साल भर फलते-फूलते हैं।
- यह उन्हें उनके **त्वरित विकास** और **शीघ्र परिपक्वता** के लिए किसानों के बीच पसंदीदा बनाता है।

पन्नीर ग्रेप के फायदे
- **वर्सटिलिटी** : ये अंगूर वाइन, स्प्रिट, जैम, डिब्बाबंद जूस और किशमिश बनाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं।
- **स्वास्थ्य लाभ** : विटामिन, टार्टरिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर पन्नीर ग्रेप पुरानी बीमारियों के खतरे को कम करने के लिए जाना जाता है।
- **सुपीरियर टेस्ट**: ये अपने विशिष्ट बैंगनी-भूरे रंग के साथ-साथ एक स्वादिष्ट स्वाद का भी दावा करते हैं।
- **भौगोलिक पहचान** : इसके अद्वितीय गुणों की मान्यता में, पन्नीर ग्रेप को 2023 में भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ।

- **तमिलनाडु** के **पश्चिमी घाट** में बसी **कंबुम घाटी** को उपयुक्त रूप से **"दक्षिण भारत का ग्रेप्स सिटी"** का उपनाम दिया गया है।
- यह क्षेत्र **पन्नीर ग्रे**प की खेती का गढ़ है, **मस्कट हैम्बर्ग किस्म** (पन्नीर का दूसरा नाम) इस क्षेत्र के अंगूर के बागानों का लगभग **85%** हिस्सा है।

8. वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड वॉच 2025 के नामांकन हेतु काज़ुवेली वाटरशेड क्षेत्र का प्रस्ताव रखा- द हिंदू

प्रासंगिकता: भारतीय संस्कृति प्राचीन से आधुनिक काल तक कला रूपों, साहित्य और वास्तुकला के प्रमुख पहलुओं को कवर करेगी।

प्रीलिम्स टेकअवे
- वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड वॉच 2025 कार्यक्रम।

समाचार:
- **विल्लुपुरम जिले** के काज़ुवेली वाटरशेड क्षेत्र में **एरी (टैंक) नेटवर्क**, जिसमें **हजारों साल** पहले बनाए गए **टैंकों** का एक अ**विश्वसनीय नेटवर्क** शामिल है, को **विश्व स्मारक निधि वॉच 2025** कार्यक्रम में नामांकन के लिए प्रस्तावित किया जाना है।

मुख्य बिंदु
- **विश्व स्मारक कोष (WMF)** एक **प्रमुख गैर-लाभकारी संगठन** है जो दुनिया के सबसे **मूल्यवान ऐतिहासिक** और **सांस्कृतिक स्थलों** की सुरक्षा के लिए समर्पित है।
- उनका मिशन न केवल इन स्थानों को संरक्षित करना है बल्कि **संस्कृतियों** के बीच समझ और प्रशंसा को बढ़ावा देने के लिए भी उनका उपयोग करना है।
- **वर्ष 1965** से, उन्होंने **112 देशों** में **700** से अधिक **ऐतिहासिक स्थलों** के संरक्षण के लिए **उच्चतम अंतरराष्ट्रीय मानकों** को लागू किया है।
- **WMF** केवल इमारतों को बचाने से आगे बढ़कर **विरासत संरक्षण** के माध्यम से वर्तमान मुद्दों से निपटता है।
- इसमें जलवायु परिवर्तन, संरक्षण प्रयासों में सभी संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना, पर्यटन के प्रभाव का प्रबंधन करना और समुदायों को संकटों से उबरने में मदद करना जैसी चुनौतियाँ शामिल हैं।
- इनका मुख्यालय **न्यूयॉर्क शहर** में है.
- **वर्ष 2015** में स्थापित **WMF** इंडिया एक **वैश्विक नेटवर्क** का हिस्सा है।
- यह **कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी कार्यक्रमों** में **विरासत संरक्षण** को शामिल करने की **भारत की नीति** के अनुरूप है।
- **WMF** की प्रमुख पहलों में से एक **वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच** है।
- हर **दो साल** में, **वॉच 25 महत्वपूर्ण स्थानों** पर प्रकाश डालता है, इन स्थानों और उनकी देखभाल करने वाले समुदायों के लिए जागरूकता और समर्थन बढ़ाता है।
- वॉच का **लक्ष्य स्थानीय प्रयासों** को सशक्त बनाना और इन **ऐतिहासिक स्थलों** से जुड़े लोगों के जीवन में सुधार करना है।

  वर्ष 2025 वॉच 25 ऐसे स्थानों पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिनमें से प्रत्येक में **वैश्विक महत्व** के साथ स्थानीय महत्व की एक अनूठी कहानी होगी।

9. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 18 स्मारकों को संरक्षित सूची से बाहर करेगा -द हिंदू

प्रासंगिकता: भारतीय संस्कृति प्राचीन से आधुनिक काल तक कला रूपों, साहित्य और वास्तुकला के प्रमुख पहलुओं को कवर करेगी।

प्रीलिम्स टेकअवे
- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
- AMASR अधिनियम

समाचार:
- ASI ने **18 संरक्षित स्मारकों को सूची** से हटाने का फैसला किया है।
- ASI का कहना है कि स्मारकों **का 'राष्ट्रीय महत्व'** नहीं रह गया है।
- **18 'खोये** हुए' **स्मारकों** में **उत्तर प्रदेश** के **नौ स्मारक शामिल** हैं।

AMASR अधिनियम

- **वर्ष 1958** में पारित और **वर्ष 2010** में अद्यतन **, AMASR अधिनियम** भारत के सबसे मूल्यवान **ऐतिहासिक स्थलों और स्मारकों** की रक्षा करने वाली ढाल की तरह है।
- यह सरकार को इन स्थानों को आधिकारिक तौर पर **"राष्ट्रीय महत्व"** घोषित करने की अनुमति देता है।
- वर्तमान में उ**त्तर प्रदेश** में इन संरक्षित स्थलों की संख्या सबसे अधिक है।
- **सार्वजनिक इनपुट** पर विचार करने के बाद, **सरकार सार्वजनिक** घोषणा के माध्यम से **आधिकारिक** तौर पर किसी **स्मारक** को इस दर्जे के योग्य घोषित कर सकती है।
- एक बार नामित होने के बाद, देखभाल और रखरखाव की जिम्मेदारी **संस्कृति मंत्रालय** के तहत **भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI)** पर आती है।
- ये इन ऐतिहासिक खजानों के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं।

स्मारकों की सुरक्षा करना

- इन स्मारकों की सुरक्षा के लिए, **AMASR अधिनियम** उनके **चारों ओर विशेष** क्षेत्र बनाता है।
- स्मारक के आसपास का **100 मीटर** का दायरा एक **"निषिद्ध क्षेत्र"** बन जाता है जहां निर्माण पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
- इसके अलावा, अतिरिक्त **100-मीटर क्षेत्र को** सख्त भवन दिशानिर्देशों के साथ **"विनियमित क्षेत्र"** के रूप में नामित किया गया है।
- यदि यह माना जाता है कि किसी स्मारक ने अपना **राष्ट्रीय महत्व** खो दिया है, तो **ASI** के पास उसे **संरक्षित सूची** से हटाने का अधिकार है।
- हालाँकि, इसका मतलब यह भी है कि ASI अब इसके रखरखाव के लिए ज़िम्मेदार नहीं है।

10. मोहिनीअट्टम: कलामंडलम ने 'लैंगिक विभाजन' को समाप्त किया- द हिंदू

प्रासंगिकता: भारतीय संस्कृति प्राचीन से आधुनिक काल तक कला रूपों, साहित्य और वास्तुकला के प्रमुख पहलुओं को कवर करेगी।

प्रीलिम्स टेकअवे
- मोहिनीअट्टम
- शास्त्रीय नृत्य

समाचार:

- **मोहिनीअट्टम, केरल** का एक **मनमोहक शास्त्रीय नृत्य,** एक **प्राचीन विरासत** का दावा करता है।
- संस्कृत पाठ **"नाट्य शास्त्र"** में निहित, इस नृत्य शैली की उत्पत्ति संभवतः **9वीं और 12वीं शताब्दी ईस्वी** के बीच हुई थी, जो **पारंपरिक रूप** से **चेरा राजवंश** के दौरान **देवदासियों** के नाम से जाने जाने वाले **मंदिर नर्तकियों** द्वारा किया जाता था।

मोहिनीअट्टम

- यह एक **एकल नृत्य** है जिसकी विशेषता इसकी **सुंदर स्त्रीत्व** है।
- यह **लास्य शैली** से संबंधित है, जो देवताओं, विशेष रूप से **भगवान विष्णु या उनके अवतार, कृष्ण** के **प्रति प्रेम और भक्ति** की **कोमल गतिविधियों** और **अभिव्यक्तियों** पर जोर देती है।
- प्रदर्शन में **नृत्य, गीत और कहानी** कहने का संयोजन होता है।
- गाने आमतौर पर **मणिप्रवलम** में गाए जाते हैं, जो **संस्कृत** और **मलयालम का मिश्रण** है, जबकि संगीत **कर्नाटक शैली** का अनुसरण करता है। **नर्तक या गायक गायन** प्रस्तुत कर सकते हैं।

विशेषताएँ

- कई नृत्यों के विपरीत, **मोहिनीअट्टम जटिल फुटवर्क** के बजाय **सुंदर शरीर** के **आंदोलनों** पर ध्यान केंद्रित करता है।
- इसके बजाय, यह **भावनाओं** को व्यक्त करने के लिए **अभिव्यंजक हाथ के इशारों** ("हस्थ लक्षणा दीपिका" पाठ से लिया गया) और **सूक्ष्म चेहरे** के भावों को **प्राथमिकता** देता है।
- नर्तक खुद को **पारंपरिक सफेद** या **हाथीदांत क्रीम साड़ियों** से सजाते हैं, जिन पर अक्सर सोने की कढ़ाई की जाती है।

- लयबद्ध संगत मृदंगम, मधलम, बांसुरी, वीणा और झांझ जैसे वाद्ययंत्रों से आती है।

INDIAN SOCIETY

11. महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले केवल दो-तिहाई कानूनी अधिकार: विश्व बैंक - डाउन टू अर्थ

प्रासंगिकता: महिलाओं और महिला संगठनों की भूमिका, जनसंख्या और संबंधित मुद्दे, गरीबी और विकास संबंधी मुद्दे, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके समाधान।

प्रीलिम्स टेकअवे
- विश्व बैंक
- महिला, व्यवसाय और कानून सूचकांक

समाचार:
- **विश्व बैंक समूह** की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, **दुनिया भर** में **महिलाओं** के लिए **कानूनी अधिकार शुरुआती** अनुमान से काफी कम हैं।

मुख्य बिंदु
- **विश्व बैंक का महिला, व्यवसाय** और **कानून सूचकांक मापता** है कि **190 देशों** में **कानून** और **नियम महिलाओं** के आर्थिक अवसरों को कैसे प्रभावित करते हैं।
- यह **0 से 100** के पैमाने का उपयोग करता है, जिसमें **100 पुरुषों** और **महिलाओं** के लिए **समान कानूनी अधिकारों** का **प्रतिनिधित्व** करता है।
- **नवीनतम 2024 रिपोर्ट** इस बात पर प्रकाश डालती है कि किसी भी देश ने अपने कानूनी ढांचे में पूर्ण **लैंगिक समानता** हासिल नहीं की है।
- **हिंसा और बच्चों** की देखभाल से संबंधित **कानूनी भेदों** पर विचार करते समय, यह पाया गया कि महिलाओं के पास पुरुषों द्वारा प्राप्त अधिकारों का **दो-तिहाई** या **64 प्रतिशत** से भी कम अधिकार हैं।
  - पहले अनुमान लगाया गया था कि **महिलाओं** के पास **77 प्रतिशत** अधिकार हैं।
- इसका मतलब यह है कि हर जगह महिलाओं को अभी भी **गतिशीलता, काम, वेतन, विवाह, माता-पिता बनने, व्यवसाय के स्वामित्व** और **संपत्ति** के अधिकार जैसे क्षेत्रों में पुरुषों की तुलना में **कानूनी बाधाओं** का सामना करना पड़ता है।
- **वैश्विक स्तर पर भारत की रैंकिंग** सुधरकर **113वीं** हो गई है, लेकिन **भारतीय महिलाओं** के पास अभी भी **पुरुषों** को दिए गए **कानूनी अधिकारों** का **केवल 60%** है, जो **वैश्विक औसत 64.2%** से कम है।

12. लिसु और सिंगफो समुदाय परिवारों में जन्म के क्रम को दर्शाते हैं- द हिंदू

प्रासंगिकता: भारतीय संस्कृति प्राचीन से आधुनिक काल तक कला रूपों, साहित्य और वास्तुकला के प्रमुख पहलुओं को कवर करेगी।

प्रीलिम्स टेकअवे
- मानचित्र आधारित प्रश्न
- सिंगफो समुदाय

समाचार:
- **अरुणाचल प्रदेश** और **असम** में **लिसु और सिंगफो समुदायों** के बच्चों का नाम उनके परिवार में पैदा हुए क्रम के अनुसार रखा जाता है, जिसमें उनके **नाम में संख्याएं शामिल** होती हैं।

एक लिसु और सिंगफो परंपरा
- **लिसु और सिंगफो समुदायों** में, **नाम एक विशेष** अर्थ रखते हैं।
- ये न केवल व्यक्तियों की पहचान करते हैं, बल्कि जन्म क्रम के आधार पर परिवार में उनके स्थान की भी पहचान करते हैं।
- लिसु लोग, जिनकी संख्या **भारत** में **लगभग 5,000** है, मुख्य रूप से **अरुणाचल प्रदेश** के **पहाड़ी क्षेत्रों** में रहते हैं।
- ये चीन, म्यांमार और थाईलैंड में भी पाए जाते हैं।
- **सिंगफो** आबादी अधिक व्यापक है, जो **चीन** के कुछ हिस्सों में निवास करती है, और **भारत के अरुणाचल प्रदेश (चांगलांग और नामसाई जिले)** और **असम (तिनसुकिया जिले)** में निवास करती है

अरुणाचल प्रदेश

- **अरुणाचल प्रदेश** का आधुनिक इतिहास **1826 में यांडाबू** की **संधि** (प्रथम आंग्ल-बर्मी युद्ध के बाद) के माध्यम से शुरू किए गए **ब्रिटिश नियंत्रण** से शुरू होता है।
  - वर्ष 1838 तक **नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी (NEFA)** की स्थापना में विकसित हुआ।
- वर्ष 1914 में, **शिमला संधि ने तिब्बत** और **नेफा** के बीच **सीमा** स्थापित की, जिसे **चीन, तिब्बत** और **ब्रिटिश शासकों** ने मान्यता दी।
- **वर्ष 1962** से पहले, **अरुणाचल प्रदेश असम** के **संवैधानिक अधिकार क्षेत्र** के अंतर्गत था, जो बाद में अपने **रणनीतिक महत्व** के कारण अलग प्रशासन के तहत एक **केंद्र शासित प्रदेश** में परिवर्तित हो गया।
- **अरुणाचल प्रदेश** को **20 फरवरी 1987** को **55वें संवैधानिक संशोधन** के माध्यम से **पूर्ण राज्य** का दर्जा प्राप्त हुआ और यह **भारतीय संघ का 24वां राज्य** बन गया।
  - **जनजातीय क्षेत्रों** को विशिष्ट **राज्य पहचान प्रदान** करने की **राष्ट्रीय नीति** के अनुरूप।

13. लैंसेट रिपोर्ट: भारत में प्रजनन दर में गिरावट इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: महिलाओं और महिला संगठनों की भूमिका, जनसंख्या और संबंधित मुद्दे, गरीबी और विकास संबंधी मुद्दे, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके समाधान।

प्रीलिम्स टेकअवे
- TFR
- मृत्यु दर

समाचार:
- **लैंसेट** की एक रिपोर्ट के अनुसार, **भारत** अगले **तीन दशकों** में एक **वृद्ध समाज** में बदल जाएगा।
- **मेडिकल जर्नल** ने बताया है कि भारत की **TFR**, एक **महिला** से पैदा होने वाले **बच्चों** की **औसत संख्या वर्ष 2050** में गिरकर **1.29** हो जाएगी।

मुख्य बिंदु
- **वर्ष 2050** में **भारत** में **हर पांच** में से एक व्यक्ति **60 वर्ष** से अधिक आयु का होगा।
- पिछले साल, **संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNPF**) की **इंडिया एजिंग रिपोर्ट** में अनुमान लगाया गया था कि **भारत में बुजुर्गों** की संख्या **वर्ष 2022** में **149 मिलियन** से **दोगुनी** होकर सदी के मध्य तक **347 मिलियन** हो जाएगी।
- बढ़ती उम्रदराज़ आबादी की चुनौतियाँ दशकों दूर हो सकती हैं।
- हालाँकि, युवा देश के लिए उनके लिए पहले से तैयारी करना अच्छा रहेगा।

जनसांख्यिकीय लाभांश चुनौती
- **लैंसेट** रिपोर्ट एक संदेश है कि भारत का **जनसांख्यिकीय लाभांश** हमेशा के लिए नहीं है।
- वैश्विक अनुभव देश के **नीति निर्माताओं** के लिए उदाहरण हो सकते हैं।
- उदाहरण के लिए, **चीन** में, **कामकाजी उम्र** की आबादी का अनुपात **वर्ष 1987** में **50 प्रतिशत** को पार कर गया और पिछले दशक के मध्य में अपने चरम पर पहुंच गया।
- यही वह अवधि थी जब देश ने प्रभावशाली आर्थिक विकास दर्ज किया था।
- पिछले साल तक, चीन की **TFR रिकॉर्ड** निचले स्तर पर आ गई थी और इसकी **कामकाजी उम्र** की आबादी में **40 मिलियन** से अधिक की कमी आई थी।
- चीनी सरकार के **जनसंख्या-वृद्धि समर्थक** उपाय काम करते नहीं दिख रहे हैं।
- वास्तव में, विकसित देशों के पिछले **60 वर्षों** के इतिहास से पता चलता है कि एक बार **प्रजनन दर प्रतिस्थापन दर** से नीचे आ जाए, तो उसे वापस स्थापित करना लगभग असंभव है।
- भारत की **TFR** वर्तमान में **प्रतिस्थापन** दर से ठीक नीचे है, और **UNPF** गणना के अनुसार, देश की कामकाजी आयु की आबादी का हिस्सा **वर्ष 2030** के अंत में, **वर्ष 2040** के दशक की शुरुआत में चरम पर होगा।
- इसलिए, **नीति निर्माताओं** को **भारत** के **जनसांख्यिकीय लाभांश** को अधिकतम करने के लिए इस विंडो का उपयोग करना चाहिए, जैसा कि चीन ने **वर्ष 1980** के दशक के अंत से लेकर पिछले दशक के शुरुआती वर्षों तक किया था।
- **कौशल की कमी** को दूर करने और ज्ञान **अर्थव्यवस्था** में कमियों को दूर करने के उपाय करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए।
- चुनौती कृषि के बाहर नौकरियां उत्पन्न करने की भी होगी, ये कम वेतन वाले **अनौपचारिक क्षेत्र** में नहीं होनी चाहिए।
- आगे बढ़ते हुए, **नीति निर्माताओं** को बढ़ती **बुजुर्ग आबादी** के लिए पर्याप्त **सामाजिक सुरक्षा** और **स्वास्थ्य** देखभाल प्रावधान भी सुनिश्चित करने होंगे और उनके **कौशल का प्रभावी ढंग** से उपयोग करने के अवसर पैदा करने होंगे।

आगे की राह

- भारत के राज्यों में अलग-अलग **TFR** दरें देश के **योजनाकारों** के लिए कुछ अनोखी चुनौती पेश कर सकती हैं, वास्तव में, पहले से ही संकेत हैं कि **दक्षिण भारत** और **पश्चिम भारत** के कुछ हिस्से उत्तर की तुलना में तेजी से भूरे हो रहे हैं।
- **नीति निर्माताओं** को इसके **सभी आयामों** में **जनसांख्यिकीय बदलाव** को समझने और बदलाव के लिए तैयार रहने के लिए तैयार रहना चाहिए।

GEOGRAPHY

14. अर्जेंटीना भारत की लिथियम खोज को बढ़ावा देगा- द हिंदू

प्रासंगिकता: दुनिया भर में प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण (दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप सहित); विश्व के विभिन्न हिस्सों (भारत सहित) में प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों की स्थिति के लिए जिम्मेदार कारक।

प्रीलिम्स टेकअवे
- लिथियम
- KABIL

समाचार:
- अधिकारियों ने कहा कि **खान मंत्रालय** ने **अर्जेंटीना में लिथियम** की खोज गतिविधियां शुरू करने के लिए **स्थानीय भागीदारों** को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की है।

मुख्य विचार
- राज्य के स्वामित्व वाली **KABIL** (खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड) नाल्को, **हिंदुस्तान कॉपर** और **मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MECL)** के बीच एक संयुक्त उद्यम है।
  - इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए, पांच लिथियम ब्राइन ब्लॉकों का अधिग्रहण किया, जिनके नाम हैं Cortadera-I, Cortadera-VII, Cortadera-VIII, Cateo-2022-01810132 और Cortadera-VI.

शाखा कार्यालय
- एक **सरकारी अधिकारी** ने **बिजनेसलाइन** को बताया कि **KABIL लैटिन-अमेरिकी राष्ट्र** में एक शाखा कार्यालय भी स्थापित करेगा।
- भारत ने इन पांच ब्लॉकों के लिए **अन्वेषण और विशिष्टता अधिकार** प्राप्त कर लिया है। समझौता हमें **भंडार** का **मूल्यांकन**, **संभावना** और **अन्वेषण करने की** अनुमति देगा।
  - और, लिथियम खनिजों की बाद की खोज पर, वाणिज्यिक उत्पादन के अधिकारों की भी अनुमति दी गई है।
- **MoU** में कहा गया है कि **KABIL** को **पांच साल** की समय सीमा दी गई है, जिसके भीतर इन ब्लॉकों में **अन्वेषण गतिविधियां** शुरू करनी होंगी, जिसके विफल होने पर **"भारी जुर्माना"** देना होगा।

लिथियम
- यह एक क्षार खनिज है, जिसे '**सफेद सोना**' भी कहा जाता है। यह **सॉफ्ट चांदी-सफेद धातु** है, जो **आवर्त** सारणी की **सबसे हल्की** धातु है।

प्रमुख गुण:
- उच्च प्रतिक्रियाशीलता
- कम घनत्व
- उत्कृष्ट विद्युत रासायनिक गुण

घटना और शीर्ष निर्माता:
- **लिथियम प्राकृतिक** रूप से विभिन्न खनिजों में पाया जाता है, जिनमें **स्पोड्यूमिन, पेटालाइट** और **लेपिडोलाइट** शामिल हैं।
- इसे इन खनिजों से निकाला जाता है और **लिथियम धातु** या इसके **यौगिकों** में **परिष्कृत** किया जाता है।
- **लिथियम** के शीर्ष उत्पादक **ऑस्ट्रेलिया, चिली, चीन और अर्जेंटीना हैं।**

- 2022 में, लिथियम खदान उत्पादन के मामले में **ऑस्ट्रेलिया विश्व** में अग्रणी था, **चिली दूसरे** और **चीन** तीसरे स्थान पर था।
- भारत में प्रमुख **लिथियम भंडार कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड और आंध्र प्रदेश** जैसे राज्यों में केंद्रित हैं।
- इन राज्यों में **लिथियम युक्त खनिजों** के महत्वपूर्ण भंडार हैं, जो निष्कर्षण की पर्याप्त क्षमता प्रदान करते हैं।

15. पूर्ण सूर्य ग्रहण 2024: कहां और कब- फाइनेंशियल एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: विश्व के भौतिक भूगोल की अलग-अलग विशेषताएँ।

प्रीलिम्स टेकअवे
- कोरोना
- ग्रहण

समाचार:
- वर्ष 2024में पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, जिससे सूर्य थोड़े समय के लिए गायब हो जाएगा।
- यह एक दुर्लभ खगोलीय घटना होगी क्योंकि यह सूर्य को पूरी तरह से ढक देगी, जिससे दिन के उजाले के दौरान रात का माहौल बन जाएगा।

पूर्ण सूर्यग्रहण:
- **पूर्ण सूर्य ग्रहण** वह स्थिति है जब **चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच** से गुजरता है और **सूर्य की डिस्क** को पूरी तरह से अवरुद्ध कर देता है, जिससे सतह पर एक बड़ी छाया बनती है।
- जो लोग उन स्थानों से ग्रहण देख रहे हैं जहां **चंद्रमा की छाया सूर्य को** पूरी तरह से ढक लेती है, जिसे **समग्रता का पथ** कहा जाता है, उन्हें **पूर्ण सूर्य ग्रहण** का अनुभव होगा।
- यदि **मौसम अनुकूल** रहा, तो समग्रता के मार्ग पर चलने वाले व्यक्तियों को **सूर्य के कोरोना** का निरीक्षण करने का अवसर मिलेगा, इसका **बाहरी वातावरण आमतौर** पर सूर्य के **उज्ज्वल चेहरे** से अस्पष्ट होता है।
- **सूर्य का कोरोना**, उसके **वायुमंडल** की सबसे बाहरी परत जो **अंतरिक्ष में लाखों किलोमीटर** तक फैली हुई है, विशेष रूप से **सूर्य ग्रहण** के दौरान दिखाई देती है।
- **सूर्य** की अं**धेरी डिस्क** को घेरते हुए एक **फीके**, **मोती-सफ़ेद प्रभामंडल** के रूप में दिखाई देना, यह केवल इस **खगोलीय घटना** के दौरान ही देखने योग्य हो जाता है।
- इस सूर्य ग्रहण की विशेषता एक ऐसी घटना होगी जिसे समग्रता के रूप में जाना जाता है, एक ऐसी स्थिति जब दर्शक कोरोना के साथ-साथ **क्रोमोस्फीयर** (सौर वातावरण का एक क्षेत्र, जो चंद्रमा के चारों ओर गुलाबी रंग के पतले घेरे के रूप में दिखाई देता है) को देखने में सक्षम हो सकते हैं।
- समग्रता एक दुर्लभ दृश्य प्रस्तुत करेगी जहां आप उस समय क्षण भर के लिए तारों को देख सकते हैं जब आसपास का वातावरण पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है।
- इसे हवा के तापमान में गिरावट से भी चिह्नित किया जाएगा।

16. भारत महत्वपूर्ण खनिजों के लिए अब अफ्रीका से बातचीत करेगा - द हिंदू

प्रासंगिकता: दुनिया भर में प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण (दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप सहित); विश्व के विभिन्न हिस्सों (भारत सहित) में प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों की स्थिति के लिए जिम्मेदार कारक।

प्रीलिम्स टेकअवे
- कोबाल्ट
- लिथियम

समाचार:
- भारत **कोबाल्ट और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों** सहित खनिजों के लिए **अफ्रीका** की ओर देख रहा है।
- देश अभी भी **लिथियम ब्लॉक** के लिए **ऑस्ट्रेलिया** के साथ बातचीत कर रहा है।

महत्वपूर्ण खनिज:
- **पहचान** : भारत ने स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा और उर्वरक सहित विभिन्न उद्योगों के लिए आवश्यक 30 महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान की है।
- **महत्व** : ये खनिज स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों और राष्ट्रीय विकास को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों और नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती मांग इन संसाधनों की बड़े पैमाने पर आवश्यकता पैदा करती है।

- **वैश्विक मांग** : जलवायु परिवर्तन शमन प्रयासों के कारण महत्वपूर्ण खनिजों की वैश्विक मांग आसमान छूने की उम्मीद है, जिससे भारत के लिए रणनीतिक योजना और संसाधन सुरक्षा महत्वपूर्ण हो जाएगी।

चुनौतियाँ और चिंताएँ:

- **एकाग्रता** : महत्वपूर्ण खनिज भंडार कुछ देशों, मुख्य रूप से चीन, में भारी मात्रा में केंद्रित हैं, जो असमान वितरण और प्रसंस्करण क्षमताओं के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में कमजोरियां पैदा कर रहे हैं।
- **चीन का प्रभुत्व** : महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ पृथ्वी को परिष्कृत करने में चीन का प्रभुत्व अपने एकाधिकार के माध्यम से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और तकनीकी प्रगति को प्रभावित करने की क्षमता के बारे में चिंता पैदा करता है।
- **निर्भरता जोखिम** : भारत के महत्वाकांक्षी स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य विशेष रूप से बैटरी निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा बुनियादी ढांचे के लिए महत्वपूर्ण खनिजों पर बहुत अधिक निर्भर हैं।
- अन्य देशों के साथ समझौतों के माध्यम से संसाधनों को सुरक्षित करने के प्रयासों के बावजूद, भारत आयात पर बहुत अधिक निर्भर है, जिससे घरेलू उद्योगों और तकनीकी प्रगति के लिए चुनौतियाँ पैदा हो रही हैं।

17. अल नीनो प्रभाव के कारण मलावी में खाद्य संकट -द हिंदू

प्रासंगिकता: महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएं जैसे भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी गतिविधि, चक्रवात आदि, भौगोलिक विशेषताएं और उनके स्थान-महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं (जल-निकायों और बर्फ-टोपियों सहित) और वनस्पतियों और जीवों में परिवर्तन और ऐसे परिवर्तनों के प्रभाव।

प्रीलिम्स टेकअवे
- मानचित्र आधारित प्रश्न
- अल नीनो

समाचार:

- **दक्षिणी अफ्रीकी** देश **मलावी** ने अपने **28 में से 23 जिलों** में **सूखे के कारण** आपदा की स्थिति घोषित कर दी है।
- इसके **राष्ट्रपति** ने यह भी कहा है कि मलावी को तत्काल **200 मिलियन डॉलर** से अधिक की **मानवीय सहायता** की आवश्यकता है, एक महीने से भी कम समय में **पड़ोसी जाम्बिया** ने भी मदद की अपील की थी।

मुख्य बिंदु

- एक तीसरा देश, जिम्बाब्वे, ने भी अपनी अधिकांश फसलों को नष्ट होते देखा है
  - और पिछले साल के अंत में **संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP)** द्वारा उठाई गई चिंताओं को रेखांकित करते हुए, सूखा आपदा घोषित करने पर विचार कर रहा है।
  - मौजूदा अल नीनो मौसम घटना के प्रभाव के कारण **दक्षिणी अफ्रीका** के कई देश भूख संकट के कगार पर थे।
- **WFP** के मौसमी **मॉनिटर** के अनुसार, पिछला महीना **ज़ाम्बिया** और **ज़िम्बाब्वे** के लिए **40 वर्षों** में सबसे शुष्क फरवरी था, जबकि म**लावी, मोज़ाम्बिक** और **अंगोला** के कुछ हिस्सों में "वर्षा की गंभीर कमी थी।
- **अल नीनो** एक **प्राकृतिक**, **आवर्ती मौसम** घटना है जो दुनिया भर के मौसम को प्रभावित करती है, जिसमें **दक्षिणी अफ्रीका** में औसत से कम वर्षा भी शामिल है।
- कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि **जलवायु परिवर्तन अल नीनो** को मजबूत बना रहा है और उनके प्रभाव अधिक गंभीर हो रहे हैं।
- **वर्ष 2015-2016 अल नीनो दक्षिणी अफ्रीका** में भयंकर सूखा लेकर आया, जो **35 वर्षों** में इस क्षेत्र का सबसे अधिक सूखा था, उदाहरण के लिए-
  - **मलावी और जाम्बिया** द्वारा **राष्ट्रीय आपदा घोषणाओं** से पहले ही **WFP USAID** ने **ग्रामीण जिम्बाब्वे** में **2.7 मिलियन लोगों** को **भोजन खिलाने** के लिए एक कार्यक्रम शुरू कर दिया था
  - जो उस **देश** की लगभग **20% आबादी** को **भोजन की कमी** का सामना करना पड़ रहा था।
- **ज़ाम्बिया** भी इस **समय हैजा** के **बड़े प्रकोप** का सामना कर रहा है।

18. जलपाईगुड़ी जिले में नॉरवेस्ट तूफान से कई लोग घायल हुए- द हिंदू

प्रासंगिकता: महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएं जैसे भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी गतिविधि, चक्रवात आदि, भौगोलिक विशेषताएं और उनके स्थान-महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं (जल-निकायों और बर्फ-टोपियों सहित) और वनस्पतियों और जीवों में परिवर्तन और ऐसे परिवर्तनों के प्रभाव।

प्रीलिम्स टेकअवे
- काल बैसाखी
- थुण्डरस्टॉर्म

समाचार:

- अधिकारियों ने कहा कि **उत्तरी बंगाल** के **जलपाईगुड़ी जिले** के कुछ हिस्सों में **नॉरवेस्टर तूफान** की चपेट में आने से **पांच लोगों की मौत** हो गई और लगभग **30 लोग घायल** हो गए।

काल बैसाखी या नॉरवेस्टर

- इसका उद्गम **छोटानागपुर पठार, रांची** और **जमशेदपुर शहरों** के आसपास होता है।
- इन ऊंचे क्षेत्रों में उच्च तापमान के बीच **नम हवा** के आक्रमण के समय, ये अत्यंत **विनाशकारी तूफान** आते हैं।
- नॉरवेस्टर का पहला संकेत उत्तर पश्चिम क्षेत्र में काले बादलों का एक निचला किनारा है, जिसकी ऊपरी रूपरेखा एक मेहराब की तरह दिखती है।
- यह पहले धीरे-धीरे और फिर तेज़ झोंके या तूफ़ान के साथ तेजी से निकट आता है।
- कभी-कभी हवा लगभग तूफ़ानी गति के साथ चलती है।

काल बैसाखी से प्रभावित राज्य कौन से हैं?

- काल बैसाखी **बिहार और झारखंड क्षेत्र** से निकलती है, पूर्व की ओर बढ़ती है और प**श्चिम बंगाल** और **ओडिशा** से टकराती है।

काल बैसाखी के लाभ

- काल बैसाखी निश्चित रूप से बिजली, तूफान, ओलावृष्टि और वर्षा के रूप में विनाश लाती है।
- हालाँकि, यह प्री-खरीफ फसलों जैसे जूट, धान और बड़ी संख्या में सब्जियों और फलों के लिए बेहद उपयोगी है।
- यह दोपहर की गर्मी के बाद वांछित राहत देता है और फसलों के विकास के लिए प्यासी मिट्टी पर अच्छी तरह से पानी डालता है।

काल बैसाखी से कौन से महीने प्रभावित होते हैं?

- काल बैसाखी अप्रैल और मई के दौरान एक सामान्य घटना है।
- हालाँकि, मार्च में काल बैसाखी की कुछ घटनाओं से भी इंकार नहीं किया जा सकता है।

सामान्य अध्ययन II

POLITY & GOVERNANCE

19. उच्च न्यायालयों के स्थगन आदेश स्वतः समाप्त नहीं होंगे: - द हिंदू/ छह महीने के बाद स्थगन आदेश स्वत: रद्द नहीं होंगे: सुप्रीम कोर्ट - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: भारत का संविधान-ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना।

प्रीलिम्स टेकअवे

- अनुच्छेद 142
- उच्च न्यायालय

समाचार:

- हाल ही में, **सुप्रीम कोर्ट** ने **एशियन रिसर्फेसिंग ऑफ रोड एजेंसी बनाम CBI** मामले में **वर्ष 2018** के फैसले की वैधता से संबंधित एक संदर्भ को संबोधित किया।
- इस मामले ने छह महीने के बाद **उच्च न्यायालयों** द्वारा पारित **अंतरिम स्थगन आदेशों** की स्वचालित **समाप्ति पर सवाल** उठाया, जब तक कि इसे बढ़ाया नहीं गया।

फैसला

- सुप्रीम कोर्ट **आपराधिक** और **सिविल कार्यवाही** पर रोक लगाने वाले **उच्च न्यायालयों** के **सुविचारित अंतरिम** आदेशों को मनमाने ढंग से पलट नहीं सकता है।
- शीर्ष अदालत के पास यह व्यापक नियम लागू करने का अधिकार नहीं है कि **उच्च न्यायालय** द्वारा जारी स्थगन **आदेश छह महीने** के बाद समाप्त हो जाएगा।
- इस तरह की बाधाएं संविधान के **अनुच्छेद 226** के तहत **उच्च न्यायालयों** के **अधिकार क्षेत्र** का अतिक्रमण करेंगी।
- इसके अलावा, फैसले में स्पष्ट किया गया कि **सुप्रीम कोर्ट** को **उच्च न्यायालयों** या **ट्रायल कोर्टों** द्वारा मामलों के निपटान के लिए निश्चित समयसीमा लागू करने से बचना चाहिए।
    - असाधारण परिस्थितियों से निपटने के लिए मामलों के निपटान के लिए बाहरी सीमा तय करने वाले आदेश केवल असाधारण परिस्थितियों में ही पारित किए जाने चाहिए।

- **पूर्ण न्याय** सुनिश्चित करने के लिए अ**नुच्छेद 142** के तहत **SC** का अधिकार उच्च न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों में **अत्यधिक हस्तक्षेप** तक नहीं है।
- **अनुच्छेद 142** को केवल अदालत के **समक्ष पक्षों के बीच पूर्ण न्याय** करने के लिए **असाधारण स्थितियों** से निपटने के लिए लागू किया जा सकता है।

20. केंद्र ने मडिगा सदस्य के लिए अनुसूचित जाति में जगह सुनिश्चित की- द हिंदू

प्रासंगिकता: केंद्र और राज्यों द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन कमजोर वर्गों की सुरक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थानों और निकायों का प्रदर्शन।

प्रीलिम्स टेकअवे
- काका कालेलकर आयोग
- 1950 का संविधान आदेश

समाचार:
- **केंद्र सरकार** ने **मडिगा समुदाय** से कम से कम एक **सदस्य की उपस्थिति** सुनिश्चित करके **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC)** का गठन करने का फैसला किया है।
- **मडिगा समुदाय** की **तेलंगाना और आंध्र प्रदेश** में बड़ी उपस्थिति है।

मुख्य बिंदु
- **सरकार** ने **दोनों राज्यों** में **मडिगा समुदाय** की दशकों पुरानी मांग के जवाब में **अनुसूचित जातियों** के **उप-वर्गीकरण** के लिए एक **आंतरिक समिति** का गठन किया।
- मडिगा समुदाय ने तर्क दिया है कि **अनुसूचित जाति** के सबसे अधिक आबादी वाले होने के बावजूद
  - अपेक्षाकृत प्रभावशाली माला समुदाय द्वारा इसे नियमित रूप से लाभ और आरक्षण से वंचित किया जाता है।
- हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस पर निर्णय नहीं लिया है कि क्या **अनुसूचित जाति आरक्षण** को **उप-वर्गीकृत** किया जा सकता है, **समिति अनुसूचित जाति** के इस वर्ग के लिए लाभ लक्षित करने के तरीकों पर विचार कर रही है।
- **मडिगा समुदाय तेलंगाना** में कुल **अनुसूचित जाति** का **लगभग 50%** हिस्सा है।
- वर्ष **2011** की जनगणना के अनुसार राज्य की **कुल आबादी में अनुसूचित जाति की आबादी 15%** से कुछ अधिक है ।
- मडिगा समुदाय **1994 से उप-वर्गीकरण के लिए संघर्ष** कर रहा था और **प्रधानमंत्री** की घोषणा को उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया था।

1950 का संविधान आदेश
- अस्पृश्यता की प्रथा से उत्पन्न होने वाली **सामाजिक विकलांगता** को संबोधित करने के लिए, इसमें शुरुआत में केवल हिंदुओं (अपवादों के साथ) को **अनुसूचित जाति** के रूप में मान्यता देने का प्रावधान किया गया था।
- **आदेश में 1956 में संशोधन किया गया था ताकि उन दलितों को शामिल किया जा सके जो सिख बन गए थे** (संपूर्ण रूप से) और **1990** में एक बार फिर उन **दलितों** को शामिल किया गया जो **बौद्ध धर्म** में परिवर्तित हो गए थे।
- दोनों संशोधनों को क्रमशः **वर्ष 1955** में **काका कालेलकर आयोग** और **वर्ष 1983** में **अल्पसंख्यकों**, **अनुसूचित जातियों** और **अनुसूचित जनजातियों** पर **उच्चाधिकार प्राप्त पैनल (HPP)** की रिपोर्टों से सहायता मिली।

21. भारत में उदार लोकतंत्र में गिरावट: वी-डेम रिपोर्ट - द हिंदू

प्रासंगिकता: कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली - सरकार के मंत्रालय और विभाग; दबाव समूह और औपचारिक/अनौपचारिक संघ और राज्य व्यवस्था में उनकी भूमिका।

प्रीलिम्स टेकअवे
- लोकतंत्र
- निरंकुशता

समाचार:
- भारत, जिसे **वर्ष 2018** में **"चुनावी निरंकुशता"** की स्थिति में **डाउनग्रेड** कर दिया गया था
- गोथेनबर्ग स्थित **वी-डेम इंस्टीट्यूट** द्वारा जारी **"डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024"** के अनुसार, वह "सबसे खराब निरंकुश लोगों में से एक" के रूप में उभरने के लिए कई मेट्रिक्स में और भी गिरावट आई है।

मुख्य बिंदु

- रिपोर्ट **लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स (LDI)** लिबरल डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी और क्लोज्ड ऑटोक्रेसी में उनके स्कोर के आधार पर **देशों** को **चार शासन प्रकारों** में वर्गीकृत करती है।
- दुनिया की **18%** आबादी के साथ भारत, **निरंकुश देशों** में रहने वाली आबादी का लगभग आधा हिस्सा है, "रिपोर्ट में कहा गया है।
- यह देखते हुए कि **लोकतंत्र** के लगभग **सभी घटक अधिक देशों** में खराब हो रहे हैं
  - ये बेहतर हो रहे थे, रिपोर्ट में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वच्छ चुनाव पर प्रकाश डाला गया
  - **निरंकुश देशों** में लोकतंत्र के **तीन सबसे बुरी** तरह प्रभावित **घटकों** के रूप में **संघ/नागरिक** समाज की स्वतंत्रता।
- **वर्ष** और काफी पीछे चला गया है, औसत भारतीय द्वारा प्राप्त "**उदार लोकतंत्र**" का स्तर अब "1975 के अंतिम स्तर तक नीचे आ गया है"
  - जब इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा की।
- **वी-डेम वर्गीकरण** के अनुसार, एक **उदार लोकतंत्र** वह है, जहां **नियमित स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव** जैसे चुनावी **लोकतंत्र** की आवश्यकताओं के अलावा, **नागरिक स्वतंत्रता** और **कानून के समक्ष समानता** की कठोर सुरक्षा के साथ-साथ **न्यायिक स्वतंत्रता** और कार्यकारी पहुंच पर प्रतिबंध के लिए तंत्र मजबूत होते हैं।
- भारत के संबंध में, रिपोर्ट में कहा गया है कि **भाजपा** और **श्री मोदी** के लिए लगातार **तीसरा कार्यकाल "मोदी** के नेतृत्व में पहले से ही पर्याप्त **लोकतांत्रिक गिरावट** और **अल्पसंख्यक अधिकारों औ**र **नागरिक समाज** पर स्थायी कार्रवाई को देखते हुए और **अधिक निरंकुशता** को जन्म दे सकता है"।

22. केवल संसद को ही खनिजों पर टैक्स लगाने का अधिकार है: सुप्रीम कोर्ट - इंडियन एक्सप्रेस

प्रीलिम्स टेकअवे
- MMDRA

प्रासंगिकता: कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली, सरकारी दबाव समूहों और औपचारिक/अनौपचारिक संघों के मंत्रालयों और विभागों और राजनीति में उनकी भूमिका।

समाचार:
- **सुप्रीम कोर्ट ने** केंद्र से पूछा कि क़ानून स्पष्ट शब्दों में यह क्यों नहीं कहता कि केवल **संसद** के पास **खनिजों** पर **टैक्स** लगाने की **शक्ति** है और **राज्यों** को इस तरह की **कार्रवाई** करने के **अधिकार** से वंचित किया गया है।

मुख्य बिंदु
- MMDRA की धारा 9 के तहत, केंद्र सरकार के पास रॉयल्टी तय करने की शक्ति है
- उन्होंने कहा कि **केंद्र द्वारा दरों** का निर्धारण एकतरफा नहीं बल्कि **राज्यों** को शामिल करने वाली **सहकारी** प्रक्रिया है, साथ ही राष्ट्र को एक इकाई के रूप में रखते हुए सार्वजनिक हित में **खनिज विकास के पर्यवेक्षण** उद्देश्य पर भी विचार किया जाता है।
- यह मुद्दा **वर्ष 1989** में **इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड बनाम तमिलनाडु राज्य** के मामले में फैसले के बाद उठा, जिसमें **शीर्ष अदालत** की **सात-न्यायाधीशों** की पीठ ने कहा कि **रॉयल्टी** एक कर है।
- हालाँकि, शीर्ष अदालत की **पांच-न्यायाधीशों** की पीठ ने **वर्ष 2004** में **पश्चिम बंगाल राज्य बनाम केसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड** मामले में फैसला सुनाया कि **वर्ष 1989** के फैसले में एक **टाइपोग्राफिक** त्रुटि थी और **रॉयल्टी** एक कर नहीं थी।
- इसके बाद विवाद को **नौ न्यायाधीशों** की बड़ी पीठ के पास भेज दिया गया।
- शीर्ष अदालत इस मुद्दे पर विभिन्न **उच्च न्यायालयों** द्वारा पारित विरोधाभासी फैसलों से उत्पन्न खनन कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र के **उपक्रमों** (**PSU**) और **राज्य सरकारों** द्वारा **दायर 86 अपीलों** पर सुनवाई कर रही है।

23. SBI ने चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड डेटा सौंपा- द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे
- चुनावी बॉन्ड
- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

प्रासंगिकता: कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली, सरकारी दबाव समूहों और औपचारिक/अनौपचारिक संघों के मंत्रालयों और विभागों और राजनीति में उनकी भूमिका।

समाचार:
- **सुप्रीम कोर्ट** के निर्देश के एक दिन बाद, **भारतीय स्टेट बैंक (SBI)** ने **चुनाव आयोग (EC)** को **12 अप्रैल, 2019** से खरीदे गए और भुनाए गए चुनावी बॉन्ड का विवरण सौंपा।

मुख्य बिंदु

- **सुप्रीम कोर्ट** ने **चुनावी बॉन्ड योजना** को **असंवैधानिक** करार देते हुए **SBI** को **चुनाव आयोग** को **चुनावी बॉन्ड डेटा** जमा करने का निर्देश दिया था।
- **शीर्ष अदालत** ने डेटा जमा करने के लिए **30 जून** तक का समय मांगने वाली **SBI** की याचिका खारिज कर दी।
- अदालत ने कहा कि डेटा चुनाव आयोग को सौंपा जाए
- चुनावी बॉन्ड की पहली बिक्री मार्च 2018 में हुई थी।
- 2018 में योजना की शुरुआत के बाद से SBI द्वारा ₹16,518 करोड़ के बॉन्ड जारी किए गए थे।

चुनावी बॉन्ड

- **चुनावी बॉन्ड** वचन पत्र की तरह धन उपकरण हैं, जिन्हें **भारत** में **कंपनियों और व्यक्तियों** द्वारा **भारतीय स्टेट बैंक (SBI)** से खरीदा जा सकता है।
- इसे एक **राजनीतिक दल** को दान दिया जाता है, जो बाद में इन बॉन्डों को भुना सकता है।
- बॉन्ड **केवल पंजीकृत राजनीतिक दल के निर्दिष्ट खाते में ही भुनाए जा सकते हैं।**
- एक व्यक्ति व्यक्तिगत होने के नाते अकेले या अन्य **व्यक्तियों** के साथ **संयुक्त रूप से बॉन्ड** खरीद सकता है।

चुनावी बॉन्ड योजना

- **भारत** में **राजनीतिक फंडिंग** को साफ़ करने के लिए 2018 में **चुनावी बॉन्ड योजना** शुरू की गई थी।
- **चुनावी बॉन्ड** योजना के पीछे मुख्य विचार **भारत** में **चुनावी फंडिंग** में पारदर्शिता लाना है।
- सरकार ने इस योजना को **"कैशलेस-डिजिटल अर्थव्यवस्था**" की ओर बढ़ रहे देश में "**चुनावी सुधार**" बताया था।

24. कावेरी पैनल चार साल के बाद पुडुचेरी में बैठक करेगा - द हिंदू

प्रासंगिकता: कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली - सरकार के मंत्रालय और विभाग; दबाव समूह और औपचारिक/अनौपचारिक संघ और राज्य व्यवस्था में उनकी भूमिका।

प्रीलिम्स टेकअवे
- कावेरी जल विवाद
- कावेरी नदी

समाचार:

- **कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC**) की हाल ही में **पुडुचेरी** में बैठक होगी
- यह दूसरी बार है जब **समिति केंद्र शासित प्रदेश** में विचार-विमर्श करेगी, जहां इसकी **आखिरी बैठक जनवरी 2020** में हुई थी।

मुख्य बिंदु

- हालाँकि **कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण** ने **कर्नाटक** को **वर्ष** के **कम महीनों** में **पर्यावरणीय प्रवाह** सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
- ऊपरी तटवर्ती **राज्य आदेश** का पालन करने में सक्षम नहीं है क्योंकि इसकी **राजधानी बेंगलुरु** गंभीर जल संकट की चपेट में है।
- इस बीच, **तमिलनाडु और कर्नाटक** के बीच **पेन्नैयार जल विवाद** पर वार्ता समिति, जिसकी पिछले महीने बैठक हुई थी, ने राज्य से डेटा मांगा है।

पेन्नैयार जल विवाद

- **वर्ष 2018** में, **तमिलनाडु** ने **पेन्नैयार नदी** पर **चेक बांध** और **डायवर्जन संरचनाओं** के निर्माण के लिए **कर्नाटक** के खिलाफ एक मूल मुकदमा दायर किया।
- **30 नवंबर, 2019** को, **तमिलनाडु** ने औपचारिक रूप से **केंद्र सरकार** से **नदी** के पानी पर विवादों के निपटारे के लिए एक **न्यायाधिकरण गठित** करने का अनुरोध किया।
- दिसंबर के मध्य में, अदालत ने **तमिलनाडु** और **कर्नाटक** के बीच विवाद को सुलझाने के लिए **ट्रिब्यूनल गठित** करने के लिए **केंद्र को तीन महीने** का समय दिया था।

कावेरी जल विवाद

- **कावेरी जल विवाद** कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर भारतीय राज्यों **कर्नाटक और तमिलनाडु** के साथ-साथ **केरल और पुडुचेरी** के बीच एक विवाद है।
- इसमें **जल आवंटन** और **उपयोग** के अधिकार के मुद्दे शामिल हैं, इसके **समाधान में ऐतिहासिक समझौते, न्यायाधिकरण और अदालती** फैसले महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

Crop cover

A look at paddy coverage in Tamil Nadu*

Region	Normal area	Target	Coverage on March 11, 2024	Coverage on March 13, 2023
			2023-24	2022-23
Samba/Thaladi/Pishanam				
Delta	8.914	13.263	11.927	13.528
Non-delta	21.716	21.902	21.055	22.984
TOTAL	**30.63**	**35.165**	**32.982**	**36.512**

* In lakh acres | Source: Department of Agriculture and Farmers' Welfare, Tamil Nadu government

25. सुप्रीम कोर्ट EC चयन पैनल में CJI को शामिल करने की याचिका पर सुनवाई करेगा- द हिंदू

प्रासंगिकता: कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली, सरकारी दबाव समूहों और औपचारिक/अनौपचारिक संघों के मंत्रालयों और विभागों और राजनीति में उनकी भूमिका।

समाचार:

प्रीलिम्स टेकअवे
- CEC और EC (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) अधिनियम, 2023
- निर्वाचन आयोग

- **सुप्रीम कोर्ट** उस याचिका पर तत्काल सहमत हो गया जिसमें कहा गया था कि **भारत चुनाव आयोग (ECI**) में **चुनाव आयुक्तों** (**EC**) की **दो रिक्तियों** को भरने में केंद्र **"अनुचित लाभ"** ले सकता है।

मुख्य बिंदु

- भारत के **मुख्य न्यायाधीश (CJI)** को शीर्ष **चुनाव निकाय** में **चुनाव आयोग** की नियुक्तियों के लिए **प्रधानमंत्री** की **अध्यक्षता** वाली **हाई-प्रोफाइल** चयन समिति में वापस लाया जाना चाहिए।
  - जैसा कि **अनूप बरनवाल** मामले में **सुप्रीम कोर्ट** के एक ऐतिहासिक फैसले द्वारा निर्देशित किया गया था

'स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव'

- अब, **कार्यपालिका** के पास **दो चुनाव आयुक्तों** को नियुक्त करने की क्षमता है जो **कार्यपालिका को अनुचित** लाभ दे सकती है।
- **स्वतंत्र** और **निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित** करने में **चुनाव आयोग** की भूमिका महत्वपूर्ण है और इसलिए, नियुक्तियाँ भी निष्पक्ष होनी चाहिए और उस समय की **सरकार** के किसी भी **पूर्वाग्रह या दबाव** से मुक्त होनी चाहिए।

अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ

- एक **संविधान पीठ** ने **मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC)** और **दो EC** को एक समिति द्वारा दी गई सलाह पर **राष्ट्रपति** द्वारा नियुक्त करने का आदेश दिया।
  - जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता या विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के नेता और CJI शामिल हैं।
- हालाँकि, **सरकार** ने फैसले को रद्द करने के लिए एक नया कानून **मुख्य चुनाव आयोग** और अन्य **चुनाव आयोग** (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) **अधिनियम, 2023** बनाया था।
- **कानून** ने **चयन समिति** में **CJI** की जगह एक **कैबिनेट मंत्री** को शामिल कर दिया, जिससे **केंद्र को** नियुक्ति प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका मिल गई।

GEO IAS
It's about quality

Matter of concern

The NGO's plea before the Supreme Court has asked for these specific interventions

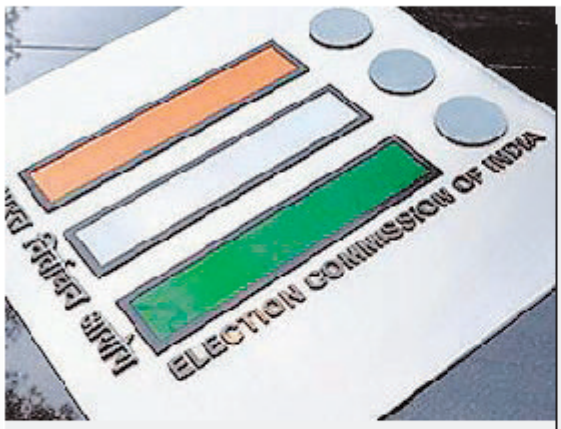

- Stay the implementation of Section 7 of The Chief Election Commission and other Election Commissions (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Act, 2023
- Direct the Union of India to appoint the vacant positions of Election Commissioners, till the pendency of the case in the Supreme Court, in accordance with the Selection Committee laid down by the *Anoop Baranwal vs Union of India* judgment of March 2023
- Bring the CJI back on board the high-profile selection committee headed by the Prime Minister for appointment of ECs

26. समान नागरिक संहिता पर उत्तराखंड विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली - द हिंदू

प्रासंगिकता: सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता।

प्रीलिम्स टेकअवे
- अनुच्छेद 44
- UCC

समाचार:
- **UCC विधेयक, 2024** को **राष्ट्रपति** की मंजूरी मिलने के बाद **उत्तराखंड** अब **स्वतंत्र भारत** में **समान नागरिक संहिता** वाला **पहला राज्य** बन गया है ।

मुख्य बिंदु
- **जनजातीय लोगों** को इसके दायरे से बाहर रखने वाले इस **विधेयक में हलाला**, **इद्दत** और **तलाक** (मुस्लिम पर्सनल लॉ में विवाह और तलाक से संबंधित रीति-रिवाज) जैसी **प्रथाओं पर प्रतिबंध** लगा दिया गया है।
- यह सुनिश्चित करता है कि महिलाओं को **संपत्ति और विरासत** के अधिकार से संबंधित मामलों में समान अधिकार दिए जाएं।
- **राष्ट्रपति** ने **'भारत के संविधान'** के **अनुच्छेद 201** के तहत **उत्तराखंड विधानसभा** द्वारा पारित **'समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024'** विधेयक को मंजूरी दे दी।

समान नागरिक संहिता (UCC)
- **UCC** पूरे देश में सभी **धार्मिक समुदायों** के लिए उनके **व्यक्तिगत मामलों** जैसे **विवाह, तलाक, विरासत**, गोद लेने आदि के लिए एक **कानून प्रदान** करता है।
- **संविधान** के **भाग IV** के भाग में **राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों (DPSP)** के हिस्से के रूप में **अनुच्छेद 44** में परिभाषित किया गया है ।

- **अनुच्छेद 44** - इसमें कहा गया है कि 'राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।'
- UCC का लक्ष्य सभी नागरिकों के लिए, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, एक समान कानूनी ढांचा लागू करना है।

27. कोविंद पैनल ने एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की- द हिंदू

प्रासंगिकता: कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली - सरकार के मंत्रालय और विभाग; दबाव समूह और औपचारिक/अनौपचारिक संघ और राज्य व्यवस्था में उनकी भूमिका।

प्रीलिम्स टेकअवे
- भारत चुनाव आयोग
- अनुच्छेद 172

समाचार:
- **पूर्व राष्ट्रपति** की **अध्यक्षता** वाली **उच्च स्तरीय समिति** ने पहले कदम के रूप में **लोकसभा** और **राज्य विधानसभाओं** के चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की है

मुख्य बिंदु
- **समिति** ने **अगले चरण** में **आम चुनाव** के **100 दिनों** के भीतर **नगरपालिका** और **पंचायत चुनाव** कराने की भी सिफारिश की।
- **22वां विधि आयोग,** जो एक साथ चुनाव के मुद्दे की जांच कर रहा है, से भी अब किसी भी समय कानून मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपने और **वर्ष 2029** के **आम चुनाव** चक्र से इसकी सिफारिश करने की उम्मीद है।
- **कोविंद पैनल** की रिपोर्ट का आगामी **लोकसभा चुनाव** पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
- **पैनल** ने सिफारिश की कि **त्रिशंकु सदन** या अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में **नई लोकसभा** के गठन के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं।
  - या ऐसी कोई घटना लेकिन **सदन** का **कार्यकाल** केवल **सदन** के **पूर्ण कार्यकाल** से ठीक पहले के शेष **कार्यकाल** के लिए होगा
- जब **विधान सभाओं** के लिए नए चुनाव होते हैं, तो ऐसी नई सभाएं, जब तक कि शीघ्र भंग न हो जाएं, **लोकसभा** के **पूर्ण कार्यकाल** के अंत तक जारी रहेंगी।
- इन परिवर्तनों को प्रभावी करने के लिए, **पैनल** ने **संविधान** के **अनुच्छेद 83** (संसद के सदनों की अवधि) और **अनुच्छेद 172** (राज्य विधानमंडलों की अवधि) में **संशोधन** की सिफारिश की है।

राज्यों द्वारा अनुसमर्थन
- पैनल ने **पंचायतों** और **नगर पालिकाओं** में एक साथ चुनाव की अनुमति देने के लिए संविधान के **अनुच्छेद 324A** में उपयुक्त संशोधन की सिफारिश की है :
- **अनुच्छेद 325 भारत** के **चुनाव आयोग (EC)** को **राज्य चुनाव अधिकारियों** के परामर्श से एक सामान्य मतदाता सूची और **मतदाता पहचान पत्र** तैयार करने की अनुमति देता है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि इन **दोनों संवैधानिक संशोधनों** के लिए **राज्यों** द्वारा **अनुसमर्थन** की आवश्यकता होगी।
- वर्तमान में, **चुनाव आयोग लोकसभा** और **विधानसभा चुनाव**ों के लिए जिम्मेदार है, जबकि नगर पालिकाओं और **पंचायतों** के लिए **स्थानीय निकाय चुनावों** का प्रबंधन **राज्य चुनाव आयोगों** द्वारा किया जाता है।

28. मद्रास HC ने OPS को ADMK के प्रतीक, झंडे का उपयोग करने से रोका- द हिंदू

प्रासंगिकता: कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली - सरकार के मंत्रालय और विभाग; दबाव समूह और औपचारिक/अनौपचारिक संघ और राज्य व्यवस्था में उनकी भूमिका।

प्रीलिम्स टेकअवे
- चुनाव चिह्न (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968

समाचार:
- **मद्रास उच्च न्यायालय** ने निष्कासित **अन्नाद्रमुक नेता** को **पार्टी के झंडे**, **'दो पत्तियां' प्रतीक** और **आधिकारिक लेटरहेड** का उपयोग करने से रोक दिया।

चुनाव चिह्न
- **चुनाव चिह्न** (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 **चुनाव आयोग** को **राजनीतिक दलों** को मान्यता देने और प्रतीक आवंटित करने का अधिकार देता है।
- आदेश के तहत किसी विवाद या विलय पर मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए **चुनाव आयोग** एकमात्र प्राधिकारी है।

- **सुप्रीम कोर्ट** ने **वर्ष 1971** में **सादिक अली** और अन्य बनाम **ECI** मामले में इसकी वैधता को बरकरार रखा।
- यह मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य पार्टियों के विवादों पर लागू होता है।
- **पंजीकृत** लेकिन **गैर-मान्यता** प्राप्त पार्टियों में विभाजन के लिए, **चुनाव आयोग** आमतौर पर **युद्धरत गुटों** को अपने मतभेदों को **आंतरिक** रूप से **सुलझाने या अदालत** का **दरवाजा खटखटाने** की सलाह देता है।
- **चुनाव आयोग** द्वारा अब तक तय किए गए लगभग **सभी विवादों** में, **पार्टी प्रतिनिधियों/पदाधिकारियों, सांसदों** और **विधायकों** के स्पष्ट बहुमत ने एक गुट का समर्थन किया है।
- **वर्ष 1968** से पहले**, चुनाव आयोग चुनाव संचालन नियम, 1961** के तहत **अधिसूचनाएं और कार्यकारी** आदेश जारी करता था।
- जिस समूह को पार्टी का चिन्ह मिला उससे पार्टी के अलग हुए समूह को खुद को एक अलग पार्टी के रूप में पंजीकृत कराना पड़ा।

29. चुनावी बॉन्ड डेटा: पहले दो वर्षों में किसे कितना मिला - द हिंदू

प्रासंगिकता: कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली - सरकार के मंत्रालय और विभाग; दबाव समूह और औपचारिक/अनौपचारिक संघ और राज्य व्यवस्था में उनकी भूमिका।

प्रीलिम्स टेकअवे
- वित्त अधिनियम, 2017
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29C

समाचार:
- सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण कारण बताते हुए **चुनावी बॉन्ड योजना** को रद्द कर दिया।
- यह योजना **संविधान** के **अनुच्छेद 19(1)(a)** के तहत **सूचना** के **अधिकार** का उल्लंघन करती है।
- इसने पैसे और राजनीति के बीच "**गहरे संबंध**" पर प्रकाश डाला और बताया कि कैसे **आर्थिक असमानता राजनीतिक असमानता** में योगदान करती है।
- राजनीतिक दलों को बड़ी मात्रा में योगदान देने की क्षमता रखने वाले लोगों के लिए बदले में बदले की व्यवस्था की संभावना को बढ़ाता है।
- अदालत ने कहा, इन व्यवस्थाओं से अनुकूल नीतिगत बदलाव और सरकारी लाइसेंस मिल सकते हैं जिनके बारे में जानने का मतदाताओं को अधिकार है।
- स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में सार्वजनिक हित दानदाता की गोपनीयता के निजी हित से अधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए।

चुनावी बॉन्ड के पक्ष में तर्क
- दानदाताओं की गोपनीयता की रक्षा करने से राजनीतिक प्रतिशोध की आशंका भी काफी कम हो जायेगी।
- **अनुच्छेद 19(1)(a)** के तहत सूचना का अधिकार केवल **अनुच्छेद 19(2)** में सूचीबद्ध आधारों पर प्रतिबंधित किया जा सकता है , जिसमें काले **धन पर अंकुश** लगाने का उद्देश्य शामिल नहीं है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29C
- **वित्त अधिनियम, 2017** द्वारा संशोधित होने से पहले, सभी **राजनीतिक दलों** को **20,000 रुपये** से अधिक के किसी भी योगदान की घोषणा करने की आवश्यकता थी।
- धारा में संशोधन, जिसने **राजनीतिक दलों** को **चुनावी बॉन्ड** के माध्यम से प्राप्त दान के लिए घोषणा करने से छूट दी थी, अदालत ने खारिज कर दिया था।

Details of bond purchases and encashments

Last week, the Election Commission of India (ECI) put up the list of donors who purchased electoral bonds and the political parties that encashed them. On Monday, the Supreme Court asked the State of Bank of India to make a "complete disclosure" of electoral bonds data including their unique hidden serial numbers by Thursday. While the numbers that link the purchasers and the donors are awaited, the following tables take a look at the share of bonds purchased and encashed across various dates, for which information is currently available in the public domain. By **Rebecca Rose Varghese** and **Gautam Doshi**

2019 LS polls: The table looks at the companies/individuals with the highest share in total electoral bonds purchased between April 12, 2019 and May 10, 2019 coinciding with the 2019 Lok Sabha elections. It also looks at the parties that got the highest share of the bonds encashed between April 12, 2019 and May 22, 2019

Companies that bought electoral bonds	% of total purchase
Keventer Foodpark Infra	13.1%
Madanlal Ltd.	12.5%
MEIL*	8.4%
Essel Mining & Industries	3.4%
Vedanta	3.3%
PHL Finivest	2.7%
Lakshmi Niwas Mittal	2.4%
Sun Pharma	2.1%
Navayuga Engineering Company	2.0%
Interglobe Real Estate	1.3%
Grasim Industries	1.3%
Finolex Cables	1.3%
Bajaj Finance	1.3%
Haldia Energy	1%
Bharti Airtel	1%
Parties that encashed electoral bonds	**% of total encashed**
Bharatiya Janata Party	84%
Congress	8%
All India Trinamool Congress	2.5%
Bharat Rashtra Samithi	1.8%

Keventer Foodpark Infra bought ₹195 crore worth of bonds (13.1% of total purchases in the period), followed by Madanlal Ltd. (12.5%) and Megha Engineering and Infrastructures (8.4%). In case of parties, the BJP encashed ₹1,771.5 crore worth of electoral bonds in the period (84% of bonds encashed) followed by the Congress at 8%*

It is important to note that in this bucket, the full list of donors has not been revealed yet. For instance, parties could have encashed some amount of the bonds that they received in the 15 days before April 12, 2019 as well

Haryana, Maharashtra, Jharkhand, Delhi polls: The table looks at the companies/individuals with the highest share in total electoral bonds purchased between July 5, 2019 and January 22, 2020, just before and during polls in these States. It also looks at the parties that got the highest share of the electoral bonds encashed between July 11, 2019 and February 3, 2020

Companies that bought electoral bonds	% of total purchase
Infina Finance	9.8%
DLF Commercial Developers	8.4%
Avees Trading Finance	6.7%
NCC Ltd.	5.6%
Navayuga Engineering Company	4.2%
Cipla Ltd.	4.2%
MKJ Enterprises	4%
Kaypee Enterprises	3.9%
UPL Ltd.	2.8%
Torrent Power	2.8%
S D Corporation	2.8%
Raju Kumar Sharma	2.8%
DLF Luxury Homes	2.8%
Apco Infratech	2.8%
Haldia Energy	1.9%
Mahalaxmi Vidyut Pvt. Ltd.	1.7%
Ultra Tech Cement	1.4%
Torrent Pharmaceuticals	1.4%
Prestige Southcity Holdings	1.4%
Prestige Notting Hill Investments	1.4%
Parties that encashed electoral bonds	**% of total encashed**
Bharatiya Janata Party	70.5%
All India Trinamool Congress	13.3%
Biju Janata Dal	5.6%
Shiv Sena	4.7%
Nationalist Congress Party	3.2%
Congress	2.2%

The share of Infina Finance was 9.8% of total purchases in the period, followed by DLF Commercial Developers Ltd. (8.4%). In case of parties, BJP's share was 70.5% of the total bonds encashed followed by the All India Trinamool Congress at 13.3%

Oct.-Nov. 2020: The table looks at the companies/individuals with the highest share in total electoral bonds purchased between October 19, 2020 and October 28, 2020. It also looks at the parties with the highest share in the electoral bonds encashed between October 22, 2020 and November 7, 2020. This period also coincided with the Bihar elections

Companies that bought electoral bonds	% of total purchase
Future Gaming and Hotel Services	53.1%
MEIL	7.1%
Essel Mining & Industries	7.1%
Haldia Energy	5.3%
Utkal Alumina International	3.5%
Ultra Tech Cement	3.5%
Grasim Industries	3.5%
S N Mohanty (Individual)	2.8%
Welspun Corporation	2.5%
Penguin Trading & Agencies	1.8%
Jindal Saw	1.8%
G R Infraprojects	1.8%
Ardent Steel	1.4%
Genus Power Infrastructures	1.1%
Bajaj Auto Ltd.	1.1%
Parties that encashed electoral bonds	**% of total encashed**
YSR Congress Party	31.5%
DMK	28.3%
Biju Janata Dal	23.7%
Bharatiya Janata Party	7.4%
All India Trinamool Congress	6.2%
Congress	1.1%
Aam Aadmi Party	1.1%

Future Gaming and Hotel Services formed 53.1% of total purchases in the period, followed by Megha Engineering and Infrastructures (7.1%). In case of parties, YSR Congress Party's share was 31.5% of the total bonds encashed followed by Dravida Munnetra Kazhagam's 28.3% and Biju Janata Dal's 23.7%

The donor and purchaser lists were sourced from the ECI's disclosure on March 14

rebecca.varghese@thehindu.co.in, gautam.doshi@thehindu.co.in

Assam, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal, Puducherry The table looks at the companies/individuals with the highest share in total electoral bonds purchased between January 4, 2021 and April 9, 2021. It also looks at the parties with the highest share in the electoral bonds encashed between January 7, 2021 and April 19, 2021. The period coincides with the State elections in Assam, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal, and Puducherry

Companies that bought electoral bonds	% of total purchase
Future Gaming and Hotel Services	14.8%
MEIL	10.6%
Haldia Energy	7.5%
Essel Mining & Industries	7.4%
Rungta Sons Pvt..Ltd.	6.8%
Phillips Carbon Black	4.1%
Honeywell Properties	4.1%
Bharti Telemedia	4.1%
Vedanta	3.4%
Infina Finance	3.4%
Rahul Bhatia	2.7%
Chander Commercials	2.7%
Misrilall Mines	2%
DLF Commercial Developers	1.4%
Torrent Power	1%
Torrent Pharmaceuticals	1%
Parties that encashed electoral bonds	**% of total encashed**
Bharatiya Janata Party	39.7%
Biju Janata Dal	15.7%
DMK	14.4%
All India Trinamool Congress	11%
YSR Congress Party	8.9%
Congress	8.9%

Future Gaming and Hotel Services formed 14.8% of total purchases in the period, followed by Megha Engineering and Infrastructures (10.6%), Haldia Energy (7.5%), Essel mining at 7.4% and Rungta Sons (6.8%). In case of parties, Bharatiya Janata Party's share was 39.7% of the total bonds encashed followed by the Biju Janata Dal's 15.7%, Dravida Munnetra Kazhagam's 14.4% and All India Trinamool Congress' 11%

30. जलवायु कार्यकर्ता वांगचुक ने सीमा मार्च का आह्वान किया - द हिंदू

प्रासंगिकता: सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ और उनका प्रबंधन - आतंकवाद के साथ संगठित अपराध का संबंध।

प्रीलिम्स टेकअवे
- मानचित्र आधारित प्रश्न
- लद्दाख

समाचार:
- **जलवायु कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक** ने कहा कि लद्दाख से लगभग **10,000 लोग** यह दिखाने के लिए **चीन की सीमा** पर **मार्च करेंगे** कि **पड़ोसी देश** ने कितनी जमीन खो दी है।

मुख्य बिंदु
- चीन के साथ **वास्तविक नियंत्रण रेखा** पर **फिंगर एरिया (पैंगोंग त्सो के उत्तरी और दक्षिणी तट), डेमचोक, चुशूल** समेत अन्य इलाकों में निकाला जाएगा ।
- "मार्च उन क्षेत्रों, **प्रमुख चारागाह भूमि** पर भी प्रकाश डालेगा, जिन्हें सौर पार्क में बदला जा रहा है।
- एक तरफ, खानाबदोश अपनी जमीनें कॉरपोरेट्स के हाथों खो रहे हैं जो अपने संयंत्र स्थापित करने आ रहे हैं, शायद भविष्य में खनन करेंगे।
- दूसरी ओर वे चीन के कारण **चारागाह भूमि** खो रहे हैं जो उत्तर से अतिक्रमण कर रहा है, **चीनियों** ने पिछले कुछ वर्षों में भूमि के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है।"

वर्जित क्षेत्र
- **15 जून, 2020** को गलवान में हुई घटना के बाद, जहां **चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी** के साथ हिंसक झड़प में **20 भारतीय सैनिक** मारे गए थे।

- **दोनों सेनाओं** के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, जिससे **सेनाएं पीछे** हट रही हैं और ब**फर जोन** या **नो-गो एरिया** का निर्माण हो रहा है।

लद्दाख का महत्व

- **लद्दाख** के दक्षिण में **ज़ांस्कर पर्वतमाला** और उत्तर में **काराकोरम पर्वतमाला** है।
- इसकी सीमाएँ **पाकिस्तान और चीन दोनों** के साथ लगती हैं।
- इसका प्रमुख स्थान इसे **भारत** की **राष्ट्रीय सुरक्षा** के लिए **महत्वपूर्ण और रणनीतिक** रूप से महत्वपूर्ण बनाता है।
- **प्राचीन काल** से लेकर **भारत और पाकिस्तान** के बीच विभाजन तक, लद्दाख **रेशम मार्ग** पर एक **महत्वपूर्ण बिंदु** बना रहा।
- **लद्दाख** के दर्रे **मध्य एशिया, दक्षिण एशिया** और **चीन सहित दुनिया** के कुछ आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जोड़ते थे।
- ऐतिहासिक रूप से, **लद्दाख में गिलगित, हुंजा, कारगिल, लेह और स्कर्दो** शामिल हैं।
- **भूमि** और **जलवायु की कठोरता** के बावजूद, इसके स्थान ने इसे एक **वांछनीय रणनीतिक** स्थान बना दिया
  - जिसके कारण **क्षेत्र के दर्रों** पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए **रूसी, चीनी, तिब्बती, फारसी** और **भारतीय सहित तत्कालीन साम्राज्यों** द्वारा कई युद्ध लड़े गए।

31. SC ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राशन कार्ड देने का निर्देश दिया- द हिंदू

प्रासंगिकता: केंद्र और राज्यों द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का प्रदर्शन; इन कमजोर वर्गों की सुरक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थाएं और निकाय।

प्रीलिम्स टेकअवे
- अंत्योदय अन्न योजना
- ईश्रम पोर्टल

समाचार:

- सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में लगभग आठ करोड़ प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड प्रदान करने के अपने **अप्रैल 2023** के आदेश के कार्यान्वयन में देरी पर आपत्ति जताई।

प्रमुख बिंदु

- ये प्रवासी **श्रमिक ईश्रम पोर्टल** में पंजीकृत हैं लेकिन **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम** के तहत कवर नहीं हैं।
- पोर्टल पर **28.6 करोड़ पंजीकरणकर्ता** हैं।
- इनमें से **2.0.63 करोड़ राशन कार्ड डेटा** पर पंजीकृत हैं।
- **खंडपीठ** ने **ईश्रम पोर्टल** पर पंजीकृत शेष **आठ करोड़ प्रवासी** और **असंगठित क्षेत्र** के **श्रमिकों** को **दो महीने में राशन कार्ड** देने का निर्देश दिया।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम

- **अंत्योदय अन्न योजना (AAY) योजना** और **प्राथमिकता** वाले घरों के माध्यम से **75% तक ग्रामीण** और **50% शहरी** आबादी **NFSA** द्वारा कवर की जाती है।
- प्राथमिकता वाले **घर प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम भोजन** के हकदार हैं।
- जबकि **AAY** परिवार **सबसे निचले गरीबों** का प्रतिनिधित्व करते हैं या प्रति परिवार **प्रति माह 35 किलोग्राम** के हकदार हैं।
- **पूर्व योजना आयोग (अब नीति आयोग)** ने **वर्ष 2011-2012** के लिए **NSS घरेलू उपभोग सर्वेक्षण डेटा** का उपयोग किया था
  - NSSA के तहत राज्यवार कवरेज का अनुमान लगाना।
- प्रत्येक राज्य के लिए स्थापित **TPDS** के दायरे में **संभावित परिवारों** की **पहचान करने** का कार्य **राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों** द्वारा पूरा किया जाना है।
- **प्राथमिकता** वाले **परिवारों** के **चयन** और उनके **वास्तविक सत्यापन** के लिए **आधार का विकास राज्य सरकार** के **कर्तव्यों** के दायरे में आता है।

32. सुप्रीम कोर्ट ने तथ्य जांच इकाई पर केंद्र के आदेश पर रोक लगाईं -द हिंदू

प्रासंगिकता: विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप और उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे
- PIB
- सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021

समाचार:

- **सुप्रीम कोर्ट** ने हाल ही में **प्रेस सूचना ब्यूरो** की तथ्य **जांच इकाई (PIB FCU)** की स्थापना की **सरकारी अधिसूचना** पर रोक लगा दी है।
- **PIB** को केंद्र के **"व्यवसाय"** के संबंध में **फर्जी समाचार या गलत सूचना** के **निर्माण और प्रसार** के खिलाफ **"निवारक"** के रूप में कार्य करना था।

मुख्य बिंदु

- **बॉम्बे हाई कोर्ट** ने **सूचना प्रौद्योगिकी** (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के **नियम 3(1)(b)(v)** के प्रावधानों की वैधता पर अंतिम फैसला लिया।
- **सुप्रीम कोर्ट** ने **नियम 3(1)(b)(v)** की **योग्यता या वैधता** पर कोई टिप्पणी नहीं की, कहा कि **स्वतंत्र भाषण** और **अभिव्यक्ति** के **मौलिक अधिकारों** पर प्रावधान के प्रभाव का **विश्लेषण उच्च न्यायालय** द्वारा किया जाएगा।

प्रेस सूचना ब्यूरो

- PIB, **सूचना** और **प्रसारण मंत्रालय** के तहत **भारत सरकार** की एक **नोडल एजेंसी** है।
- **राष्ट्रीय मीडिया केंद्र,** नई दिल्ली में स्थित, **प्रेस सूचना ब्यूरो** सरकारी योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रम पहलों और उपलब्धियों पर **प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक** और **वेब मीडिया** में जानकारी प्रसारित करता है।
- यह 1**4 भारतीय आधिकारिक भाषाओं** में उपलब्ध है, जो डोगरी, पंजाबी, बंगाली, उड़िया, गुजराती, मराठी, मैतेई (मणिपुरी) हैं।
  - भारतीय गणराज्य की **22 आधिकारिक भाषाओं** में से **हिंदी और अंग्रेजी** के अलावा तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, कोंकणी और उर्दू शामिल हैं।
- **PIB** का प्रमुख **भारत सरकार** का **आधिकारिक प्रवक्ता** भी है और **प्रधान महानिदेशक** (विशेष सचिव समकक्ष) का पद रखता है।

33. प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया -द हिंदू

प्रासंगिकता: कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली - सरकार के मंत्रालय और विभाग; दबाव समूह और औपचारिक/अनौपचारिक संघ और राज्य व्यवस्था में उनकी भूमिका।

प्रीलिम्स टेकअवे
- प्रवर्तन निदेशालय

समाचार :

- **दिल्ली के मुख्यमंत्री** और **आम आदमी पार्टी (आप) नेता अरविंद केजरीवाल** को **प्रवर्तन निदेशालय** (ED) ने **उत्पाद शुल्क नीति** से जुड़े **मनी लॉन्ड्रिंग** मामले में गिरफ्तार कर लिया।

प्रवर्तन निदेशालय (ED)

- **प्रवर्तन निदेशालय** की स्थापना **वर्ष 1956** में **आर्थिक मामलों** के विभाग के तहत एक **'प्रवर्तन इकाई'** के रूप में की गई थी।
- बाद में, **वर्ष 1957** में इस इकाई का नाम बदलकर **'प्रवर्तन निदेशालय'** कर दिया गया।

प्रशासनिक नियंत्रण

- वर्तमान में, यह परिचालन उद्देश्यों के लिए **राजस्व विभाग (वित्त मंत्रालय)** के **प्रशासनिक नियंत्रण** में है।

कार्य

- ED **विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम**, 1999 (FEMA) और **PMLA** के तहत कुछ प्रावधानों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
- **ED** के पास **FEMA** के उल्लंघन के दोषी पाए गए **दोषियों** की **संपत्ति कुर्क** करने का अधिकार है।
- इसे **PMLA** के तहत किए गए **अपराधों** के **खिलाफ कार्रवाई**, **तलाशी, जब्ती, गिरफ्तारी, अभियोजन कार्रवाई और सर्वेक्षण** आदि करने का भी अधिकार दिया गया है।

ED के निदेशक की नियुक्ति

- ED निदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है।
- इसकी अध्यक्षता केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सदस्य सतर्कता आयुक्त, गृह सचिव, सचिव DOPT और राजस्व सचिव करते हैं।

34. क्या हिरासत में रहते हुए भी केजरीवाल सीएम बने रह सकते हैं? - हिन्दू

प्रीलिम्स टेकअवे
- ED

प्रासंगिकता: कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली - सरकार के मंत्रालय और विभाग; दबाव समूह और औपचारिक/अनौपचारिक संघ और राजनीति में उनकी भूमिका **।**

- मुख्यमंत्री

समाचार:

- इस बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या **दिल्ली** के **मुख्यमंत्री न्यायिक हिरासत** में भेजे जाने के बाद भी ऐसे **सार्वजनिक पद** पर बने रह सकते हैं जो **उच्च स्तर** की **नैतिकता** की मांग करता है।

मुख्य बिंदु

- **सर्वोच्च न्यायालय** और **उच्च न्यायालयों** में पहले के निर्णयों से यह निष्कर्ष निकला है कि **संवैधानिक नैतिकता, सुशासन** और **संवैधानिक विश्वास सार्वजनिक** पद संभालने के लिए बुनियादी मानदंड हैं।
- **एस रामचंद्रन बनाम वी सेंथिलबालाजी** मामले में **मद्रास उच्च न्यायालय** के हालिया फैसले में अदालत में दी गई दलीलों का उल्लेख किया गया है।
  - क्या किसी मंत्री पर "**वित्तीय घोटाले**" का आरोप लगने पर उसे **उच्च स्तर** की **नैतिकता** की मांग करने वाले **सार्वजनिक पद** पर रहने का अपना अधिकार खो देना चाहिए।
- **तमिलनाडु** के एक **पूर्व मंत्री** को पिछले **साल मनी लॉन्ड्रिंग** के आरोप में **ED** ने गिरफ्तार किया था।
- **न्यायिक हिरासत** में रहने के दौरान भी वह बिना **विभाग के मंत्री** बने रहे।
- **दलीलों** में **मनोज नरूला बनाम भारत संघ** मामले में **सुप्रीम कोर्ट** की **वर्ष 2014** की **संविधान पीठ** के फैसले का हवाला दिया गया।
  - जिसने माना था कि **सार्वजनिक** पद संभालने का मूल मानदंड **संवैधानिक नैतिकता** है, यानी कानून के शासन के विपरीत कार्य करने से बचना।
- उच्च न्यायालय ने कहा था, "**राजनीतिक मजबूरी सार्वजनिक नैतिकता**, अच्छे/स्वच्छ शासन की आवश्यकताओं और संवैधानिक नैतिकता को ताक पर नहीं रख सकती।"

35. शक्तियों के नियमित प्रयोग द्वारा प्रिवेंटिव डिटेंशन अवश्य होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट- इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली - सरकार के मंत्रालय और विभाग; दबाव समूह और औपचारिक/अनौपचारिक संघ और राज्य व्यवस्था में उनकी भूमिका।

प्रीलिम्स टेकअवे

- प्रिवेंटिव डिटेंशन
- प्यूनिटिव डिटेंशन

समाचार:

- **सुप्रीम कोर्ट** ने **तेलंगाना उच्च न्यायालय** के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें एक **बंदी की अपील** को खारिज कर दिया गया था कि **प्रिवेंटिव डिटेंशन** एक कठोर उपाय है।
- इसमें पाया गया कि शक्तियों के **मनमौजी या नियमित प्रयोग** पर आधारित ऐसे किसी भी कदम को शुरुआत में ही ख़त्म कर देना चाहिए।

प्रिवेंटिव डिटेंशन

- **भारत प्रिवेंटिव डिटेंशन कानूनों** के माध्यम से **व्यक्तिगत स्वतंत्रता** के साथ **सुरक्षा की आवश्यकता** को संतुलित करता है।
- ये **कानून अधिकारियों** को **लोगों को बिना मुकदमे** के डिटेंशन में रखने की अनुमति देते हैं यदि उन्हें लगता है कि वे **लोग भविष्य** में अपराध कर सकते हैं।
- भारतीय संविधान लोगों को **गलत तरीके से गिरफ्तार** होने से बचाता है।
- यह प्रिवेंटिव डिटेंशन की अनुमति देता है, लेकिन सुरक्षा उपायों के साथ।
- उदाहरण के लिए, डिटेंशन को **तीन महीने** से **अधिक समय तक नहीं रखा** जा सकता जब तक कि समीक्षा बोर्ड इसे बढ़ाने का कोई कारण न ढूंढ ले।
- बंदियों को यह जानने का भी अधिकार है कि उन्हें क्यों **डिटेंशन** में रखा जा रहा है (जब तक कि उस कारण का खुलासा करने से **सार्वजनिक सुरक्षा** को नुकसान न पहुंचे)।

- इन कानूनों को बनाने की शक्ति विभाजित है।
- केन्द्रीय सरकार **राष्ट्रीय सुरक्षा** कारणों से कानून बना सकती है, जबकि **राष्ट्रीय** और **राज्य** दोनों सरकारें **सार्वजनिक व्यवस्था** या **आवश्यक सेवाओं** के लिए कानून बना सकती हैं।
- भारत में प्रिवेंटिव डिटेंशन कानूनों के उदाहरणों में **राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम** और **राज्य-विशिष्ट सार्वजनिक सुरक्षा** अधिनियम शामिल हैं।
- ये **कानून अधिकारियों** को बिना किसी आरोप के लेकिन **समीक्षा प्रक्रिया** के साथ लोगों को **एक साल** तक **डिटेंशन** में रखने की अनुमति देते हैं।

36. असाधारण मामलों में ही मीडिया रिपोर्टों पर रोक लगाएं - सुप्रीम कोर्ट -द हिंदू

प्रासंगिकता: कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली - सरकार के मंत्रालय और विभाग; दबाव समूह और औपचारिक/अनौपचारिक संघ और राज्य व्यवस्था में उनकी भूमिका।

प्रीलिम्स टेकअवे
- अंतरिम निषेधाज्ञा
- SLAPP

समाचार:
- **सुप्रीम कोर्ट** ने **मीडिया और नागरिक समाज** के खिलाफ **अमीरों को अदालतों** से **प्री-ट्रायल निषेधाज्ञा** प्राप्त करने, **मुक्त भाषण** और महत्वपूर्ण मामलों के बारे में **जनता के सूचना के अधिकार** को बंद करने की समस्या पर प्रकाश डाला है।

मुख्य बिंदु
- शीर्ष अदालत ने कहा, "**पत्रकारिता की अभिव्यक्ति** की रक्षा के **संवैधानिक आदेश** को कम करके नहीं आंका जा सकता है और **अदालतों को प्री-ट्रायल अंतरिम निषेधाज्ञा** देते समय सावधानी से चलना चाहिए।"
- बेंच ने सभी न्यायक्षेत्रों में ध्यान आकर्षित करने वाली **SLAPP सूट'** या '**सार्वजनिक भागीदारी** के खिलाफ रणनीतिक मुकदमेबाजी' की घटना पर प्रकाश डाला।
- यह एक व्यापक शब्द है जिसका उपयोग मुख्य रूप से उन **संस्थाओं** द्वारा शुरू की गई मुकदमेबाजी को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जो **मीडिया या नागरिक समाज** के सदस्यों के खिलाफ अत्यधिक आर्थिक शक्ति रखते हैं।
  - अदालत ने कहा कि जनता को जनहित में महत्वपूर्ण मामलों के बारे में जानने या उनमें भाग लेने से रोका जाए।''
- **एकपक्षीय निषेधाज्ञा** के साथ किसी **मीडिया आउटलेट** को निकट भविष्य में या यहां तक कि दूर के भविष्य में भी लेख या **सामग्री प्रकाशित** करने से रोका जा सकता है।
- ऐसा मामला जिसमें **मीडिया** या **नागरिक समाज** के खिलाफ **धन-संपन्न इकाई** द्वारा मानहानि के महंगे आरोप शामिल हो सकते हैं, लंबा खिंचता है।
- इसमें कहा गया है कि अदालतों को केवल असाधारण मामलों में ही सुनवाई-पूर्व निषेधाज्ञा देनी चाहिए।
- अदालत ने रेखांकित किया कि अभिव्यक्ति की **स्वतंत्रता को निरंकुश** रखने का महत्व **अंतरिम निषेधाज्ञा** देने के साथ सबसे सावधानी और सावधानी से निपटने का एक मजबूत कारण है।

अंतरिम निषेधाज्ञा
- यह मुकदमे से पहले कानूनी कार्यवाही के दौरान मांगा जाने वाला एक अनंतिम उपाय है।
- निषेधाज्ञा अदालत का एक आदेश है जिसके लिए किसी पक्ष को या तो एक विशिष्ट कार्य करने की आवश्यकता होती है, या किसी विशिष्ट कार्य को करने से बचना होता है।
- अंतरिम निषेधाज्ञा का उद्देश्य मुकदमे के लंबित रहने तक अन्याय को रोकना है।

37. POCSO अपराध के आरोपी बच्चे पर JJ एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए: केरल HC - द हिन्दू

प्रासंगिकता: कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली - सरकार के मंत्रालय और विभाग; दबाव समूह और औपचारिक/अनौपचारिक संघ और राज्य व्यवस्था में उनकी भूमिका।

प्रीलिम्स टेकअवे
- JJ एक्ट 2015
- POCSO

समाचार:
- केरल उच्च न्यायालय ने माना है कि एक बच्चे पर **POCSO, 2012** के तहत अपराध का आरोप लगाया गया है।
  - **किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) (JJ) अधिनियम** के प्रावधानों के अनुसार मुकदमा चलाया जाना है।

मुख्य बिंदु
- अदालत ने कहा कि '**बच्चे**' को **POCSO अधिनियम** में परिभाषित नहीं किया गया है जबकि इसे **JJ अधिनियम, 2015** में परिभाषित किया गया है।
- **JJ अधिनियम** की **धारा 2(12)** में बच्चे को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसने **18 वर्ष** की आयु पूरी नहीं की है।
- अदालत ने कहा कि "उपरोक्त परिभाषाएँ यह निष्कर्ष सुनिश्चित करेंगी कि एक बच्चा **POCSO अधिनियम** में परिभाषित **यौन अपराधों** का अपराधी हो सकता है।
- जब कोई बच्चा अपराधी होता है, तो उस पर **सामान्य आपराधिक अदालत** में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, बल्कि **JJ अधिनियम** के प्रावधानों के तहत ही निपटा जा सकता है।

किशोर न्याय अधिनियम, 2015
- संसद ने किशोर **अपराध कानून** और **किशोर न्याय** (बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम) 2000 को बदलने के लिए **2015** में **किशोर न्याय** (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) **अधिनियम** पारित किया गया ।
- अधिनियम में **16-18 वर्ष** की आयु वर्ग के **उन किशोरों** के खिलाफ वयस्क के रूप में **मुकदमा चलाने** की अनुमति देने के **प्रावधान** की पेशकश की गई, जो विशेष रूप से **जघन्य अपराधों** में कानून के उल्लंघन में पाए गए थे।
- इस अधिनियम ने **हिंदू दत्तक ग्रहण** और **भरण-पोषण अधिनियम (1956)** और **संरक्षक वार्ड अधिनियम** (1890) को **अधिक सार्वभौमिक** रूप से **सुलभ दत्तक ग्रहण** कानून से बदल दिया।
- अधिनियम ने **केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA)** को **गोद लेने** से संबंधित मामलों के लिए **वैधानिक निकाय** बनाया गया
  - **अनाथों, आत्मसमर्पण** करने वाले और **परित्यक्त बच्चों** के लिए **गोद लेने** की **प्रक्रियाओं** के **सुचारू कामकाज** को सक्षम बनाया।

बाल देखभाल संस्थान (CCI)
- सभी बाल देखभाल संस्थान, चाहे वे **राज्य सरकार** द्वारा संचालित हों या **स्वैच्छिक या गैर-सरकारी संगठनों** द्वारा संचालित हों,
  - उन्हें **अधिनियम** के प्रारंभ होने की तारीख से **6 महीने** के भीतर **अधिनियम** के तहत **अनिवार्य** रूप से पंजीकृत होना होगा।

किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2021
- **JJ अधिनियम, 2015** के अध्याय "**बच्चों के खिलाफ अन्य अपराध**" में उल्लिखित बच्चों के खिलाफ अपराध, जिसमें **तीन से सात साल** के बीच **कारावास** की सजा का प्रावधान है, को "**गैर-संज्ञेय**" माना जाएगा।

दत्तक ग्रहण:
- संशोधन में प्रावधान है कि **जिला मजिस्ट्रेट** को ऐसे गोद लेने के आदेश जारी करने का अधिकार है।

38. सुप्रीम कोर्ट: PMLA से जुड़ी याचिका अदालत ने खारिज की- इकोनॉमिक टाइम्स

प्रासंगिकता: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पहलू, ई-गवर्नेंस-अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और क्षमता; नागरिक चार्टर, पारदर्शिता और जवाबदेही और संस्थागत और अन्य उपाय।

प्रीलिम्स टेकअवे
- आपराधिक षड़यंत्र
- धारा 120 IPC

समाचार:
- **सुप्रीम कोर्ट** ने अपने फैसले की समीक्षा की मांग करने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि यदि कथित **आपराधिक साजिश PMLA** के तहत **अनुसूचित अपराध** से संबंधित नहीं है।
- किसी व्यक्ति पर **IPC** की धारा **120 B** लागू करके **धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA)** के तहत मामला दर्ज नहीं किया जा सकता है।

IPC की धारा 120A
- भारत में **आपराधिक साजिश** वह अपराध है जिसमें **दो या दो** से अधिक लोग मिलकर किसी अपराध को अंजाम देने की योजना बनाते हैं।
- सीधे तौर पर कुछ गैरकानूनी करने के लिए सहमत होना।
- कुछ कानूनी करने के लिए सहमत होना, लेकिन अवैध तरीकों से।
- किसी आपराधिक साजिश को साबित करने के लिए तीन प्रमुख आवश्यकताएं हैं:
- **समझौता:** षडयंत्रकारियों के बीच विचारों का मिलन अवश्य होना चाहिए, जो स्पष्ट रूप से बोले या लिखे न जाने पर भी उनके कार्यों से स्पष्ट हो सकता है।
- **सामान्य इरादा:** सभी षड्यंत्रकारियों को एक विशिष्ट अपराध करने का लक्ष्य साझा करना चाहिए।
- **प्रत्यक्ष अधिनियम:** कम से कम एक साजिशकर्ता को योजनाबद्ध अपराध को अंजाम देने की दिशा में एक ठोस कदम उठाना चाहिए।
- कानून सह-षड्यंत्रकारियों के साथ अपराध में भागीदार की तरह व्यवहार करता है।
- इसका मतलब यह है कि यदि साजिश का एक सदस्य अपराध करता है, तो एजेंसी के सिद्धांत के अनुसार, सभी सदस्यों को कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
- आपराधिक साजिश की सज़ा नियोजित अपराध की गंभीरता के आधार पर भिन्न होती है:
- **गंभीर अपराध:** यदि साजिश मौत, आजीवन कारावास या कम से कम दो साल के कठोर कारावास से दंडनीय कोई बड़ा अपराध करने के लिए है, तो साजिश के लिए सजा योजनाबद्ध अपराध के समान ही है।
- **कम अपराध:** गैरकानूनी कार्य करने की अन्य सभी साजिशों के लिए, सजा अधिकतम छह महीने की कैद, जुर्माना या दोनों है।
- यह IPC की धारा 120B के महत्व पर प्रकाश डालता है, जो आपराधिक साजिश के लिए दंड की रूपरेखा बताती है।

39. चुनाव आयोग का सीविजिल ऐप नागरिकों को सशक्त बनाएगा - पीआईबी

प्रासंगिकता: विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप और उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे
- सीविजिल
- निर्वाचन आयोग

समाचार:
- **भारत निर्वाचन आयोग** का **सीविजिल ऐप** लोगों के हाथ में **चुनाव आचार संहिता** के उल्लंघन को चिह्नित करने का एक प्रभावी उपकरण बन गया है।
- **आम चुनाव 2024** की **घोषणा** के बाद से आज तक **79,000** से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं।
- गति और पारदर्शिता **सीविजिल ऐप** की आधारशिला हैं।

सीविजिल: निष्पक्ष चुनाव के लिए नागरिकों को सशक्त बनाना
- **भारतीय चुनाव आयोग (ECI)** ने चुनावी कदाचार की रिपोर्ट करने की शक्ति सीधे आपकी जेब में डालते हुए **सीविजिल ऐप लॉन्च** किया है।
- यह **उपयोगकर्ता-अनुकूल ऐप** चुनाव के दौरान **आदर्श आचार संहिता (MCC)** के उल्लंघन की रिपोर्ट करना पहले से कहीं अधिक आसान बनाता है।

सतर्क नागरिकों के लिए सुविधाएँ:

- **रिपोर्ट:** राजनीतिक कदाचार के गवाह सीविजिल के साथ, आप मिनटों के भीतर शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिससे रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।
- **रीयल-टाइम साक्ष्य कैप्चर:** सीधे ऐप के माध्यम से फोटो, वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग कैप्चर करें, जो उल्लंघन के मूल्यवान सबूत प्रदान करता है।
- **अपनी शिकायत को ट्रैक करें:** अपनी शिकायत के लिए एक अद्वितीय आईडी प्राप्त करें, जिससे आप अपने फोन पर इसकी प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं।
- **समयबद्ध कार्रवाई** : ऐप आपकी रिपोर्ट पर त्वरित प्रतिक्रिया की गारंटी देते हुए 100 मिनट की प्रतिक्रिया विंडो सुनिश्चित करता है।
- **प्रेसिस लोकेशन ट्रैकिंग:** : जियो-टैगिंग स्वचालित रूप से उल्लंघन के स्थान को पकड़ लेती है, जिससे उड़न दस्तों को तत्काल कार्रवाई में सहायता मिलती है।
- **लाइव इंसीडेंट फोकस:** सीविजिल केवल चल रहे उल्लंघनों के लिए रिपोर्टिंग की अनुमति देता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि नवीनतम जानकारी अधिकारियों तक पहुंचे।
- **सीविजिल नागरिकों** को **निष्पक्ष और नैतिक चुनाव सुनिश्चित** करने में **सक्रिय भागीदार** बनने का अधिकार देता है।

40. दिल्ली पुलिस ने UAPA मामले में न्यूज़क्लिक के ख़िलाफ़ आरोप पत्र दायर किया -द हिंदू

प्रासंगिकता: विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप और उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे
- UAPA
- जमानत का प्रावधान

समाचार:

- दिल्ली पुलिस ने **गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967** के तहत दर्ज एक मामले में समाचार **पोर्टल न्यूज़क्लिक** के खिलाफ अपनी पहली **चार्जशीट** दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्हें **चीन समर्थक प्रचार फैलाने** के लिए **चीनी कंपनियों** के माध्यम से धन प्राप्त हुआ था।
- **UAPA** की **धारा 43D** के तहत किसी मामले में आरोप पत्र दायर करने का समय **90 दिन** से लेकर **180 दिन** तक होता है।
- मौजूदा मामले में, अदालत ने **दिल्ली पुलिस** की **स्पेशल सेल** को आरोपपत्र दाखिल करने के लिए **तीन बार** मोहलत दी है।

UAPA में जमानत संबंधी प्रावधान और मुद्दे

- **UAPA** के साथ बड़ी समस्या इसकी **धारा 43(D)(5)** में है, जो किसी भी **आरोपी व्यक्ति** को जमानत पर रिहा करने से रोकती है।
  - यदि, पुलिस ने आरोप पत्र दायर किया है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सच है।
- **धारा 43(D)(5)** का प्रभाव यह है कि एक बार जब पुलिस किसी व्यक्ति पर **UAPA** के तहत आरोप लगाती है, तो जमानत देना बेहद मुश्किल हो जाता है।
- **जमानत स्वतंत्रता** के **संवैधानिक अधिकार** की **सुरक्षा और गारंटी** है।
- **जहूर अहमद शाह वताली** के मामले में, **सुप्रीम कोर्ट** ने **वर्ष 2019** में पुष्टि की कि अदालतों को राज्य के मामले को उसकी खूबियों की जांच किए बिना स्वीकार करना चाहिए।
- हालाँकि, अदालतों ने इस प्रावधान को अलग तरह से पढ़ा है, त्वरित सुनवाई के अधिकार पर जोर दिया है और राज्य के लिए **UAPA** के तहत किसी व्यक्ति पर मामला दर्ज करने की सीमा बढ़ा दी है।

41. इलाहाबाद HC ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा अधिनियम को 'असंवैधानिक' बताया - द हिंदू

प्रासंगिकता: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे
- उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा अधिनियम, 2004

समाचार:
- **उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा अधिनियम, 2004** को "**असंवैधानिक**" करार देते हुए, **इलाहाबाद उच्च न्यायालय** ने कहा कि यह **अधिनियम धर्मनिरपेक्षता** के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।

मुख्य बिंदु
- **अदालत** ने कहा कि **राज्य** के पास **धार्मिक शिक्षा** के लिए **बोर्ड बनाने** या केवल **किसी विशेष धर्म** और **उससे जुड़े दर्शन** के लिए **स्कूली शिक्षा** के लिए **बोर्ड स्थापित** करने की कोई शक्ति नहीं है।
- यह राज्य का कर्तव्य है कि वह ऐसी शिक्षा प्रदान करे जो **प्रकृति** में **धर्मनिरपेक्ष** हो।
- यह **अलग-अलग धर्मों** के बच्चों के साथ भेदभाव नहीं कर सकता और उन्हें **अलग-अलग** तरह की **शिक्षा** नहीं दे सकता।
- राज्य की ओर से ऐसी कोई भी कार्रवाई **धर्मनिरपेक्षता** का **उल्लंघन** होगी, जो **संविधान की मूल संरचना** का हिस्सा है।
- राज्य की ओर से इस तरह की कार्रवाई न केवल **असंवैधानिक** है, बल्कि **धार्मिक आधार** पर समाज को **अत्यधिक विभाजित** करने वाली भी है।"

'कोई समानता नहीं'
- "**सुप्रीम कोर्ट** ने बार-बार **आधुनिक विषयों** के साथ **आधुनिक शिक्षा** पर जोर दिया है
- अदालत ने **सरकार** को इन **छात्रों को नियमित स्कूलों** में **समायोजित** करने के लिए तुरंत कदम उठाने का निर्देश दिया
  - **प्राथमिक शिक्षा बोर्ड** के तहत मान्यता प्राप्त और **उत्तर प्रदेश** के **हाई स्कूल** और **इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड** के तहत मान्यता प्राप्त स्कूल।

42. भारत में सबसे अधिक 'जीरो-फूड' बच्चे: JAMA नेटवर्क रिपोर्ट - द हिंदू

प्रासंगिकता: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे
- कुपोषण
- FAO

समाचार:
- हाल ही में **पीयर-रिव्यू JAMA** नेटवर्क ओपन **जर्नल** में **प्रकाशित** एक अध्ययन में भारत में **'शून्य-खाद्य बच्चों'** की व्यापकता **19.3%** पाई गई, जो बच्चों में **अत्यधिक भोजन अभाव** की ओर ध्यान आकर्षित करती है।

मुख्य बिंदु
- अध्ययन में **भारत** को **गिनी (21.8%)** और **माली (20.5%)** से ऊपर, **शून्य-खाद्य बच्चों** का **तीसरा सबसे बड़ा प्रतिशत वाला देश** माना गया है।
- संख्या के संदर्भ में, **भारत** में **'शून्य-भोजन वाले बच्चों'** की संख्या सबसे अधिक है, जो **छह मिलियन** से अधिक है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश (28.4%), बिहार (14.2%), महाराष्ट्र (7.1%), राजस्थान (6.5%), और मध्य प्रदेश (6%) राज्यों में भारत में **कुल शून्य-खाद्य बच्चों** का **लगभग दो-तिहाई हिस्सा** है।
- छह महीने का होने के बाद **स्तनपान** से **शिशुओं को आवश्यक पोषण** नहीं मिल पाता है।
- **स्तनपान** के साथ-साथ **ठोस** या अ**र्ध-ठोस खाद्य पदार्थों** की शुरूआत **बचपन की वृद्धि** और **विकास** में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

- **खाद्य और कृषि संगठन (FAO)** के अनुसार **कैलोरी** आवश्यकताओं में योगदान देने वाले अन्य खाद्य पदार्थों का हिस्सा **नौ से 11 महीने** की **उम्र के बच्चों** के लिए **लगभग 50%** होना चाहिए (यानी 700 किलो कैलोरी/दिन में से 300)
  - जबकि **छह-आठ महीने की उम्र** के **बच्चों** के लिए **मां के दूध का हिस्सा** अन्य भोजन से अधिक होना चाहिए (यानी 600 किलो कैलोरी/दिन में से 400)।
- **"वंचित आर्थिक पृष्ठभूमि की महिलाएं** अपने **परिवार** का **भरण-पोषण** करने के लिए काम करती हैं, जिसके परिणामस्वरूप **छह महीने** से अधिक **उम्र के बच्चों** को **स्तनपान** कराने के लिए उनके पास अपर्याप्त समय होता है।
- तेजी से **औद्योगीकरण** के साथ, **शहरी** और **ग्रामीण दोनों क्षेत्रों** में **एकल परिवार** बढ़ गए हैं, इसलिए **माँ** के अलावा, **बच्चे को खिलाने** के लिए **आवश्यक समय** और **ऊर्जा** लगाने वाला कोई नहीं है।
  - **बच्चों की पोषण संबंधी** आवश्यकताओं के बारे में **जागरूकता** की कमी और **सामाजिक भ्रांतियाँ** भी **संभावित संख्या** में योगदान करती हैं।

43. फ्रांस ने अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को शामिल किया - द हिंदू

प्रासंगिकता: भारत के हितों, भारतीय प्रवासियों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव।

प्रीलिम्स टेकअवे
- भारत गर्भपात कानून
- गर्भपात का अधिकार

समाचार:
- फ्रांस ने **8 मार्च** को अपने **संविधान में गर्भपात** के **गारंटीकृत अधिकार** को अंकित किया, जो **अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर** महिलाओं के अधिकारों के समर्थन का एक **महत्वपूर्ण संदेश** है।

मुख्य बिंदु
- **जनवरी 2024** में, **फ्रांस की संसद** ने **गर्भपात** के **अधिकार** को **संवैधानिक वैधता** प्रदान करने के लिए एक संशोधन पारित किया था।
- गर्भपात, हालांकि फ्रांस में **वर्ष 1975** से वैध है, अब महिलाओं के लिए एक **"गारंटी स्वतंत्रता"** बन गया है।
- हालाँकि संविधान में **दुर्लभ संशोधन फ्रांस** में मिसाल से रहित नहीं है।
- **वर्ष 1958** में अपनाए जाने के बाद से **फ्रांसीसी संविधान** को लगभग **25 बार संशोधित** किया गया है।
- आखिरी संशोधन उदाहरण **वर्ष 2008** में था जब **संसद को अधिक शक्तियां** प्रदान की गईं और **राष्ट्रपति का कार्यकाल** कार्यालय में **अधिकतम दो लगातार पांच साल** के कार्यकाल तक सीमित था।
- वर्तमान में **गर्भपात** के बारे में ऐसी **विशिष्टता** रखने वाला **फ्रांस एकमात्र देश** है।

अन्य यूरोपीय देशों के बारे में क्या?
- वर्तमान में **40** से अधिक **यूरोपीय देशों** में **गर्भपात** की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन कुछ देशों में इस प्रक्रिया तक पहुंच को सीमित करने के प्रयास बढ़ रहे हैं।
- **सितंबर 2022** में, **हंगरी** की **धुर दक्षिणपंथी सरकार** ने **सुरक्षित गर्भपात कराने** से पहले **महिलाओं** के लिए **भ्रूण की नाड़ी सुनना** अनिवार्य कर दिया, जिसे कभी-कभी **"भ्रूण की दिल की धड़कन"** भी कहा जाता है।
- **पोलैंड**, जहां **यूरोप में सबसे** कड़े **गर्भपात कानून** हैं, केवल **बलात्कार, अनाचार** या **मां** के **स्वास्थ्य** या **जीवन के लिए खतरा** होने पर ही **गर्भपात** की अनुमति देता है।
- **ब्रिटेन गर्भावस्था** के **24 सप्ताह** तक **गर्भपात** की अनुमति देता है यदि इसे **दो डॉक्टरों** द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

44. विधि आयोग ने व्यापार रहस्यों की सुरक्षा के लिए नए कानून की सिफारिश की- इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधन जुटाने, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे
- राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति
- विधि आयोग

समाचार:
- **22वें विधि आयोग** ने सिफारिश की कि **व्हिसिलब्लोअर संरक्षण, अनिवार्य लाइसेंसिंग, सरकारी उपयोग** और **सार्वजनिक हित** से संबंधित अपवादों के साथ **व्यापार रहस्यों की रक्षा** के लिए **नया कानून** पेश किया जाए।

मुख्य बिंदु
- व्यापार रहस्य गोपनीय जानकारी पर **बौद्धिक संपदा अधिकार** हैं जिन्हें बेचा या **लाइसेंस** दिया जा सकता है।
- वे अपना मूल्य गुप्त रखे जाने से प्राप्त करते हैं।
- हालाँकि, बौद्धिक संपदा के अन्य रूपों के विपरीत, जिनकी अवधि सीमित है, व्यापार रहस्यों को अनिश्चित काल तक संरक्षित किया जा सकता है।
- वर्तमान में, **भारत में व्यापार रहस्यों** की सुरक्षा के लिए एक विशिष्ट कानून का अभाव है।
- इसके बजाय, उन्हें अनुबंधों, **सामान्य कानून, आपराधिक कानून** और **विश्वास और समानता** के उल्लंघन के **सिद्धांतों** को नियंत्रित करने वाले **सामान्य कानूनों** के तहत सुरक्षित किया जाता है।
- हालाँकि, **'व्यापार रहस्य** और **आर्थिक जासूसी'** पर प्रकाशित **289वीं विधि आयोग** की रिपोर्ट में कहा गया है कि:
  - आयोग का संदर्भ सरकार में विचार-विमर्श के बाद आया, जहां इस विषय पर कानून की आवश्यकता महसूस की गई।
- हालाँकि, **राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति, 2016** और **संसदीय स्थायी समिति** की रिपोर्ट ने ध्यान वापस ला दिया है
  - व्यापार रहस्यों से निपटने के लिए कानून लाने की आवश्यकता पर रिपोर्ट बताती है।
- आर्थिक जासूसी के विषय पर, रिपोर्ट में कहा गया है कि "यहां तक कि **भारत सरकार** द्वारा रखे गए व्यापार रहस्यों को भी **सक्रिय और निष्क्रिय** आर्थिक जासूसी के कृत्यों में विदेशी सरकारों द्वारा लगातार निशाना बनाया गया है।"
  - इसलिए, "व्यापार रहस्य लीक और आर्थिक जासूसी से संबंधित सभी मुद्दों" को संबोधित करने के लिए एक एकल क़ानून की आवश्यकता है।

GOVERNMENT SCHEME

45. कैबिनेट ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दी - द हिंदू/ कैबिनेट ने 75 हजार करोड़ रुपये की छत सौर योजना को मंजूरी दी - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप और उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे
- पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना
- वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड (OSOWOG) पहल
- नवीकरणीय ऊर्जा

समाचार:
- हाल ही में, **केंद्रीय मंत्रिमंडल** ने **₹75,021 करोड़** के बजट के साथ **पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना** को मंजूरी दी।

पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना
- **मुफ्त बिजली योजना** की घोषणा पहले **वित्त मंत्री** ने **अंतरिम बजट भाषण** में की थी।
- **उद्देश्य:** पूरे भारत में छत पर सौर ऊर्जा संयंत्रों को बढ़ावा देना, एक करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा करना।

वित्तीय सहायता

- सरकार लाभार्थियों पर कोई **वित्तीय बोझ** नहीं पड़ने की गारंटी देती है।
  - सीधे उनके बैंक खातों में महत्वपूर्ण सब्सिडी प्रदान करके।
  - अत्यधिक रियायती बैंक ऋण की पेशकश करके।
- यह **2 किलोवाट सिस्टम** के लिए स्थापना लागत का **60%** और **2-3 किलोवाट क्षमता** वाले **सिस्टम** के लिए **40% वित्त पोषण** करेगा।
- **3 किलोवाट** से अधिक क्षमता वाले **सिस्टम केंद्रीय सब्सिडी** के लिए पात्र नहीं होंगे।
- शेष स्थापना लागत परिवारों द्वारा **संपार्श्विक-मुक्त, कम-ब्याज ऋण के माध्यम** से कवर की जाएगी, जो वर्तमान में लगभग **7%** पर उपलब्ध है।

अतिरिक्त घटक

- **ग्रामीण क्षेत्रों** में छत पर **सौर ऊर्जा** अपनाने को प्रदर्शित करने के लिए प्रत्येक जिले में एक **"मॉडल सौर गांव"** विकसित करने का प्रावधान।
- **शहरी स्थानीय निकायों** और **पंचायतों** को अपने **अधिकार क्षेत्र** में छत पर **सौर प्रणाली** को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनियों (RESCOs) के लिए भुगतान सुरक्षा
- छत पर सौर प्रौद्योगिकी में नवीन परियोजनाओं के लिए समर्पित धनराशि।

कार्यान्वयन

- यह योजना स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए **भारत में निर्मित सौर पैनलों और प्रणालियों** के उपयोग पर बल देती है ।
- प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र इकाई **निजी कंपनियों के साथ विशेष प्रयोजन वाहन (SPVs)** बनाकर कार्यक्रम को निष्पादित करने के लिए विशिष्ट राज्यों के साथ जुड़ेगी।

अपेक्षित फायदे

- मुफ्त सौर बिजली और वितरण कंपनियों को अधिशेष बेचने से
  - परिवारों को सालाना पंद्रह से अठारह हजार रुपये तक की बचत होती है।
- इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग
- **आपूर्ति और स्थापना** के लिए बड़ी संख्या में **विक्रेताओं के लिए उद्यमिता** के अवसर
- **विनिर्माण, स्थापना** और **रखरखाव** में तकनीकी **कौशल वाले युवाओं** के लिए **रोजगार** के अवसर।

46. शिक्षा मंत्री ने SWAYAM Plus प्लेटफॉर्म लॉन्च किया - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप और उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे
• स्वयं (SWAYAM) प्लस प्लेटफार्म
• स्वयं (SWAYAM) मंच

समाचार:

- हाल ही में **केंद्रीय शिक्षा** एवं **कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री** ने **'स्वयं प्लस'(SWAYAM Plus)** प्लेटफॉर्म लॉन्च किया।

स्वयं प्लस प्लेटफार्म

- यह मंच **रोजगार और व्यावसायिक विकास** पर ध्यान केंद्रित करने वाले **उद्योग के नेताओं** के साथ **सहयोगात्मक रूप** से **विकसित पाठ्यक्रम** प्रदान करता है ।
- यह विनिर्माण, ऊर्जा, कंप्यूटर विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रबंधन अध्ययन, स्वास्थ्य सेवा, आतिथ्य, पर्यटन और भारतीय ज्ञान प्रणाली जैसे कई क्षेत्रों में कार्यक्रम पेश करेगा।
- इसमें **बहुभाषी सामग्री** (देश की 12 प्रमुख भारतीय भाषाओं में उपलब्ध), **AI-सक्षम चैटबॉट** और **क्रेडिट** पहचान जैसे नवीन तत्व शामिल हैं।
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास (IIT मद्रास) **'स्वयं प्लस'** प्लेटफॉर्म संचालित करेगा।
  - IIT मद्रास **स्वयं-NPTEL** और **MOOC** मंच का संस्थापक संस्थान है।

उद्देश्य

- **व्यावसायिक** और **करियर विकास** में **सभी हितधारकों** के लिए एक **पारिस्थितिकी तंत्र** का निर्माण करना
  - शिक्षार्थियों, पाठ्यक्रम प्रदाताओं, उद्योग, शिक्षा जगत और रणनीतिक साझेदारों सहित।

- **सर्वोत्तम उद्योग** और **शैक्षणिक साझेदारों** द्वारा पेश किए जाने वाले **उच्च गुणवत्ता** वाले **प्रमाणपत्रों** और **पाठ्यक्रमों** को मान्यता देने के लिए एक तंत्र को सक्षम करना।
- **टियर 2 और 3 कस्बों** और **ग्रामीण क्षेत्रों** पर विशेष जोर देते हुए, देश भर में एक **बड़े शिक्षार्थी** आधार तक पहुंचना।
- **प्लेटफ़ॉर्म** पर **मेंटरशिप**, **स्कॉलरशिप** और **जॉब प्लेसमेंट** जैसी सुविधाएं लाने के लिए, **सर्टिफिकेट,** डिप्लोमा या डिग्री जैसे सभी स्तरों पर **अपस्किलिंग** और **री-स्किलिंग** के लिए एक **व्यापक डिजिटल इकोसिस्टम** बनाना।

महत्व

- इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से **एक्सपोजर छात्रों** को **सैद्धांतिक ज्ञान, व्यावहारिक कौशल और नवीनतम** नौकरी बाजार रुझानों के बारे में जागरूकता से लैस करेगा।
- यह कोर्स **अकादमिक और उद्योग** के बीच का **समंजस्य** स्थान बनाए रखने के लिए होते हैं, जिससे **कॉलेज स्नातकों** को **नौकरी के लिए** और **प्रतिस्पर्धी** बनाया जा सकता है।

47. प्रधानमंत्री ने सशक्त नारी - विकसित भारत कार्यक्रम में हिस्सा लिया - पीआईबी

प्रासंगिकता: देश के विभिन्न हिस्सों में प्रमुख फसल-फसल पैटर्न, - विभिन्न प्रकार की सिंचाई और सिंचाई प्रणाली, कृषि उपज का भंडारण, परिवहन और विपणन और मुद्दे और संबंधित बाधाएं; किसानों की सहायता में ई-प्रौद्योगिकी।

प्रीलिम्स टेकअवे
- स्वयं सहायता समूह
- ड्रोन दीदी

समाचार:

- प्रधानमंत्री ने **सशक्त नारी - विकसित भारत कार्यक्रम** में भाग लिया और **भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान** में नमो **ड्रोन दीदियों** द्वारा आयोजित **कृषि ड्रोन प्रदर्शन** देखा।

विकसित भारत संकल्प यात्रा

- यह सभी **ग्राम पंचायतों, नगर पंचायतों** और **शहरी स्थानीय निकायों** को कवर करते हुए देश भर में **भारत सरकार** की योजनाओं की संतृप्ति प्राप्त करने के लिए **आउटरीच गतिविधियों** के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने का एक राष्ट्रव्यापी अभियान है।
- यह अभियान भारत सरकार के विभिन्न **मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों**, **केंद्र सरकार के संगठनों** और संस्थानों की **सक्रिय भागीदारी** के साथ **संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण** अपनाकर चलाया जा रहा है।

नमो ड्रोन दीदी योजना

- **ग्रामीण क्षेत्रों** में **महिलाओं** को सशक्त बनाने और उन्हें **आर्थिक रूप** से स्वतंत्र बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है
- **केंद्र सरकार** ने एक पहल की जिसमें **15,000 महिलाओं** के नेतृत्व वाले **स्वयं सहायता समूहों (SHG)** को **कृषि ड्रोन** प्राप्त होंगे
  - फसल की निगरानी, उर्वरक छिड़काव और बीज बोने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में सहायता करना।
- यह पहल न केवल **महिलाओं को रोजगार** के अवसर प्रदान करती है बल्कि **आधुनिक प्रौद्योगिकी** के **एकीकरण** के **माध्यम से कृषि उत्पादकता** को भी बढ़ाती है।
- **ड्रोन गैजेट्स** का उपयोग दूध, किराने का सामान, **दवाएं और चिकित्सा नमूने** जैसी वस्तुओं को वितरित करने के लिए किया जाएगा।
- इसका उद्देश्य उन कमजोर लोगों तक पहुंचना है जो विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र हैं लेकिन अब तक लाभ नहीं उठा पाए हैं।

48. प्रधानमंत्री ने पीएम-सूरज पोर्टल लॉन्च किया - द हिंदू

प्रासंगिकता: केंद्र और राज्यों द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन कमजोर वर्गों की सुरक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थानों और निकायों का प्रदर्शन।

प्रीलिम्स टेकअवे
- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

समाचार:

- प्रधानमंत्री **ने प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधार जनकल्याण** (पीएम-सूरज) **पोर्टल** लॉन्च किया ।

मुख्य बिंदु

- इसका उद्देश्य **समाज के वंचित वर्गों के उद्यमियों** को **ऋण** सहायता प्रदान करना है

- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक राष्ट्रव्यापी पहल शुरू की गई है
- इसने अनुसूचित जाति, विमुक्त, खानाबदोश और अर्ध-घुमंतू जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और सफाई कर्मचारियों के एक लाख लाभार्थियों को लगभग **₹720 करोड़ का ऋण** वितरित किया।
- पोर्टल एक **वन-स्टॉप पॉइंट** होगा जहां **समाज** के वंचित वर्गों के लोग आवेदन कर सकते हैं और उनके लिए पहले से उपलब्ध सभी ऋण और **क्रेडिट योजनाओं** की प्रगति की निगरानी कर सकते हैं।

कमजोर वर्ग के लिए कल्याण योजना

- नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (PCR) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (PoA)
- स्टैंड-अप इंडिया योजना
- प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना
- प्रधानमंत्री वन धन योजना
- वन बंधु कल्याण योजना
- जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र
- हमारी धरोहर
- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

49. प्रधानमंत्री ने हजरतबल तीर्थ विकास परियोजना का उद्घाटन किया- पीआईबी

प्रासंगिकता: भारतीय संस्कृति प्राचीन से आधुनिक काल तक कला रूपों, साहित्य और वास्तुकला के प्रमुख पहलुओं को कवर करेगी।

प्रीलिम्स टेकअवे
- मथुरा-वृंदावन को मेगा टूरिस्ट सर्किट
- प्रसाद योजना

समाचार:

- **40 करोड़ रुपये** की **हजरतबल तीर्थ विकास परियोजना**, जिसका उद्घाटन **प्रधानमंत्री** ने किया था, प्रसाद योजना के तहत स्वीकृत **46 परियोजनाओं** में से एक है।
- **पर्यटन मंत्रालय** द्वारा **वर्ष 2014** में **तीर्थयात्रा कायाकल्प** और **आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रसाद)** योजना शुरू की गई।

मुख्य बिंदु

- पिछले दशक में **50 प्रतिशत** (22 परियोजनाएं) से भी कम पूरी होने के कारण यह योजना देरी के कारण खराब हो गई है
- **प्रसाद योजना** को पहले **प्रसाद** कहा जाता था क्योंकि '**विरासत स्थलों** का विकास' को केवल **वर्ष 2020** में नाम में जोड़ा गया था।
- इसका उद्देश्य आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए **लोकप्रिय धार्मिक, आध्यात्मिक और विरासत** स्थलों का एकीकृत विकास करना है
  - जैसे पार्किंग, रास्ते, शौचालय, रोशनी, पर्यटक सूचना केंद्र, आदि, और उन्हें लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के रूप में प्रचारित करें।
- इस योजना के तहत, बड़ी संख्या में परियोजनाएं **हिंदू तीर्थ स्थलों** पर शुरू की जा रही हैं
  - इनमें सोमनाथ मंदिर (गुजरात), श्रीशैलम मंदिर (आंध्र प्रदेश), कामाख्या मंदिर (असम) और केदारनाथ (उत्तराखंड) शामिल हैं।
- **हजरतबल दरगाह** और **अजमेर शरीफ दरगाह** सहित अन्य **धार्मिक और विरासत स्थलों** पर भी विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है
  - फोर पैट्रन सेंट्स, युकसोम (सिक्किम) में तीर्थयात्रा सुविधा का विकास;
  - चमकौर साहिब (पंजाब) का विकास, पटना साहिब (बिहार) का विकास;
  - जुन्हेबोटो (नागालैंड) में तीर्थयात्रा पर्यटन बुनियादी ढांचे का विकास;
  - पिछले महीने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में मंत्रालय के अनुसार, वाराणसी में नदी क्रूज पर्यटन सहित अन्य।
- **कार्यान्वयन एजेंसियों** की पहचान के साथ-साथ **वन विभाग** और **स्थानीय अधिकारियों** से मंजूरी में देरी

- परियोजनाओं के पूरा होने में देरी के लिए **महामारी** को जिम्मेदार ठहराया गया।
- परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी, जिसे संबंधित **राज्य सरकारों** द्वारा क्रियान्वित किया जाना है
- यह विभिन्न कारकों के कारण हुआ है, जैसे राज्य प्राधिकरणों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने में देरी, विस्तृत **परियोजना रिपोर्ट (DPR)** की तैयारी और भूमि की उपलब्धता, आदि।

"मथुरा वृन्दावन को **मेगा टूरिस्ट सर्किट (Ph-II)** के रूप में विकसित करने और **विष्णुपद मंदिर, गया, बिहार** में बुनियादी सुविधाओं के विकास जैसी कुछ परियोजनाओं में **चार साल** की देरी हुई है।

50. केंद्र ने साइबर अपराध, वित्तीय धोखाधड़ी की जांच हेतु DIP और Chakshu पोर्टल लॉन्च किए- पीआईबी

प्रासंगिकता: विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियाँ; प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण और नई प्रौद्योगिकी का विकास।

प्रीलिम्स टेकअवे
- चक्षु
- साथी पोर्टल

समाचार:
- हाल ही में, संचार, **रेलवे और इलेक्ट्रॉनिक्स** और **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** ने **दूरसंचार विभाग** (**DoT**) के **'डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (DIP)'** और **संचार साथी पोर्टल** पर **'चक्षु' सुविधा** लॉन्च की है।

डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफार्म:
- इसे **दूरसंचार विभाग** द्वारा विकसित किया गया है।
- यह हितधारकों, **दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (TSP)**, **कानून प्रवर्तन एजेंसियों (LEA)**, **बैंकों** और **वित्तीय संस्थानों (FI),** सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, पहचान दस्तावेज जारी करने वाले प्राधिकरणों आदि के बीच वास्तविक समय में खुफिया जानकारी साझा करने, **सूचना के आदान-प्रदान** और **समन्वय** के लिए एक **सुरक्षित और एकीकृत मंच** है।
- **पोर्टल** में **दूरसंचार संसाधनों** के दुरुपयोग के रूप में पाए गए मामलों की जानकारी भी शामिल है।
- साझा की गई जानकारी हितधारकों के लिए उनके संबंधित डोमेन में उपयोगी हो सकती है।
- यह **हितधारकों** द्वारा कार्रवाई के लिए **संचार साथी पोर्टल** पर **नागरिकों** द्वारा शुरू किए गए अनुरोधों के लिए **बैकएंड रिपॉजिटरी** के रूप में भी काम करता है।
- **DIP सुरक्षित कनेक्टिविटी** पर **हितधारकों** के लिए **सुलभ** है और **प्रासंगिक** जानकारी उनकी संबंधित **भूमिकाओं** के आधार पर साझा की जाती है। उक्त **प्लेटफॉर्म नागरिकों** के लिए सुलभ नहीं है।

चक्षु(Chakshu) क्या है?
- यह **दूरसंचार विभाग** के **संचार साथी पोर्टल** पर पहले से उपलब्ध **नागरिक केंद्रित सुविधाओं** में नवीनतम वृद्धि है।
- यह नागरिकों को धोखाधड़ी के इरादे से कॉल, **SMS या व्हाट्सएप** पर प्राप्त संदिग्ध धोखाधड़ी संचार की रिपोर्ट करने की सुविधा देता है:
  - जैसे केवाईसी की समाप्ति या बैंक खाते/भुगतान वॉलेट/सिम/गैस कनेक्शन/बिजली कनेक्शन का अद्यतनीकरण,
  - पैसे भेजने के लिए सरकारी अधिकारी/रिश्तेदार के रूप में प्रतिरूपण करना, दूरसंचार विभाग द्वारा सभी मोबाइल नंबरों को डिस्कनेक्ट करना आदि।
- यदि कोई नागरिक पहले से ही साइबर अपराध या वित्तीय धोखाधड़ी का शिकार है
- सलाह दी जाती है कि साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 या भारत सरकार की वेबसाइट https://www.cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें।

51. TDB और FNDR को इनोवेटिव एंटीबायोटिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हेतु 75 लाख रूपये का अनुदान- पीआईबी

प्रासंगिकता: विज्ञान और प्रौद्योगिकी- विकास और रोजमर्रा की जिंदगी में उनके अनुप्रयोग और प्रभाव।

प्रीलिम्स टेकअवे
- ग्राम-नेगेटिव बैक्टीरिया
- दवा-प्रतिरोधी बैक्टीरिया

समाचार:
- **स्वास्थ्य सेवा नवाचार** को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से एक अभिनव पहल में, **प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड** ने **"ANAGRANINF"** परियोजना के लिए **₹75 लाख** का अनुदान स्वीकृत किया है।
- यह **ग्रामनेगेटिव जीवाणु-संक्रमण** के विरुद्ध **एंटीबायोटिक दवाओं** की एक **नवीन श्रेणी** का विकास है।

बैक्टीरिया से रक्षा हेतु नया एंटीबायोटिक

- इस परियोजना का लक्ष्य **ग्राम-नेगेटिव बैक्टीरिया** से होने वाले **गंभीर संक्रमण** से निपटने के लिए एक नए प्रकार का **एंटीबायोटिक विकसित** करना है।
- इन **बैक्टीरिया से इलाज** करना विशेष रूप से कठिन होता है क्योंकि उनके पास **दवाओं का विरोध** करने के कई तरीके होते हैं।

ग्राम-नेगेटिव बैक्टीरिया

- उनकी **कोशिका भित्ति** की संरचना अन्य बैक्टीरिया की तुलना में भिन्न होती है, जिससे उन्हें **एंटीबायोटिक दवाओं** से मारना कठिन हो जाता है।
- ये **नई दवाओं** के प्रति तेजी से **प्रतिरोध विकसित** कर सकते हैं और इस **प्रतिरोध** को **अन्य बैक्टीरिया** के साथ शेयर कर सकते हैं।
- ये **बैक्टीरिया निमोनिया, रक्तप्रवाह संक्रमण** और **सर्जिकल साइट संक्रमण** जैसे गंभीर संक्रमण का कारण बन सकते हैं।

परियोजना का लक्ष्य

- एक नई दवा (एंटीबायोटिक) विकसित करें जो **ग्राम-नेगेटिव बैक्टीरिया** में एक विशिष्ट एंजाइम (फैबी) को लक्षित कर सके।
- यह नई दवा इन मुश्किल इलाज वाले संक्रमणों के खिलाफ प्रभावी होगी।

परियोजना का वित्तपोषणकर्ता

- प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (TDB) एक सरकारी एजेंसी है जो भारत में नई प्रौद्योगिकियों के विकास का समर्थन करती है।

TDB अनुसंधान परियोजनाओं को वित्त पोषित करता है और कंपनियों को बाजार में नई तकनीक लाने में मदद करता है।

52. केंद्रीय गृहमंत्री राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (NCD) लॉन्च करेंगे- पीआईबी

प्रासंगिकता: विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप और उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे

- सहकारिता मंत्री
- 'राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस 2023

समाचार:

- **केंद्रीय गृहमंत्री** और **सहकारिता मंत्री नई दिल्ली** में **राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस** लॉन्च करेंगे।
- सहकारिता मंत्री '**राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस 2023**: एक रिपोर्ट' भी जारी करेंगे।

राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (NCD)

- यह **भारत** की **सहकारी समितियों** की जानकारी के लिए एक केंद्रीय केंद्र है, जिसे **सहकारिता मंत्रालय** द्वारा बनाया गया है।
- इस **ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म** का **लक्ष्य व्यापक और अद्यतन संसाधन प्रदान** करके सहकारी क्षेत्र को मजबूत करना है।
- **राज्य सरकारों**, **संघों** और अन्य हितधारकों के इनपुट के साथ विकसित, **NCD केंद्र सरकार**, **राज्यों** और **व्यक्तिगत सहकारी समितियों** के बीच एक पुल के रूप में कार्य करता है।
- **पंजीकरण विवरण**, **स्थान, सदस्यता संख्या** और **वित्तीय डेटा** सहित प्रत्येक **सोसायटी** की जानकारी एकत्र और मान्य की जाती है।
- यह **सहकारी नेटवर्क** में बेहतर **संचार और सहयोग** की अनुमति देता है।

NCD के लाभ:

- **आसान पहुंच:** सभी डेटा एक ही स्थान पर उपलब्ध है, जिससे सूचना पुनर्प्राप्ति सरल हो गई है।
- **विश्वसनीय जानकारी:** डेटा व्यापक, नवीनतम और सटीक है।
- **उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफ़ेस** : सिस्टम को नेविगेट करना और उपयोग करना आसान है।
- **नेटवर्क कनेक्शन** : डेटाबेस सहकारी समितियों के बीच संबंधों की पहचान करने में मदद करता है।
- **अनुकूलन योग्य रिपोर्ट** : उपयोगकर्ता विशिष्ट मानदंडों के आधार पर रिपोर्ट और ग्राफ़ तैयार कर सकते हैं।
- **डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि** : NCD निर्णय लेने की जानकारी देने के लिए डेटा विश्लेषण की अनुमति देता है।

- **दृश्य प्रतिनिधित्व** : भौगोलिक मानचित्रण सहकारी वितरण की स्पष्ट तस्वीर प्रदान करता है।

53. नीति आयोग ने 'वोकल फॉर लोकल' पहल का अनावरण किया- पीआईबी

प्रासंगिकता: विकास प्रक्रियाएँ और विकास उद्योग - गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, विभिन्न समूहों और संघों, दाताओं, दान, संस्थागत और अन्य हितधारकों की भूमिका।

प्रीलिम्स टेकअवे
- नीति आयोग
- लोकल के लिए वोकल

समाचार:
- नीति आयोग ने अपने आकांक्षी **ब्लॉक कार्यक्रम** के तहत '**वोकल फॉर लोकल**' पहल शुरू की है।

वोकल फॉर लोकल' पहल:
- यह लोगों के बीच **आत्मनिर्भरता** की **भावना** को **प्रोत्साहित** करने और उन्हें **सतत विकास और समृद्धि** की ओर प्रेरित करने के लिए अपने **आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम** के तहत **नीति आयोग** की एक पहल है।
- इस पहल के एक भाग के रूप में, **500 आकांक्षी ब्लॉकों** के **स्थानीय उत्पादों** को **आकांक्षा ब्रांड** के तहत मैप और समेकित किया गया है।
- आकांक्षा एक **व्यापक ब्रांड** है, जिसे कई **उप-ब्रांडों** में शामिल किया जा सकता है, जिनमें **अंतरराष्ट्रीय** बाजार बनाने की क्षमता है।
- इन उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए, **आकांक्षा ब्रांड** नाम के तहत **एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम** के लिए
  - एक समर्पित विंडो गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल पर स्थापित की गई है।
- भागीदार सुविधा के लिए तकनीकी और परिचालन सहायता भी प्रदान करेंगे

ई-कॉमर्स ऑनबोर्डिंग, लिंकेज स्थापित करना, वित्तीय/डिजिटल साक्षरता, दस्तावेज़ीकरण/प्रमाणन, और कौशल वृद्धि, आदि।

54. केंद्र ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार की योजना का अनावरण किया- द हिंदू

प्रासंगिकता: केंद्र और राज्यों द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का प्रदर्शन; इन कमजोर वर्गों की सुरक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थाएं और निकाय।

प्रीलिम्स टेकअवे
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण
- मोटर वाहन दुर्घटना निधि

समाचार:
- **सड़क परिवहन** और **राजमार्ग मंत्रालय** ने **सड़क दुर्घटनाओं** के **सभी पीड़ितों** को **₹1.5 लाख** तक का **कैशलेस इलाज** प्रदान करने के लिए एक **पायलट परियोजना** की घोषणा की है।

मुख्य बिंदु
- **गोल्डन ऑवर** के दौरान **सड़क दुर्घटनाओं** के पीड़ितों को समय पर **चिकित्सा देखभाल** प्रदान करने के लिए एक **पारिस्थितिकी तंत्र** स्थापित करने के लिए **चंडीगढ़** में **पायलट परियोजना** शुरू की जाएगी।
- **पीड़ित दुर्घटना** की तारीख से अधिकतम **सात दिनों** की अवधि के लिए **प्रति व्यक्ति ₹1.5 लाख** तक के **कैशलेस इलाज** के हकदार होंगे।
- यह योजना किसी भी श्रेणी की **सड़क** पर हुई **मोटर वाहन** से जुड़ी **सड़क दुर्घटनाओं** के सभी पीड़ितों पर लागू होगी।
- **प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना** के तहत दिए जाने वाले **ट्रॉमा** और **पॉलीट्रॉमा** के **पैकेज** को भी इस योजना के तहत शामिल किया जाएगा।
- उपचार प्रदान करने के लिए अस्पतालों द्वारा उठाए गए दावों की प्रतिपूर्ति **मोटर वाहन दुर्घटना निधि** से की जाएगी।
- **मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, 2019** के अनुसार, **गोल्डन ऑवर चोट** लगने के बाद की अवधि है, जिसके दौरान त्वरित चिकित्सा देखभाल प्रदान करके मृत्यु को रोकने की सबसे अधिक संभावना होती है।
- संशोधन में " **सड़क दुर्घटना पीड़ितों के कैशलेस इलाज के लिए एक योजना"** के साथ-साथ एक मोटर वाहन **दुर्घटना निधि** भी प्रदान की गई।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन एजेंसी होगी , और पुलिस, अस्पतालों और राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के साथ समन्वय करेगी।

मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, 2019

- अ**धिनियम मोटर वाहनों** से संबंधित **लाइसेंस** और **परमिट** देने, **मोटर वाहनों** के लिए **मानक** और इन प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान करता है।
- **केंद्र सरकार गोल्डन आवर** के दौरान **सड़क दुर्घटना पीड़ितों** के **कैशलेस इलाज** के लिए **एक योजना** विकसित करेगी।
- **भारत** में सभी **सड़क उपयोगकर्ताओं** को अनिवार्य **बीमा कवर** प्रदान करने के लिए **केंद्र सरकार** को एक **मोटर वाहन दुर्घटना कोष** का गठन करने की आवश्यकता है।
- यह अधिनियम एक अच्छे व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो **दुर्घटना स्थल** पर पीड़ित को **आपातकालीन चिकित्सा** या **गैर-चिकित्सा सहायता** प्रदान करता है।

यह केंद्र सरकार को **मोटर वाहनों** को वापस बुलाने का आदेश देने की अनुमति देता है यदि वाहन में खराबी से **पर्यावरण, चालक या अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं** को नुकसान हो सकता है।

INTERNATIONAL RELATION

55. भारत EFTA ब्लॉक के साथ व्यापार समझौता करने के लिए तैयार- इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: भारत के हितों, भारतीय प्रवासियों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव।

प्रीलिम्स टेकअवे
- EFTA
- यूरोपीय संघ

समाचार:
- **भारत** और **चार देशों** का **यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA**) समूह जिसमें **आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे** और **स्विट्जरलैंड** शामिल हैं।
- उनके **10 मार्च** को लंबे समय से बातचीत वाले **द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते** पर **हस्ताक्षर** करने की संभावना है
- कई स्रोतों के अनुसार, इसका उद्देश्य **व्यापार और निवेश प्रवाह, रोजगार सृजन** और **आर्थिक विकास** को बढ़ाना है।

यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA)
- EFTA **आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे** और **स्विट्जरलैंड** का **अंतर सरकारी संगठन** है।
- इसकी **स्थापना 1960** में (स्टॉकहोम कन्वेंशन द्वारा 1960 में) इसके तत्कालीन **सात सदस्य राज्यों** द्वारा अपने सदस्यों के बीच **मुक्त व्यापार** और **आर्थिक एकीकरण** को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।
- **संगठन यूरोपीय संघ (EU)** के समानांतर संचालित होता है, और **सभी चारों सदस्य** देश **यूरोपीय** एकल बाजार में भाग लेते हैं और **शेंगेन क्षेत्र** का हिस्सा हैं।
- हालाँकि, वे **यूरोपीय संघ सीमा शुल्क संघ** के पक्षकार नहीं हैं।
- एसोसिएशन के मुख्य कार्य **तीन प्रकार** के हैं-
  - EFTA कन्वेंशन को बनाए रखना और विकसित करना, जो चार EFTA राज्यों के बीच आर्थिक संबंधों को नियंत्रित करता है;
  - **यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र** (EEA समझौते) पर समझौते का प्रबंधन करना, जो **यूरोपीय संघ** और **EFTA** के **3 राज्यों आइसलैंड, लिकटेंस्टीन** और **नॉर्वे** को एक एकल (आंतरिक) बाजार में एक साथ लाता है।

  EFTA के **मुक्त व्यापार समझौतों** के **विश्वव्यापी नेटवर्क** का विकास करना।

56. कई देशों ने VASP के दुरुपयोग को रोकने के लिए मानको को पूरी तरह से लागू नहीं किए: FATF - द हिंदू

प्रासंगिकता: महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, एजेंसियां और मंच - उनकी संरचना, अधिदेश।

प्रीलिम्स टेकअवे
- FATF
- आभासी संपत्ति सेवा प्रदाताओं (VASP)

समाचार:
- **फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF)** ने पाया है कि कई देशों ने अभी तक **आभासी संपत्तियों** और **आभासी संपत्ति सेवा प्रदाताओं (VASP)** के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से इसकी आवश्यकताओं को पूरी तरह से लागू नहीं किया है।
- यह **वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग** और **आतंकवादी वित्तपोषण** निगरानी संस्था है,

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF)

- **FATF** एक **अंतरराष्ट्रीय संगठन** है जो **वित्तीय अपराध** से लड़ता है।
- यह **मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण** को रोकने के लिए नियम (मानक) बनाता है और देशों को उनका पालन करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- **FATF** की शुरुआत **वर्ष 1989** में **मनी लॉन्ड्रिंग** से निपटने के लिए की गई थी और बाद में **वर्ष 2001** में इसका ध्यान **आतंकवाद के वित्तपोषण** को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया।
- इसका **मुख्यालय पेरिस** में है और इसमें **39 सदस्य** हैं, जिनमें **अमेरिका, भारत** और **चीन** जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, **भारत** वर्ष **2010** में इसमें शामिल हुआ था।
- **वित्तीय अपराध** से लड़ने में कमज़ोर **देशों** की पहचान करने के लिए **FATF दो सूचियों** का उपयोग करता है:
- **ब्लैकलिस्ट** : जो देश सक्रिय रूप से मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवाद के वित्तपोषण का समर्थन करते हैं उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाता है।
- इससे उन्हें **विश्व बैंक** जैसे संगठनों से मिलने वाली **वित्तीय सहायता** से वंचित होना पड़ सकता है और **आर्थिक प्रतिबंधों** का सामना करना पड़ सकता है।
- वर्तमान में, **उत्तर कोरिया, ईरान और म्यांमार** को **ब्लैकलिस्ट** किया गया है।
- **ग्रे सूची:** मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवाद के वित्तपोषण के जोखिम वाले देशों को ग्रे सूची में डाल दिया जाता है।
- यह उनके नियंत्रण में सुधार करने या काली सूची में डाले जाने के जोखिम के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है।
- किसी भी सूची में होने से किसी देश के लिए **अंतरराष्ट्रीय स्तर** पर व्यापार करना कठिन हो सकता है।

57. ओपेक+ देशों ने कीमतें बढ़ाने के लिए तेल कटौती का विस्तार किया - द हिंदू

प्रासंगिकता: भारत के हितों, भारतीय प्रवासियों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव।

प्रीलिम्स टेकअवे
- ओपेक
- क्रूड ऑयल

समाचार:

- **मॉस्को, रियाद** और कई अन्य **ओपेक+ सदस्यों** ने आर्थिक अनिश्चितता के बाद कीमतों को बढ़ावा देने के लिए तेल उत्पादकों के बीच एक समझौते के हिस्से के रूप में **वर्ष 2023** में पहली बार घोषित तेल उत्पादन कटौती के विस्तार की घोषणा की है ।

ओपेक+

- यह **तेल निर्यातक देशों** का एक समूह है जो **विश्व बाजार** में कितना कच्चा तेल बेचना है यह तय करने के लिए नियमित रूप से बैठक करता है।
- ये देश **वर्ष 2016** के अंत में "**ओपेक और गैर-ओपेक उत्पादक देशों** के बीच **नियमित और सतत आधार पर सहयोग** के लिए एक ढांचे को **संस्थागत** बनाने के लिए" एक समझौते पर पहुंचे।
- इन देशों का **लक्ष्य तेल बाजार** में **स्थिरता** लाने के लिए **कच्चे तेल** के **उत्पादन को समायोजित** करने पर मिलकर काम करना है।
- **ओपेक+** लगभग **40% वैश्विक तेल आपूर्ति** और **80%** से अधिक सिद्ध तेल भंडार को नियंत्रित करता है।
- इस समूह के मूल में **ओपेक (तेल निर्यातक देशों का संगठन)** के सदस्य हैं, जो मुख्य रूप से **मध्य पूर्वी** और **अफ्रीकी देश** हैं।
- **सदस्य** : इसमें ओपेक देशों के अलावा अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, रूस, मैक्सिको, मलेशिया, दक्षिण सूडान, सूडान और ओमान शामिल हैं।
    - EFTA

58. भारत और EFTA देशों के बीच प्रस्तावित FTA को जल्द ही औपचारिक रूप दिया जा सकता है – द हिंदू

प्रासंगिकता: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधन जुटाने, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे
- EFTA
- व्यापार और निवेश समझौता

समाचार:

- **भारत** और **यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) देशों** के बीच प्रस्तावित **मुक्त व्यापार समझौते** को जल्द ही औपचारिक रूप दिया जा सकता है क्योंकि समझौता "**तैयार**" है और **कानूनी जांच** से गुजर रहा है।

मुख्य बिंदु

- समझौते में अगले **15 वर्षों** में **चार देशों** के समूह से **भारत** में **100 अरब डॉलर** के निवेश की **प्रतिबद्धता** जताई गई है, जिससे **अनुमानित 10 लाख नौकरियाँ** पैदा होंगी।
- यह **भारत** के लिए **पहला FTA** है जहां वह **भागीदार देशों** से **निवेश** और **रोजगार** पर **प्रतिबद्धता** प्राप्त करने में सक्षम हुआ है।
- **EFTA** देश **फार्मास्यूटिकल्स** जैसे क्षेत्रों में **संयुक्त उद्यमों** में **निवेश** करने पर विचार कर रहे हैं
  - विशेष रूप से चिकित्सा उपकरण, कुछ रसायन, खाद्य प्रसंस्करण और इंजीनियरिंग उत्पाद,''

मुक्त व्यापार समझौता

- EFTA देशों, जिनमें **स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे और लीचेंस्टीन** शामिल हैं, ने **अक्टूबर 2016** में भारत के साथ एक **मुक्त व्यापार समझौते** के लिए बातचीत फिर से शुरू की, जिसे **व्यापार और निवेश समझौता** कहा जाता है।
- प्रस्तावित समझौते में शामिल अध्यायों में वस्तुओं में व्यापार, उत्पत्ति के नियम, सेवाओं में व्यापार, निवेश प्रोत्साहन और सहयोग, व्यापार और सतत विकास,सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा शामिल हैं।
- देशों ने जिन **संयुक्त उद्यम क्षेत्रों** को शॉर्टलिस्ट किया है उनमें मुख्य रूप से वे क्षेत्र शामिल हैं जहां **भारत** से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है।
- **EFTA** ने **भारत** में किए जाने वाले **निवेश की शर्त** पर सहमति जताई है क्योंकि उन्हें **बाजार पहुंच** मिल रही है।

EFTA को निर्यात

- **वर्ष 2023** में **EFTA ब्लॉक** में **भारत** का **निर्यात 1.87 बिलियन डॉलर** था, जिसमें **रसायन, फार्मास्यूटिकल्स, परिधान और मोती, कीमती और अर्ध-कीमती पत्थरों** जैसी वस्तुओं का निर्यात बास्केट पर दबदबा था।
- दूसरी ओर, इसने 2023 में **EFTA** देशों से **20.45 बिलियन डॉलर** का **सामान आयात** किया, जिसमें मोती, कीमती या अर्ध-कीमती पत्थर, कीमती धातुएं और सिक्के शामिल थे, जिनकी कीमत **16.7 बिलियन डॉलर** थी।

59. भारत-अमेरिका त्रि-सेवा अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ शुरू -द हिंदू

प्रासंगिकता: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते जिनमें भारत शामिल है और/या भारत के हितों को प्रभावित करते हैं।

प्रीलिम्स टेकअवे

- HADR

समाचार:

- **भारत और अमेरिका** के बीच **त्रि-सेवा मानवीय सहायता** और **आपदा राहत (HADR)** अभ्यास टाइगर **ट्रायम्फ पूर्वी समुद्री** तट पर शुरू हुआ।

मुख्य बिंदु

- इस अभ्यास का उद्देश्य **HADR संचालन** के **संचालन** और **मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP)** को परिष्कृत करने के लिए अंतरसंचालनीयता विकसित करना है।
  - ताकि दोनों देशों की सेनाओं के बीच तीव्र और सुचारू समन्वय हो सके।
  - बंदरगाह चरण **18 से 25 मार्च** के लिए निर्धारित है, **दोनों नौसेनाओं** के **कार्मिक प्रशिक्षण दौरों,** विषय वस्तु विशेषज्ञ **आदान-प्रदान, खेल आयोजनों और सामाजिक बातचीत** में भाग लेंगे।
- इसमें कहा गया है कि **हार्बर चरण के** पूरा होने पर, **जहाज समुद्री चरण** के लिए रवाना होंगे और **इंजेक्शन** स्थितियों के अनुसार **समुद्री, उभयचर और HADR** संचालन करेंगे।

HADR

- भारत वै**श्विक स्तर** पर **मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR)** में प्रथम प्रत्युत्तरदाता बनकर उभरा है।
- मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) पर कार्यशाला का उद्देश्य **सूचनाओं का आदान-प्रदान** करना है।
  - जोखिम में कमी, **क्षेत्रीय प्रतिक्रिया** और **आपदा बुनियादी** ढांचे में **सशस्त्र बलों** के एकीकरण और एससीओ सदस्यों के बीच वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने पर **सर्वोत्तम गतिविधियों** को साझा करें।
- SCO का मुख्य लक्ष्य सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास और पड़ोसी भाव को मजबूत करना है।
  - राजनीति, व्यापार, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और संस्कृति के साथ-साथ शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण और अन्य क्षेत्रों में प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देना।

- क्षेत्र में **शांति, सुरक्षा और स्थिरता** बनाए रखने और सुनिश्चित करने के लिए **संयुक्त प्रयास** करना और एक **लोकतांत्रिक, निष्पक्ष** और **तर्कसंगत नई अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक** और **आर्थिक व्यवस्था** की स्थापना की दिशा में आगे बढ़ना।

60. राइट्स लिमिटेड IMEC कॉरिडोर के साथ विकास के अवसरों को लक्षित करेगा - द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे
- भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा
- मानचित्र आधारित प्रश्न

प्रासंगिकता: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते जिनमें भारत शामिल है और/या भारत के हितों को प्रभावित करते हैं।

समाचार:

- अग्रणी रेलवे PSU, **राइट्स (RITES) लिमिटेड** रणनीतिक **भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे** (IMEC) के साथ विकास पर नजर रखने वाली अन्य **भारतीय रेलवे कंपनियों** के बीच एक प्रमुख दावेदार के रूप में उभरी है।

मुख्य बिंदु

- **राइट्स (RITES)** और **AD पोर्ट्स** अब मौजूदा **रेल गलियारे** में छूटे हुए लिंक के साथ विकास की व्यवहार्यता का विश्लेषण कर रहे हैं।
  - जो **संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन और इज़राइल** से होकर गुजरती है।
- किस प्रकार की क्षमता वृद्धि की आवश्यकता है, किस प्रकार के डिज़ाइन और इसमें शामिल लागत पर आकलन किया जा रहा है।
- भले ही यह एक रेगिस्तानी इलाका है, लेकिन इलाका इतना चुनौतीपूर्ण नहीं है कि यह नहीं किया जा सके।''
- इसी तरह, **जेबेल अली (UAE)** से **हाइफ़ा** तक प्रस्तावित **रेल मार्ग 2,565 किमी** तक फैला है, जिसमें **745 किमी** का **लिंक** गायब है।
- **अबू धाबी से हाइफ़ा** तक का दूसरा मार्ग **2,449 किमी लंबा** है जिसमें **629 किमी लिंक** गायब है, जबकि **दम्मम बंदरगाह** से हैफ़ा तक प्रस्तावित मार्ग **2,149 किमी** है जिसमें **289 किमी लिंक** गायब है।
- अंत में, **रास अल-खैर बंदरगाह** से हाइफ़ा तक **1,809 किमी** तक फैला है और **269 किमी लिंक** गायब है।

भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) परियोजना

- के बारे में:
- प्रस्तावित **IMEC** में रेलमार्ग, **शिप-टू-रेल नेटवर्क** और **सड़क परिवहन मार्ग** शामिल होंगे जो दो गलियारों तक फैले होंगे, अर्थात,-
  - पूर्वी गलियारा - भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ता है,
  - उत्तरी गलियारा - खाड़ी को यूरोप से जोड़ता है।
- IMEC कॉरिडोर में एक **बिजली केबल,** एक **हाइड्रोजन पाइपलाइन** और एक **हाई-स्पीड डेटा केबल** भी शामिल होगी।

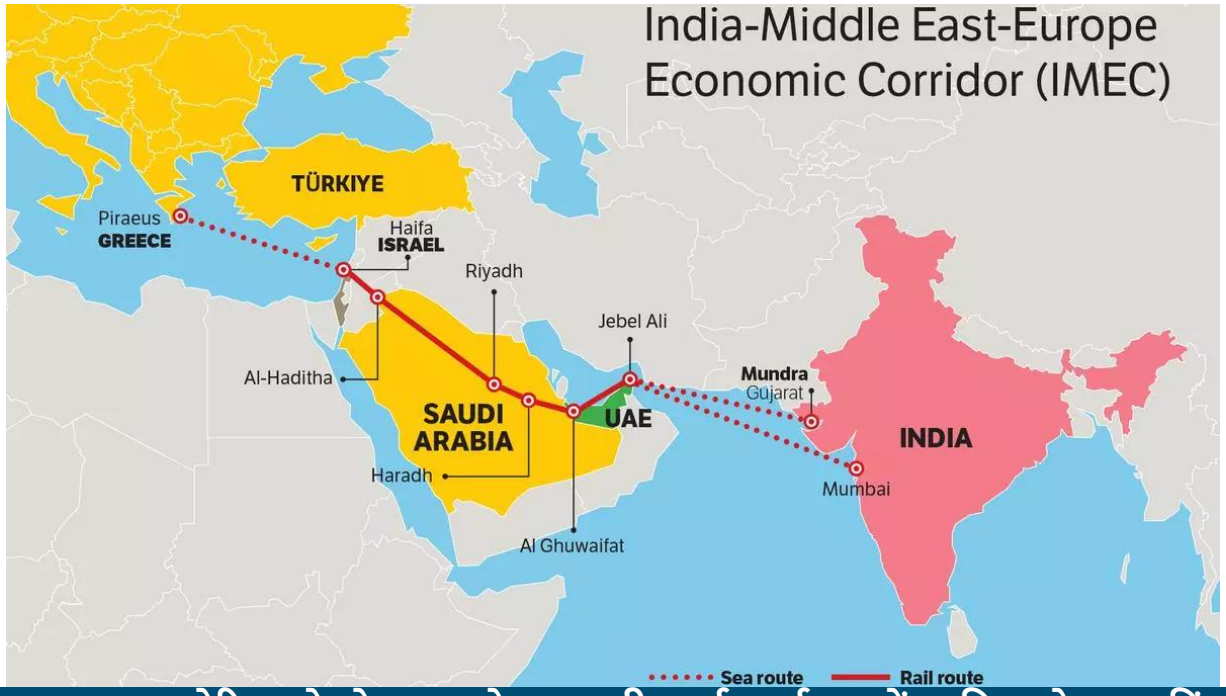

61. भारत अमेरिका के नेतृत्व वाले सहकारी कार्य कार्यक्रम में शामिल होगा -द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे
- इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF)
- मानचित्र आधारित प्रश्

प्रासंगिकता: भारत के हितों, भारतीय प्रवासियों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव।

समाचार:
- **भारत** ने **अमेरिका** के नेतृत्व वाले **इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF)** के '**स्वच्छ ऊर्जा स्तंभ**' के तहत हाल ही में अनावरण किए गए **चार सहकारी कार्य कार्यक्रमों** में से कम से कम एक में शामिल होने का फैसला किया है।
- यह **कार्बन-बाज़ार गतिविधियों** को सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने में से एक है।

मुख्य बिंदु
- **नई दिल्ली** दो अन्य **सहकारी कार्य-कार्यक्रम पहलों** पर भी विचार कर रही है, जिनमें से एक **स्वच्छ बिजली** पर है
  - दूसरा स्थायी **विमानन ईंधन** के उपयोग पर, लेकिन **गहन विश्लेषण** के बाद इसमें शामिल होने या न होने पर फैसला लिया जाएगा।
- **भारत विद्युत मंत्रालय** के माध्यम से कार्बन मार्केट पर **सहकारी कार्य समूह** में शामिल होगा और **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो नोडल** निकाय होगा
- **IPEF**, **अमेरिका** के नेतृत्व में एक पहल का **मई 2022** में अनावरण किया गया, जिसमें **14 क्षेत्रीय** साझेदार एक साथ आए
  - ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, अमेरिका और वियतनाम।
- यह **अमेरिका** के नेतृत्व वाली एक पहल है जिसका उद्देश्य भाग लेने वाले देशों के बीच **आर्थिक साझेदारी** को मजबूत करना है
  - हिंद-प्रशांत क्षेत्र में लचीलापन, स्थिरता, समावेशिता, आर्थिक विकास, निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए।

चार स्तंभ
- कई विश्लेषकों द्वारा इसे क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए अमेरिका के प्रयास के रूप में देखा गया है।
- IPEF का लक्ष्य **कनेक्टिविटी और डिजिटल व्यापार** जैसे **चार स्तंभों** के आसपास **नियमों और मानकों** का एक सामान्य सेट बनाना है
  - मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाएँ
  - स्वच्छ ताक़त

- भ्रष्टाचार मुक्त निष्पक्ष व्यापार

62. IMF ने पाकिस्तान के साथ कर्मचारी स्तर पर समझौता किया- द हिंदू

प्रासंगिकता: महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, एजेंसियां और मंच- उनकी संरचना, अधिदेश।

प्रीलिम्स टेकअवे
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
- बेलआउट

समाचार:
- **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)** ने कहा कि वह **नकदी संकट** से जूझ रहे **पाकिस्तान** में **3 अरब डॉलर** के **बेलआउट पैकेज** की अंतिम समीक्षा पर **नई सरकार** के साथ **कर्मचारी स्तर** के समझौते पर पहुंच गया है।
- यह वैश्विक ऋणदाता से **अंतिम $1.1 बिलियन किश्त** जारी करने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

IMF बेलआउट्स
- **बेलआउट** : संभावित दिवालियापन के खतरे का सामना कर रही कंपनी/देश को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बेलआउट एक सामान्य शब्द है।
- यह ऋण, नकद, बांड या स्टॉक खरीद का रूप ले सकता है।
- बेलआउट के लिए प्रतिपूर्ति की आवश्यकता नहीं हो सकती है लेकिन अक्सर अधिक निरीक्षण और नियमों के साथ होती है।
- देश आमतौर पर IMF से मदद मांगते हैं जब उनकी अर्थव्यवस्थाएं बड़े व्यापक आर्थिक जोखिम, ज्यादातर मुद्रा संकट का सामना करती हैं।
- देश अपने विदेशी ऋण और अन्य दायित्वों को पूरा करने के लिए IMF से ऐसी सहायता चाहते हैं।
  - आवश्यक आयात ख़रीदना, और अपनी मुद्राओं के विनिमय मूल्य को बढ़ाना।

IMF
- यह एक **अंतर्राष्ट्रीय संगठन** है जो **वैश्विक आर्थिक विकास** और **वित्तीय स्थिरता** को बढ़ावा देता है, **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार** को प्रोत्साहित करता है और **गरीबी को कम** करता है।
- इसकी स्थापना **वर्ष 1945** में **ब्रेटन वुड्स सम्मेलन** से की गई थी।
- मूल रूप से, IMF का प्राथमिक लक्ष्य अपने स्वयं के निर्यात को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे देशों द्वारा **प्रतिस्पर्धी मुद्रा अवमूल्यन** को रोकने के लिए **अंतरराष्ट्रीय आर्थिक समन्वय** लाना था।
- अंततः, यह उन देशों की सरकारों के लिए अंतिम उपाय का ऋणदाता बन गया, जिन्हें गंभीर मुद्रा संकट से जूझना पड़ा।
- **भारत** ने **IMF** से **सात** बार **वित्तीय सहायता** मांगी है लेकिन **वर्ष 1993** के बाद से कभी **वित्तीय सहायता** नहीं मांगी।

63. SCO स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ- द प्रिंट

प्रासंगिकता: भारत के हितों, भारतीय प्रवासियों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव।

प्रीलिम्स टेकअवे
- शंघाई सहयोग संगठन

समाचार:
- **शंघाई सहयोग संगठन (SCO)** स्टार्टअप फोरम का **चौथा संस्करण** यहां नई दिल्ली में आयोजित किया गया।
- यह पहल **SCO** सदस्य देशों के बीच **स्टार्टअप इंटरैक्शन** को व्यापक बनाने, नवाचार के लिए अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने, **रोजगार सृजन** को बढ़ावा देने और **युवा प्रतिभाओं** को **नवीन समाधान** विकसित करने के लिए प्रेरित करने पर केंद्रित है।

SCO स्टार्टअप फोरम: यूरेशिया में नवाचार के लिए एक पुल का निर्माण
- **शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम** (SCO स्टार्टअप फोरम) सभी **SCO सदस्य देशों** में **स्टार्टअप** को जोड़ने और सशक्त बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया एक मंच है।
- यह **उद्यमियों, निगमों, निवेशकों और सरकारों** के बीच सहयोग और ज्ञान साझा करने को बढ़ावा देता है।

मुख्य लक्ष्य:

- **नवाचार और सहयोग को बढ़ावा दें:** फोरम का लक्ष्य एक ऐसा स्थान बनाना है जहां स्टार्टअप एक-दूसरे की सर्वोत्तम गतिविधियों से सीख सकें और अभूतपूर्व विचारों को विकसित करने के लिए मिलकर काम कर सकें।
- **अंतर को पाटें:** निगमों और निवेशकों को स्टार्टअप के साथ लाकर, फोरम युवा कंपनियों के लिए बहुत जरूरी समर्थन और बाजार पहुंच प्रदान करता है।
- **स्केलिंग अप:** फोरम सामाजिक नवाचार समाधानों की पहचान करने और उन्हें बढ़ावा देने के साथ-साथ स्टार्टअप्स को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचने में मदद करने के लिए मेंटरशिप और कार्यक्रम भी पेश करता है।
- **सीमा पार सहयोग** : फोरम SCO सदस्य देशों में इनक्यूबेटरों और एक्सेलेरेटर के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करता है, जिससे स्टार्टअप के लिए ज्ञान के आदान-प्रदान और बाजार विस्तार की सुविधा मिलती है।

भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है:

- भारत इस **SCO स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र** को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है।
- ये जनवरी 2025 में आगामी SCO **स्टार्टअप फोरम 5.0** की मेजबानी करेंगे, साथ ही **नवंबर 2024** में **स्टार्टअप और इनोवेशन (SWG)** पर विशेष कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेंगे।
- यह नेतृत्व भूमिका पिछले मंचों की सफलता पर आधारित है, जिसमें **SCO स्टार्टअप हब** (संपर्क का एक केंद्रीय बिंदु) और **वर्ष 2023** में पहला **भौतिक मंच लॉन्च** किया गया है।
- **SCO स्टार्टअप फोरम** एक आशाजनक पहल है जिसका उद्देश्य पूरे **यूरेशिया** में **नवाचार** का एक संपन्न और परस्पर जुड़ा नेटवर्क बनाना है।

64. भारत ने पांच वर्षों में भूटान की सहायता को दोगुना करने का फैसला किया- द हिंदू

प्रासंगिकता: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते जिनमें भारत शामिल है और/या भारत के हितों को प्रभावित करते हैं।

प्रीलिम्स टेकअवे
- गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी
- पुनात्सांगछू-II जलविद्युत परियोजना

समाचार:

- **भारतीय प्रधानमंत्री** ने **थिम्पू** में कहा कि **भारत** ने अगले **पांच वर्षों** में **भूटान** की **सहायता को दोगुना** करने का फैसला किया है, जो **वर्ष 2019-2024** में **₹5,000 करोड़** से बढ़कर **वर्ष 2029** तक की अवधि के लिए **₹10,000 करोड़** हो जाएगी।

मुख्य बिंदु

- **भारतीय प्रधानमंत्री** को भूटान के सर्वोच्च सम्मान, '**ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो**' से सम्मानित किया गया, जिसकी घोषणा **वर्ष 2021** में की गई थी।
  - "**कोविड-19 महामारी** के **प्रबंधन** में **भूटान की सफलता**" सुनिश्चित करने में **भारत की भूमिका** को स्वीकार करने के लिए।
- **भूटान** के **प्रधानमंत्री** से मुलाकात के बाद, **भारत** और **भूटान** ने **ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, खेल** और **अनुसंधान** के साथ-साथ एक **अंतरिक्ष सहयोग रोडमैप** पर **सात समझौतों** पर हस्ताक्षर किए।
- दोनों जल्द ही बेहतर कनेक्टिविटी के लिए एक **नए हवाई अड्डे, कोकराझार-गेलेफू** और **बनारहाट-सामत्से** के बीच **रेल लिंक** के लिए हमारी पहल देखेंगे।
- ब्रह्मपुत्र पर जलमार्ग नेविगेशन।
- व्यापार बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए, **एकीकृत चेक पोस्ट** बनया जायेगा ।"

भारत भूटान द्विपक्षीय संबंध

- **भूटान राजा** ने **ऑपरेशन ऑल क्लियर** को याद किया जो **वर्ष 2003** में **भूटान** के **दक्षिणी क्षेत्रों** में **असम अलगाववादी विद्रोही** समूहों के खिलाफ **रॉयल भूटान सेना** द्वारा चलाया गया एक **सैन्य अभियान** था।
- **भारत और भूटान क्षेत्रीय कनेक्टिविटी** के नए मार्गों पर चर्चा करने पर सहमत हुए हैं, जिसमें **भूटान** में **गेलेफू और असम** में **कोकराझा**र के बीच **58 किमी** तक **सीमा पार रेल लिंक** का विकास शामिल है।

- इसके अतिरिक्त, **भूटान** के **समत्से** और **पश्चिम बंगाल** के **चाय बागानों** के क्षेत्र **बानरहाट** के बीच लगभग **18 किमी लंबे दूसरे रेल लिंक** की खोज करने की योजना है।
- **1020 मेगावाट पुनात्सांगछू-II जलविद्युत परियोजना** के निर्माण की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया, इसके **वर्ष 2024** में शीघ्र चालू होने की उम्मीद है।

65. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गाजा में तत्काल युद्धविराम की मांग की -इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, एजेंसियां और मंच - उनकी संरचना, अधिदेश।

प्रीलिम्स टेकअवे
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद
- संयुक्त राष्ट्र

समाचार:
- **संयुक्त राज्य अमेरिका** के मतदान से अनुपस्थित रहने के बाद **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद** ने **इजरायल** और **फिलिस्तीनी आतंकवादी** हमास के बीच तत्काल युद्धविराम और सभी बंधकों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई की मांग की है।

मुख्य बिंदु
- शेष **14 परिषद सदस्यों** ने उस प्रस्ताव के लिए मतदान किया जो निकाय के **10 निर्वाचित सदस्यों** द्वारा प्रस्तावित किया गया था।
- **वाशिंगटन** पहले **गाजा पट्टी** में लगभग **छह महीने पुराने युद्ध** में **युद्धविराम शब्द** के खिलाफ था और उसने **हमास** के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए **अमेरिकी सहयोगी इज़राइल** को बचाने के लिए अपनी **वीटो शक्ति** का इस्तेमाल किया था।
- **सुरक्षा परिषद** का प्रस्ताव "**पूरे गाजा पट्टी** में **नागरिकों की सुरक्षा** को मजबूत करने और **मानवीय सहायता** के प्रवाह को बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता पर भी जोर देता है।"
  - और बड़े पैमाने पर **मानवीय सहायता** के प्रावधान में सभी **बाधाओं** को हटाने की अपनी मांग दोहराता है।
- **रूस और चीन** ने **अक्टूबर और शुक्रवार** को संघर्ष पर **अमेरिका** द्वारा तैयार किए गए **दो प्रस्तावों** को भी वीटो कर दिया है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद:
- **सुरक्षा परिषद** की स्थापना **वर्ष 1945** में **संयुक्त राष्ट्र चार्टर** द्वारा की गई थी ।
- यह संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक है।
- **संयुक्त राष्ट्र** के अन्य **5 भाग महासभा** (UNGA) ट्रस्टीशिप काउंसिल, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय हैं।
- इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए काम करना है।
- परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है।
- परिषद में **15 सदस्य** होते हैं जिनमें से **पांच स्थायी सदस्य** और **दस अस्थायी सदस्य** दो साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं।
- **पांच स्थायी** सदस्य **संयुक्त राज्य अमेरिका, रूसी संघ, फ्रांस, चीन और यूनाइटेड किंगडम** हैं।
- **भारत** ने पिछले साल (2021) आठवीं बार **UNSC** में **अस्थायी सदस्य** के रूप में प्रवेश किया है और वह दो साल यानी 2021-22 तक परिषद में रहेगा।

66. पाकिस्तान भारत के साथ व्यापार संबंध फिर से शुरू करने के लिए तैयार -द हिन्दू

प्रासंगिकता: भारत के हितों, भारतीय प्रवासियों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव।

प्रीलिम्स टेकअवे
- मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा
- मानचित्र आधारित प्रश्न

समाचार:
- **वर्ष 2019** में **जम्मू-कश्मीर** में **संवैधानिक** बदलाव के बाद **पाकिस्तान** ने व्यापार बंद कर दिया।

- **भारत-पाक** संबंधों के अन्य पहलुओं की तरह, व्यापार भी **कश्मीर पर इस्लामाबाद** के **सख्त रुख** और **आतंकवाद** के प्रति उसके समर्थन से प्रभावित हुआ है।
- हालाँकि, **पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था** की गंभीर स्थिति ने **पाकिस्तान के दृष्टिकोण** में बदलाव की उम्मीद जगाई है।

लाभ के बावजूद पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापार सीमित किया:

- यद्यपि **वर्ष 1996** से **अनुकूल व्यापारिक शर्तें** प्रदान की गईं, **पाकिस्तान ने अधिकांश भारतीय आयातों** को प्रतिबंधित कर दिया।
- **कपास और रसायनों** के प्रमुख **पाकिस्तानी आयात** होने के कारण **भारत** को अभी भी **व्यापार लाभ** प्राप्त है।

व्यापार रुका और कारण:

- **भारत** द्वारा **कश्मीर** के लिए विशेष दर्जा रद्द करने के बाद **पाकिस्तान** ने **वर्ष 2019** में भारत के साथ **आधिकारिक व्यापार** बंद कर दिया।
- इसके बाद भारत ने **पाकिस्तानी वस्तुओं** पर टैरिफ बढ़ा दिया और अपना **मोस्ट फेवर्ड नेशन** का दर्जा वापस ले लिया।

पाकिस्तान व्यापार क्यों फिर से शुरू कर सकता है?

- नई **पाकिस्तानी सरकार और आर्थिक संकट नीति परिवर्तन** के लिए दबाव बनाते हैं।
- अधिक दूरी से आयात करने से **पाकिस्तान** की **वित्तीय स्थिति** पर दबाव पड़ता है।
- भारत के साथ सीधा व्यापार अधिक कुशल होगा।
- **पाकिस्तान** के अन्य **पड़ोसियों** के साथ रिश्ते इस समय तनावपूर्ण हैं।

व्यापार पुनः प्रारंभ करने में चुनौतियाँ:

- **पाकिस्तान** में **राजनीतिक हस्तियां व्यापार सामान्यीकरण** का विरोध कर सकती हैं।
- **पाकिस्तान** की **सेना परंपरागत** रूप से बेहतर संबंधों की **पक्षधर** है।
- पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर का दर्जा बदला जाए, जो भारत नहीं करेगा।
- **भारत** ने **पाकिस्तान से व्यापार** फिर से शुरू होने से पहले **आतंकवाद संबंधी चिंताओं** को दूर करने की मांग की है।

वर्तमान स्थिति:

- **भारत** की स्थिति **मजबूत** है और वह **कोई रियायत** नहीं देगा।
- **पाकिस्तान** को यह तय करने की ज़रूरत है कि क्या **आर्थिक लाभ राजनीतिक** कठिनाइयों से अधिकहै

67. चीन श्रीलंका में सामरिक बंदरगाह, हवाईअड्डा विकसित करेगा-द हिंदू

प्रासंगिकता: भारत के हितों, भारतीय प्रवासियों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव।

प्रीलिम्स टेकअवे

- हंबनटोटा
- मानचित्र आधारित प्रश्न

समाचार:

- **श्रीलंका** के **प्रधानमंत्री** ने कहा कि **चीन** ने **बीजिंग** में अपने समकक्ष के साथ बातचीत के बाद **द्वीप राष्ट्र** के रणनीतिक गहरे **समुद्री बंदरगाह** और **राजधानी** के **हवाई अड्डे** को विकसित करने का वादा किया है।

मुख्य बिंदु

- **श्रीलंका** ने कहा कि **द्वीप** का सबसे बड़ा **द्विपक्षीय ऋणदाता** चीन **श्रीलंका** के **विदेशी ऋण** के पुनर्गठन में "सहायता" करेगा, जो **2.9 बिलियन डॉलर के IMF बेलआउट** को बनाए रखने की एक महत्वपूर्ण शर्त है।
- ऋण पुनर्गठन पर बीजिंग का रुख सार्वजनिक नहीं किया गया है।
  - श्रीलंकाई अधिकारियों ने कहा है कि **चीन** अपने **ऋणों** पर **कटौती** करने के लिए अनिच्छुक है, लेकिन कार्यकाल बढ़ा सकता है और ब्याज दरों को समायोजित कर सकता है।
- **वर्ष 2022** में **श्रीलंका** के पास आवश्यक आयातों के **वित्तपोषण** के लिए **विदेशी मुद्रा** खत्म हो गई और उसने अपने **46 बिलियन डॉलर** के **विदेशी ऋण** पर संप्रभु डिफ़ॉल्ट की घोषणा कर दी गई है।

- **बीजिंग** ने **कोलंबो** अंतर्राष्ट्रीय **हवाई अड्डे** और **हंबनटोटा बंदरगाह** को "विकसित करने के लिए सहायता" की पेशकश की थी।

जापानी प्रोजेक्ट रुका

- **श्रीलंका** के **संप्रभु ऋण डिफ़ॉल्ट** के बाद से **कोलंबो हवाई अड्डे** का **जापानी-वित्त पोषित** विस्तार रुका हुआ था।

भारत की चिंता

- **हंबनटोटा** का **दक्षिणी समुद्री बंदरगाह** 2017 में **1.12 बिलियन डॉलर** में **99 साल** की **लीज** पर एक **चीनी राज्य** के स्वामित्व वाली कंपनी को सौंप दिया गया था।
- **भारत और अमेरिका** दोनों चिंतित हैं कि द्वीप के **दक्षिणी तट** पर **हंबनटोटा** में **चीनी** पैर जमाने से हिंद महासागर में उसकी **नौसैनिक** बढ़त बढ़ सकती है।

68. भारत ने 4 यूरोपीय देशों के साथ 100 अरब डॉलर का मुक्त व्यापार समझौता किया - द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे
- व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता
- यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन

प्रासंगिकता: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते जिनमें भारत शामिल है और/या भारत के हितों को प्रभावित करते हैं।

समाचार:

- भारत ने **चार यूरोपीय** देशों **आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विटजरलैंड** के साथ **मुक्त व्यापार समझौते (FTA)** पर हस्ताक्षर किए
- **15 वर्षों** के भीतर भारत में **100 अरब डॉलर** के निवेश और **10 लाख नौकरियों** तक पहुंचने का लक्ष्य।

मुख्य बिंदु

- **व्यापार** और **आर्थिक साझेदारी समझौता (TEPA) संयुक्त अरब अमीरात** के साथ **भारत के समझौते** के बाद हस्ताक्षरित दूसरा पूर्ण **FTA** है।
  - टैरिफ में उल्लेखनीय कटौती होगी, बाजार पहुंच बढ़ेगी और सीमा शुल्क प्रक्रियाएं सरल होंगी।
- **यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA)** देशों, जो **यूरोपीय संघ** से अलग हैं
- **FTA** में **मानवाधिकारों और सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धताओं** पर एक अध्याय भी शामिल है।
- **TEPA** के **अध्याय 7** के अनुसार जो **"निवेश संवर्धन और सहयोग"** से संबंधित है
  - **दोनों पक्षों** ने **EFTA** राज्यों से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को **10 वर्षों** के भीतर **50 अरब डॉलर** और अगले **पांच वर्षों** में **50 अरब डॉल**र तक बढ़ाने का साझा उद्देश्य रखा था।
- उन निवेशों के परिणामस्वरूप **भारत में 15 वर्षों के भीतर 1 मिलियन नौकरियों के सृजन को सुविधाजनक बनाना** भी होगा ।
- इसका लक्ष्य उन निवेशों के परिणामस्वरूप **भारत** में **15 वर्षों** के भीतर **1 मिलियन नौकरियों** के सृजन को सुविधाजनक बनाना भी होगा।
- यदि लक्ष्य **15 वर्षों** के भीतर हासिल नहीं किए जाते हैं, तो **तीन साल** की **छूट अवधि** और **बातचीत में दो** साल और लगेंगे
  - समझौते में कहा गया है कि **भारत** अपनी कुछ **व्यापार रियायतें "अस्थायी रूप से"** वापस लेने का हकदार होगा।

69. भारत ने UN शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों को रिकॉर्ड करने के लिए डेटाबेस लॉन्च किया- बिजनेस स्टैंडर्ड

प्रीलिम्स टेकअवे
- संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना
- संयुक्त राष्ट्र

प्रासंगिकता: महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, एजेंसियां और मंच - उनकी संरचना, अधिदेश।

समाचार:

- भारत ने **संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों** के खिलाफ अपराधों को रिकॉर्ड करने और अपराधियों को जवाबदेह ठहराने में प्रगति की निगरानी के लिए एक **नया डेटाबेस लॉन्च** किया है

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना

- इस वर्ष इसकी **75वीं वर्षगांठ** है और इसके लिए ए**क साल का अभियान** आयोजित किया गया है।
- **संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षा** दुनिया भर में **संघर्ष** को कम करने और **शांति और सुरक्षा** को बढ़ावा देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक रही है।
- **संयुक्त राष्ट्र** का शांति संचालन विभाग **"स्थायी शांति** के लिए स्थितियां बनाने के लिए **संघर्ष** से जूझ रहे देशों की मदद करने के तरीके के रूप में **संगठन** द्वारा विकसित एक उपकरण" के रूप में शांति स्थापना का कार्य करता है।
- हालाँकि **संयुक्त राष्ट्र** मानता है कि सभी कार्रवाइयां "**परस्पर सुदृढ़ करने वाली**" हैं और उनके बीच ओवरलैप व्यवहार में आम है, इसे **शांति निर्माण**, **शांति निर्माण और शांति प्रवर्तन** से अलग किया गया है।
- **75वीं वर्षगांठ** की थीम "शांति मुझसे शुरू होती है" अतीत और वर्तमान के शांति सैनिकों की सेवा और बलिदान को मान्यता देती है।
- यह उन समुदायों के लचीलेपन को भी श्रद्धांजलि देता है जिनकी हम सेवा करते हैं, जो शांति के लिए प्रयास करना जारी रखते हैं

ECONOMY

70. संयुक्त राष्ट्र ने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 जारी की - इकोनॉमिक टाइम्स

प्रासंगिकता: महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, एजेंसियां और मंच- उनकी संरचना, अधिदेश।

प्रीलिम्स टेकअवे
- वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट

समाचार:

- **संयुक्त राष्ट्र** की **वार्षिक वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट** के अनुसार **फिनलैंड** लगातार **सातवीं बार दुनिया** का **सबसे खुशहाल देश** बन गया है।

मुख्य बिंदु

- **वर्ल्ड हैप्पीनेस** रिपोर्ट **विभिन्न देशों** में **लोग कितने खुश** हैं इसकी **वार्षिक रैंकिंग** है।
- वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट **गैलप, ऑक्सफोर्ड वेलबीइंग रिसर्च सेंटर,** UN **सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क** और के **संपादकीय बोर्ड** की साझेदारी है।
- यह सर्वेक्षणों पर आधारित है जिसमें लोगों से पूछा जाता है कि वे कितना खुश महसूस करते हैं, साथ ही **पैसे, स्वास्थ्य** और **सामाजिक संबंधों** जैसी चीज़ों पर भी विचार किया जाता है।
- इस वर्ष, **फ़िनलैंड** लगातार **सातवें वर्ष** पहले स्थान पर आया, उसके बाद **डेनमार्क और आइसलैंड** जैसे अन्य **नॉर्डिक** देश थे।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि **दुनिया भर** में हर क्षेत्र में **महिलाएं पुरुषों** की तुलना में कम खुश हैं, उम्र बढ़ने के साथ **लैंगिक अंतर** भी बढ़ता जा रहा है।
- सूची में सबसे नीचे **अफगानिस्तान** है, और लंबे समय में पहली बार, **अमेरिका और जर्मनी शीर्ष 20** सबसे खुशहाल स्थानों में भी नहीं हैं।

भारत की रैंकिंग

- ये इस वर्ष फिर से **126वें** स्थान पर हैं, और **वृद्ध लोग, विशेष** रूप से **विवाहित शिक्षित पुरुष, युवा लोगों** या **महिलाओं** की तुलना में अधिक खुश रहते हैं।
- यदि आप अपने साथ **भेदभाव** महसूस करते हैं तो **भारत में खुशी** को प्रभावित करने वाली **सबसे बड़ी** चीजें आप कहां रहते हैं, और आपका **स्वास्थ्य** है।

71. पीएम ने कोलकाता में भारत की पहली अंडरवॉटर मेट्रो लाइन लॉन्च की- द हिंदू

प्रासंगिकता: बुनियादी ढांचा: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़कें, हवाई अड्डे, रेलवे आदि।

प्रीलिम्स टेकअवे

- अंडरग्राउंड मेट्रो
- मानचित्र आधारित प्रश्न

समाचार:

- **प्रधानमंत्री** ने **कोलकाता मेट्रो** के **एस्प्लेनेड-हावड़ा मैदान** खंड का उद्घाटन किया।
- यह देश की पहली पानी के नीचे **परिवहन सुरंग** के माध्यम से **हुगली नदी** के नीचे से गुजरती है।

मुख्य बिंदु

- उन्होंने **एस्प्लेनेड** से **हावड़ा मैदान** तक **मेट्रो ट्रेन** की सवारी भी की और **सुरंग** से गुजरते हुए यात्रा के दौरान स्कूली छात्रों के साथ बातचीत की, जो देश की **इंजीनियरिंग क्षमताओं** का एक प्रमाण है।

कोलकाता मेट्रो का इतिहास: भारत का पहला रैपिड ट्रांजिट सिस्टम

- **कोलकाता मेट्रो भारत** के **पश्चिम बंगाल** में **कोलकाता शहर** और **व्यापक कोलकाता महानगर** क्षेत्र की सेवा करने वाली एक **तीव्र पारगमन प्रणाली** है।
- यह **भारत** में पहला परिचालन **रैपिड ट्रांजिट सिस्टम** है, जो **वर्ष 1984** में शुरू हुआ, और **जनवरी 2023** तक **भारत** में **दूसरा सबसे व्यस्त** और **चौथा सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क** है।
- इसकी **चार परिचालन** लाइनें हैं, जिनकी कुल **लंबाई 59.38 किमी** और **48 स्टेशन** हैं, और **तीन अन्य लाइनें निर्माण** के विभिन्न चरणों में हैं।
- इस प्रणाली में **ब्रॉड-गेज** और **मानक-गेज** दोनों ट्रैकों का उपयोग करते हुए भूमिगत, **एटी-ग्रेड** और **ऊंचे स्टेशनों** का मिश्रण है।

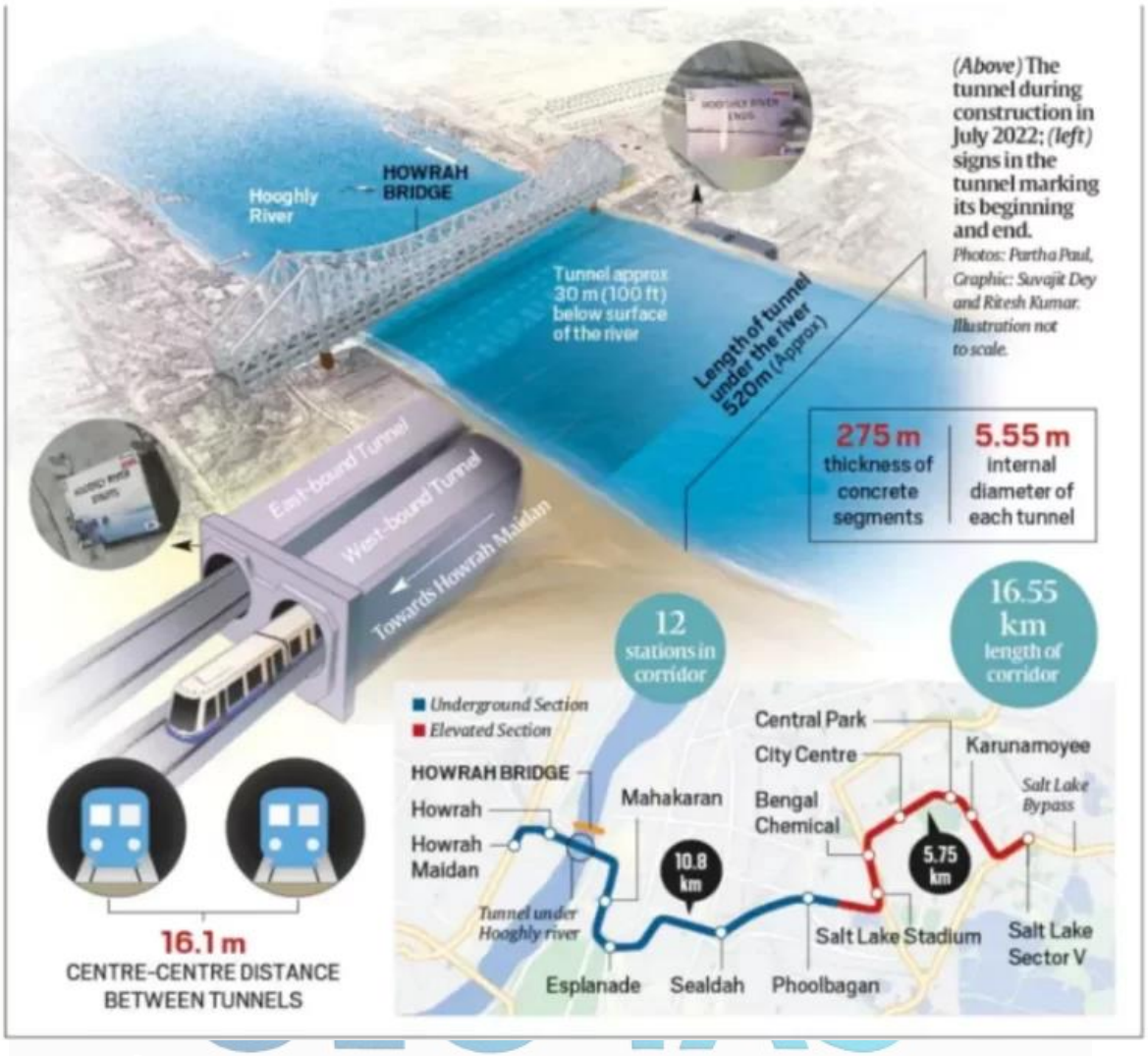

72. केंद्रीय कैबिनेट ने सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली इकाइयों को मंजूरी दी - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: विज्ञान और प्रौद्योगिकी- विकास और रोजमर्रा की जिंदगी में उनके अनुप्रयोग और प्रभाव।

प्रीलिम्स टेकअवे
- सेमीकंडक्टर
- प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव(PLI) योजना

समाचार:
- हाल ही में **केंद्रीय मंत्रिमंडल** ने लगभग **1.26 लाख करोड़ रुपये** की **तीन सेमीकंडक्टर परियोजनाओं** को मंजूरी दी।
- यह भारत की चिप निर्माण क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्य बिंदु
- **परियोजनाओं** का लक्ष्य **विभिन्न उद्योगों** में **चिप्स** की बढ़ती मांग को पूरा करना है।
- इसमें **उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रिक वाहन, रक्षा और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स** शामिल हैं।

परियोजनाएं

1. गुजरात के धोलेरा में एक सेमीकंडक्टर फैब
- इसकी स्थापना टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा ताइवान की पावरचिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्प के सहयोग से की जाएगी।
- यह **28 nm** तकनीक का उपयोग करके उच्च-प्रदर्शन वाले **कंप्यूटर चिप्स** का उत्पादन करने में माहिर होगा, जिसका उपयोग **ईवी, दूरसंचार, रक्षा** आदि में किया जाएगा।

- सालाना **300 करोड़ चिप्स** की **उत्पादन क्षमता** के साथ यह **सुविधा देश** की **सेमीकंडक्टर** जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

2. असम के मोरीगांव में एक सेमीकंडक्टर इकाई

- इसे **टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड (TSAT)** द्वारा **27,000 करोड़ रुपये** के निवेश के साथ स्थापित किया जाएगा।
- यह **ऑटोमोटिव** और **इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रों** की जरूरतों को पूरा करते हुए प्रति दिन **प्रभावशाली 48 मिलियन चिप्स** का उत्पादन करने के लिए तैयार है।

3. गुजरात के साणंद में एक सेमीकंडक्टर इकाई

- इसकी स्थापना सीजी पावर द्वारा **7,600 करोड़ रुपये** के निवेश से की जायेगी.
- यह जापान के **रेनेसा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्प और थाईलैंड के स्टार्स माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स** के साथ मिलकर है।

महत्व

- ये मंजूरी **भू-राजनीतिक तनाव** और **वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों** के बीच अपने **सेमीकंडक्टर उद्योग** को मजबूत करने के भारत के प्रयासों को रेखांकित करती है।
- इस पहल से **भारत** के **सेमीकंडक्टर बाजार** को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिसके **वर्ष 2026** तक **63 बिलियन डॉलर** तक पहुंचने का अनुमान है।
- ये विकास **भारत** को **सेमीकंडक्टर विनिर्माण** के लिए **वैश्विक केंद्र** के रूप में स्थापित करने की **भारत** की **व्यापक दृष्टि** का हिस्सा हैं।
- परियोजनाओं से लगभग **1 लाख अप्रत्यक्ष नौकरियाँ** उत्पन्न होने, **आर्थिक विकास** में योगदान देने और **वैश्विक चिप उद्योग** में लाभ उठाने की उम्मीद है।

सरकारी प्रोत्साहन

- परियोजनाओं को **सरकार** की **76,000 करोड़ रुपये** की **चिप प्रोत्साहन योजना** से लाभ होता है, जो संयंत्र की **पूंजीगत व्यय लागत** के लिए **सब्सिडी प्रदान** करती है।
- **स्मार्टफोन** और **लैपटॉप विनिर्माण** के लिए **प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव(PLI)** योजना जैसी योजनाएं भी हैं।
- इसके अतिरिक्त, **राज्य सेमीकंडक्टर निवेश** को आकर्षित करने के लिए **भूमि अधिग्रहण लाभ** जैसे प्रोत्साहन भी देते हैं।

73. RBI ने नियामक सैंडबॉक्स योजना से संबंधित मानदंडों में बदलाव किया - द इकोनॉमिक टाइम्स

प्रासंगिकता: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधन जुटाने, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे

- नियामक सैंडबॉक्स (RS) योजना
- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023
- पेमेंट्स बैंक

समाचार:

- हाल ही में, **RBI** ने **वित्तीय क्षेत्र** में **नवाचार** को बढ़ावा देने के लिए अपने **नियामक सैंडबॉक्स** ढांचे को नया रूप दिया है।

फ्रेमवर्क में मुख्य परिवर्तन

- नया ढांचा **प्रौद्योगिकी कंपनियों** को **पिछली समूह-आधारित प्रणाली** की जगह, **ऑन-टैप** प्रस्ताव प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
- **नियामक सैंडबॉक्स प्रक्रिया** के विभिन्न **चरणों** की **समयसीमा सात महीने** से बढ़ाकर **नौ महीने** कर दी गई है।
- RS में प्रवेश के लिए लक्षित आवेदक **फिनटेक कंपनियां** हैं, **जिनमें स्टार्टअप, बैंक, वित्तीय संस्थान**, कोई **अन्य कंपनी, सीमित देयता भागीदारी (LLP)** और **साझेदारी फर्म** शामिल हैं, जो **वित्तीय सेवा व्यवसायों** के साथ साझेदारी करती हैं या उन्हें सहायता प्रदान करती हैं।
- **सैंडबॉक्स संस्थाओं** को अब **डेटा सुरक्षा** और **गोपनीयता सुनिश्चित** करने के लिए **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023** के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है।

चिंताओं का समाधान

- यह कदम उन चिंताओं के बीच आया है कि **नियामक अनुपालन** पर **RBI** का सख्त रुख, जैसा कि **पेटीएम पेमेंट्स बैंक** के मामले में देखा गया, नवाचार को रोक सकता है।
- नए ढांचे का लक्ष्य नवाचार को बढ़ावा देने और **नियामक अनुपालन सुनिश्चित** करने के बीच संतुलन बनाना है।

नियामक सैंडबॉक्स (RS) योजना

- **RBI ने अगस्त 2019** में **'रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के लिए सक्षम फ्रेमवर्क'** जारी किया था।
- इस योजना में **नियंत्रित नियामक वातावरण** में **नए वित्तीय उत्पादों** या **सेवाओं** का **लाइव परीक्षण** शामिल है।
- यह व्यवसाय के लिए एक "**सुरक्षित स्थान**" के रूप में कार्य करता है क्योंकि **नियामक परीक्षण** के **सीमित उद्देश्य** के लिए कुछ छूट की अनुमति दे भी सकते हैं और नहीं भी।
- यह नियामकों, नवप्रवर्तकों, **वित्तीय सेवा प्रदाताओं** और **ग्राहकों** को नए **वित्तीय नवाचारों** का **परीक्षण करने, लाभ** और **जोखिमों** पर साक्ष्य एकत्र करने की अनुमति देता है।
- यह **नवाचार-अनुकूल नियमों** के विकास की सुविधा प्रदान करता है, जिससे कम लागत वाले **वित्तीय उत्पादों** की **डिलीवरी संभव** हो पाती है।
- यह संभावित रूप से एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो **उभरती प्रौद्योगिकियों** के **अनुकूल अधिक गतिशील, साक्ष्य-आधारित नियामक वातावरण** को सक्षम बनाता है।

74. जनवरी में पूंजीगत व्यय 40.5% कम हो गया - द हिंदू

प्रासंगिकता: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधन जुटाने, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे।

समाचार:

प्रीलिम्स टेकअवे
- राजकोषीय घाटा
- राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम

Spending squeeze

Govt. shrinks January capital expenditure by a sharp 40.5% to ₹47,600 crore containing 10-month fiscal deficit at 64% of RE

- **Overall fiscal deficit stood at ₹11 lakh crore by January**
- **Full-year capex likely to undershoot by at least ₹50,000 crore: ICRA's Nayar**
- **Less than 70% of planned expenditure met at agriculture, consumer affairs ministries: BoB's Sabnavis**

75. RBI ने बैंकों को एकाधिक कार्ड नेटवर्क विकल्प प्रदान करने का निर्देश दिया-द हिंदू

प्रासंगिकता: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधन जुटाने, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे
- भारतीय रिजर्व बैंक
- कार्ड जारीकर्ता

समाचार:
- **भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)** ने कार्ड जारीकर्ताओं को निर्देश दिया है कि ये **कार्ड नेटवर्क** के साथ ऐसी कोई व्यवस्था या समझौता न करें जो उन्हें अन्य **कार्ड नेटवर्क** की **सेवाओं** का लाभ उठाने से रोकता हो।
- **कार्ड जारीकर्ता** में **अधिकृत भुगतान प्रणाली प्रदाता**, **बैंक और गैर-बैंक** शामिल हैं

मुख्य बिंदु
- इस निर्देश के अनुसार, **कार्ड जारीकर्ताओं** को अपने **पात्र ग्राहकों** को जारी करते समय कई **कार्ड नेटवर्क** में से चुनने का विकल्प प्रदान करना होगा।
- मौजूदा **कार्डधारकों** के लिए, अगले **नवीनीकरण** के समय यह विकल्प प्रदान किया जाना आवश्यक है।
- ये निर्देश इस परिपत्र के जारी होने की **तारीख से छह महीने** तक प्रभावी रहेंगे।
- वर्तमान प्रथा के अनुसार, **अधिकृत कार्ड नेटवर्क क्रेडिट कार्ड** जारी करने के लिए **बैंकों/गैर-बैंकों** के साथ गठजोड़ करते हैं और ग्राहक को जारी किए जाने वाले कार्ड के लिए नेटवर्क का **विकल्प कार्ड जारीकर्ता (बैंक/गैर-बैंक)** द्वारा तय किया जाता है।
  - यह उन व्यवस्थाओं से जुड़ा है जो **कार्ड जारीकर्ताओं** के पास उनके द्विपक्षीय समझौतों के संदर्भ में कार्ड नेटवर्क के साथ हैं।
- **बैंकिंग नियामक** ने कार्ड जारीकर्ताओं और **कार्ड नेटवर्क** से **परिवर्तनों को समायोजित** करने के लिए नए समझौते निष्पादित करने को कहा है।

76. गिग वर्कर सामाजिक सुरक्षा, विनियमन की कमी से पीड़ित- द हिंदू

प्रासंगिकता: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधन जुटाने, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे
- गिग वर्कर

समाचार:
- **ऐप-आधारित कैब ड्राइवरों** में से लगभग **एक तिहाई प्रतिदिन 14 घंटे** से अधिक काम करते हैं
- **10,000** से अधिक **भारतीय कैब ड्राइवरों, गिग** और **प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों** के एक अध्ययन के अनुसार, **83%** से अधिक **10 घंटे** से अधिक काम करते हैं और **60%** से अधिक **12 घंटे** से अधिक काम करते हैं।

मुख्य बिंदु
- इसमें कहा गया है कि **सामाजिक असमानताएं** स्थिति को बदतर बनाती हैं, **अनुसूचित जाति और जनजाति** के **60%** से अधिक **ड्राइवर दिन में 14 घंटे** से अधिक काम करते हैं, जबकि **अनारक्षित श्रेणी** से केवल **16%** ही इतने लंबे समय तक काम करते हैं।

- अध्ययन पीपुल्स एसोसिएशन इन **ग्रासरूट्स एक्शन एंड मूवमेंट्स** और **इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप-आधारित ट्रांसपोर्ट वर्कर्स** द्वारा आयोजित किया गया था।
    - पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय और जर्मन फाउंडेशन फ्रेडरिक-एबर्ट-स्टिफ्टंग इंडिया के तकनीकी सहयोग से।
- अध्ययन के लेखकों ने **ऐप-आधारित श्रमिकों** के लिए **मजबूत सामाजिक सुरक्षा** की सिफारिश की
    - और **सरकार से ऐसे श्रमिकों** की निगरानी के लिए **प्लेटफार्मों** द्वारा उपयोग किए जाने वाले **एल्गोरिदम** और **तंत्र की निष्पक्षता** पर निगरानी रखने का आह्वान किया।
- अध्ययन रिपोर्ट में कहा गया है कि अध्ययन में भाग लेने वाले **43%** से अधिक प्रतिभागी अपनी सभी लागतों को काटने के बाद प्रतिदिन **₹500** या **प्रति माह ₹15,000** से कम कमाते हैं।
- इसमें पाया गया कि **34% ऐप-आधारित डिलीवरी व्यक्ति प्रति माह ₹10,000** से कम कमाते हैं, जबकि **78%** हर दिन काम पर **10 घंटे** से अधिक समय बिताते हैं।
- विभिन्न **जातियों के श्रमिकों** के **बीच मतभेदों** को ध्यान में रखते हुए, रिपोर्ट में कहा गया है कि **"ये आय असमानताएं** पहले से मौजूद **सामाजिक असमानताओं** को और बढ़ा देती हैं।"
    - और इन समुदायों के भीतर गरीबी और संकट के चक्र को कायम रखना"।"।
- कुल मिलाकर, **आठ** शहरों **दिल्ली**, **हैदराबाद**, **बेंगलुरु**, **मुंबई**, **लखनऊ**, **कोलकाता**, **जयपुर** और **इंदौर** में **5,302** कैब ड्राइवर और **5,028** डिलीवरी व्यक्ति हैं।
    - 50-प्रश्न वाले सर्वेक्षण में भाग लिया; 78% उत्तरदाता 21 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के थे।
- **कर्मचारियों** की **दूसरी बड़ी** शिकायत **आईडी डिएक्टिवेशन और ग्राहकों** से दुर्व्यवहार का मामला है।

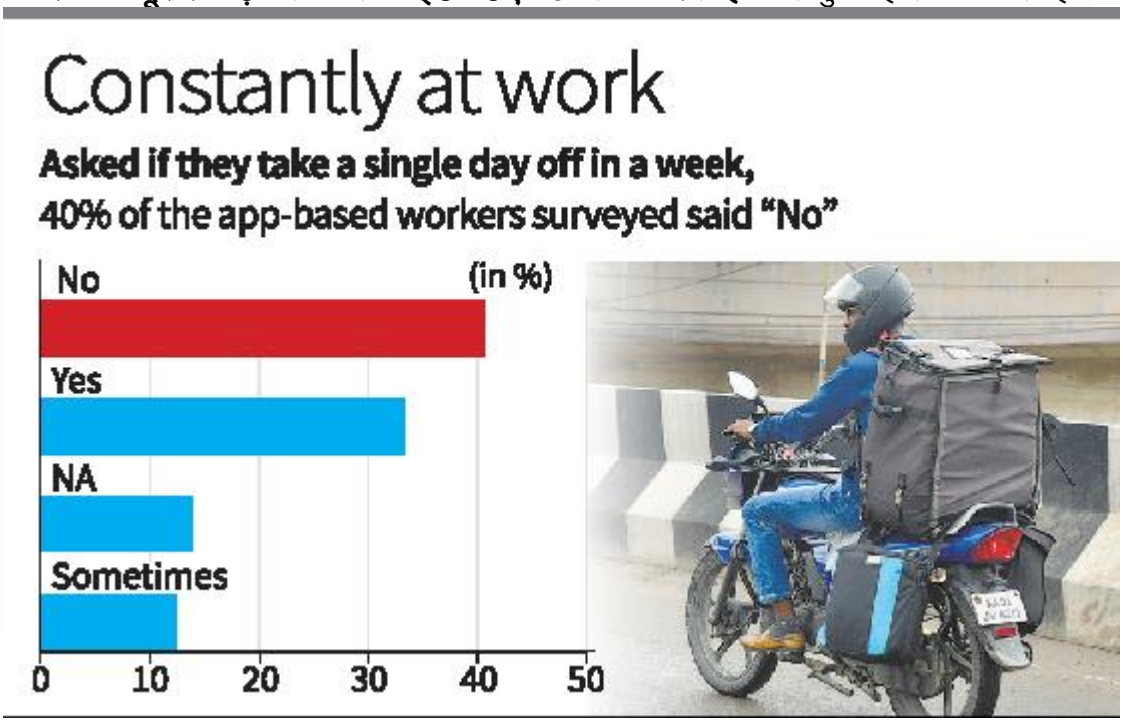

77. जनवरी 2024 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 3.8 प्रतिशत बढ़ा- द प्रिंट

प्रीलिम्स टेकअवे
- IIP
- लास्पेयर का सूत्र

प्रासंगिकता: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधन जुटाने, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे।

समाचार:

- **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय** ने **जनवरी 2024** के लिए **औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP)** का त्वरित अनुमान जारी किया है, जिसमें **3.8 प्रतिशत** की वृद्धि का खुलासा किया गया है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP):

- यह किसी चुने हुए **आधार वर्ष** के संदर्भ में एक निश्चित अवधि में **औद्योगिक उत्पादन** के व्यवहार में रुझान के मापन के लिए **आर्थिक विकास** के प्रमुख संकेतकों में से एक है।

- यह विस्तृत **औद्योगिक सर्वेक्षणों** के **वास्तविक परिणाम उपलब्ध** होने तक **औद्योगिक विकास** को मापने वाला एक **अल्पकालिक** संकेतक है।
- यह **पिछले वर्ष** की तुलना में एक निर्दिष्ट वर्ष के दौरान **उद्योगों के क्षेत्र** में **भौतिक उत्पादन** में सापेक्ष परिवर्तन को इंगित करता है।
- इसकी गणना और **प्रकाशन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (CSO), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा** मासिक आधार पर किया जाता है।
- IIP एक **क्वांटम सूचकांक** है, इसमें **वस्तुओं** का **उत्पादन भौतिक** रूप में व्यक्त किया जाता है।
- हालाँकि, मशीनरी, मशीन टूल्स, जहाज निर्माण आदि जैसी कुछ वस्तुओं के संबंध में रिपोर्टिंग की इकाई मूल्य के संदर्भ में है।
- इसे **लास्पेयर** के सूत्र का उपयोग करके उत्पादन सापेक्षों के एक **सरल भारित अंकगणितीय माध्य** के रूप में संकलित किया गया है।
- **सूचकांक** से **मूल्य वृद्धि** के प्रभाव को हटाने के लिए, ऐसी वस्तुओं के उत्पादन के **आंकड़ों को वाणिज्य** और **उद्योग मंत्रालय** के **आर्थिक सलाहकार कार्यालय** द्वारा संकलित **थोक मूल्य सूचकांक** (आधार **2011-12)** के आधार पर घटाया जाता है।
- आधार वर्ष को हमेशा 100 का मान दिया जाता है।
- **भारत में IIP श्रृंखला** के लिए वर्तमान **आधार वर्ष 2011-12** है।
- इसलिए, यदि वर्तमान **IIP 116** पढ़ता है, तो इसका मतलब है कि **आधार वर्ष** की तुलना में **16%** की वृद्धि हुई है।

78. RBI इस साल कुछ NBFC को शीर्ष स्तर पर 'अपग्रेड' कर सकता है- द हिंदू

प्रासंगिकता: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधन जुटाने, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे
- NBFC
- भारतीय रिजर्व बैंक

समाचार:
- **गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs)** के लिए एक **संशोधित नियामक फ्रेमवर्क** पेश करने के लगभग दो साल बाद -
- **भारतीय रिजर्व बैंक 2024** में **NBFC** के वर्गीकरण की समीक्षा करने के लिए तैयार है।

मुख्य बिंदु
- यह देखते हुए समीक्षा अपरिहार्य हो गई है कि NBFC ने विकास के मामले में किस तरह एक्स्प्लोडेड किया है
- **बड़े कॉर्पोरेट घरानों** और **समूह** द्वारा समर्थित कुछ **NBFC** इस समीक्षा के उद्देश्य से **फोकस** में हो सकते हैं

शीर्ष स्तर NBFC
- **"विशिष्ट मापदंडों** के आधार पर, कुछ **NBFC** को **ऊपरी स्तरों** से **शीर्ष स्तर** में ले जाया जा सकता है, और यह इस पर निर्भर करता है कि वे **शीर्ष स्तर** में कैसा प्रदर्शन करते हैं।
- वर्तमान में, **16 गैर-बैंकों** को **ऊपरी स्तर** पर रखा गया है, जिनमें **टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड** सहित **नौ NBFC** का नेतृत्व **बड़े व्यापारिक घरानों** द्वारा किया जाता है।

अपग्रेडेशन का आधार
- यह पता चला है कि केवल **NBFC** का **पैमाना** और **आकार** ही पैमाने में उन्नयन के लिए **निर्धारण कारक** नहीं हो सकता है।
- स्केल आधारित नियम **अक्टूबर 2021** में लागू हुए और एक साल बाद लागू किए गए।
- चार स्तर होते हैं अर्थात् आधार स्तर, मध्य स्तर, ऊपरी स्तर और शीर्ष स्तर।
- **30 सितंबर, 2023** तक, आधार, मध्य और ऊपरी **स्तरों** में **NBFC** क्रमशः **NBFC** की **कुल संपत्ति** का 6%, 71% और 23% थी।
- वर्तमान में, **कोई भी NBFC शीर्ष स्तर** में सूचीबद्ध नहीं है।

NBFC

- यह **कंपनी अधिनियम 1956** के तहत **पंजीकृत कंपनी** है जो **ऋण** और **अग्रिम** के कारोबार में लगी हुई है
  - सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी **शेयरों/स्टॉक/बॉन्ड/डिबेंचर/प्रतिभूतियों** या **समान प्रकृति** की **अन्य विपणन योग्य प्रतिभूतियों** का अधिग्रहण।
- ये विभिन्न **बैंकिंग सेवाएँ** प्रदान करते हैं लेकिन उनके पास **बैंकिंग लाइसेंस** नहीं है।
- ये ऋण, **क्रेडिट सुविधाएं, TFC, सेवानिवृत्ति योजना, निवेश** और **मुद्रा बाजार** में **स्टॉकिंग** जैसी **बैंकिंग** सेवाएं प्रदान करते हैं।
- आम तौर पर इन **संस्थानों को पारंपरिक मांग** जमा लेने की अनुमति नहीं है
- NBFC **चिट-रिजर्व** और **अग्रिम** जैसी **व्यापक मौद्रिक** सलाह भी प्रदान करते हैं।

79. Paytm को थर्ड पार्टी एप्लिकेशन प्रदाता बनने हेतु NPCI की मंजूरी मिली- इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधन जुटाने, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे
- NPCI
- UPI

समाचार:

- **नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI)** ने हाल ही में कहा, उसने **One97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (OCL)** को **मल्टी-बैंक मॉडल** के तहत **यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI)** में **थर्ड-पार्टी एप्लिकेशन प्रोवाइडर (TPAP)** के रूप में भाग लेने की अनुमति दी है।

मुख्य बिंदु

- **NPC**I ने कहा कि **चार बैंक** एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और यस बैंक OCL के लिए **PSP (भुगतान प्रणाली प्रदाता)** बैंकों के रूप में कार्य करेंगे, जो **Paytm** की मूल कंपनी है।
- पिछले महीने, **भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)** ने **NPCI** को, जो **UPI** प्लेटफॉर्म का मालिक है और संचालित करता है, **OCL** द्वारा **TPAP** बनने के अनुरोध पर विचार करने का निर्देश दिया था।
- **थर्ड-पार्टी एप्लिकेशन प्रदाता** एक इकाई है जो **अंतिम-उपयोगकर्ता** ग्राहकों को **UPI-आधारित भुगतान** लेनदेन की सुविधा के लिए **UPI** अनुरूप ऐप प्रदान करता है।
- ये **एप्लिकेशन मोबाइल वॉलेट**, **मर्चेंट ऐप** या कोई अन्य **प्लेटफ़ॉर्म** हो सकते हैं जो भुगतान के लिए **UPI** का उपयोग करते हैं।
- वर्तमान में, Paytm ऐप पर सभी UPI लेनदेन OCL की सहयोगी कंपनी Paytm पेमेंट्स बैंक (PPBL) के माध्यम से किए जा रहे हैं, जो अब TPAP के रूप में पंजीकृत है।

यूनिफ़ाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI)

- यह कैशलेस भुगतान को तेज, **आसान** और **सहज** बनाने के लिए **चौबीस घंटे** की फंड ट्रांसफर सेवा, तत्काल भुगतान सेवा (IMPS) का एक उन्नत संस्करण है।
- UPI एक ऐसी प्रणाली है जो कई बैंक खातों को एक ही **मोबाइल एप्लिकेशन** (किसी भी भाग लेने वाले बैंक के) में शक्ति प्रदान करती है, कई **बैंकिंग सुविधाओं, निर्बाध फंड रूटिंग** और **मर्चेंट भुगतान** को एक हुड में विलय कर देती है।
- UPI वर्तमान में **भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम** (NPCI) सहित संचालित प्रणालियों में सबसे बड़ी है
  - नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (NACH), तत्काल भुगतान सेवा (IMPS), आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS), भारत बिल भुगतान प्रणाली (BBPS), RuPay आदि।
- आज शीर्ष UPI ऐप्स में PhonePe, Paytm, Google Pay, Amazon Pay और BHIM शामिल हैं, जो बाद में सरकारी पेशकश हैं।

80. रेलवे ने मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब विकसित करने की योजना बनाई - द हिंदू

प्रासंगिकता: बुनियादी ढांचा: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़कें, हवाई अड्डे, रेलवे आदि।

प्रीलिम्स टेकअवे
- भारतीय रेलवे
- 'विकसित भारत' पहल

समाचार:
- **भारतीय रेलवे** देश भर के **10 लाख** से अधिक आबादी वाले आकांक्षी शहरों में **मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी** वाले मेगा **रेलवे टर्मिनल** बनाएगा।

मुख्य बिंदु
- यह कार्यक्रम **प्रधानमंत्री** की **'विकसित भारत' पहल** के लिए विकसित किए जा रहे बुनियादी ढांचे का हिस्सा है।

अनुभव में वृद्धि
- **रेल मंत्रालय** ने भी **मिशन मोड** पर **यात्री अनुभव** को बढ़ाने का काम किया है और चेतावनी दी है कि उसके **वरिष्ठ अधिकारियों** की ओर से किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
- देश भर में **वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों** के प्रसार के साथ, जिसे **गेम चेंजर** के रूप में पेश किया जा रहा है
- **रेलवे बोर्ड** ने **कोचों** की बेहतर **साफ-सफाई** और **रेलवे परिसर** में सुविधाओं के समुचित रखरखाव के **माध्यम से यात्रियों** के यात्रा **अनुभव** को बेहतर बनाने का काम किया है।

भारतीय रेलवे के बारे में कुछ तथ्य:
- **नेटवर्क** : भारतीय रेलवे 67,000 किमी से अधिक की दूरी तय करती है और 7,000 से अधिक स्टेशनों पर चलती है। यह देश के लगभग सभी हिस्सों को जोड़ती है और हर दिन लाखों यात्रियों और सामानों का परिवहन करती है।
- **माल ढुलाई** : भारतीय रेलवे हर दिन 3 मिलियन टन से अधिक माल ढुलाई करती है, जो कि मुंबई की पूरी आबादी को हर दिन ले जाने के बराबर है, एक वर्ष में यह 1 बिलियन टन से अधिक माल ढुलाई करती है।
- **राजस्व** : भारतीय रेलवे भारत सरकार के लिए सबसे बड़े राजस्व उत्पादकों में से एक है। वर्ष 2019-20 में इसने 1.9 ट्रिलियन रुपये (लगभग 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर) से अधिक का राजस्व अर्जित किया।
- **प्रौद्योगिकी** : भारतीय रेलवे ने हाल के वर्षों में कई तकनीकी प्रगति शुरू की है जैसे GPS-आधारित ट्रेन ट्रैकिंग, ऑनलाइन आरक्षण प्रणाली और ट्रेनों में जैव-शौचालय का उपयोग।
- **विरासत** : भारतीय रेलवे के पास एक समृद्ध विरासत है, इसकी कुछ ट्रेनें और स्टेशन एक सदी से भी अधिक पुराने हैं। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे और नीलगिरि माउंटेन रेलवे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं।

81. ट्रेडमार्क नियमों के तहत 'पासिंग ऑफ' क्या है ?- इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: विज्ञान और प्रौद्योगिकी- विकास और रोजमर्रा की जिंदगी में उनके अनुप्रयोग और प्रभाव।

प्रीलिम्स टेकअवे
- ट्रेड मार्क
- पेटेंट

समाचार:
- हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के एक फैसले ने ग्राहकों को गुमराह करने की चिंताओं के कारण एक ट्रेडमार्क पंजीकरण रद्द कर दिया।

पंजीकृत ट्रेडमार्क के बिना प्रतिष्ठा की रक्षा करना
- **"पासिंग ऑफ"** एक कानूनी अवधारणा है जो किसी व्यवसाय की स्थापित **प्रतिष्ठा (सद्भावना)** की रक्षा करती है, भले ही उसका **ट्रेडमार्क आधिकारिक** तौर पर पंजीकृत न हो।
- यह दूसरों को समान ब्रांडिंग का उपयोग करके या उनके **उत्पादों या सेवाओं** को प्रसिद्ध व्यवसाय से संबंधित बताकर गलत तरीके से पेश करके ग्राहकों को गुमराह करने से रोकता है।

पंजीकृत बनाम अपंजीकृत ट्रेडमार्क
- यदि कोई **ट्रेडमार्क पंजीकृत** है और कोई उसका **उल्लंघन** करता है, तो यह एक अलग कानूनी मुद्दा है।
- लेकिन **"पासिंग ऑफ"** तब लागू होता है जब कोई **ट्रेडमार्क पंजीकृत** नहीं होता है और कोई **ग्राहकों** को यह सोचकर धोखा (अनधिकृत गतिविधि) देता है कि उनके **सामान या सेवाएं** स्थापित व्यवसाय से जुड़ी हैं।

गलतबयानी के खिलाफ कार्रवाई करना
- कानून ऐसी भ्रामक प्रथाओं से अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने के व्यवसाय के अधिकार को मान्यता देता है।
- व्यवसाय स्वामी धोखाधड़ी को रोकने और अपने ग्राहक आधार की सुरक्षा के लिए कानूनी कार्रवाई कर सकता है।

अनधिकृत गतिविधि (धोखाधड़ी

- **"पासिंग ऑफ"** तब होता है जब कोई व्यक्ति समान ब्रांड नाम, डिज़ाइन या मार्केटिंग रणनीति का उपयोग करता है जो ग्राहकों के बीच भ्रम पैदा करता है।
- इससे उन्हें यह विश्वास हो सकता है कि वे मूल व्यवसाय से खरीदारी कर रहे हैं, जो संभावित रूप से स्थापित ब्रांड की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है।

उत्पादों और सेवाओं से परे

- "**पासिंग ऑफ**" केवल उत्पादों और सेवाओं तक ही सीमित नहीं है।
- यह कंपनी की समग्र छवि से जुड़ी सद्भावना की रक्षा करते हुए **व्यापक व्यावसायिक गतिविधियों** और पहलों पर भी लागू हो सकता है।

धोखे को साबित करने की चुनौती

- यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि "**पासिंग ऑफ**" साबित करना मुश्किल हो सकता है।
- व्यवसाय स्वामी को यह प्रदर्शित करने की आवश्यकता है कि ग्राहकों को संबंधित उत्पादों या सेवाओं की उत्पत्ति के बारे में गुमराह किए जाने की संभावना है।

82. स्टार्ट-अप इकोसिस्टम के राजस्व की मांग में वृद्धि- फाइनेंशियल एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधन जुटाने, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे

- राजस्व-आधारित वित्तपोषण
- हिस्सेदारी

समाचार:

- **राजस्व-आधारित वित्तपोषण (RBF)**, या **सकल राजस्व** के **प्रतिशत** के मुकाबले **गैर-संपार्श्विक ऋण, स्टार्टअप** और **डिजिटल SME** के बीच आकर्षण प्राप्त कर रहा है।
- उद्यम पूंजी प्रवाह शुष्क बना हुआ है और पारंपरिक ऋण कई लोगों की पहुंच से बाहर है।

आपके व्यवसाय का वित्तपोषण स्वामित्व नहीं, बल्कि बिक्री पर आधारित है

- **राजस्व-आधारित वित्तपोषण** बढ़ते व्यवसायों के लिए **पारंपरिक ऋण** और **निवेश** का विकल्प प्रदान करता है, विशेष रूप से **पूर्वानुमानित ऑनलाइन** बिक्री वाले व्यवसायों के लिए।
- **स्वामित्व (इक्विटी)** छोड़ने या ब्याज के साथ **निश्चित ऋण भुगतान** करने के बजाय, आपको अपने भविष्य के **मासिक राजस्व** के एक हिस्से के साथ-साथ **एकमुश्त शुल्क** के बदले में धन मिलता है।

यह काम किस प्रकार करता है:

- **क्लाउड किचन** या **सॉफ़्टवेयर फर्मों** जैसे स्थिर **ऑनलाइन बिक्री** वाले व्यवसायों के लिए बिल्कुल सही।
- आप अग्रिम पूंजी प्राप्त करते हैं और हर महीने अपने **सकल राजस्व** का एक प्रतिशत चुकाते हैं, आमतौर पर जब तक आप मूल निवेश राशि का **3-5 गुना** भुगतान नहीं कर देते।
- कोई निश्चित ब्याज दरें या ऋण पुनर्भुगतान नहीं हैं, इसलिए आपके भुगतान में आपकी बिक्री के साथ उतार-चढ़ाव होता है।
- ऋण के विपरीत, आपको **संपार्श्विक** (सुरक्षा के रूप में उपयोग की जाने वाली संपत्ति) की आवश्यकता नहीं होती है।
- इक्विटी निवेश के विपरीत, आप अपनी कंपनी का स्वामित्व नहीं छोड़ते हैं।
- निवेशकों को आपकी सफलता के आधार पर रिटर्न मिलता है, और आपको नियंत्रण छोड़े बिना बढ़ने के लिए आवश्यक पूंजी मिलती है।

83. WTO में, भारत सीमा पार प्रेषण की लागत कम करने का प्रयास कर रहा है - द हिंदू

प्रासंगिकता: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधन जुटाने, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे

- विश्व व्यापार संगठन
- MC 13

समाचार:

- **भारत सीमा** पार **प्रेषण** की लागत को कम करने के अपने प्रस्ताव पर दृढ़ता से काम कर रहा है, जो उसने पिछले महीने **अबू धाबी** में **WTO** के 1**3वें मंत्रिस्तरीय** सम्मेलन में किया था, जो काफी हद तक अनिर्णीत रहा।
- इसने अब **बहुपक्षीय निकाय** की **सामान्य परिषद (GC)** से इसके लिए सिफारिशें करने के लिए एक **कार्य कार्यक्रम शुरू** करने के लिए कहा है

मुख्य बिंदु

- भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम '**प्रेषण की लागत**' विषय पर एक सत्र के लिए एक प्रस्तुति पर काम कर रहा है।
  - जिनेवा में **वित्तीय सेवाओं** में व्यापार पर **WTO** की समिति, देश में एक मजबूत भौतिक और साथ ही **इलेक्ट्रॉनिक भुगतान** और **निपटान प्रणाली स्थापित** करने के अपने अनुभव से सीख रही है।
- अनुमान के अनुसार, **प्रेषण** की लागत कम करने से **अधिकतर निम्न और मध्यम** आय वाले देशों को लाभ होगा, जिनका **वर्ष 2023** में प्रेषण प्रवाह में **78% योगदान** था।
- **भारत** ने पिछले महीने **अबू धाबी** में **MC13** में अपने **मसौदा प्रस्ताव** में बताया कि प्रेषण भेजने की **वैश्विक औसत** लागत **SDG** लक्ष्य के **दोगुने** से भी अधिक **6.18%** अधिक है।

अंतर्संबंध को बढ़ावा देना

- **डिजिटल प्रेषण** की **वैश्विक** औसत लागत **4.84%** है जो **गैर-डिजिटल प्रेषण** की लागत से काफी कम है।

प्रेषण

- **प्रेषण धन हस्तांतरण** है जो **प्रवासी** अपने **गृह देशों** में अपने **परिवारों और दोस्तों** को भेजते हैं।
- भारत **वर्ष 2022** में 1**00 बिलियन अमेरिकी डॉलर** प्राप्त करने वाला **दुनिया का सबसे बड़ा प्रेषण** प्राप्तकर्ता है।
- **सेवा निर्यात** के बाद **प्रेषण बाह्य वित्तपोषण** का **दूसरा सबसे** बड़ा स्रोत है

भारत के लिए प्रेषण के शीर्ष स्रोत

- **भारत का** लगभग **36% प्रेषण तीन उच्च** आय वाले गंतव्यों में **उच्च-कुशल** और **बड़े पैमाने** पर **उच्च तकनीक** वाले **भारतीय प्रवासियों** से है।
  - अमेरिका **, यूनाइटेड किंगडम और सिंगापुर।**
- महामारी के बाद सुधार के कारण इन क्षेत्रों में श्रम बाजार व्यस्त हो गया और वेतन वृद्धि से प्रेषण को बढ़ावा मिला।

84. समावेशी विकास के साथ असमानता में कमी- द हिंदू

प्रासंगिकता: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधन जुटाने, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे

- घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण

समाचार:

- **वित्त मंत्रालय** ने **वर्ष 2022-23** के **घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण** के "**आश्वस्त करने वाले निष्कर्षों**" का हवाला देते हुए कहा कि **भारत ने पिछले दशक** में **"समावेशी विकास"** का अनुभव किया है।

मुख्य बिंदु

- **मंत्रालय** ने कहा, "**MPCE** [मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय] में **ग्रामीण-शहरी विभाजन** में काफी गिरावट आई है।"
- **"ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों** में, MPCE आबादी के सबसे निचले **5%** की खपत शीर्ष **5%** की तुलना में तेज़ दर से बढ़ी,
  - जो पिछले दशक में असमानता में गिरावट की ओर इशारा करती है।
- प्रति व्यक्ति **सकल राष्ट्रीय आय** के साथ **MPCE** संख्याओं को जोड़ने से **आर्थिक विकास** में एक समावेशी प्रवृत्ति का पता चलता है।
- "**ग्रामीण भारत** में शीर्ष **5%** और **शहरी भारत** में शीर्ष **10%** को छोड़कर सभी **उपभोग वर्गों** के लिए **MPCE/PCI** अनुपात में वृद्धि हुई है।

घरेलू खपत व्यय सर्वेक्षण (HCES)

- यह प्रत्येक **5 वर्ष** में **राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO)** द्वारा आयोजित किया जाता है।
- इसे परिवारों द्वारा **वस्तुओं और सेवाओं** की खपत के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- HCES में एकत्र किए गए डेटा का उपयोग **सकल घरेलू उत्पाद (GDP)**, **गरीबी दर और उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति (CPI)** जैसे विभिन्न अन्य व्यापक आर्थिक संकेतक प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है।
- **नीति आयोग** ने कहा है कि **नवीनतम उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण** से संकेत मिलता है कि देश में **गरीबीघटकर 5%** हो गई है।
- अंतिम **HCES** के निष्कर्ष सरकार द्वारा "**डेटा गुणवत्ता**" मुद्दों का हवाला देने के बाद जारी नहीं किए गए थे।

- उत्पन्न सूचना वस्तुओं (खाद्य और गैर-खाद्य वस्तुओं सहित) और सेवाओं दोनों पर सामान्य खर्च की जानकारी प्रदान करती है।
- इसके अतिरिक्त, **घरेलू मासिक प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय (MPCE)** के अनुमानों की गणना करने और विभिन्न **MPCE** श्रेणियों में घरों और व्यक्तियों के वितरण का विश्लेषण करने में सहायता करता है।

हालिया सर्वेक्षण की मुख्य विशेषताएं

- औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय का अनुमान तैयार किया गया
  - प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसे विभिन्न सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से
  - परिवारों द्वारा मुफ्त प्राप्त वस्तुओं के मूल्य आंकड़ों को लागू किए बिना।

85. NAAC की मान्यता प्रणाली में बदलाव की आवश्यकता- इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे
- राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (NAAC)
- UGC

समाचार:

- **राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (NAAC)** ने अपनी **कार्यकारी परिषद** की बैठक में **उच्च शिक्षण** संस्थानों के लिए **"मान्यता प्राप्त"** या **"मान्यता प्राप्त नहीं"** का एक **द्विआधारी वर्गीकरण** शुरू करने का निर्णय लिया।

NAAC: भारतीय उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करना

- **वर्ष 1994** में स्थापित**, NAAC शिक्षा मंत्रालय** के तहत एक **स्वतंत्र निकाय** है जो **भारत में कॉलेजों** और **विश्वविद्यालयों** के लिए **गुणवत्ता** जांच के रूप में कार्य करता है।
- रेस्तरां के लिए एक समीक्षक की तरह, **NAAC** पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों, अनुसंधान आउटपुट और छात्र सहायता सहित **सात प्रमुख क्षेत्रों** के **आधार** पर इन **संस्थानों** का **मूल्यांकन** करता है।
- जो संस्थान **NAAC** के मानकों को पूरा करते हैं, उन्हें मान्यता प्राप्त होती है, जो **पांच साल** के लिए वैध होती है, जो **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा** के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
- रेटिंग **A++ (उच्चतम)** से **C** तक होती है, जिसमें **D** यह दर्शाता है कि संस्थान मान्यता प्राप्त नहीं है।
- ऐसे **विश्वविद्यालय** और **कॉलेज** जो कम से कम **छह वर्षों** से कार्यरत हैं या जिन्होंने **छात्रों** के **दो बैचों** में स्नातक किया है, **NAAC** की मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो वर्तमान में स्वैच्छिक है।
- **NAAC** एक **सामान्य परिषद** और एक कार्यकारी समिति के तहत काम करता है, दोनों में **भारत की उच्च** शिक्षा प्रणाली के विशेषज्ञ शामिल हैं।
- यह संस्थानों का मूल्यांकन करते समय निष्पक्ष और सूचित निर्णय सुनिश्चित करता है।

86. ILO और IHD ने भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 जारी की - द हिंदू

प्रासंगिकता: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधन जुटाने, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे
- LFPR
- बेरोजगारी की दर

समाचार:

- हाल ही में, **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)** और **मानव विकास संस्थान (IHD)** द्वारा **भारत रोजगार रिपोर्ट 2024** जारी की गई।
- भारत में **बेरोजगार युवाओं** में **माध्यमिक** या **उच्च शिक्षा प्राप्त** लोगों की हिस्सेदारी **वर्ष 2000** में **35.2%** से लगभग दोगुनी होकर वर्ष 2022 में **65.7%** हो गई है।

मुख्य बिंदु

- रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के बेरोजगार कार्यबल में लगभग 83% युवा हैं।
- मुख्य आर्थिक सलाहकार **वी. अनंत नागेश्वरन** द्वारा जारी अध्ययन में कहा गया है कि **वर्ष 2000** और **वर्ष 2019** के बीच **युवाओं** के रोजगार और **अल्परोजगार** में वृद्धि हुई, लेकिन महामारी के वर्षों के दौरान इसमें गिरावट आई है।
- अध्ययन में कहा गया है की **श्रम बल भागीदारी दर (LFPR)**, श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR) और **बेरोजगारी दर (UR)** में **वर्ष 2000** और **वर्ष 2018** के बीच **दीर्घकालिक गिरावट** देखी गई है ।

- लेकिन 2019 के बाद सुधार देखा गया।

विरोधाभास

- **वर्ष 2018** से पहले की विभिन्न अवधियों में **गैर-कृषि रोजगार कृषि रोजगार** की तुलना में अधिक दर से बढ़ा है
- कृषि से श्रम मुख्य रूप से **निर्माण और सेवा क्षेत्रों** द्वारा अवशोषित किया गया था।
- इसके अलावा, लगभग **90% श्रमिक अनौपचारिक** काम में लगे हुए हैं, जबकि नियमित काम की हिस्सेदारी, जो **वर्ष 2000** के बाद लगातार बढ़ी, **वर्ष 2018** के बाद घट गई।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि बड़े पैमाने पर आजीविका संबंधी असुरक्षाएं हैं और **गैर-कृषि संगठित क्षेत्र** में केवल एक **छोटा प्रतिशत** ही **सामाजिक सुरक्षा उपायों** के तहत कवर किया गया है।
- जबकि **भारत का बड़ा युवा कार्यबल** एक **जनसांख्यिकीय** लाभांश है, रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि उनके पास परिणाम देने का कौशल नहीं है।
  - 75% युवा अटैचमेंट्स के साथ ईमेल भेजने में असमर्थ हैं, 60% फ़ाइलें कॉपी और पेस्ट करने में असमर्थ हैं, और 90% गणितीय सूत्र को स्प्रेडशीट में डालने में असमर्थ हैं।
- **महिला श्रम बल भागीदारी** की कम दर के साथ, देश श्रम बाजार में पर्याप्त **लैंगिक अंतर** की चुनौती का भी सामना कर रहा है।

सामाजिक असमानताएँ

- **सकारात्मक कार्रवाई** और **लक्षित नीतियों** के बावजूद, **अनुसूचित जाति** और **अनुसूचित जनजाति** बेहतर **नौकरियों** तक पहुंच के मामले में अभी भी पीछे हैं।
- **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति** की **आर्थिक** आवश्यकता के कारण काम में अधिक भागीदारी है, लेकिन वे कम वेतन वाले **अस्थायी आकस्मिक वेतन** वाले **काम** और **अनौपचारिक रोजगार** में अधिक लगे हुए हैं।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि सभी समूहों के बीच शैक्षिक उपलब्धि में सुधार के बावजूद, सामाजिक समूहों के भीतर पदानुक्रम कायम है।

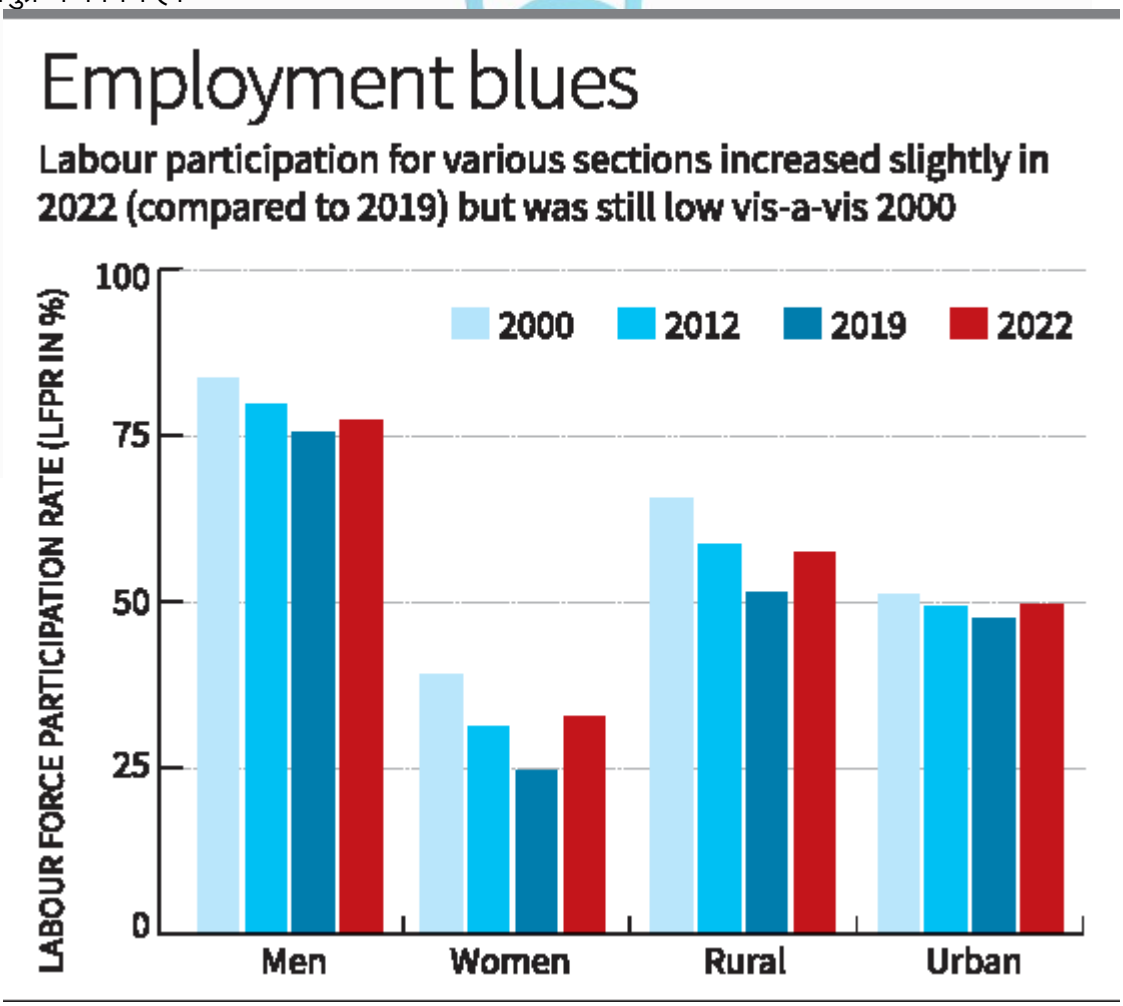

87. भारत के शुद्ध विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) प्रवाह में गिरावट'-द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
- FPI

प्रासंगिकता: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधन जुटाने, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे।

समाचार:
- भारत के **शुद्ध विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI)** प्रवाह में गिरावट , जो **वर्ष 2023-24** के पहले **10 महीनों** में लगभग **31%** गिरकर **25.5 बिलियन डॉलर** हो गया था।
- **वित्त मंत्रालय** ने इस कैलेंडर वर्ष में निवेश में बढ़ोतरी की उम्मीद जताते हुए कहा है कि यह **विकासशील देशों** में ऐसे निवेश में मंदी के अनुरूप है।

मुख्य बिंदु
- जबकि व**र्ष 2023** में समग्र वैश्विक **FDI प्रवाह 3%** बढ़कर अनुमानित **$1.4 ट्रिलियन** हो गया, आर्थिक **अनिश्चितता** और **उच्च ब्याज दरों** ने **वैश्विक निवेश** को प्रभावित किया
- **मंत्रालय** ने फरवरी में **अर्थव्यवस्था** के प्रदर्शन की समीक्षा में कहा कि इसका असर **विकासशील देशों** में **FDI प्रवाह** में **9%** की गिरावट के रूप में सामने आया है।
- **विकासशील** देशों में **FDI प्रवाह** में मंदी को प्रतिबिंबित करते हुए **भारत** में **सकल FDI** प्रवाह में भी गिरावट आई, लेकिन **अप्रैल 2023-जनवरी 2024** की अवधि में **$61.7 बिलियन** से थोड़ा ही कम हुआ।
- अंकटाड रिपोर्ट का हवाला देते हुए, **मंत्रालय** ने कहा कि **FDI प्रवाह** में गिरावट के बावजूद, देश में "**नई परियोजना घोषणाओं** की स्थिर **संख्या**" देखी गई।
    - इसे **वैश्विक ग्रीनफील्ड परियोजनाओं** के लिए **शीर्ष 5 गंतव्यों** में बनाए रखना।
- मंत्रालय ने कहा कि **नीदरलैंड, सिंगापुर, जापान, अमेरिका और मॉरीशस** का **भारत** में कुल **FDI इक्विटी प्रवाह** में लगभग **70%** योगदान है।

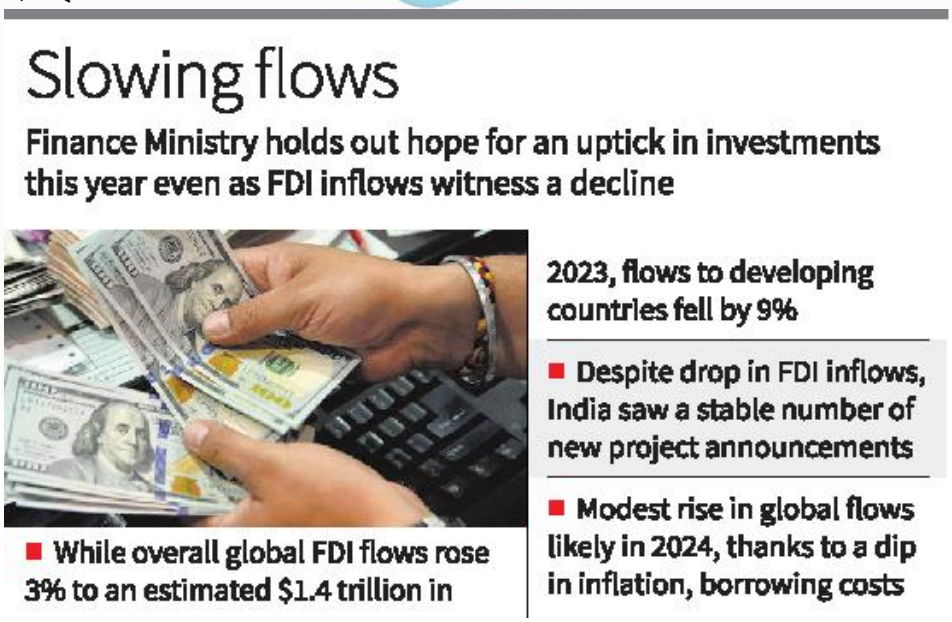

88. RBI ने AIF में निवेश करने वाले ऋणदाताओं हेतु मानदंडों में संशोधन किया - द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे
- सेबी
- वैकल्पिक निवेश कोष

प्रासंगिकता: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधन जुटाने, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे।

समाचार:
- **भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)** ने **वैकल्पिक निवेश निधि (AIF)** में अपने निवेश के संबंध में **विनियमित संस्थाओं (RE)** के लिए मानदंडों को संशोधित किया है।

मुख्य बिंदु

- नए निर्देश के अनुसार, **RE** को केवल उस सीमा तक प्रावधानों को अलग रखने की आवश्यकता है, जिस हद तक **AIF** योजना में उनका निवेश **AIF** द्वारा देनदार की कंपनी में निवेश किया जाता है, न कि **AIF योजना** में संपूर्ण निवेश।
- **प्रावधानीकरण** की आवश्यकता केवल **RE** द्वारा **AIF** योजना में निवेश की सीमा तक होगी जिसे **AIF** द्वारा देनदार कंपनी में निवेश किया जाता है।
  - और **AIF** योजना में **RE** के संपूर्ण निवेश पर नहीं,'' यह जोड़ा गया।
- **RBI** ने दिसंबर में **RE** को **AIF** में निवेश करने से रोक दिया था, जिसमें **RE** के किसी देनदार की कंपनी में **प्रत्यक्ष** या **अप्रत्यक्ष** रूप से **डाउनस्ट्रीम** निवेश था।
  - यह ऋणों की सदाबहार वृद्धि को रोकने के लिए था

वैकल्पिक निवेश कोष (AIF):

- यह एक **विशेष निवेश** श्रेणी है जो पारंपरिक निवेश साधनों से भिन्न है।
- **AIF भारत** में स्थापित कोई भी फंड है जो एक निजी तौर पर **एकत्रित निवेश** माध्यम है जो निवेश के लिए **भारतीय या विदेशी** दोनों **परिष्कृत निवेशकों** से धन एकत्र करता है।
- यह **निवेशकों** से धन एकत्र करता है और उन्हें निवेशकों के लाभ के लिए **सेबी** द्वारा निर्दिष्ट निवेश की **विभिन्न श्रेणियों** के तहत निवेश करता है।
- ये निवेश वाहन **सेबी (वैकल्पिक निवेश निधि) विनियम, 2012** का पालन करते हैं।
- AIF को एक कंपनी, सीमित देयता भागीदारी (LLP), ट्रस्ट आदि के रूप में बनाया जा सकता है।
- यह **भारत** में **घरेलू** और **विदेशी निवेशकों** सहित **उच्च रोलर्स** के लिए एक निवेश विकल्प है।
- आम तौर पर, **संस्थान** और **उच्च निवल मूल्य** वाले व्यक्ति **AIF** में निवेश करते हैं क्योंकि इसमें **उच्च निवेश** राशि की आवश्यकता होती है।

89. GeM पोर्टल: FY24 में खरीद 4 ट्रिलियन रुपये के पार - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधन जुटाने, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे
- GeM
- PSU

समाचार:

- **केंद्र** के **सरकारी ई-मार्केट (GeM)** पोर्टल के माध्यम से **वस्तुओं और सेवाओं** की खरीद इस **वित्तीय वर्ष** में अब तक **4 ट्रिलियन रुपये** को पार कर गई है।
- एक **वरिष्ठ सरकारी अधिकारी** ने कहा कि **विभिन्न मंत्रालयों** और विभागों द्वारा खरीदारी गतिविधियों में तेजी आई है
- **वर्ष 2016** में लॉन्च किया गया, **GeM (गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस) सरकारी एजेंसियों** के लिए सामान और सेवाएँ खरीदने और बेचने का एक **ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म** है।
- **केंद्र और राज्य सरका**र के **विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों** और **संबद्ध संगठनों** के लिए खरीद के लिए **GeM** का उपयोग करना अनिवार्य है।

GeM के लाभ:

- **बढ़ी हुई दक्षता, पारदर्शिता और गति** : GeM बोली और सीधी खरीद जैसे विभिन्न खरीद विकल्पों की पेशकश करके सार्वजनिक खरीद को सुव्यवस्थित करता है।
- **व्यापक चयन और मूल्य तुलना:** खरीदारों के पास कई आपूर्तिकर्ताओं से उत्पादों की एक बड़ी विविधता तक पहुंच होती है, जिससे मूल्य तुलना और लागत-प्रभावशीलता की अनुमति मिलती है।
- **विक्रेताओं के लिए लाभ** : व्यवसायों को बोली और निगरानी के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल मंच के साथ, राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद बाजार और सरकारी संगठनों तक आसान पहुंच मिलती है।

अनौपचारिक क्षेत्र के विक्रेताओं के लिए चुनौतियाँ:

- **पंजीकरण बाधाएँ** : वर्तमान पंजीकरण प्रक्रिया लंबी हो सकती है और इसके लिए GSTIN या पैन कार्ड जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, जिनकी अनौपचारिक क्षेत्र के व्यवसायों में अक्सर कमी होती है।
- **अवास्तविक मूल्य निर्धारण** : सरकारी विभागों द्वारा निर्धारित कम अनिवार्य कीमतें और अनिवार्य न्यूनतम छूट छोटे व्यवसायों के लिए ऑर्डर पूरा करना अलाभकारी बना सकती है।

- **दूरी कारक** : बोलियाँ अक्सर दूर के स्थानों के लिए होती हैं, जिसमें लॉजिस्टिक लागत जोड़ी जाती है और लाभ मार्जिन कम किया जाता है।

प्रस्तावित समाधान:

- **सरलीकृत पंजीकरण:** MSME मंत्रालय के उद्यम पोर्टल के समान पंजीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने से अनौपचारिक व्यवसायों के लिए GeM में शामिल होना आसान हो जाएगा।
- **गतिशील मूल्य निर्धारण:** बाजार दरों और पिछले आदेशों के आधार पर एक अधिक लचीली मूल्य निर्धारण प्रणाली विक्रेताओं के लिए उचित मुआवजा सुनिश्चित कर सकती है।
- **स्थानीय मिलान:** स्थानीय विक्रेताओं के साथ सरकारी आदेशों का मिलान करने से शिपिंग लागत कम हो जाएगी और "वोकल फॉर लोकल" अभियान के साथ जुड़कर स्थानीय व्यवसायों को समर्थन मिलेगा।

आगे की राह

- कुल मिलाकर, **GeM** एक अधिक **कुशल और पारदर्शी सार्वजनिक खरीद प्रणाली** की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।
- **अनौपचारिक क्षेत्र** के विक्रेताओं के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करके, **GeM छोटे व्यवसायों** को और **सशक्त** बना सकता है और अधिक समावेशी बाज़ार बना सकता है।

90. पूरे भारत के 60 से अधिक उत्पादों को भौगोलिक संकेत (GI) टैग मिला - द हिंदू

प्रासंगिकता: आईटी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-प्रौद्योगिकी, जैव-प्रौद्योगिकी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित मुद्दों के क्षेत्र में जागरूकता।

प्रीलिम्स टेकअवे
- भौगोलिक संकेत
- ट्रिप्स (TRIPS)

समाचार:

- **बनारस ठंडाई** सहित पूरे **भारत** के **60** से **अधिक उत्पादों** को **भौगोलिक संकेत (GI) टैग** दिया गया है।
- यह पहली बार है कि एक साथ इतनी **बड़ी संख्या** में उत्पादों को **GI टैग** दिया गया है

मुख्य बिंदु

- **असम** के छह पारंपरिक शिल्प अशरीकंडी टेराकोटा शिल्प, पानी मेटेका शिल्प, सार्थेबारी धातु शिल्प, जापी (बांस की टोपी), मिशिंग हथकरघा उत्पाद और बिहू ढोल ने **GI टैग** हासिल किया है।
- **असम** के **13** अन्य **उत्पादों** को यह **टैग** दिया गया है, जिसमें **बोडो महिलाओं की पारंपरिक पोशाक बोडो दोखोना** भी शामिल है।
- **बोडो एरी रेशम,** जिसे **शांति या अहिंसा** के कपड़े के रूप में जाना जाता है, जो **रेशमकीट सामिया रिसिनी** से आता है जो ज्यादातर **अरंडी के पौधे** (रिकिनस कम्युनिस) और **कसावा की पत्तियों** पर फ़ीड करता है।
- बोडो ज्वमगरा (एक पारंपरिक दुपट्टा), बोडो गमसा (बोडो पुरुषों की पारंपरिक पोशाक), बोडो थोरखा (एक संगीत वाद्ययंत्र), और बोडो सिफंग (एक लंबी बांसुरी) भी सूची में हैं।
- प्रसिद्ध **बनारस ठंडाई, दूध** को **मेवे, बीज** और **मसालों** के मिश्रण से बनाया गया पेय, को भी **टैग** मिला।
- **बनारस तबला, बनारस शहनाई, बनारस लाल भरवामिर्च,** और **बनारस लाल पेड़ा** उन उत्पादों में से हैं जो इस क्षेत्र में **GI टैग** के साथ चले गए।
- **त्रिपुरा क्षेत्र** को **दो टैग** मिले, एक **पचरा-रिगनाई** के लिए, जो विशेष अवसरों पर पहनी जाने वाली एक **पारंपरिक पोशाक** है, और **दूसरा माताबारी पेड़ा** के लिए, जो एक मीठी तैयारी है।
- **मेघालय गारो कपड़ा** बुनाई, जो **सामाजिक-सांस्कृतिक** और **धार्मिक अनुष्ठानों** से जुड़ी है, **मेघालय लिरनाई पॉटरी और मेघालय चुबिची** ने भी टैग हासिल किया।

भौगोलिक संकेत (GI) टैग टैग

- **GI टैग** एक ऐसा नाम या चिह्न है जिसका उपयोग कुछ उत्पादों पर किया जाता है जो किसी **विशिष्ट भौगोलिक स्थान** या **मूल** से मेल खाते हैं।
- **GI टैग** यह सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत **उपयोगकर्ताओं** या **भौगोलिक क्षेत्र** में रहने वाले लोगों को ही **लोकप्रिय उत्पाद नाम** का उपयोग करने की अनुमति है।
- यह उत्पाद को दूसरों द्वारा कॉपी या नकल किये जाने से भी बचाता है।
- एक पंजीकृत **GI 10 वर्षों** के लिए वैध है।
- **GI पंजीकरण** की देखरेख **वाणिज्य** और **उद्योग मंत्रालय** के तहत उद्योग और **आंतरिक व्यापार संवर्धन** विभाग द्वारा की जाती है।

ENVIRONMENT

91. कॉल फॉर जस्टिस अध्ययन:5 राज्यों में FRA का कार्यान्वयन मिश्रित है -द हिंदू

प्रासंगिकता: केंद्र और राज्यों द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का प्रदर्शन; इन कमजोर वर्गों की सुरक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थाएं और निकाय।

प्रीलिम्स टेकअवे
- सामुदायिक वन अधिकार
- वन अधिकार अधिनियम

समाचार:
- **दिल्ली** स्थित संगठन **कॉल फॉर जस्टिस** द्वारा गठित एक तथ्य-खोज समिति ने देश भर के **पांच राज्यों** में **2006** के **वन अधिकार अधिनियम (FRA)** के **"मिश्रित"** कार्यान्वयन को पाया है।

मुख्य बिंदु
- **न्यायमूर्ति एसएन ढींगरा** (सेवानिवृत्त) की अगुवाई वाली **आठ सदस्यीय समिति** ने **आठ महीने** तक असम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों का अध्ययन किया हैं ।
- **FRA** अपने वर्तमान स्वरूप में **स्थानांतरण** या **झूम खेती** के संबंध में **पूर्वोत्तर राज्यों** में मौजूद अनोखी स्थिति का समाधान नहीं करता है।
- **पहाड़ी ढलानों** पर **पौधों** को काटने और जलाने वाली खेती के इस रूप को **वन-निवास समुदायों** की **पारिस्थितिक और सांस्कृतिक** आवश्यकताओं के अनुकूल एक अभ्यास के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए।
- **महाराष्ट्र** के **गढ़चिरौली** में **FRA** कार्यान्वयन संतोषजनक पाया गया जबकि **नासिक** में प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी।
- **टीम** ने **ओडिशा** के **कंधमाल** और **सुंदरगढ़ जिलों** में **FRA** के कार्यान्वयन में **"पर्याप्त प्रगति"** पाई।
- हालाँकि, यह देखा गया कि जिलों में प्रस्तुत और मान्यता प्राप्त **व्यक्तिगत वन अधिकार (IFR)** और **सामुदायिक वन अधिकार (CFR)** दावों के बीच महत्वपूर्ण अंतर मौजूद था।

वन अधिकार अधिनियम, 2006
- यह **अधिनियम वनों** में रहने वाली **अनुसूचित जनजातियों (FDST)** और अन्य **पारंपरिक वनवासियों (OTFD)** को **वन अधिकारों** और **वन भूमि** पर कब्जे को मान्यता देता है और उन्हें अधिकार देता है, जो पीढ़ियों से ऐसे जंगलों में रह रहे हैं।
- वन अधिकारों का दावा किसी भी **सदस्य** या **समुदाय** द्वारा किया जा सकता है, जो **13 दिसंबर, 2005** से पहले कम से **कम तीन पीढ़ियों** (75 वर्ष) का है।
  - मुख्य रूप से वास्तविक आजीविका आवश्यकताओं के लिए वन भूमि में निवास करते हैं।
- यह **FDST** और **OTFD** की **आजीविका** और **खाद्य सुरक्षा** सुनिश्चित करते हुए **वनों** की **संरक्षण व्यवस्था** को मजबूत करता है।
- ग्राम सभा प्रकृति निर्धारण की प्रक्रिया शुरू करने का प्राधिकारी है
- और **व्यक्तिगत वन अधिकार (IFR)** या **सामुदायिक वन अधिकार (CFR)** या **दोनों** की **सीमा** जो **FDST** और **OTFD** को दी जा सकती है।

92. पर्यावरण मंत्रालय ने तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की - द हिंदू/ मध्यप्रदेश तेंदुओं की संख्या में शीर्ष स्थान पर - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट

प्रीलिम्स टेकअवे
- भारतीय तेंदुआ
- भारत में तेंदुओं की स्थिति
- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA)

समाचार:
- हाल ही में **पर्यावरण मंत्रालय** ने **भारत** में **तेंदुओं की स्थिति** पर एक रिपोर्ट जारी की है ।
- सर्वेक्षण में **20 राज्यों** को शामिल किया गया, जिसमें **बाघ अभयारण्यों** और **संरक्षित वन क्षेत्रों** सहित **तेंदुए के लगभग 70%** अपेक्षित आवास पर ध्यान केंद्रित किया गया।

मुख्य निष्कर्ष
- **भारत** में **तेंदुए** की आबादी वर्ष **2018** में **12,852** से बढ़कर **वर्ष 2022** में **13,874** हो गई, जो **8%** की वृद्धि है।

- यह अनुमान हिमालय और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों को छोड़कर, **70% तेंदुए** के आवास को कवर करता है।
- **मध्य प्रदेश** में **तेंदुओं** की **सबसे अधिक संख्या (3,907)** दर्ज की गई, इसके बाद **महाराष्ट्र, कर्नाटक** और **तमिलनाडु** का स्थान है।
- जबकि **मध्य भारत** में स्थिर या थोड़ी बढ़ती जनसंख्या देखी गई, **शिवालिक पहाड़ियों** और **गंगा** के **मैदानी** इलाकों जैसे क्षेत्रों में गिरावट का अनुभव हुआ।
  - अवैध शिकार और **मानव-पशु संघर्ष** के कारण **उत्तराखंड** में **तेंदुओं** की **संख्या** में **22%** की गिरावट देखी गई।
  - **तेंदुए** की लगभग **65%** आबादी **शिवालिक परिदृश्य** में संरक्षित क्षेत्रों के बाहर मौजूद है।
- **अरुणाचल प्रदेश**, **असम** और **पश्चिम बंगाल** में **सामूहिक** रूप से **तेंदुओं** की संख्या में **150%** की वृद्धि देखी गई, जो **349 जानवरों** तक पहुंच गई।
  - **पूर्वोत्तर राज्यों में तेंदुओं** की संख्या में तेज वृद्धि का श्रेय **नमूना कलाकृतियों** को दिया गया।
- **टाइगर रिजर्व** या सबसे अधिक **तेंदुए** की आबादी वाले स्थान **नागार्जुनसागर श्रीशैलम (AP)** हैं, इसके बाद **पन्ना (MP), और सतपुड़ा (AP**) हैं।

भारतीय तेंदुआ (पेंथेरा पार्डस फुस्का)

- **भारतीय तेंदुआ, बड़ी बिल्लियों** में सबसे छोटा, **भारतीय उपमहाद्वीप** में व्यापक रूप से वितरित **तेंदुए** की एक **उप-प्रजाति** है।
- ये विभिन्न प्रकार के **आवासों** में **अनुकूलन** करने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं।
- ये **मजबूत** और **फुर्तीले शिकारी** हैं जो पेड़ों पर चढ़ सकते हैं और **सुरक्षा** के लिए अपने **शिकार** को ऊपर खींच सकते हैं।
- **संरक्षण की स्थिति**
  - IUCN लाल सूची: असुरक्षित
  - उद्धरण: परिशिष्ट I।
  - वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची I।

93. कैबिनेट ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA) की स्थापना को मंजूरी दी- पीआईबी/भारत बड़ी बिल्लियों की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय गठबंधन स्थापित करेगा - द हिंदू

प्रासंगिकता: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट

प्रीलिम्स टेकअवे
- इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA)
- प्रोजेक्ट टाइगर
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)

समाचार:

- हाल ही में, **केंद्रीय मंत्रिमंडल** ने **भारत में मुख्यालय** के साथ **इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA)** की स्थापना को मंजूरी दी।

इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA)

- **IBCA** की अवधारणा **भारत के प्रधान मंत्री द्वारा** 2019 में **ग्लोबल टाइगर डे** के दौरान पेश की गई थी।
- **उद्देश्य:** सात प्रमुख बड़ी बिल्लियों अर्थात बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता की सुरक्षा और संरक्षण की दिशा में प्रयासों को आगे बढ़ाना।
  - इनमें से पाँच बड़ी बिल्लियाँ अर्थात बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता भारत में पाए जाते हैं।
- इसका लक्ष्य **96 बड़े कैट रेंज देशों,** गैर-रेंज देशों**, संरक्षण भागीदारों, वैज्ञानिक संगठनों** और **कॉर्पोरेट** संस्थाओं को एकजुट करना है
- **अनुदान**
  - भारत सरकार ने **वर्ष 2023-24** से **वर्ष 2027-28** की अवधि के लिए **150 करोड़ रुपये** की एकमुश्त बजटीय सहायता आवंटित की है।
  - गठबंधन अपने कोष को बढ़ाने के लिए **द्विपक्षीय** और **बहुपक्षीय एजेंसियों, वित्तीय संस्थानों** और **दाता एजेंसियों** के योगदान का भी पता लगाएगा।
- **गतिविधियाँ:** ज्ञान साझा करना, क्षमता निर्माण, नेटवर्किंग, वकालत, वित्तीय सहायता, अनुसंधान, तकनीकी सहायता, शिक्षा और जागरूकता।

- गठबंधन **SDG** के साथ **जैव विविधता नीतियों** को एकीकृत करने और **सभी क्षेत्रों** में **जैव विविधता** को **मुख्यधारा** में लाने पर जोर देता है।

शासन और वित्त पोषण

- IBCA की शासन संरचना में **सदस्यों की एक महासभा** , **निर्वाचित सदस्य देशों** की एक **परिषद** और एक **सचिवालय शामिल** है।
- परिषद की सिफारिश पर **महासभा IBCA** के **महासचिव** की नियुक्ति करती है ।
- समझौते की रूपरेखा **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)** के अनुरूप तैयार की गई है और इसे **अंतर्राष्ट्रीय संचालन समिति (ISC)** द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा।

94. पहले सर्वेक्षण के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की संख्या 718: पर्यावरण मंत्रालय - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन।

प्रीलिम्स टेकअवे
- पूर्वी घाट
- पश्चिमी घाट

समाचार:

- **भारत सरकार** की एक **नई रिपोर्ट** से पता चलता है कि **वर्ष 2018** के बाद से **राष्ट्रीय तेंदुए** की आबादी में **8% की वृद्धि** हुई है, **भारत में** अनुमानित **13,874 तेंदुए** हैं।
- हालाँकि, **20 राज्यों** में **तेंदुओं** के **70% आवास** को कवर करने वाले **सर्वेक्षण** में **क्षेत्रीय विविधताओं** की भी पहचान की गई।

मुख्य बिंदु:

- **समग्र वृद्धि** : **राष्ट्रीय तेंदुए** की आबादी **वर्ष 2018** में **12,852** से बढ़कर **वर्ष 2022** में **13,874** हो गई।

क्षेत्रीय विषमताएं:

- **मध्य भारत और पूर्वी घाट** : स्थिर या थोड़ी बढ़ती जनसंख्या (प्रति वर्ष 1.5% की सबसे बड़ी वृद्धि दर)।
- **शिवालिक पहाड़ियाँ और गंगा के मैदान:** प्रति वर्ष 3.4% की चिंताजनक गिरावट।

पर्यावास वितरण:

- 65% तेंदुए संरक्षित क्षेत्रों के बाहर, खासकर शिवालिक परिदृश्य (हिमालय की तलहटी) में रहते हैं।
- मध्य प्रदेश में तेंदुओं की सबसे अधिक संख्या (3,907) है, इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु हैं।
- ओडिशा, उत्तराखंड, केरल और तेलंगाना सहित कई राज्यों ने जनसंख्या में गिरावट की सूचना दी है।

सकारात्मक पहलुओं:

- **बाघ संरक्षण से तेंदुओं को लाभ:** रिपोर्ट बताती है कि शिकार की उपलब्धता और सुरक्षा उपायों में वृद्धि के कारण बाघ अभयारण्यों में तेंदुओं की आबादी बढ़ती है।

खतरे:

- **अवैध शिकार** : तेंदुओं को सीधे निशाना बनाना या उनके शिकार का अवैध शिकार करना (बुशमीट व्यापार)।
- **पर्यावास की क्षति:** खनन और विकास जैसी गतिविधियाँ तेंदुओं के आवासों को खतरे में डालती हैं।
- **सड़क दुर्घटनाएँ:** यह तेंदुओं की मृत्यु का एक महत्वपूर्ण कारण है ।
- रिपोर्ट **क्षेत्रीय गिरावट** को दूर करने और **भारत में तेंदुओं** के सामने आने वाले **विभिन्न खतरों** को कम करने के लिए **निरंतर संरक्षण प्रयासों** की आवश्यकता पर जोर देती है।

95. UNEA-6: भौतिक संसाधनों का वैश्विक उत्पादन और खपत में 50 वर्षों में तीन गुना बढ़ी - डाउन टू अर्थ

प्रासंगिकता: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन।

प्रीलिम्स टेकअवे
- UNEP
- अंतर्राष्ट्रीय संसाधन पैनल

समाचार:

- **UNEP** की रिपोर्ट के अनुसार पिछले **50 वर्षों** में भौतिक संसाधनों का **वैश्विक उत्पादन** और **खपत तीन गुना** से अधिक बढ़ गई है
- यह **प्रति वर्ष औसतन 2.3 प्रतिशत** से अधिक की **दर** से बढ़ रहा है, बावजूद इसके कि यह **वृद्धि तीन ग्रहों** के संकट का मुख्य कारण है।

वैश्विक संसाधन उपयोग बढ़ रहा है, असमान रूप से वितरित: UNEP रिपोर्ट

असमान उपभोग:

- **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP)** और अं**तर्राष्ट्रीय संसाधन पैनल (IRP)** की एक नई रिपोर्ट में संसाधन खपत में वैश्विक असमानता की एक स्पष्ट तस्वीर सामने आई है।

उच्च आय वाले देश:

- अधिकांश **संसाधन मांग** को प्रेरित करें, जो **55%** से अधिक **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन** और **40% पार्टिकुलेट मैटर प्रदूषण** के लिए जिम्मेदार है।
- पिछले **50 वर्षों** में उपभोग दोगुना से भी अधिक हो गया है।

निम्न आय वाले देश:

- अमीर देशों की तुलना में छह गुना कम संसाधनों का उपभोग करें।
- 10 गुना कम जलवायु प्रभाव उत्पन्न करें।

संसाधन उपयोग रुझान:

- वर्ष 1970 के बाद से वैश्विक संसाधन उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है (2020 में 30 बिलियन टन से 106 बिलियन टन)।
- **वर्ष 2060** तक **60%** की संभावित वृद्धि के साथ यह प्रवृत्ति जारी रहने की उम्मीद है।

पर्यावरणीय प्रभावों:

- वर्तमान **संसाधन उपयोग पैटर्न** अस्थिर हैं और **तीन ग्रहों के संकट** (जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और प्रदूषण) में योगदान करते हैं।

कार्यवाई के लिए बुलावा:

- रिपोर्ट में संसाधन दक्षता और समर्थन नीतियों पर बल दिया गया है ।
- सामग्री का प्रयोग कम करें।
- पर्यावरणीय प्रभाव को कम करें ।
- विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण में खुशहाली और आर्थिक विकास में सुधार लाना।
- सतत भविष्य के लिए आर्थिक विकास को संसाधनों के उपयोग से अलग करना आवश्यक है।
- उपभोग पैटर्न को बदलना महत्वपूर्ण है, धनी देशों को खपत में भारी कमी करने की आवश्यकता है और विकासशील देशों को बुनियादी जरूरतों के लिए संसाधनों तक पहुंच बढ़ाने की आवश्यकता है।

समाधान:

- चक्रीय अर्थव्यवस्था सिद्धांतों को लागू करना (मना करना, कम करना, पुनः डिज़ाइन करना, पुन: उपयोग करना, मरम्मत करना, पुनर्चक्रण करना)।
- सहायक विनियम और मौजूदा प्रणालियों का मूल्यांकन।
- पर्यावरणीय समझौतों में संसाधनों को शामिल करना।
- सतत संसाधन उपयोग मार्गों को परिभाषित करना।
- वित्तीय, व्यापार और आर्थिक प्रोत्साहन लागू करना।

रिपोर्ट का दायरा:

- विभिन्न आय समूहों और क्षेत्रों में संसाधन उपयोग के रुझान, प्रभाव और वितरण का विश्लेषण करता है।
- सतत संसाधन उपयोग और असमानताओं को कम करने के लिए समाधान प्रदान करता है।

96. UN ने खेतों और ग्रामीण इलाकों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की चेतावनी दी -द हिंदू

प्रासंगिकता: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन।

प्रीलिम्स टेकअवे

- FAO
- संयुक्त राष्ट्र

समाचार:

- संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि गरीब देशों में खेत और ग्रामीण घर चलाने वाली महिलाएं जलवायु परिवर्तन से अधिक पीड़ित होती हैं और उनके साथ भेदभाव किया जाता है क्योंकि वे संकट के समय आय के अन्य स्रोतों को अपनाने की कोशिश करती हैं।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- खाद्य और कृषि संगठन, द अनजस्ट क्लाइमेट की एक नई रिपोर्ट में यह पाया गया
  - पुरुष प्रधान परिवारों की तुलना में महिला प्रधान ग्रामीण परिवारों को गर्मी के दौरान औसतन 8 प्रतिशत और बाढ़ के दौरान 3 प्रतिशत अधिक आय का नुकसान होता है।
- यह **असमानता गर्मी** के तनाव के कारण प्रति व्यक्ति **83 अमेरिकी डॉलर** की कमी में बदल जाती है
  - **संयुक्त राष्ट्र एजेंसी** ने रिपोर्ट में कहा कि **गरीब देशों** में बाढ़ के कारण सालाना **35 अमेरिकी डॉलर** और क्रमशः **37 बिलियन अमेरिकी डॉलर** और **16 बिलियन अमेरिकी डॉलर** का नुकसान होता है।
- महिलाओं और पुरुषों के बीच कृषि उत्पादकता और मजदूरी में महत्वपूर्ण मौजूदा अंतर को ध्यान में रखते हुए, अध्ययन से पता चलता है
  - **FAO** ने कहा कि अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले वर्षों में **जलवायु परिवर्तन** इन अंतरों को काफी बढ़ा देगा।
- गौरतलब है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि **जलवायु परिवर्तन** से निपटने और **अनुकूलन रणनीतियों** को बढ़ावा देने के लिए कुछ **सरकारी योजनाएं ग्रामीण महिलाओं** और **युवाओं की विशिष्ट कमजोरियों** को ध्यान में रखती हैं।
- सर्वेक्षण में शामिल देशों की **राष्ट्रीय जलवायु अनुकूलन योजनाओं** में शामिल **4,000** से अधिक प्रस्तावों में से केवल **6 प्रतिशत** ने महिलाओं का उल्लेख किया।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि कई गरीब देशों में महिलाओं के साथ जमीन पर अधिकार पाने या अपने काम पर निर्णय लेने की क्षमता में भेदभाव किया जाता है।
- जब वे **कृषि** और **पशुधन उत्पादकता** को कम करने वाले **जलवायु संकट के परिणामस्वरूप** अपनी आय के स्रोतों में विविधता लाने की कोशिश करते हैं
  - उन्हें सूचना, **वित्तपोषण** और **प्रौद्योगिकी** तक पहुंच प्राप्त करने में भी **भेदभाव** का सामना करना पड़ता है।
- रिपोर्ट में **महिलाओं** की अध्यक्षता वाले **ग्रामीण परिवारों** की **विशेष कमजोरियों** को दूर करने के लिए लक्षित रणनीतियों का आह्वान किया गया।
- **'स्थान, धन, लैंगिक और उम्र** के आधार पर **सामाजिक मतभेद** एक शक्तिशाली हैं
  - जलवायु संकट के प्रभावों के प्रति ग्रामीण लोगों की संवेदनशीलता पर प्रभाव को अभी तक कम समझा गया है

97. जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता: कार्बन कैप्चर क्या है? - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन।

प्रीलिम्स टेकअवे
- CO_2
- कार्बन कैप्चर और स्टोरेज

समाचार:
- पिछले हफ्ते, **जर्मनी** ने घोषणा की कि वह **वर्ष 2045** तक **कार्बन तटस्थ** बनने के अपने लक्ष्य को पूरा करने में मदद करने के लिए **सीमेंट उत्पादन** जैसे कुछ **औद्योगिक क्षेत्रों** के लिए **कार्बन कैप्चर** और **ऑफ-शोर भंडारण** की अनुमति देगा।
- देश **वर्तमान** में **यूरोप** में सबसे बड़ा **कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2)** उत्सर्जक है।

कार्बन कैप्चर और स्टोरेज (CCS)
- **CCS** एक ऐसी तकनीक है जो **औद्योगिक सुविधाओं** और **बिजली संयंत्रों** से **ग्रीनहाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2)** को एकत्र करती है और फिर इसे गहरे भूमिगत में संग्रहीत करती है।
- यह हवा से **CO_2** को हटाने से अलग है, क्योंकि **CCS** विशेष रूप से स्रोत पर उत्सर्जन को लक्षित करता है।

इस प्रक्रिया में निम्नलिखित तीन चरण शामिल हैं:
- **कैप्चर** : CO_2 को रासायनिक सॉल्वेंट्स (दहन के बाद), गैसीकरण (पूर्व-दहन), या शुद्ध ऑक्सीजन जलने (ऑक्सीफ्यूल दहन) जैसे विभिन्न तरीकों का उपयोग करके निकास गैसों से अलग किया जाता है।
- **परिवहन** : कैप्चर की गई CO_2 को एक तरल में संपीड़ित किया जाता है और पाइपलाइनों या अन्य माध्यमों से भंडारण स्थलों तक पहुंचाया जाता है।

- **भंडारण** : CO_2 को भूवैज्ञानिक संरचनाओं जैसे खारे जलभृतों या घटते तेल और गैस भंडारों में गहरे भूमिगत में सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जाता है।
- जबकि **CCS ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन** को कम करने का एक तरीका प्रदान करता है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विभिन्न **कैप्चर विधियों** में **अलग-अलग दक्षता स्तर और ऊर्जा** आवश्यकताएं होती हैं।

98. MNRE हाइड्रोजन भंडारण के लिए विशेष सिलेंडरों पर चर्चा करेगा- इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन ।

प्रीलिम्स टेकअवे
- ग्रीन हाइड्रोजन
- राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन

समाचार:
- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) **ग्रीन हाइड्रोजन भंडारण** के लिए विशेष सिलेंडर के विकास पर चर्चा करने के लिए संबंधित हितधारकों के साथ एक बैठक बुलाने की योजना बना रहा है।

राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन
- **ग्रीन हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव** के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए **वैश्विक केंद्र** बनाना ।
- यह **स्वच्छ ऊर्जा** के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने के **भारत के लक्ष्य** में योगदान देगा और **वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा** परिवर्तन के लिए प्रेरणा के रूप में काम करेगा।
- **मिशन से अर्थव्यवस्था** में उल्लेखनीय रूप से **डीकार्बोनाइजेशन** होगा, **जीवाश्म ईंधन** के आयात पर निर्भरता कम होगी और **भारत ग्रीन हाइड्रोजन** में **प्रौद्योगिकी** और **बाजार** का नेतृत्व संभालने में सक्षम होगा।''
- **निर्यात** : मिशन सहायक नीतियों और रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से निर्यात के अवसरों को सुविधाजनक बनाएगा।
- **घरेलू मांग** : भारत सरकार ऊर्जा या फीडस्टॉक के रूप में नामित उपभोक्ताओं द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन या इसके व्युत्पन्न उत्पादों जैसे ग्रीन अमोनिया, ग्रीन मेथनॉल आदि की खपत का न्यूनतम हिस्सा निर्दिष्ट करेगी।
- खपत के ऐसे न्यूनतम हिस्से का वर्षवार प्रक्षेपवक्र अधिकार प्राप्त समूह (EG) द्वारा तय किया जाएगा।
- **प्रतिस्पर्धी बोली:** प्रतिस्पर्धी बोली मार्ग के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया की मांग एकत्रीकरण और खरीद की जाएगी।
- **प्रमाणन ढांचा:** MNRE संसाधनों से उत्पादित ग्रीन हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव के प्रमाणीकरण के लिए एक उपयुक्त नियामक ढांचा भी विकसित करेगा।

99. SC ने पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य को गैर-अधिसूचित करने के असम सरकार के निर्णय रोका - द हिंदू

प्रासंगिकता: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन।

प्रीलिम्स टेकअवे
- काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य
- पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य

समाचार:
- **सुप्रीम कोर्ट** ने **पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य** का गठन करने वाली लगभग **26 साल पुरानी अधिसूचना** को वापस लेने के अ**सम सरकार** के कदम पर रोक लगा दी, जो देश में **गैंडों की सबसे बड़ी** आबादी में से एक है।

मुख्य बिन्दु
- **सरकार** ने तर्क दिया कि **अभयारण्य की घोषणा थेंगाभंगा, मुरकटा** और **मायोंग** सहित क्षेत्र के गांवों में रहने वाले लोगों के अधिकारों का निपटान किए बिना की गई थी।
- ये ग्रामीण हाशिए पर रहने वाले समुदायों से थे और आजादी से पहले भी इस क्षेत्र में रहते थे।

पैनल की स्थापना
- **सरकार** ने **वन्यजीव अभ्यारण्य** घोषित करने वाली **1998 की अधिसूचना** वापस ले ली है ।
- इसने क्षेत्र में वनवासियों के अधिकारों को देखने के लिए एक समिति भी गठित की थी
  - साथ ही इस बार पोबितोरा क्षेत्र को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का सुविचारित निर्णय लिया।

पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य

- **पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य** में दुनिया में **एक सींग** वाले **गैंडों का घनत्व** सबसे अधिक है और **काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान** के बाद असम में दूसरा सबसे अधिक घनत्व है।
- समान परिदृश्य और वनस्पति के कारण इसे अक्सर '**मिनी काजीरंगा**' कहा जाता है।
- **वन्यजीव अभयारण्य लुप्तप्राय** एक **सींग वाले गैंडे** और अन्य **स्तनधारियों** जैसे **तेंदुआ, तेंदुआ बिल्ली, मछली** पकड़ने वाली **बिल्ली, जंगली बिल्ली, जंगली भैंस, जंगली सूअर, चीनी पैंगोलिन** आदि का घर है।
- पोबितोरा अभयारण्य का लगभग **72%** भाग **अरुंडो डोनैक्स** और **सैकरम** के आद्र (नम) सवाना से बना है।
  - शेष क्षेत्र जल निकायों से आच्छादित है।
- **जलकुंभी** (एक आक्रामक जलीय पौधा) इस क्षेत्र के लिए विशेष रूप से **जलपक्षियों** के लिए एक **बड़ी** समस्या है, क्योंकि यह पानी की **सतह पर मोटी परतें** बनाती है।

100. सौर ऊर्जा की शॉक्ले-क्विसर दक्षता सीमा - द हिंदू

प्रासंगिकता: विज्ञान और प्रौद्योगिकी- विकास और रोजमर्रा की जिंदगी में उनके अनुप्रयोग और प्रभाव।

प्रीलिम्स टेकअवे
- फोटॉनों
- सेमीकंडक्टर

समाचार:
- **फोटोवोल्टिक्स** में यानी **प्रकाश ऊर्जा** को **विद्युत ऊर्जा** में परिवर्तित करने के अध्ययन में **शॉक्ले क्विसर सीमा** एक **सैद्धांतिक अवधारणा** है जो बिजली पैदा करने के लिए **सौर सेल** की **अधिकतम क्षमता** को परिभाषित करती है।

प्रमुख बिंदु
- सौर सेल जैसे **फोटोवोल्टिक** उपकरण हमें **सौर ऊर्जा** का उपयोग करने की अनुमति देते हैं।
- **फोटोवोल्टिक सेल (doped)** सिलिकॉन जैसे **अर्धचालक पदार्थों** से बने होते हैं।
- जब **सूर्य** का **प्रकाश अर्धचालक** के साथ संपर्क करता है, तो यह **निम्न-ऊर्जा वैलेंस बैंड** से **उच्च-ऊर्जा चालन बैंड** तक **इलेक्ट्रॉनों** को उत्तेजित करता है।
- यह ट्रांसिशन वैलेंस बैंड में एक रिक्त स्थान छोड़ जाता है जिसे होल कहा जाता है।
  - अधिक सटीक होने के लिए, एक छेद एक खाली जगह है जहां एक इलेक्ट्रॉन माना जाता है।
  - चूँकि यह एक इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति को दर्शाता है, एक होल भी धनात्मक आवेश वाला एक स्थान है।
- इलेक्ट्रॉन जो कन्डक्शन बैंड में चला जाता है और वैलेंस बैंड में एक छोड़ता है, उस प्रक्रिया से एक इलेक्ट्रॉन-होल युग्म बनती है।
- ये जोड़े अर्धचालकों में मौलिक आवेश वाहक हैं और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- संक्षेप में, इलेक्ट्रॉन-होल जोड़े फोटोकरंट बनाते हैं
  - अर्धचालक में विकिरण के परिणामस्वरूप निर्मित विद्युत प्रवाह।
- हम जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश पड़ने पर सौर सेल जिस दक्षता से विद्युत धारा उत्पन्न कर सकता है वह 100% नहीं हो सकती।
  - क्योंकि कुछ प्रकाश कण (फोटॉन) सामग्री के साथ संपर्क किए बिना ही उसमें से गुजर जाते हैं (अर्थात् पारदर्शिता की हानि, लगभग 25%)
  - कुछ ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित किए बिना सामग्री को गर्म कर देती है (थर्मलाइजेशन, लगभग 30%)।
- परिणामस्वरूप, **पारंपरिक सौर सेल** की **अधिकतम दक्षता सीमित** हो जाती है, और इस सीमा को **शॉक्ले-क्वेसर सीमा** कहा जाता है।
- आजकल, एक **सौर सेल** आपतित **सौर ऊर्जा** का केवल **एक तिहाई भाग** ही **विद्युत ऊर्जा** में परिवर्तित कर सकता है।
- **सेमीकंडक्टर बैंड गैप** में कूदने के लिए **इलेक्ट्रॉनों** द्वारा **आवश्यक ऊर्जा** से कम **ऊर्जा** वाले **फोटॉन** का उपयोग नहीं कर सकता है।
- इसी तरह, **बैंड गैप** के आकार से काफी अधिक ऊर्जा ले जाने वाले **फोटॉन** केवल डिवाइस को गर्म करते हैं।

- शोधकर्ता **शॉक्ले-क्वेसर सीमा** को पार करने और अधिक **सौर ऊर्जा** का उपयोग करने के तरीके खोजने की कोशिश कर रहे हैं
- इस प्रकार कोशिकाओं की कार्यक्षमता में सुधार होता है, लेकिन यह कहना जितना आसान है, करना उतना आसान नहीं है।

101. UNEP रिपोर्ट: प्लास्टिक रसायन अनुमान से अधिक- द हिंदू

प्रासंगिकता: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन।

प्रीलिम्स टेकअवे
- UNEP
- वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण संधि

समाचार:
- **खाद्य पैकेजिंग** से लेकर **खिलौनों** से लेकर **चिकित्सा उपकरणों** तक **प्लास्टिक** में **पर्यावरण एजेंसियों** के पहले के अनुमान से कम से कम **3,000** अधिक रसायन मौजूद हैं।
- हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट में **प्रदूषण और उपभोक्ता सुरक्षा** पर सवाल उठाए गए हैं।

मुख्य विचार
- जबकि **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP)** ने पहले लगभग **13,000 प्लास्टिक रसायनों** की पहचान की थी,
  - **यूरोपीय वैज्ञानिकों** की एक टीम की रिपोर्ट में **प्लास्टिक** में **16,000** से अधिक रसायन पाए गए
  - जिनमें से एक चौथाई को मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरनाक माना जाता है।
- **प्लास्टिक प्रदूषण** को मजबूती से हल करने के लिए, हमें **प्लास्टिक** के **पूर्ण जीवन चक्र** को देखना होगा और **रसायनों** के मुद्दे का समाधान करना होगा
- ऐसा इसलिए है क्योंकि प्लास्टिक रसायन पानी और भोजन में मिल सकते हैं।
- ऐसे प्रभावों में प्रजनन संबंधी समस्याएं और हृदय रोग शामिल हैं।
- वैज्ञानिकों ने इस बात पर अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता पर जोर दिया कि **पुनर्नवीनीकरण उत्पादों** सहित **एडिटिव्स, प्रसंस्करण सहायता** और **अशुद्धियों** सहित कौन से र**सायन प्लास्टिक** में जा रहे हैं।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि पहचाने गए रसायनों में से **एक चौथाई** में उनकी **मूल रासायनिक पहचान** पर बुनियादी जानकारी का अभाव है।
- यह कुछ ऐसा है जिसे **प्लास्टिक संधि** संबोधित करने में मदद कर सकती है।
- दिसंबर में **दक्षिण कोरियाई** शहर बुसान में एक संधि को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से **कनाडा** के **ओटावा** में अगले महीने बातचीत जारी रहेगी।

संयुक्त राष्ट्र वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण संधि
- **वर्ष 2022** में, **संयुक्त राष्ट्र** के सदस्य देश **प्लास्टिक प्रदूषण** को समाप्त करने के लिए एक **नई वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण संधि** पर बातचीत शुरू करने पर सहमत हुए।
- यह **वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण संधि** प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए कानूनी रूप से **बाध्यकारी, अंतर्राष्ट्रीय समझौता** होगी, जिसमें परिभाषित किया जाएगा कि क्या उपाय किए जाएं, कैसे और कब उन्हें लागू किया जाए।
- **UNEA संकल्प 5/14**: इसके तहत, **वर्ष 2025** तक **वैश्विक प्लास्टिक संधि** देने के लिए **अंतर सरकारी वार्ता समिति (INC)** की स्थापना की गई थी।
- **कांग्रेस** ने **वर्ष 2022** की दूसरी छमाही के दौरान अपना काम शुरू किया, जिसका लक्ष्य **वर्ष 2024** के अंत तक वार्ता पूरी करना है।
- **INC (INC-1)** का पहला सत्र **28 नवंबर** से **2 दिसंबर 2022** तक **पुंटा डेल एस्टे, उरुग्वे** में हुआ।
- दूसरा सत्र (INC-2) 29 मई से 2 जून 2023 तक पेरिस, फ्रांस में।
- तीसरा सत्र (INC-3) 13 से 19 नवंबर 2023 तक नैरोबी, केन्या में।
- **चौथा सत्र** (INC-4) कनाडा के ओटावा में शॉ सेंटर में होने वाला है।

102. दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी: वैश्विक वायु गुणवत्ता रिपोर्ट-द हिंदू

प्रासंगिकता: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन।

प्रीलिम्स टेकअवे
- WHO
- AQI

समाचार:
- एक नई रिपोर्ट के अनुसार, **बिहार** का **बेगुसराय** दुनिया के सबसे **प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र** के रूप में उभरा, जबकि **दिल्ली** की पहचान **सबसे खराब वायु गुणवत्ता** वाले **राजधानी शहर** के रूप में की गई।

मुख्य बिंदु

विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट
- **एयर क्वालिटी टेक कंपनी** IQAir की यह रिपोर्ट **वैश्विक स्तर** पर **वायु प्रदूषण** के स्तर की जांच करती है।
- ये **देशों और शहरों** को इस **आधार पर रैंक** करते हैं कि उनकी हवा कितनी **साफ़ या गंदी** है।

इसका आकलन कैसे होता हैं:
- PM2.5 (सूक्ष्म कण पदार्थ) वायु गुणवत्ता का मुख्य संकेतक है।
- डेटा 134 देशों के 30,000 से अधिक निगरानी स्टेशनों से आता है।
- ये सरकारी एजेंसियों और अपने स्वयं के सेंसर दोनों से जानकारी का उपयोग करते हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के वायु गुणवत्ता दिशानिर्देश:
- **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** वायु प्रदूषण को एक बड़े **स्वास्थ्य खतरे** के रूप में देखता है।
- वर्ष 2021 में, उन्होंने **छह प्रदूषकों** के लिए सख्त **सीमा की सिफारिश** करते हुए, अपने **वायु गुणवत्ता दिशानिर्देशों** को अद्यतन किया।

मुख्य निष्कर्ष (2023):
- विश्व के अधिकांश देशों की हवा **अस्वास्थ्यकर** है, केवल **7 देश** ही **WHO के PM2.5** दिशानिर्देश पर खरे उतरे है।
- शीर्ष पांच सबसे प्रदूषित देश **एशिया और अफ्रीका** में हैं।
- भारत **तीसरा सबसे प्रदूषित देश** था, इसके **42 शहर वैश्विक** स्तर पर **शीर्ष 50** सबसे प्रदूषित शहरों में थे।
- दस सबसे प्रदूषित शहरों में से **नौ भारत** में हैं।
- कुल मिलाकर, यह रिपोर्ट **वैश्विक वायु गुणवत्ता** की एक चिंताजनक तस्वीर पेश करती है।

Rank	Country	2023	2022	2021	2020	2019
1	Bangladesh	79.9	65.8	76.9	77.1	83.3
2	Pakistan	73.7	70.9	66.8	59	65.8
3	India	54.4	53.3	58.1	51.9	58.1
4	Tajikistan	49	46	59.4	30.9	--
5	Burkina Faso	46.6	63	--	--	--
6	Iraq	43.8	80.1	49.7	--	39.6
7	United Arab Emirates	43	45.9	36	29.2	38.9
8	Nepal	42.4	40.1	46	39.2	44.5
9	Egypt	42.4	46.5	29.1	--	18
10	Democratic Republic of the Congo	40.8	15.5	--	--	32.1

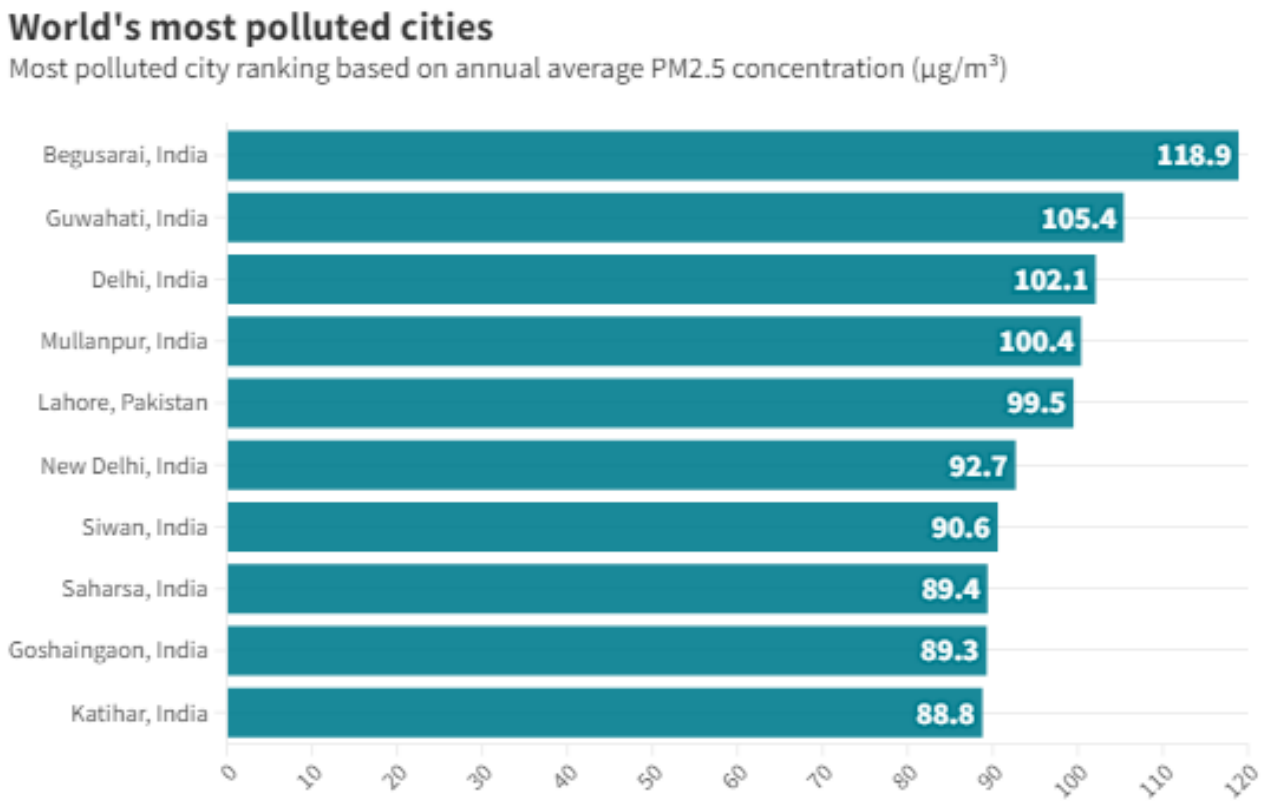

103. दिल्ली की बायोमाइनिंग परियोजना 2024 की समय सीमा से चूकने की संभावना - द हिंदू

प्रासंगिकता: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन।

प्रीलिम्स टेकअवे
- बायोलीचिंग
- बायोऑक्सीडेशन

समाचार:
- लैंडफिल साइटों को साफ करने के लिए **दिल्ली की बायोमाइनिंग परियोजना** वर्ष 2024 की समय सीमा से चूकने की संभावना है, ताजा **कचरे** की **डंपिंग और मौसमी** चुनौतियों के कारण धीमी प्रगति हो रही है।

छोटे खनिकों का दोहन: बायोमाइनिंग
- **बायोमाइनिंग धातु** निष्कर्षण की एक नई लहर है जो **सूक्ष्म सहयोगी बैक्टीरिया, शैवाल, कवक** या यहां तक कि **पौधों** का उपयोग करती है
- ये **छोटे कर्मचारी चट्टानों और खनिजों** को तोड़ते हैं, जिससे **तांबा या सोना** जैसी मूल्यवान धातुएँ मुक्त होती हैं।
- यह **पर्यावरण-अनुकूल विधि** कठोर रसायनों पर निर्भर नहीं करती है और **पारंपरिक खनन** की तुलना में **पर्यावरण** पर **बहुत कम प्रभाव** डालती है।

बायोमाइनिंग की दो मुख्य तकनीकें निम्नलिखित हैं:
- **बायोलीचिंग** : यहां, सूक्ष्मजीव सीधे धातुओं को घोलते हैं, जिससे उन्हें एकत्र करना आसान हो जाता है।
- **बायोऑक्सीकरण** : इस दृष्टिकोण में, सूक्ष्मजीव धातु के चारों ओर की चट्टान को कमजोर कर देते हैं, जिससे इसे निकालना आसान हो जाता है।
- सल्फर युक्त खनिजों में उपलब्ध धातुओं से निपटने के लिए बायोमाइनिंग विशेष रूप से अच्छा है।
- यह विधि अभी भी विकास के अधीन है, लेकिन यह धातु निष्कर्षण के स्वच्छ भविष्य की आशा रखती है।

104. सुप्रीम कोर्ट ने बस्टर्ड संरक्षण को संतुलित करने हेतु पैनल का गठन किया-द हिंदू

प्रासंगिकता: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन।

प्रीलिम्स टेकअवे
- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड
- IUCN

समाचार:
- **सुप्रीम कोर्ट** ने **ऊर्जा** के **नवीकरणीय स्रोतों** को बढ़ावा देने के लिए देश की **अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं** के साथ लुप्तप्राय **ग्रेट इंडियन बस्टर्ड** पक्षी आबादी के **संरक्षण और सुरक्षा** को संतुलित करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया।

मुख्य बिंदु
- **बड़े पंख** वाले **पक्षी विलुप्त** होने के कगार पर हैं और इसका एक कारण **उच्च शक्ति** वाले **बिजली के तारों** से लगातार टकराना है
  - **गुजरात और राजस्थान** में इस**के मुख्य निवास स्थान** के निकट।
- समिति **सतत विकास लक्ष्यों** और **पक्षियों के संरक्षण** को संतुलित करने के लिए विकल्प तलाशेगी।

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB)
- **ग्रेट इंडियन बस्टर्ड** (आर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स), **राजस्थान का राज्य पक्षी**, भारत का सबसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी माना जाता है।
- यह घास क्षेत्र के स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है, जो कि **घास क्षेत्र** की **पारिस्थितिकी** को दर्शाता है।
- इसकी आबादी ज्यादातर **राजस्थान और गुजरात** तक ही सीमित है, छोटी आबादी **महाराष्ट्र, कर्नाटक** और **आंध्र प्रदेश** में होती है।
- पक्षी निम्न कारणों से लगातार खतरे में है:
  - विद्युत पारेषण लाइनों के साथ टकराव
  - शिकार (अभी भी पाकिस्तान में प्रचलित)
  - व्यापक कृषि विस्तार आदि के परिणामस्वरूप निवास स्थान की हानि और परिवर्तन।
- **प्रकृति संरक्षण** के लिए **अंतर्राष्ट्रीय संघ** की **लाल सूची (IUCN)**: गंभीर रूप से लुप्तप्राय

105. पर्यावरण मंत्रालय ने बायोप्लास्टिक पर नियम सख्त किये -द हिंदू

प्रासंगिकता: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन।

प्रीलिम्स टेकअवे
- CPCB
- माइक्रोप्लास्टिक्स

समाचार:
- **पर्यावरण मंत्रालय** ने ऐसे नियम पेश किए हैं जो **डिस्पोजेबल प्लास्टिक** के **बर्तनों के निर्माताओं** के लिए ऐसे उत्पादों को '**बायोडिग्रेडेबल**' के रूप में लेबल करना कठिन बना देते हैं।
- एक शर्त लागू करते हुए कि उन्हें कोई भी **माइक्रोप्लास्टिक** पीछे नहीं छोड़ना चाहिए।

मुख्य बिंदु
- **बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक** और **कम्पोस्टेबल प्लास्टिक** को **भारत** की **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रदूषण** की बढ़ती समस्या के **दो व्यापक प्रकार** के **तकनीकी समाधान** के रूप में पेश किया जाता है।
- **बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक** में **प्लास्टिक** के सामानों को बेचने से पहले उनका उपचार किया जाता है।
- दूसरी ओर, **कंपोस्टेबल प्लास्टिक** नष्ट हो जाते हैं लेकिन ऐसा करने के लिए **औद्योगिक या बड़े नगरपालिका अपशिष्ट प्रबंधन** सुविधाओं की आवश्यकता होती है।
- भारत के **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन** (संशोधन) **नियम, 2024** में **संशोधनों** का एक **नया सेट**, जिसे हाल ही में सार्वजनिक किया गया है, **बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक** को परिभाषित करता है, जो न केवल मिट्टी, लैंडफिल जैसे विशिष्ट वातावरणों में जैविक प्रक्रियाओं द्वारा गिरावट में सक्षम है।
  - बल्कि ऐसी सामग्री के रूप में भी जो "कोई माइक्रोप्लास्टिक नहीं छोड़ती।"
- अद्यतन नियमों में **माइक्रोप्लास्टिक्स** के बारे में चेतावनी यह निर्दिष्ट नहीं करती है कि **माइक्रोप्लास्टिक्स** की **अनुपस्थिति** को स्थापित करने के लिए कौन से **रासायनिक परीक्षणों** का उपयोग किया जा सकता है
  - या किसी नमूने में **माइक्रोप्लास्टिक** को किस हद तक कम किया जाना चाहिए ताकि उन्हें समाप्त माना जा सके
- **माइक्रोप्लास्टिक** को **नदियों** और **महासागरों** को प्रभावित करने वाले **प्रदूषण** का एक **प्रमुख स्रोत** बताया गया है।

- कई कंपनियाँ अधर में लटक गईं क्योंकि **केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)** ने उनके उत्पादों को **बायोडिग्रेडेबल** के रूप में लाइसेंस देने के लिए '**अनंतिम प्रमाणपत्र**' प्रदान करने से इनकार कर दिया।
  - ऐसा इसलिए है क्योंकि **CPCB** केवल उसी **प्लास्टिक नमूने** को **बायोडिग्रेडेबल** मानता है जो **90%** तक खराब हो चुका होता है और ऐसी प्रक्रिया में कम से कम **दो साल** लगते हैं।

106. कोडागु (बेंगलुरु) में भूजल स्तर में भारी गिरावट -द हिंदू

प्रासंगिकता: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन।

प्रीलिम्स टेकअवे
- नीति आयोग
- जल संकट

समाचार:
- **कोडागु और कावेरी बचाओ** अभियान ने कहा है कि **बेंगलुरु में पानी की कमी** का एक कारण **कोडागु** का बड़े पैमाने पर और **अनियंत्रित वाणिज्यिक भूमि रूपांतरण** और **शहरीकरण** है।

मुख्य बिंदु

भूमि परिवर्तन
- **ग्राम पंचायतों** को **व्यावसायिक उद्देश्यों** के लिए **भूमि रूपांतरण** के लिए **NOC** जारी नहीं करनी चाहिए।
- यदि **बेंगलुरु** का निरंतर **विकास** होता और **कोडागु** के परिदृश्य का विनाश होता, तो यह **कैंडल एट बोथ एंड्स** का एक उत्कृष्ट मामला होता।
- **"कावेरी** न केवल **बेंगलुरु** के लिए, बल्कि **मांड्या** के **किसानों और मैसूर** के लोगों के लिए भी **जीवन रेखा** है।"
- यदि **लेआउट और कॉलोनियों** के प्रसार के कारण कोडागु की **जनसंख्या** वर्तमान **छह लाख** से बढ़कर **10 लाख** या उससे अधिक हो जाती है
  - यदि जिले में **बारिश की विफलता** के परिणामस्वरूप सूखे की स्थिति और पानी की कमी होती है, तो सरकार **राष्ट्रीय आपदा अधिनियम** लागू कर सकती है।
- सरकार उस **अधिनियम** को लागू कर सकती है जिसके द्वारा **कोडागु** भर में **कॉफी उत्पादकों** के **बोरवेल** और **पानी के टैंक जब्त** किए जा सकते हैं
  - इसे जिले में किसी भी तरह की **सिंचाई** करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिसके **परिणामस्वरूप कॉफी की पैदावार** में भारी कमी आएगी

भारत में जल संकट के कारण
- **पानी की बढ़ती मांग-** नीति आयोग के अनुसार, भारत में पानी की मांग तेजी से बढ़ रही है **वर्ष 2030** तक **भारत की पानी** की मांग उपलब्ध आपूर्ति से दोगुनी हो जाएगी।
  - साथ ही, वर्ष **2041-2080** के दौरान **भारत** में **भूजल की कमी** की दर मौजूदा **दर से तीन गुना** होगी।
- **कृषि** के लिए **भूजल** का **उपयोग दोषपूर्ण फसल पैटर्न** के कारण **कृषि** में **भूजल का अधिक उ**पयोग होता है।
  - **उदाहरण के लिए** - पंजाब और हरियाणा राज्यों में जल-गहन धान की खेती।
- **प्राकृतिक जल निकायों का अतिक्रमण-** बढ़ती आबादी की बुनियादी ढांचे की जरूरतों को पूरा करने के लिए झीलों और छोटे तालाबों का विनाश हुआ है।
  - उदाहरण के लिए- बेंगलुरु में झीलों का अतिक्रमण।
- **जलवायु परिवर्तन-** जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून अनियमित हो गया है और कई नदियों में जल स्तर कम हो गया है, जिससे भारत में जल संकट पैदा हो गया है।
  - प्रदूषकों का निर्वहन- औद्योगिक रसायनों, सीवरों और अनुचित खनन गतिविधियों के निर्वहन से भूजल संसाधन प्रदूषित हो गए हैं।

107. ऑस्ट्रेलिया की कार्बन क्रेडिट योजना वैश्विक स्तर पर विफल रही -हिन्दू

प्रासंगिकता: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन।

प्रीलिम्स टेकअवे
- कार्बन क्रेडिट
- मानचित्र आधारित प्रश्न

समाचार:
- **ऑस्ट्रेलिया** की **कार्बन क्रेडिट योजना** को **नए अनुसंधान** द्वारा कमजोर कर दिया गया, जिसमें पाया गया कि **विश्व-अग्रणी पुनर्वनीकरण परियोजना** एक खराब प्रदर्शन वाली "प्रलय" थी।
- **ऑस्ट्रेलिया** के **रेगिस्तानी आउटबैक** में **भूमि के विशाल** हिस्से को **देशी वन पुनर्जनन** के लिए चिह्नित किया गया है, जिसका उद्देश्य **उत्सर्जन को संतुलित** करना है क्योंकि नए पेड़ कार्बन सोखते हैं।

मुख्य बिंदु

- लेकिन **शोधकर्ताओं** ने पाया है कि इनमें से लगभग **80% वृक्षारोपण** में **वन विकास** या तो स्थिर था या **वुडलैंड्स सिकुड़** रहे थे।
- इसके बावजूद, वैज्ञानिकों ने कहा कि **ऑस्ट्रेलिया** ने इन परियोजनाओं का उपयोग लाखों टन संदिग्ध **कार्बन क्रेडिट** को बैंक करने के लिए किया था, जिसका उपयोग कथित तौर पर **प्रदूषणकारी उद्योगों** की भरपाई के लिए किया जाता है।
- अधिकारियों का दावा है कि **वर्ष 2013** के बाद से, इस भूमि पर फैले **देशी जंगल** ने **27 मिलियन टन** से अधिक कार्बन सोख लिया है।
- इन वनों द्वारा एकत्र किए गए प्रत्येक टन **कार्बन** को **एकल कार्बन क्रेडिट** के रूप में तैयार किया जाता है।
- ये **क्रेडिट खनन कंपनियों, एयरलाइंस** और अन्य **भारी प्रदूषणकारी उद्योगों** द्वारा अपने उत्सर्जन की भरपाई के लिए खरीदे जाते हैं।
- नियामक ने कहा कि यह "केवल **कार्बन क्रेडिट** जारी करता है जहां एक **परियोजना देशी वन** को **पुनर्जीवित** करने का प्रदर्शन कर सकती है"।
- **ऑस्ट्रेलिया** में **जलवायु नीति लं**बे समय से एक जटिल मामला रही है, जिसे **"जलवायु युद्ध"** कहे जाने वाले एक दशक के **राजनीतिक** झगड़े ने पीछे धकेल दिया है।
- जलवायु से जुड़ी **प्राकृतिक आपदाओं** के प्रति अपनी बढ़ती संवेदनशीलता के बावजूद, **ऑस्ट्रेलिया गैस** और **थर्मल कोयले** के दुनिया के सबसे बड़े **निर्यातकों** में से एक बना हुआ है।
- ऑस्ट्रेलिया ने **वर्ष 2050** तक **शुद्ध-शून्य उत्सर्जन** तक पहुंचने की राह पर, **वर्ष 2005** के स्तर से **वर्ष 2030** तक कार्बन उत्सर्जन में **43%** की कटौती करने की प्रतिबद्धता जताई है।
- **विश्व बैंक** के आंकड़ों से पता चलता है कि **ऑस्ट्रेलिया** का प्रति व्यक्ति **कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 15.3** टन के साथ **दुनिया में सबसे अधिक** है, जो **अमेरिकी स्तर** को पार कर गया है।

108. मोयार घाटी संरक्षण: जिप्स गिद्धों को प्राकृतिक आवास - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन।

प्रीलिम्स टेकअवे
- मुदुमलाई टाइगर रिजर्व
- मोयार घाटी

समाचार:

- **मोयार घाटी या मायर** (अदृश्य नदी) **घाटी गुडलुर** से **मुदुमलाई टाइगर रिजर्व** के मुख्य क्षेत्र तक फैली हुई है।
- लगभग **85 किमी** का यह पूरा क्षेत्र एक **वन्यजीव आश्रय स्थल** और **नीलगिरि बायोस्फीयर रिजर्व** में महत्वपूर्ण बायोम है, जो **बाघ और हाथी** और **गंभीर रूप** से लुप्तप्राय **जिप्स गिद्ध** जैसी कई महत्वपूर्ण प्रजातियों को आश्रय देता है।
- यह प्रायद्वीपीय **भारत** का एकमात्र क्षेत्र है जहां **जंगली जिप्स गिद्धों** की सबसे **बड़ी रहने योग्य** स्थल है।

मुदुमलाई: भारत में एक महत्वपूर्ण वन्यजीव गलियारा

- **मुदुमलाई नीलगिरि बायोस्फीयर रिज़र्व** के भीतर एक महत्वपूर्ण क्षेत्र तक फैला हुआ है।
- यह क्षेत्र **बाघ, हाथी** और **जिप्स गिद्ध** (प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ी घोंसले वाली कॉलोनी) जैसी लुप्तप्राय प्रजातियों का घर है।
- **मुदुमलाई** के भीतर **मोयार घाटी गिद्धों** जैसे **सफाईकर्मियों** के लिए एक **प्राकृतिक भोजन स्रोत** प्रदान करती है।
- ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां शिकार करने वाले **जानवर प्राकृतिक कारणों** से मरते हैं और उनमें **हानिकारक रसायनों** की कमी होती है।

मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में मुख्य विवरण:

- **तमिलनाडु** में **तीन राज्यों** (तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल) के मिलन बिंदु पर स्थित है।
- पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का हिस्सा।
- यह कई **संरक्षित क्षेत्रों** के साथ सीमा साझा करता है, जिससे एक महत्वपूर्ण **वन्यजीव गलियारा** बनता है।

109. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड विलुप्त होने के कगार पर - द हिन्दू

प्रासंगिकता: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन।

प्रीलिम्स टेकअवे
- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड
- IUCN

समाचार:
- **सुप्रीम कोर्ट** ने पिछले हफ्ते कहा था कि वह **ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB)** के निवास स्थान में सभी बिजली लाइनों को भूमिगत करने के अपने **अप्रैल 2021** के आदेश की समीक्षा करेगा, क्योंकि **केंद्र** ने आदेश को लंबी दूरी पर **"व्यावहारिक रूप से लागू करना असंभव"** पाया था।

द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड: ए बर्ड ऑन द ब्रिंक
- **भारत** की **चार बस्टर्ड प्रजातियों** में से सबसे बड़ी **ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB)** को अस्तित्व की गंभीर लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है।

पर्यावास और पतन:
- एक समय पूरे **भारतीय उपमहाद्वीप** में व्यापक रूप से फैले होने के बाद, उनका निवास स्थान घटकर मात्र **10%** रह गया है।
- ये **चरागाह पक्षी, स्वस्थ घास** के मैदानों के महत्वपूर्ण संकेतक, अब केवल **50-249 व्यक्तियों** के साथ गंभीर रूप से खतरे में हैं।

मुख्य ख़तरा: बिजली लाइनें
- GIB के लिए सबसे बड़ा खतरा ओवरहेड बिजली लाइनें हैं।
- उनकी खराब ललाट दृष्टि और वजन के कारण इन रेखाओं से बचना मुश्किल हो जाता है, जिससे टकराव और मौतें होती हैं।
- शोध से पता चलता है कि अकेले **राजस्थान** में हर साल **18 GIB** इस कारण से मर जाते हैं।
- उनके मुख्य निवास स्थान (कच्छ और थार रेगिस्तान) में नवीकरणीय ऊर्जा बुनियादी ढांचे में हालिया उछाल ने समस्या को बढ़ा दिया है।

अन्य खतरे:
- फ्री-रेंजिंग डॉग्स से खतरा
- खेतों में कीटनाशकों का उपयोग
- घास के मैदान का नुकसान (विशेष रूप से घोंसले के शिकार स्थल)
- स्थानीय समुदायों से समर्थन में कमी

संरक्षण के प्रयासों:
- **प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम:** भविष्य में पुनरुत्पादन के लिए बंदी प्रजनन आबादी बनाने की एक सरकारी पहल।
- **बर्ड डायवर्टर:** GIB को दृश्यमान बनाने और टकराव को रोकने के लिए बिजली लाइनों पर रिफ्लेक्टर लगाए जाते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप:
- **सुप्रीम कोर्ट** ने मुख्य **GIB आवास** में **बिजली लाइनों** को द**फनाने और कार्यान्वयन** की निगरानी के लिए समितियों का गठन करना अनिवार्य कर दिया है।
- केंद्र तकनीकी और आर्थिक चुनौतियों के कारण सभी लाइनों को दफनाने के खिलाफ तर्क देता है।
- मार्च 2024 में, न्यायालय ने आगे के संरक्षण उपायों का पता लगाने के लिए एक नई समिति की स्थापना की गई।
- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का भविष्य अधर में है।
- महत्वपूर्ण प्रजातियों के संरक्षण के साथ विकास की जरूरतों को संतुलित करना एक चुनौती बनी हुई है।

110. CPCB ग्रीन फंड का 80% अप्रयुक्त: NGT -इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन।

प्रीलिम्स टेकअवे
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)
- प्रदूषण

समाचार:
- **केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)** ने **दिल्ली-NCR** में **वायु प्रदूषण** को कम करने और **पर्यावरण** की रक्षा के लिए अब तक एकत्र किए गए **पर्यावरण संरक्षण शुल्क** और **पर्यावरण** मुआवजे का केवल **20 प्रतिशत** ही खर्च किया है।

- **केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)** को मोटे तौर पर दो मदों **पर्यावरण संरक्षण शुल्क** (EPC) और **पर्यावरण मुआवजा (EC)** के तहत मुआवजा मिलता है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)

- **भारत** में **जल** और **वायु प्रदूषण से निपटने** के लिए **वर्ष 1974** में स्थापित एक **सरकारी एजेंसी** है ।
- यह इन मुद्दों पर सरकार को सलाह देता है और **पानी और वायु** की गुणवत्ता के लिए मानक निर्धारित करता है।
- यह **अपशिष्ट प्रबंधन** और **प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों** के लिए दिशानिर्देश भी बनाता है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुख्य कार्यों में शामिल हैं:

- जल प्रदूषण को रोककर नदियों एवं कुओं को स्वच्छ रखना।
- वायु प्रदूषण को कम करके वायु को स्वच्छ बनाना।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) इनके लिए मानक तय करता है:

  - पानी की गुणवत्ता
  - हवा की गुणवत्ता
  - औद्योगिक अपशिष्ट उत्सर्जन
  - चिकित्सा अपशिष्ट निपटान
  - वाहन उत्सर्जन
  - ईंधन की गुणवत्ता
  - इंजनों और जनरेटरों के लिए शोर सीमा

- **केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)** विभिन्न उद्योगों के लिए **न्यूनतम प्रदूषण** मानक भी बनाता है, जिनका राज्यों को पालन करना चाहिए।

SECURITY

111. रक्षा मंत्री डेफकनेक्ट 2024 का उद्घाटन करेंगे- पीआईबी

प्रासंगिकता: विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप और उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे

- रक्षा नवाचार संगठन
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

समाचार:

- इनोवेशन फॉर **डिफेंस एक्सीलेंस-डिफेंस इनोवेशन ऑर्गनाइजेशन (iDEX-DIO),** मानेकशॉ सेंटर, नई दिल्ली में **डेफकनेक्ट 2024** का आयोजन कर रहा है।

रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार-रक्षा नवाचार संगठन:

- यह **वर्ष 2018** में शुरू की गई **भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय** की प्रमुख योजना है।

उद्देश्य :

- योजना का उद्देश्य **स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स, MSME, इनक्यूबेटर्स और शिक्षाविदों** के साथ सहयोग करके **रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र** में एक नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है।
- **वित्त पोषण:** इसे 'डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन (DIO)' द्वारा वित्त पोषित और प्रबंधित किया जाएगा, जिसे इस उद्देश्य के लिए कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार दो संस्थापक सदस्य रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (DPSU) HAL और BEL द्वारा 'लाभकारी नहीं' कंपनी के रूप में बनाया गया है।
- यह **DIO** की कार्यकारी शाखा के रूप में कार्य करता है, सभी आवश्यक गतिविधियों को पूरा करता है जबकि **DIO iDEX** को **उच्च स्तरीय नीति मार्गदर्शन** प्रदान करेगा।
- यह **भारतीय रक्षा और एयरोस्पेस** में भविष्य में अपनाने की महत्वपूर्ण संभावनाओं के साथ अनुसंधान एवं विकास के लिए अनुदान और सहायता प्रदान करता है।

112. सरकार ने नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में AFSPA बढ़ाया - द हिंदू

प्रासंगिकता: सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ और उनका प्रबंधन - आतंकवाद के साथ संगठित अपराध का संबंध।

प्रीलिम्स टेकअवे
- AFSPA
- मानचित्र आधारित प्रश्न

समाचार:
- **केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA)** ने **नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश** के कुछ हिस्सों में **सशस्त्र बल** (विशेष शक्तियां) **अधिनियम (AFSPA)** को अगले **छह महीने** के लिए बढ़ा दिया है।

मुख्य बिंदु
- अधिसूचना के अनुसार, **नागालैंड** के पूरे **आठ जिलों** और **पांच अन्य जिलों** के **21 पुलिस स्टेशनों** में AFSPA बढ़ा दिया गया है।
- **अरुणाचल प्रदेश** में, इसे **तीन जिलों** और **नामसाई जिले** के **तीन पुलिस स्टेशनों** के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में विस्तारित किया गया है।

AFSPA की उत्पत्ति
- विभाजन के दंगों के मद्देनजर, **वर्ष 1947** में **चार अध्यादेश** जारी किये गये।
- इन्हें एक सामान्य कानून, **सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1948** द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
- इसे एक वर्ष के लिए लागू किया जाना था, लेकिन इसे **वर्ष 1957** में ही निरस्त कर दिया गया।
- लेकिन बाद में संसद के एक **अधिनियम द्वारा सशस्त्र बल** (असम और मणिपुर) विशेष शक्तियां **अधिनियम, 1958** को बढ़ा दिया गया।

AFSPA के अंतर्गत देश के हिस्से
- इस कानून के तहत, किसी क्षेत्र को '**अशांत क्षेत्र**' घोषित किया जा सकता है, जिससे **अधिसूचित क्षेत्र** में **बल प्रयोग** के लिए **सशस्त्र बलों** को मिलने वाली सुरक्षा लागू हो जाएगी।
- अधिसूचना को समय-समय पर, अधिकतर एक बार में **छह महीने** के लिए बढ़ाया जाता है।
- आज तक, पूरे **असम** और **नागालैंड**, **मणिपुर**, **इम्फाल नगरपालिका क्षेत्र** को छोड़कर, **अरुणाचल प्रदेश** के कुछ जिले '**अशांत क्षेत्र**' के रूप में अधिसूचित हैं।
- **त्रिपुरा और मेघालय** से **AFSPA** हटा लिया गया गया है।

अधिनियम क्या कहता है?
- अधिनियम किसी भी राज्य के **राज्यपाल, या केंद्र शासित प्रदेश** के **प्रशासक, या केंद्र सरकार** को राज्य या **केंद्र शासित प्रदेश** के कुछ हिस्सों या पूरे को '**अशांत क्षेत्र**' के रूप में अधिसूचित करने का अधिकार देता है।
  - यदि वे मानते हैं कि ऐसे क्षेत्रों में स्थिति इतनी **खतरनाक या अशांत** है कि **नागरिक शक्ति** की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक है।
- ऐसे अधिसूचित क्षेत्र में, **सशस्त्र बलों** का कोई भी अधिकारी **सार्वजनिक व्यवस्था** बनाए रखने के लिए किसी भी व्यक्ति के खिलाफ गोली चला सकता है या बल का प्रयोग कर सकता है, यहां तक कि मौत का कारण भी बन सकता है।
- **अधिनियम अधिसूचित क्षेत्र** में बिना वारंट के किसी भी परिसर की **गिरफ्तारी और तलाशी** की अनुमति देता है, और किसी भी **सीमित व्यक्ति, या गैरकानूनी** रूप से संग्रहीत किसी भी **हथियार** और **गोला-बारूद** की बरामदगी की अनुमति देता है।
- **केंद्र सरकार** की **पूर्व मंजूरी** के बिना **अधिनियम** के तहत की गई कार्रवाई के लिए किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है या किसी **कानूनी कार्यवाही** के अधीन नहीं किया जा सकता है।
- **सशस्त्र बलों** द्वारा इन **असाधारण शक्तियों** के प्रयोग से अक्सर **अशांत क्षेत्रों** में **सुरक्षा बलों** द्वारा फर्जी **मुठभेड़ों** और अन्य **मानवाधिकारों** के उल्लंघन के आरोप लगते हैं।

नागा पीपुल्स मूवमेंट ऑफ़ ह्यूमन राइट्स बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया
- इस फैसले में **सुप्रीम कोर्ट** ने **अधिनियम** की **संवैधानिकता** को बरकरार रखा है।
  - लेकिन यह भी कहा कि घोषणा सीमित अवधि के लिए होनी चाहिए और **6 महीने** के बाद इसकी समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए।
  - **AFSPA** द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, **अधिकृत अधिकारी** को प्रभावी कार्रवाई के लिए आवश्यक **न्यूनतम बल** का उपयोग करना चाहिए।

जीवन रेड्डी समिति

- **वर्ष 2005** में, सेवानिवृत्त **सुप्रीम कोर्ट** के **न्यायाधीश, बीपी जीवन रेड्डी** की अध्यक्षता में **सरकार** द्वारा नियुक्त **पांच सदस्यीय समिति** ने सिफारिश की कि **AFSPA** को निरस्त कर दिया जाए।
- इसने सुझाव दिया कि आतंकवाद से निपटने के लिए **गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम** में उपयुक्त संशोधन किया जा सकता है।

आगे की राह

- व्यवधान को कम करने और **मानवाधिकारों** की रक्षा के लिए, **AFSPA** का उपयोग केवल सिद्ध अशांति वाले विशिष्ट जिलों में किया जाना चाहिए, पूरे राज्यों में नहीं होना चाहिए ।
- इसके अतिरिक्त, **सरकार और सुरक्षा बलों** को **सर्वोच्च न्यायालय**, **जीवन रेड्डी आयोग** और **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** द्वारा स्थापित नियमों का पालन करना चाहिए।

113. "ग्रे जोन वॉरफेयर" अनौपचारिक युद्ध में नवीनतम: CDS- इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: भारत के हितों, भारतीय प्रवासियों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव।

प्रीलिम्स टेकअवे
- शीत युद्ध
- द्वितीय विश्व युद्ध

समाचार:

- वर्ष 2024 **रायसीना डायलॉग** के आखिरी दिन भारत के **चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ** ने कहा कि **"ग्रे जोन वॉरफेयर"** अनौपचारिक युद्ध में नवीनतम है।

ग्रे जोन वॉरफेयर

- **ग्रे ज़ोन वॉरफेयर** का मतलब आम तौर पर एक मध्य, अस्पष्ट स्थान होता है जो **अंतरराष्ट्रीय संबंधों** में **प्रत्यक्ष संघर्ष और शांति** के बीच मौजूद होता है।
- इस क्षेत्र में **अनैतिक आर्थिक गतिविधियों, प्रभाव अभियानों** और **साइबर हमलों** से लेकर भाड़े के **ऑपरेशनों, हत्याओं और दुष्प्रचार अभियानों** तक बहुत सारी गतिविधियाँ आती हैं।
- ग्रे ज़ोन में गतिविधियाँ हमेशा से ही महान-शक्तियों की प्रतिस्पर्धा की विशेषता रही हैं।
- छद्म युद्ध, अस्थिर करने वाले विद्रोह, कानूनी युद्ध (लॉफेयर), और विरोधियों और सहयोगियों द्वारा समान रूप से सूचना युद्ध इस संघर्ष की एक विशेषता रही है।
- विशेषज्ञों का दावा है कि ऐसे तरीके अक्सर उन पार्टियों द्वारा अपनाए जाते हैं जिनकी **परंपरागत** रूप से बड़े पैमाने पर **संसाधनों या सत्ता** तक पहुंच नहीं होती है।
- इसलिए, इस तरह की **रणनीति तकनीकी** रूप से अधिक **सुसज्जित प्रतिद्वंद्वी** पर लाभ हासिल करने में मदद कर सकती है जो **पारंपरिक युद्ध** के लिए अधिक अभ्यस्त है।

शुरुआत

- विशेषज्ञों का मानना है कि **शीत युद्ध** का युग, जो **वर्ष 1945** में **द्वितीय विश्व युद्ध** की समाप्ति के बाद शुरू हुआ, ने ऐसी स्थितियाँ पैदा कीं जो **ग्रे ज़ोन युद्ध** के पक्ष में थीं।
- **वैचारिक** और **आर्थिक प्रभुत्व** के लिए **अमेरिका-सोवियत संघ** प्रतिद्वंद्विता के बीच, यह ज्ञान कि दोनों पक्ष **परमाणु हथियारों** से लैस थे, का मतलब था कि सीधे संघर्षों को रोकना होगा।
- आज के परमाणु युग में, **पारंपरिक युद्धों** की कीमत बहुत अधिक हो गई है, और चीजों के बदतर होने का खतरा बहुत गंभीर है।
- इस वजह से देश **छिपकर** या **छिपकर आक्रामक** होकर अपने **लक्ष्य हासिल** करने की कोशिश कर रहे हैं।

ग्रे जोन वॉरफेयर कैसा दिखता है?

- **अमेरिका और यूरोप** के विशेषज्ञों ने हाल ही में कुछ **रूसी और चीनी** कार्रवाइयों को **ग्रे जोन वॉरफेयर** के उदाहरण के रूप में चित्रित किया है।
- इसमें **दक्षिण चीन सागर में चीनी सेना** की मौजूदगी भी शामिल है।
- **फिलीपींस** उन देशों में से एक है जिसने लगभग **80 प्रतिशत क्षेत्र** में फैले **चीन** के दावों को चुनौती दी है।
- **दिसंबर 2023** में, इसने **विवादित चट्टान के पास 135** से अधिक **चीनी समुद्री मिलिशिया जहाजों** की उपस्थिति को अवैध करार दिया।
- इसने **चीन** पर उसकी **नौकाओं** पर पानी की बौछारें करने और अन्य **नौकाओं** को टक्कर मारने का आरोप लगाया, जबकि **चीनी तट रक्षक** ने **चीनी नौकाओं** पर हमला करने के लिए **फिलीपींस** को दोषी ठहराया।

- हाल ही में रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ताइवान पिछले चार सालों से चीन की बढ़ती सैन्य कार्रवाइयों को लेकर चिंता व्यक्त करता रहा है।
- इसमें नियमित रूप से **जलडमरूमध्य** के ऊपर से उड़ान भरने वाले **चीनी लड़ाकू विमान** भी शामिल हैं।
- यह **ताइवान** पर उन गतिविधियों के लिए दबाव डालने की **चीन की रणनीति** का हिस्सा है जो पूर्ण पैमाने पर संघर्ष शुरू करने से कुछ ही कम हैं।
- विश्लेषकों का दावा है कि **अमेरिका** भी इसी तरह की **रणनीति** में लगा हुआ है।
  इनमें **चीन के खिलाफ** उसके **आर्थिक प्रतिबंध** और **समुद्री सैनिक सर्वेक्षण** के साथ-साथ **अमेरिका** में **चीनी आयात** पर **शुल्क** लगाना शामिल है।

114. भारतीय नौसेना मिनिकॉय द्वीप में INS जटायु को तैनात करेगी - पीआईबी

प्रासंगिकता: विभिन्न सुरक्षा बल और एजेंसियां और उनका अधिदेश।

प्रीलिम्स टेकअवे
- लक्षद्वीप
- कावारत्ती

समाचार:
- **भारतीय नौसेना की** एक सैन्य टुकड़ी **मिनिकॉय** को **INS जटायु** के रूप में कमीशन करेगी
- यह आयोजन **रणनीतिक** रूप से महत्वपूर्ण **लक्षद्वीप द्वीप समूह** में सुरक्षा **बुनियादी ढांचे** को बढ़ाने के **नौसेना** के संकल्प में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

INS जटायु:
- **कावारत्ती** में **INS द्वीपरक्षक** के बाद यह **लक्षद्वीप** में **दूसरा नौसेना बेस** है।
- **INS जटायु** के चालू होने से, **भारतीय नौसेना लक्षद्वीप द्वीपों** में अपनी पकड़ मजबूत करेगी और साथ ही **परिचालन निगरानी,** पहुंच और **रखरखाव** का विस्तार करेगी।
- यह क्षमता **निर्माण** और **द्वीप क्षेत्रों के व्यापक विकास** के एक नए युग की शुरुआत करेगा।
- यह आयोजन **रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लक्षद्वीप द्वीप समूह** में **सुरक्षा बुनियादी ढांचे** को बढ़ाने के **नौसेना** के संकल्प में एक **महत्वपूर्ण उपलब्धि** है।

लक्षद्वीप
- यह एक **उष्णकटिबंधीय द्वीपसमूह** है जिसमें **36 एटोल** और **प्रवाल भित्तियाँ** शामिल हैं जो **लैकाडिव सागर** में स्थित हैं, जो **केरल तट** से **280 किमी** से **480 किमी** दूर स्थित है।
- इनमें से **11 द्वीप** बसे हुए हैं, लेकिन **समुद्री कटाव** के कारण **पराली 1** के डूब जाने के कारण वर्तमान में इनकी संख्या 35 है।
- **लक्षद्वीप** नाम, जिसका अर्थ **मलयालम** में "**एक लाख द्वीप**" है, इस क्षेत्र की **आधिकारिक** और **व्यापक** रूप से बोली जाने वाली मूल भाषा है, जो इसकी उत्पत्ति को दर्शाता है।
- मछली पकड़ना यहाँ का एक प्रमुख उद्योग है।
- **भारत** के सबसे **छोटे केंद्र शासित प्रदेश** के रूप में, ये **द्वीप सामूहिक** रूप से केवल **32 वर्ग किलोमीटर** के सतह क्षेत्र को कवर करते हैं।
- कवरत्ती **केरल उच्च न्यायालय** के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इस ए**क-जिला केंद्र शासित प्रदेश** की **राजधानी** के रूप में कार्य करती है।

115. संयुक्त अभ्यास के लिए अमेरिकी तटरक्षक जहाज बर्थोल्फ पोर्ट ब्लेयर पहुंचा- इंडिया टुडे

प्रासंगिकता: संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौतियाँ, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा मनी-लॉन्ड्रिंग की मूल बातें और इसकी रोकथाम।

प्रीलिम्स टेकअवे
- भारतीय तट रक्षक
- समुद्री रक्षक

समाचार:
- **यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड (USCG)** जहाज, बर्थोल्फ, **भारतीय तटरक्षक (ICG)** के साथ **संयुक्त अभ्यास** के लिए **पोर्ट ब्लेयर** पहुंचा, जो **दोनों सेनाओं** के बीच **द्विपक्षीय सहयोग** को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण कदम है।

समुद्री डिफेंडर्स-2024
- यह **भारतीय** और **संयुक्त राज्य अमेरिका** के तट **रक्षकों** के बीच एक सहयोगात्मक **प्रशिक्षण मिशन** है।

- **भारत** के **पोर्ट ब्लेयर** के तट पर आयोजित यह **अभ्यास विभिन्न समुद्री खतरों** का अनुकरण करता है।
- इनमें **समुद्री डाकू हमले**, **वाणिज्यिक जहाजों** पर **ड्रोन हमले, समुद्र** में **खोज** और **बचाव, बड़ी** आग से लड़ना, **समुद्र प्रदूषण** का जवाब देना और **नशीली दवाओं** की **तस्करी** को **रोकना** शामिल है।
- यह आयोजन **आपातकालीन प्रतिक्रिया** क्षमताओं में सुधार के लिए समुद्र के रास्ते **चिकित्सा निकासी** का भी अभ्यास करता है।

भारतीय तट रक्षक (ICG)

- यह एक **सशस्त्र बल** है जो समुद्र में **भारत के हितों** की रक्षा करता है और **समुद्री कानूनों** को लागू करता है।
- **ICG** की जिम्मेदारी के क्षेत्र में **भारत** के **क्षेत्रीय जल, आसपास के क्षेत्र** और **विशेष आर्थिक क्षेत्र** शामिल हैं।
- ये **भारत** के **समुद्री हितों** को सुरक्षित करने, **नावों और जरूरतमंद मछुआरों** की सहायता करने और **समुद्री पर्यावरण** की सुरक्षा के लिए अन्य **भारतीय संगठनों** के साथ काम करते हैं।

116. प्रधानमंत्री ने असम को अरुणाचल से जोड़ने वाली सेला सुरंग का उद्घाटन किया- प्रिंट

प्रासंगिकता: सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ और उनका प्रबंधन, आतंकवाद के साथ संगठित अपराध का संबंध।

प्रीलिम्स टेकअवे
- बालीपारा-चारिद्वार-तवांग सड़क
- नेचिफू सुरंग

समाचार:

- पूर्वी क्षेत्र में **भारतीय सशस्त्र बलों** को लंबे समय से प्रतीक्षित बढ़ावा देते हुए, **प्रधानमंत्री** ने **अरुणाचल प्रदेश** में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण **सेला सुरंग** का उद्घाटन किया।

मुख्य बिंदु

- इसका निर्माण **असम के तेजपुर** को **अरुणाचल के तवांग** से जोड़ने वाली सड़क पर किया गया है, जिस पर **वर्ष 1962** के युद्ध में **चीनी सैनिकों** ने कब्ज़ा कर लिया था।
- **13,000 फीट** से अधिक की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी **द्वि-लेन सुरंग सेला** की आधारशिला **अरुणाचल** के **पश्चिम कामेंग जिले** में रखी गई थी।
- **सेला सुरंग, 317 किलोमीटर लंबी बालीपारा-चारिद्वार-तवांग (BCT)** सड़क पर **नेचिफू सुरंग** के साथ , जो **पश्चिम कामेंग और तवांग** की ओर जाती है
  - यह सुनिश्चित करेगा कि **रक्षा** और **निजी दोनों वाहनों** में पूरे वर्ष गतिशीलता रहेगी।
- वर्तमान में, **सेना और नागरिक** तवांग तक पहुंचने के लिए **बालीपारा-चारिद्वार रोड (असम)** का उपयोग करते हैं, क्योंकि भारी बर्फबारी के कारण सर्दियों में **सेला दर्रा बंद** हो जाता है।
- दोनों सुरंगों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि बड़े तोपखाने के टुकड़ों सहित सेना के सभी उपकरणों का उपयोग किया जा सके
  - **बोफोर्स तोपों** की तरह, **T-90** और **वज्र हॉवित्जर** जैसे टैंक पूरे साल आसानी से इसमें यात्रा कर सकते हैं, साथ ही समय भी कम लगता है।
- यह **सुरंग** यह भी सुनिश्चित करेगी कि **चीनी क्षेत्र** में यातायात की आवाजाही पर नजर न रख सकें।
- **13,700 फीट** की **ऊंचाई** पर स्थित **सेला दर्रा वर्तमान** में **चीनियों** के लिए दृश्यमान है और इसलिए सभी प्रकार की **सैन्य गतिविधियों** को देख सकता है।
- जबकि **सेला परियोजना** अब पूरी हो चुकी है, **दूसरी बड़ी परियोजना** जो शुरू की गई है वह है **अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे,** जो देश की **सबसे बड़ी** और **कठिन परियोजनाओं** में से एक है।
- **मैकमोहन रेखा** पर चलने वाली **2,000 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना, अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे, भूटान** से **सटे अरुणाचल** के मागो से शुरू होगी
- और तवांग, ऊपरी सुबनसिरी, तूतिंग, मेचुका, ऊपरी सियांग, दिबांग घाटी, देसाली, चगलागम, किबिथू और डोंग से होकर **म्यांमार सीमा** के पास **विजयनगर** पर समाप्त होगी।

117. भारत के पहले मानवयुक्त सबमर्सिबल मिशन, समुद्रयान हेतु मुख्य परीक्षण पूरा किया - द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे
- समुद्रयान
- राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान

प्रासंगिकता: विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियाँ; प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण और नई प्रौद्योगिकी का विकास।

समाचार:
- **समुद्रयान** एक **मानवयुक्त पनडुब्बी मिशन** है जो वैज्ञानिकों को **उनएक्सप्लोरड डीप समुद्र क्षेत्रों** का सीधे निरीक्षण करने की अनुमति देगा।
- **राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (NIOT)** ने भारत के पहले **मानवयुक्त पनडुब्बी मिशन समुद्रयान** के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षण पूरा कर लिया है।

मुख्य बिंदु
- **समुद्रयान** एक **मानवयुक्त पनडुब्बी** मिशन है जो वैज्ञानिकों को **उनएक्सप्लोरड डीप समुद्र क्षेत्रों** का सीधे निरीक्षण करने की अनुमति देगा।
- डीप ओशन मिशन का लक्ष्य गहराई के रहस्यों को उजागर करना है
  - और सफल होने पर, भारत को समुद्र के भीतर गतिविधियों को अंजाम देने के लिए प्रौद्योगिकी और वाहन विकसित करने में अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन सहित देशों के एक विशिष्ट क्लब में शामिल कर देगा।
- मंत्रालय ने इसे "**समुद्र** में **6,000 मीटर** की गहराई तक **तीन मनुष्यों** को ले जाने वाली **स्व-चालित मानव चालित पनडुब्बी**" कहा।
  - डीप समुद्र में अन्वेषण के लिए वैज्ञानिक सेंसर और उपकरणों के एक सेट के साथ"।
- **"मानवयुक्त पनडुब्बी निकल, कोबाल्ट, दुर्लभ पृथ्वी, मैंगनीज** आदि से **समृद्ध खनिज संसाधनों** की खोज में **गहरे समुद्र में मानव द्वारा प्रत्यक्ष** अवलोकन की सुविधा प्रदान करती है।
  - **नमूनों का संग्रह,** जिसका **उपयोग विश्लेषण** के लिए किया जा सकता है, **"मंत्रालय** ने अपने मिशन दस्तावेज़ में कहा।
- केंद्र ने पांच वर्षों के लिए **₹4,077 करोड़** के कुल बजट पर गहरे **महासागर मिशन** को मंजूरी दी।
- **सरकारी आंकड़ों** से पता चलता है कि **तीन वर्षों (2021-24)** के लिए **पहले चरण** की अनुमानित लागत **₹2,823.4 करोड़** है।

GEO IAS It's about quality

118. अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास/कटलैस एक्सप्रेस 23 में INS त्रिकंद की भागीदारी- पीआईबी

प्रीलिम्स टेकअवे
- INS त्रिकांड
- मानचित्र आधारित प्रश्न

प्रासंगिकता: विभिन्न सुरक्षा बल और एजेंसियां और उनका अधिदेश **।**

समाचार:
- **INS त्रिकंद** ने **05 से 09 मार्च 2023** तक **खाड़ी** में आयोजित **अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास/कटलैस एक्सप्रेस** 2023 (IMX/CE-23) के **समुद्री चरण-I** में भाग लिया।
- इस अवधि के दौरान, जहाज ने **बहरीन, जापान, ओमान, सऊदी अरब, यूएई, यूके और यूएसए** की **नौसैनिक इकाइयों** के साथ अभ्यास किया।

उद्देश्य:
- इसका उद्देश्य **समुद्री सुरक्षा** को बढ़ाना, **शिपिंग** लेन को खुला रखना और **नेविगेशन** की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
- **INS त्रिकंद भारतीय नौसेना** के **पश्चिमी बेड़े** का हिस्सा है और **मुंबई स्थित पश्चिमी नौसेना कमान** के तहत संचालित होता है।
- यह एक आधुनिक युद्धपोत है जिसमें उन्नत तकनीकें हैं जो उसे गुढ़, तेज़ और दुर्जेय बनाती हैं।
- लंबी पहुंच और अत्याधुनिक लड़ाकू सूट के साथ, जहाज को नौसेना संचालन की एक विस्तृत श्रृंखला को अंजाम देने के लिए डिज़ाइन किया गया है

119. वर्ष 2019-23 के बीच भारत दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक: SIPRI- द हिंदू

प्रासंगिकता: सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ और उनका प्रबंधन, आतंकवाद के साथ संगठित अपराध का संबंध।

प्रीलिम्स टेकअवे
- स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान (SIPRI)
- मानचित्र आधारित प्रश्न

समाचार:
- स्वीडिश थिंक टैंक **SIPRI** की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, **वर्ष 2019-23** के बीच, वर्ष 2014-18 की तुलना में हथियारों के आयात में **4.7%** की वृद्धि के साथ **भारत दुनिया** के **शीर्ष हथियार आयातकों** में से एक रहा है।
- वहीं, **रूस-यूक्रेन युद्ध** के कारण यू**रोपीय देशों** द्वारा हथियारों का **आयात 94%** बढ़ गया।

रिपोर्ट की मुख्य बिंदु
- रूस भारत का एक प्रमुख हथियार आपूर्तिकर्ता है (36% हथियार आयात)।
  - यह भारत के 50% हथियार आयात के सामान्य रुझान से कम हो गया है।
- **10** सबसे बड़े **हथियार आयातकों** में से **9 एशिया** और **ओशिनिया** या **मध्य पूर्व** से हैं।
- **वर्ष 2022-23** में **30 से अधिक राज्यों** से प्रमुख हथियारों के हस्तांतरण प्राप्त करने के बाद **यूक्रेन विश्व** स्तर पर **चौथा सबसे बड़ा हथियार** आयातक बन गया।
- **वर्ष 2019-23** में पांचवें सबसे बड़े हथियार आयातक **पाकिस्तान** का आयात **43%** बढ़ गया, चीन ने अपने सभी हथियारों के आयात का **82%** तक आपूर्ति करता है।

120. राजस्थान में सेना की पोखरण रेंज में युद्धाभ्यास 'भारत शक्ति' का आयोजन - द प्रिंट

प्रासंगिकता: विभिन्न सुरक्षा बल और एजेंसियां और उनका अधिदेश।

प्रीलिम्स टेकअवे
- आकाश मिसाइल प्रणाली
- MBT अर्जुन

समाचार:
- राजस्थान में सेना की पोखरण रेंज त्रि-सेवा अग्नि और युद्धाभ्यास **'भारत शक्ति'** की लाइव गवाह बनी।

मुख्य बिंदु
- **स्वदेशी रक्षा क्षमताओं** का एक समन्वित प्रदर्शन, यह अभ्यास **प्रधानमंत्री** और कम से **कम 30 देशों** के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में **लगभग 50 मिनट** तक चला।
- स्वदेशी हथियार प्रणालियों और प्लेटफार्मों पर एक सरणी के अलावा
  - इस अभ्यास का उद्देश्य संचार, प्रशिक्षण, अंतरसंचालनीयता और रसद सहित क्षेत्रों में तीनों सेनाओं के एकीकरण को प्रदर्शित करना है।

T--90 टैंक
- T--90 भीष्म रूसी T-90S टैंक का **तीसरी पीढ़ी** का **भारतीय संस्करण** है।
- इनका निर्माण अब **रूस के लाइसेंस** के तहत भारत में किया जाता है।

धनुष तोपें
- धनुष एक 155 मिमी, 45-कैलीबर **टोवड हाउविट्जर** है जो **राज्य-स्वामित्व वाली एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया** द्वारा **गन कैरिज फैक्ट्री, जबलपुर** में निर्मित किया गया है।
- इसकी मारक क्षमता **36 किमी** है और यह 155 मिमी, 39-कैलिबर **बोफोर्स FH 77** तोप का आधुनिक अपडेट है।

MBT अर्जुन
- DRDO द्वारा विकसित, मुख्य युद्धक टैंक (MBT) अर्जुन स्वदेशी फिन स्टैबिलाइज्ड आर्मर पियर्सिंग डिस्कार्डिंग सबोट (FSAPDS) गोला-बारूद और 120 मिमी कैलिबर राइफल गन से लैस है।

आकाश मिसाइल प्रणाली
- आकाश एक मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है जिसे **DRDO** ने **इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम (IGMDP)** के तहत विकसित किया है।
- **सेना** और **वायु सेना दोनों** इस **मिसाइल प्रणाली** का संचालन करती हैं, जिसमें **अंतर्निहित इलेक्ट्रॉनिक काउंटर-काउंटर मीजर्स (ECCM)** विशेषताएं हैं और यह एक साथ **स्वायत्त मोड** में कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है।

SCIENCE & TECH

121. भारत के युवाओं में मोटापा बढ़ रहा है: लांसेट अध्ययन- इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे
- मोटापा
- कुपोषण

समाचार:
- भारत में पिछले **32 वर्षों** में न केवल **वयस्कों** बल्कि **बच्चों** में भी **मोटापे के स्तर** में लगातार वृद्धि देखी गई है।
- साथ ही, देश में अल्पपोषण का प्रसार भी उच्च स्तर पर बना हुआ है।
- परिणामस्वरूप, लैंसेट के एक नए अध्ययन के अनुसार, **भारत उच्च "दोहरे भार"** वाले देशों में से एक बन गया है।

लैंसेट द्वारा प्रकाशित अध्ययन की मुख्य विशेषताएं:

भारत में मोटापा:
- अध्ययन के अनुसार, पिछले **तीन दशकों** में महिलाओं में **मोटापा तेजी** से बढ़ा है, यह **वर्ष 1990** में 1.2% से बढ़कर **वर्ष 2022** में **9.8%** हो गया है।
- वर्ष 2022 में 44 मिलियन महिलाएं मोटापे से ग्रस्त थीं।
- इस बीच, इसी अवधि के दौरान **पुरुषों** में **मोटापा 4.9 प्रतिशत** अंक बढ़ गया, **वर्ष 2022** में **26 मिलियन पुरुष मोटापे** के साथ जी रहे हैं।
- विशेष रूप से, बचपन के मोटापे में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।
- अध्ययन में जांच की गई **32 वर्षों** में लड़कियों में **3 प्रतिशत अंक** और **लड़कों में 3.7 प्रतिशत अंक** की वृद्धि हुई है।
- **वर्ष 2022** में **3.1% लड़कियां** और **3.9%** लड़के मोटापे से ग्रस्त थे।

भारत में कम वजन:
- उल्लेखनीय गिरावट के बावजूद, **लैंगिक और आयु समूहों** में **कम वजन** और **दुबलेपन** का प्रचलन **उच्च** बना हुआ है।
- अध्ययन में पाया गया कि **13.7% महिलाएं और 12.5% पुरुष कम वजन** वाले थे।
- **भारतीय लड़कियों** में **दुबलेपन** को कम वजन का माप माना जाता है, जो **20.3%** की व्यापकता के साथ दुनिया में सबसे ज्यादा पाया गया।
- भारतीय लड़कों में यह **21.7%** की व्यापकता के साथ **दूसरे स्थान** पर है।

पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक मोटापे से ग्रस्त क्यों हैं?
- महिलाओं में वजन बढ़ने की संभावना अधिक होती है क्योंकि उनमें से अधिकांश के पास **जिम** जैसी **शारीरिक गतिविधियों** के लिए समय या पहुंच नहीं होती है।
- वे परिवार के पोषण को अपने से ऊपर रखने की भी संभावना रखते हैं।
- यदि **केंद्रीय मोटापे** पर विचार किया जाए, तो देश के कई हिस्सों में **महिलाओं** में **मोटापा 40% से 50%** तक होगा।
- **मधुमेह** और **उच्च रक्तचाप** जैसी **बीमारियों के भविष्य** के जोखिम का एक बेहतर **भविष्यवक्ता, केंद्रीय मोटापा पेट क्षेत्र** में **वसा का अतिरिक्त संचय** है।

122. अंतर्राष्ट्रीय HPV जागरूकता दिवस- द हिंदू

प्रासंगिकता: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे
- HPV
- यौन संचारित संक्रमण

समाचार:
- जनवरी को **सर्वाइकल कैंसर जागरूकता** माह के रूप में मनाया गया। इसके अतिरिक्त, **हर साल 4 मार्च** को **अंतर्राष्ट्रीय HPV जागरूकता दिवस** के रूप में मनाया जाता है।

ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV)

- **HPV 200** से अधिक संबंधित **वायरस** का एक समूह है, जिनमें से **40** से अधिक सीधे यौन संपर्क के माध्यम से फैलते हैं।
- इनमें से, दो HPV प्रकार जननांग मस्से का कारण बनते हैं, और लगभग एक दर्जन HPV प्रकार कुछ प्रकार के कैंसर का कारण बन सकते हैं। 95% से अधिक सर्वाइकल कैंसर HPV वायरस के कारण होता है।

ट्रांसमिशन:

- यह विश्व स्तर पर सबसे आम **यौन संचारित संक्रमण (STI) है।**
- यह त्वचा से त्वचा के संपर्क में आने से भी फैलता है।
- एक बार संक्रमित होने के बाद, अधिकांश लोगों में कोई लक्षण विकसित नहीं होते हैं, जिससे उन्हें पता नहीं चलता कि उनमें वायरस है।
- HPV के खिलाफ टीका लगवाने से पुरुषों और महिलाओं में कैंसर को रोकने में मदद मिलती है।

HPV टीकाकरण:

- यह HPV संक्रमण को रोकता है जो कैंसर या जननांग मस्सों में बदल सकता है।
- यदि 9-26 वर्ष के आयु वर्ग के बीच दिया जाए तो HPV टीकाकरण अधिक प्रभावशाली होता है।
- एक बार जब किसी व्यक्ति को HPV हो जाता है, तो टीका उतना प्रभावी नहीं हो सकता है।
- HPV टीका गर्भावस्था के दौरान नहीं दिया जाता है।

123. Google भारतीय ऐप्स को अस्थायी रूप से बहाल करने पर सहमत- द हिंदू

प्रासंगिकता: विज्ञान और प्रौद्योगिकी- विकास और रोजमर्रा की जिंदगी में उनके अनुप्रयोग और प्रभाव।

समाचार:

- **Google** उन द**र्जनों ऐप्स** को बहाल कर रहा है, जिन्हें **ऐप भुगतान** पर कंपनी के **प्लेटफ़ॉर्म शुल्क** का विरोध करने के कारण **1 मार्च** को **कंपनी** द्वारा हटा दिया गया था।

प्रीलिम्स टेकअवे

- OTT
- सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021

मुख्य बिंदु

- वे **सुप्रीम कोर्ट** में लंबित अपीलों के साथ **डेवलपर्स के ऐप्स** को अस्थायी रूप से बहाल कर रहे हैं
- **"Google** अपने **व्यवसाय मॉडल** को लागू करने और लागू करने के अपने **अधिकार** को **बरकरार** रखता है, जैसा कि **विभिन्न अदालतों** में स्थापित किया गया है।

ओवर-द-टॉप (OTT) प्लेटफार्म

- **OTT प्लेटफॉर्म ऑडियो और वीडियो होस्टिंग** और **स्ट्रीमिंग सेवाएं** हैं जो **कंटेंट होस्टिंग प्लेटफॉर्म** के रूप में शुरू हुईं
  - लेकिन जल्द ही **लघु फिल्मों, फीचर फिल्मों, वृत्तचित्रों** और **वेब-श्रृंखलाओं** के **निर्माण** और **रिलीज** में भी शामिल हो गए।
- ये **प्लेटफ़ॉर्म** विभिन्न प्रकार की **सामग्री** प्रदान करते हैं और **कृत्रिम बुद्धिमत्ता** का उपयोग करके **उपयोगकर्ताओं** को उस **सामग्री** का सुझाव देते हैं जिसे वे **प्लेटफ़ॉर्म** पर अपने पिछले **दर्शकों** के आधार पर देख सकते हैं।

सेवाएँ:

- अधिकांश **OTT प्लेटफॉर्म** आम तौर पर **कुछ सामग्री मुफ्त** में पेश करते हैं और **प्रीमियम सामग्री** के लिए **मासिक सदस्यता शुल्क** लेते हैं जो **आम तौर** पर अन्यत्र उपलब्ध नहीं है।
- वर्ष 2022 में **केंद्र सरकार** ने **OTT प्लेटफार्मों** को विनियमित करने के लिए **सूचना प्रौद्योगिकी** (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) **नियम 2021** को अधिसूचित किया।

124. एंथ्रोपिक का नया क्लाउड 3 AI मॉडल -द इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: विज्ञान और प्रौद्योगिकी- विकास और रोजमर्रा की जिंदगी में उनके अनुप्रयोग और प्रभाव।

समाचार:

- **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्ट-अप एंथ्रोपिक** ने **AI मॉडल** के अपने **नवीनतम परिवार** की घोषणा की जिसे **क्लाउड 3** कहा जाता है

प्रीलिम्स टेकअवे

- क्लाउड 3 हाइकु
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

क्लाउड: शक्तिशाली AI भाषा मॉडल

- क्लाउड एंथ्रोपिक के उन्नत AI मॉडल का एक परिवार है, जो पाठ, आवाज और दस्तावेजों को समझने और प्रतिक्रिया देने में सक्षम है।
- ये मॉडल प्रासंगिक और संदर्भ-जागरूक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करने में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं, गति और गुणवत्ता में कई प्रतिस्पर्धियों से आगे निकल जाते हैं।

विभिन्न आवश्यकताओं के लिए तीन मॉडल:

- **क्लॉड 3 हाइकु** : यह सबसे लाइटवेट और प्रतिक्रियाशील विकल्प है, उन परिदृश्यों के लिए आदर्श जहां तत्काल उत्तर महत्वपूर्ण होते हैं।
- **क्लाउड 3 सॉनेट:** शक्ति और सामर्थ्य के बीच संतुलन बनाते हुए, सॉनेट विभिन्न उपयोग के मामलों के लिए मजबूत क्षमताएं प्रदान करता है और वर्तमान में मुफ्त क्लाउड AI चैटबॉट के माध्यम से पहुंच योग्य है।
- **क्लॉड 3 ओपस** : फैमिली का सबसे पावरफुल सदस्य, ओपस बेहतर प्रदर्शन का दावा करता है और जटिल कार्यों को संभाल सकता है।
- हालाँकि, इसके लिए एंथ्रोपिक की वेबसाइट पर सशुल्क सदस्यता की आवश्यकता होती है।
- **उन्नत क्षमताएं:** सभी तीन मॉडलों में अब 2,000,000-टोकन विंडो की सुविधा है, जिससे संभावित रूप से प्रदर्शन, सटीकता और उपयोगकर्ता संकेतों में अधिक जानकारी को संभालने की क्षमता में सुधार होगा।

125. नासा उपग्रह ने बादलों में अजीब छिद्रों को कैप्चर किया - टाइम्स ऑफ इंडिया

प्रासंगिकता: विश्व के भौतिक भूगोल की अलग-अलग विशेषताएँ।

प्रीलिम्स टेकअवे
- अल्टोक्यूम्यलस क्लाउड्स
- कैवम क्लाउड्स

समाचार:

- नासा के टेरा उपग्रह के अनुसार, बादलों में छिद्रों के केंद्र में बर्फ के क्रिस्टल वर्षा की टेढ़ी-मेढ़ी धारियाँ बनाते हैं जो जमीन से नहीं टकराती हैं।

कैवम क्लाउड्स:

- इन बादलों को **"होल-पंच क्लाउड** या **फॉलस्ट्रेक होल"** के रूप में भी जाना जाता है।

बादल (क्लाउड्स) का निर्माण

- ये तब बनते हैं जब हवाई जहाज **अल्टोक्यूम्यलस बादलों** की परतों से गुजरते हैं, जो **मध्य स्तर** के बादल होते हैं जिनमें **सुपरकूल पानी** की **बूंदें** होती हैं (पानी शून्य तापमान से नीचे लेकिन फिर भी तरल रूप में होता है)।
- जैसे-जैसे विमान आगे बढ़ता है, **रुद्धोष्म विस्तार नामक** एक प्रक्रिया के कारण पानी की **बूंदें बर्फ** के **क्रिस्टल** में जम जाती हैं।
- ये **बर्फ** के **क्रिस्टल** अंततः बहुत भारी हो जाते हैं और **बादल की परत** से बाहर गिर जाते हैं, जिससे बादलों में एक होल बन जाता है।
- इनका निर्माण तब होता है जब **विमान अपेक्षाकृत तीव्र कोण** पर गुजरते हैं।

आल्टोक्यूम्यलस क्लाउड्स

- ये आम तौर पर समूहों में या एक साथ गुच्छित ढेर में पाए जाते हैं।
- वे **क्षोभमंडल** की मध्य परत में पाए जाते हैं, जो **सिरोक्यूम्यलस** से नीचे और उनके **क्यूम्यलस** और **स्ट्रैटोक्यूम्यलस समकक्षों** से अधिक ऊंचे होते हैं।
- **मैकेरल आकाश** शब्द **अल्टोक्यूम्यलस** (और सिरोक्यूम्यलस) बादलों के लिए भी आम है जो **मछली के शल्क** के समान पैटर्न प्रदर्शित करते हैं।

126. WHO ने डोलटेग्रेविर के प्रति बढ़ती HIV दवा प्रतिरोध पर प्रकाश डाला- डाउन टू अर्थ

प्रासंगिकता: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे
- यौन संचारित संक्रमण
- HIV

समाचार:

- **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** की एक नई रिपोर्ट में **HIV रोगियों** के बीच **एंटीरेट्रोवायरल दवा डोलटेग्रेविर (DTG)** के प्रति प्रतिरोध बढ़ रहा है।

डोलटेग्रेविर (DTG):

- यह एक एंटीवायरल दवा है जिसका उपयोग **ह्यूमन इम्युनोडेफिशिएंसी वायरस (HIV)** संक्रमण के इलाज के लिए अन्य दवाओं के साथ किया जाता है, यह वायरस **एक्वायर्ड इम्यूनोडिफीसिअन्सी सिंड्रोम** (AIDS) का कारण बन सकता है।
- **डोलटेग्रेविर HIV इंटीग्रेज़ इनहिबिटर** नामक दवाओं के एक वर्ग में है।
- यह रक्त में **HIV** की मात्रा को कम करके और **प्रतिरक्षा कोशिकाओं** की संख्या को बढ़ाकर काम करता है।
- हालाँकि **डोलटेग्रेविर HIV** का इलाज नहीं करता है , लेकिन अन्य दवाओं के साथ इसका उपयोग करने से **एड्स** और **HIV** से संबंधित बीमारियों जैसे गंभीर **संक्रमण या कैंसर** के विकास की संभावना कम हो सकती है।
- **WHO** ने सभी **जनसंख्या समूहों** के लिए पसंदीदा पहली और दूसरी **पंक्ति के HIV** उपचार के रूप में **डोलटेग्रेविर** के उपयोग की सिफारिश की है।
- यह वर्तमान में उपयोग में आने वाली अन्य दवाओं की तुलना में अधिक प्रभावी, लेने में आसान और कम दुष्प्रभाव वाली है।
- डोलटेग्रेविर के सामान्य दुष्प्रभावों में शामिल हो सकते हैं:
  - सिरदर्द;
  - थकान
  - अनिद्रा
  - कुछ **दुष्प्रभाव गंभीर** हो सकते हैं इनमें गंभीर **त्वचा** पर चकत्ते और **एलर्जी प्रतिक्रियाएं, यकृत** की समस्याएं और दवाओं की परस्पर क्रिया शामिल हैं।

HIV /एड्स

- **एड्स HIV** के कारण होने वाली एक **दीर्घकालिक,** संभावित **जीवन-घातक** स्थिति है ।
- **HIV शरीर** की **प्रतिरक्षा प्रणाली** पर हमला करता है, जिससे व्यक्ति अन्य **संक्रमणों और बीमारियों** के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है।
- यदि **HIV** का इलाज न किया जाए तो यह **एड्स** का कारण बन सकता है।

ट्रांसमिशन:

- यह एक **यौन संचारित संक्रमण (STI)** है, जो संक्रमित रक्त के संपर्क से, **अवैध इंजेक्शन नशीली दवाओं** के उपयोग या सुइयों को साझा करने से भी फैल सकता है।
- यह **गर्भावस्था**, **प्रसव** या **स्तनपान** के दौरान **मां से बच्चे** में भी फैल सकता है।

127. याउंडे घोषणा: अफ्रीका में मलेरिया से होने वाली मौतों को समाप्त करने की प्रतिज्ञा- डाउन टू अर्थ

प्रासंगिकता: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे

- याउंडे घोषणा
- WHO

समाचार:

- **मलेरिया** से सबसे अधिक प्रभावित **अफ्रीकी देशों** के **स्वास्थ्य नेताओं** ने **मलेरिया** से होने वाली मौतों को पूरी तरह खत्म करने की कसम खाते हुए **याओंडे** घोषणा में शामिल हो गए।

मुख्य बिंदु

- **WHO** और **कैमरून** द्वारा सह-आयोजित **याउंडे** में एक सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षरित इस समझौते में **विश्व स्तर** पर **मलेरिया का सबसे बड़ा बोझ** उठाने वाले **ग्यारह अफ्रीकी देश** शामिल हैं।
- इन देशों ने मजबूत नेतृत्व, **मलेरिया-रोधी कार्यक्रमों** के लिए **राष्ट्रीय वित्त पोषण में वृद्धि, डेटा प्रौद्योगिकियों** में निवेश और **नवीनतम मलेरिया नियंत्रण** तरीकों को लागू करने का वादा किया।
- इसके अतिरिक्त, उन्होंने **राष्ट्रीय** और **स्थानीय स्तर** पर **स्वास्थ्य** देखभाल के बुनियादी ढांचे, कर्मियों और कार्यक्रम कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता जताई।
- विभिन्न क्षेत्रों में **सहयोग** और **वित्त पोषण, अनुसंधान** और **नवाचार** के लिए साझेदारी स्थापित करने पर भी जोर दिया गया।

- घोषणा पर हस्ताक्षर करके, ये **देश मलेरिया** से होने वाली मौतों को उल्लेखनीय रूप से कम करने और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए खुद को जवाबदेह बनाने के प्रति अपने समर्पण को मजबूत करते हैं।

128. सरकार ने फार्मा कंपनियों के लिए मार्केटिंग कोड जारी किया- द हिंदू

प्रासंगिकता: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे
- UCPMP
- फार्मास्युटिकल विपणन प्रथाओं के लिए आचार समिति

समाचार:
- फार्मास्यूटिकल्स विभाग फार्मास्युटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेज (UCPMP) 2024 के लिए **यूनिफ़ॉर्म कोड** जारी किया

मुख्य बिंदु
- इसमें दवाओं के लिए **"सुरक्षित"** और **"नए"** शब्दों के उपयोग के नियमों को निर्दिष्ट किया गया है, और कहा गया है कि **चिकित्सा प्रतिनिधियों** को कोई **प्रलोभन** या **छल** नहीं करना चाहिए।
  - साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए, और किसी स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर तक पहुंच के लिए उन्हें किसी भी आड़ में भुगतान नहीं करना चाहिए।
- केवल **सतत चिकित्सा शिक्षा (CME)** के लिए स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के साथ **फार्मास्युटिकल उद्योग** की भागीदारी की अनुमति दी जानी चाहिए
  - दिशानिर्देशों के एक अच्छी तरह से परिभाषित, पारदर्शी और सत्यापन योग्य सेट के माध्यम से, और विदेशी स्थानों में ऐसे आयोजनों का संचालन समान संहिता द्वारा निषिद्ध है।
- **कंपनियों** या उनके **प्रतिनिधियों** को किसी भी बहाने से किसी भी स्वास्थ्य देखभाल **पेशेवर** या उनके **परिवार के सदस्यों** (तत्काल और विस्तारित दोनों) को नकद या **मौद्रिक अनुदान** का भुगतान नहीं करना चाहिए।
- नवीनतम **UCPMP** में यह भी कहा गया है कि **फार्मास्युटिकल कंपनियों** द्वारा भुगतान यात्रा, होटल में ठहरने आदि का लाभ स्वास्थ्य **पेशेवरों** या उनके **परिवार** के सदस्यों को नहीं दिया जाना चाहिए।
- **UCPMP** को सख्त अनुपालन के लिए प्रसारित किया जाना है, और सभी **संघों** से **फार्मास्युटिकल विपणन गतिविधिओं** के लिए एक आचार समिति गठित करने का अनुरोध किया गया है।
  - अपनी वेबसाइट पर एक समर्पित UCPMP पोर्टल स्थापित करें, और कोड के कार्यान्वयन के लिए आगे आवश्यक कदम उठाएं।
  - सभी **भारतीय फार्मास्युटिकल एसोसिएशनों** को **शिकायत दर्ज** करने की विस्तृत प्रक्रिया के साथ **UCPMP** को अपनी वेबसाइट पर **अपलोड** करना होगा, जो **फार्मास्यूटिकल्स विभाग** के **UCPMP पोर्टल** से जुड़ा होगा।

129. सरकार ने अश्लील सामग्री स्ट्रीम करने के लिए OTT प्लेटफार्मों को ब्लॉक किया- द हिंदू

प्रासंगिकता: आईटी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-प्रौद्योगिकी, जैव-प्रौद्योगिकी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित मुद्दों के क्षेत्र में जागरूकता।

प्रीलिम्स टेकअवे
- सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियम, 2023
- भारतीय दंड संहिता

समाचार:
- **सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय** ने **अश्लील** और **अभद्र सामग्री स्ट्रीम** करने वाले **18 OTT प्लेटफॉर्म** को ब्लॉक कर दिया है।
- इन प्लेटफार्मों से जुड़ी **उन्नीस वेबसाइटों**, **10 ऐप्स** और **57 सोशल मीडिया हैंडल** को भी ब्लॉक कर दिया गया है।

मुख्य बिंदु
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, **भारतीय दंड संहिता** और **महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व** (निषेध) **अधिनियम** के **उल्लंघन** के लिए विभिन्न **मध्यस्थों** के साथ **समन्वय** में कार्रवाई की गई है।
- मंत्रालय ने कहा कि अवरुद्ध किए गए ऐप्स में से सात **Google Play Store** पर होस्ट किए गए थे, जबकि तीन **Apple ऐप स्टो**र पर थे।
- **केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री** ने बार-बार **'रचनात्मक अभिव्यक्ति'** की **आड़ में अश्लीलता, अश्लीलता** और **दुर्व्यवहार का प्रचार** न करने के लिए **प्लेटफार्मों की जिम्मेदारी** पर जोर दिया है।

- **मंत्रालय** ने कहा कि **सामग्री** का एक **महत्वपूर्ण हिस्सा अश्लील** पाया गया और **महिलाओं** को **अपमानजनक** तरीके से चित्रित किया गया।

सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियम, 2023

- कोई भी **प्लेटफ़ॉर्म हानिकारक** अस्वीकृत **ऑनलाइन गेम** और **उनके विज्ञापनों** की अनुमति नहीं दे सकता।
- उन्हें भारत सरकार के बारे में गलत जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए, जैसा कि एक तथ्य-जाँच इकाई ने पुष्टि की है।
- **ऑनलाइन गेमिंग** प्रदान करने वाले **प्लेटफार्मों** को एक **स्व-नियामक निकाय (SRB)** के साथ **पंजीकरण** करना होगा जो यह निर्धारित करेगा कि **गेम "अनुमत"** है या नहीं।
- यदि आगामी तथ्य जांच इकाई द्वारा किसी भी जानकारी को नकली के रूप में चिह्नित किया जाता है,
  - **बिचौलियों** को इसे हटाने की आवश्यकता होगी, ऐसा न करने पर वे अपने सुरक्षित आश्रय को खोने का जोखिम उठाएंगे जो उन्हें **तीसरे पक्ष** की **सामग्री के खिलाफ** मुकदमेबाजी से बचाता है।

130. कर्नाटक सरकार ने रोडामाइन-B फूड कलर पर प्रतिबंध लगाया - द हिंदू

प्रासंगिकता: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे
- खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (FSS अधिनियम)
- केसर

समाचार:

- विश्लेषण के बाद **चेन्नई** में **स्टालों** से उठाए गए नमूनों में **रोडामाइन-B**, एक **औद्योगिक डाई** की उपस्थिति की पुष्टि होने के बाद **तमिलनाडु** ने **कॉटन कैंडी** या **कैंडी फ्लॉस** की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया।

मुख्य बिंदु

- **रोडामाइन-B** एक कपड़ा **डाई** है और **भोजन** में इसका उपयोग **स्वास्थ्य** पर भारी प्रभाव डालता है।
- **रोडामाइन-B** एक **फ्लोरोसेंट डाई** है जिसका उपयोग **सौंदर्य प्रसाधन, कपड़ा और चमड़ा उद्योगों** में किया जाता है।
- यह शानदार **गुलाबी, हरा** और **नीला रंग** देता है।
- दुर्भाग्य से, इसका उपयोग न केवल **कॉटन कैंडी** में खाद्य रंग भरने वाले एजेंट के रूप में किया जाता है, बल्कि मिठाइयों, विभिन्न **मंचूरियन वस्तुओं और पकौड़ों** की तैयारी और **चीनी भोजन** के लिए सॉस की तैयारी में भी किया जाता है।
- लंबे समय तक इसके सेवन से **एलर्जी** हो सकती है जो **होंठ, जीभ** के साथ-साथ **आंखों** में **जलन** के रूप में प्रकट हो सकती है और ऊपरी श्वसन एलर्जी का कारण भी बन सकती है।
- अध्ययनों से पता चला है कि **रोडामाइन-B कोशिका** मृत्यु का कारण बन सकता है।
- यह कोई खाद्य रंग नहीं है लेकिन **मानव शरीर** के लिए **विषैला** और **कैंसरकारी** है।
- FSSAI ने कुछ **खाद्य रंगों और स्वादों** को उपभोग के लिए सुरक्षित माना है।
- इनमें कैरेमल, राइबोफ्लेविन (लैक्टोफ्लेविन), केसर, एनाट्टो, करक्यूमिन (हल्दी), कैरोटीन और कैरोटीनॉयड आदि शामिल हैं।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI)

- यह **खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम,** 2006 (FSS अधिनियम) के तहत स्थापित एक **स्वायत्त वैधानिक** निकाय है।
- का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय **FSSAI** का **प्रशासनिक मंत्रालय** है।

समारोह:

- खाद्य सुरक्षा के **मानकों और दिशानिर्देशों** को निर्धारित करने के लिए विनियम तैयार करना।
- खाद्य व्यवसायों के लिए FSSAI **खाद्य सुरक्षा लाइसेंस और प्रमाणन** प्रदान करना।
- खाद्य व्यवसायों में प्रयोगशालाओं के लिए प्रक्रिया और दिशानिर्देश निर्धारित करना।

131. पीलीभीत में FMD रोग से दुधारू पशु प्रभावित - टाइम्स ऑफ इंडिया

प्रासंगिकता: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे
- खुरपका-मुँहपका रोग

समाचार:

- **खुरपका-मुंहपका रोग (FMD)** ने पीलीभीत जिले में लगभग **60% दुधारू मवेशियों** को प्रभावित किया है।
- इसके अलावा, आवारा मवेशियों को भी अत्यधिक संक्रामक बीमारी से संक्रमित होने का खतरा है।

खुरपका-मुंहपका रोग (FMD) पशुधन को खतरा

- खुरपका-मुंहपका रोग (FMD) एक गंभीर और **संक्रामक वायरल बीमारी** है जो मुख्य रूप से गाय, भेड़, सूअर और बकरियों जैसे खेत जानवरों को प्रभावित करती है।
- यह आसानी से फैलता है और पशुधन उत्पादन और पशुओं और पशु उत्पादों के **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार** पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकता है।

महत्वपूर्ण बिंदु:

- **FMD** केवल **कटे-खुर** वाले जानवरों को प्रभावित करता है, **घोड़े, कुत्ते** या **बिल्ली** जैसे पालतू जानवरों को नहीं।
- वायरस के विभिन्न प्रकार होते हैं, और किसी एक की प्रतिरक्षा दूसरों से रक्षा नहीं करती है।
- इस बीमारी के कारण बुखार होता है, **मुंह और खुरों** में **छाले** हो जाते हैं और अक्सर ठीक हो चुके **जानवरों** में भी **कमजोरी और उत्पादन** में कमी आ जाती है।
- **FMD** से **युवा जानवरों** के मरने की संभावना अधिक होती है, जबकि **वयस्क आमतौर** पर जीवित रहते हैं।
- FMD **विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन** द्वारा आधिकारिक दर्जा प्राप्त पहली बीमारी थी।

132. पेट्रोलियम मंत्री ने इथेनॉल 100 ईंधन लॉन्च किया- पीआईबी

प्रासंगिकता: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन।

प्रीलिम्स टेकअवे
- इथेनॉल
- जैव ईंधन

समाचार:

- केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री ने **इंडियन ऑयल रिटेल आउटलेट** पर एक क्रांतिकारी ऑटोमोटिव **ईंधन 'एथनॉल 100'** लॉन्च किया।

इथेनॉल 100 का परिचय: हरित भविष्य के लिए एक जैव ईंधन

- **इथेनॉल 100** एक अभूतपूर्व ईंधन है जो पूरी तरह से **मकई या गन्ने** जैसे **नवीकरणीय स्रोतों** से बनाया गया है।

इस जैव ईंधन का उद्देश्य परिवहन उद्योग में क्रांति लाना :

- **जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना** : इथेनॉल 100 गैसोलीन का एक स्थायी विकल्प प्रदान करता है, जो हमें सीमित जीवाश्म ईंधन भंडार पर निर्भरता से दूर जाने में मदद करता है।
- **पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना** : गैसोलीन की तुलना में, इथेनॉल 100 कम ग्रीनहाउस गैसों का उत्पादन करता है, जो स्वच्छ वातावरण में योगदान देता है।
- **राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ तालमेल:** यह पहल वर्ष 2025-26 तक गैसोलीन (E20) में 20% इथेनॉल मिश्रण प्राप्त करने, आयातित तेल पर निर्भरता कम करने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करती है।

भविष्य के लिए एक ईंधन

- **इथेनॉल 100 टिकाऊ प्रौद्योगिकियों** और **कार्बन उत्सर्जन (डीकार्बोनाइजेशन)** को कम करने के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- इसकी **बहुमुखी प्रतिभा** एक और फायदा है इसका उपयोग विभिन्न वाहनों में किया जा सकता है, जिसमें **गैसोलीन, इथेनॉल** या **दोनों** के **मिश्रण** पर चलने के लिए **डिज़ाइन** किए गए **फ्लेक्स-फ्यूल वाहन (FFV)** शामिल हैं।
- यह **उचित बुनियादी ढांचे** के विकास के साथ मिलकर, **इथेनॉल 100** को भविष्य के लिए एक आशाजनक **मुख्यधारा ईंधन विकल्प** के रूप में स्थापित करता है।

133. SAKH ऐप: गगनयान दल की सहायता के लिए बहुउद्देश्यीय ऐप - द हिंदू

प्रासंगिकता: विज्ञान और प्रौद्योगिकी- विकास और रोजमर्रा की जिंदगी में उनके अनुप्रयोग और प्रभाव।

प्रीलिम्स टेकअवे
- इसरो
- SAKHI

समाचार:

- **तिरुवनंतपुरम** के **थुम्बा** में **भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO)** की सुविधा, **विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (VSSC)** ने एक **बहुउद्देश्यीय ऐप** विकसित किया है।

- यह गगनयान **अंतरिक्ष उड़ान मिशन** पर **अंतरिक्ष यात्रियों** को महत्वपूर्ण तकनीकी जानकारी देखने या एक दूसरे के साथ संचार करने जैसे कई कार्यों को पूरा करने में मदद करेगा।

मुख्य बिंदु

- **अंतरिक्ष-जनित सहायक और क्रू इंटरेक्शन (SAKHI)** के लिए **नॉलेज ह**ब, अन्य चीजों के अलावा, **अंतरिक्ष यात्रियों** के **स्वास्थ्य की निगरानी** करेगा, उन्हें पृथ्वी से जुड़े रहने में मदद करेगा और यहां तक कि उन्हें उनके **आहार कार्यक्रम** के बारे में भी सचेत करेगा।
- अंतरिक्ष सुविधा ने **SAKHI** की विशेषता वाले कस्टम-निर्मित, हाथ से पकड़े जाने वाले **स्मार्ट डिवाइस** के **इंजीनियरिंग मॉडल** का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है।
- एक उड़ान मॉडल का विकास प्रगति पर है।
- **VSSC** एप्लिकेशन को **चालक दल** के लिए एक **अपरिहार्य सहायक** के रूप में वर्णित करता है।
- SAKHI यह सुनिश्चित करेगी कि सभी आवश्यक डेटा उनकी फिंगरटिप पर हो
- इसरो **वर्ष 2025** में **गगनयान मिशन लॉन्च** करने की उम्मीद कर रहा है।

134. डेंगू का टीका वर्ष 2026 के मध्य तक बाज़ार में आ सकता है: IIL - द हिंदू

प्रासंगिकता: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे
- डेंगू
- क्यासनूर फारेस्ट रोग (KFD)।

समाचार:

- **डेंगू** का **टीका व्यावसायिक तौर** पर **वर्ष 2026** के मध्य तक उपलब्ध हो सकता है।
- **इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड** ने **वैक्सीन की सुरक्षा निर्धारित** करने के लिए **क्लिनिकल परीक्षण** का **पहला चरण** पूरा कर लिया है।

मुख्य विचार

- **IIL** वर्ष 1982 में स्थापित **राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड** की पूर्ण **स्वामित्व वाली** सहायक कंपनी है।
- "कंपनी जीका वायरस और **क्यासानूर वन रोग (KFD)** के लिए एक **टीका** भी विकसित कर रही है।
- यह वायरस, जिसे पहली बार **वर्ष 1957** में **कर्नाटक के जंगलों** में पहचाना गया था, बताया जाता है कि तब से इसने **सालाना 400 से 500 लोगों** को संक्रमित किया है।
- मनुष्यों में संचरण **संक्रमित टिक** के काटने से या **संक्रमित जानवर**, विशेष रूप से **बीमार या मृत बंदर** के संपर्क के कारण होता है
- यह बीमारी अभी तक कर्नाटक और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों तक ही सीमित है।

डेंगू

- डेंगू एक मच्छर जनित **उष्णकटिबंधीय रोग** है जो **डेंगू वायरस** (जीनस फ्लेविवायरस) के कारण होता है।
- यह **जीनस एडीज,** मुख्य रूप से **एडीज एजिप्टी** के भीतर **मादा मच्छर** की कई **प्रजातियों** द्वारा फैलता है।
- यह **मच्छर चिकनगुनिया, पीला बुखार** और **जीका संक्रमण** भी फैलाता है।
- **डेंगू** का कारण बनने वाले वायरस के **4 अलग-अलग** (DEN-1, DEN-2, DEN-3 और DEN-4)**,** लेकिन बारीकी से संबंधित, **सीरोटाइप** (सूक्ष्मजीवों की एक प्रजाति के भीतर अलग-अलग समूह, जिनकी सभी विशेषताएं समान होती हैं) हैं।

135. एनवीडिया का प्रोजेक्ट GR00T क्या है -द हिंदू

प्रासंगिकता:आईटी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-प्रौद्योगिकी, जैव-प्रौद्योगिकी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित मुद्दों के क्षेत्र में जागरूकता।

प्रीलिम्स टेकअवे
- प्रोजेक्ट GR00T
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

समाचार:

- AI चिप **लीडर एनवीडिया** ने **प्रोजेक्ट GR00T** या **जनरलिस्ट रोबोट 00** टेक्नोलॉजी की घोषणा की, जो **ह्यूमनॉइड रोबोट** के विकास में क्रांति लाने का सुनिश्चित करता है।
- इस परियोजना का उद्देश्य **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)** का उपयोग करके **ह्यूमनॉइड रोबोट** को **मानव** जैसी समझ और गति के साथ सशक्त बनाना है।

प्रोजेक्ट GR00T (जनरलिस्ट रोबोट 00 टेक्नोलॉजी)

- यह एक **AI सिस्टम** है जिसे **ह्यूमनॉइड रोबोट** के **मस्तिष्क** के रूप में डिज़ाइन किया गया है।
- यह इन **रोबोटों** को **सीखने** और **वास्तविक दुनिया** के साथ बातचीत करने में मदद करने के लिए **प्राकृतिक भाषा** को समझने और **मानवीय कार्यों** की नकल करने सहित **तकनीकों** के संयोजन का उपयोग करता है।
- लक्ष्य उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से मानव जैसी क्षमताएं प्रदान करना है।
- **GR00T** रोबोट **दो तरह** से सीखते हैं: **मानवीय क्रियाओं** को देखकर और उनकी नकल करके (जैसे कोई छात्र शिक्षक की नकल करता है)
  - **कार्यों** को स्वयं करने का सर्वोत्तम तरीका जानने के लिए **NVIDIA Isaac Lab** नामक एक विशेष कार्यक्रम का उपयोग करना।

136. MeitY/NIXI ने भाषानेट पोर्टल का सफलतापूर्वक अनावरण किया- पीआईबी

प्रासंगिकता: विज्ञान और प्रौद्योगिकी- विकास और रोजमर्रा की जिंदगी में उनके अनुप्रयोग और प्रभाव।

प्रीलिम्स टेकअवे
- नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया

समाचार:
- **नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NIXI)** को आगामी **यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस (UA)** दिवस के लिए **भाषानेट पोर्टल** के लॉन्च की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है।

NIXI: अपने भारतीय इंटरनेट को तेज़ और किफायती बनाए रखना
- **वर्ष 2003** में स्थापित, **NIXI** एक **गैर-लाभकारी संगठन** है जो **भारत** के **इंटरनेट बुनियादी ढांचे** में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- ये विदेशों में जाने के बजाय, देश के भीतर **भारतीय इंटरनेट ट्रैफ़िक** को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं।
- इसका मतलब **इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISP)** के लिए **तेज इंटरनेट (कम विलंबता)** और सस्ती लागत है क्योंकि उन्हें उतनी **अंतरराष्ट्रीय बैंडविड्थ** के लिए भुगतान नहीं करना पड़ता है।
- NIXI भारत में इंटरनेट को अधिक सुलभ बनाने में भी भूमिका निभाता है।
- इसके अतिरिक्त, ये **इंटरनेट नाम और नंबरों** के लिए **भारतीय रजिस्ट्री (IRINN)** का संचालन करते हैं, जो देश के भीतर विभिन्न इंटरनेट नेटवर्क को जोड़ने में मदद करता है।

सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस: इंटरनेट को समावेशी बनाना
- यह खंड एक अलग पहल, **सार्वभौमिक स्वीकृति (UA) दिवस** के बारे में बात करता है।
- प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला यह एक **वैश्विक** प्रयास है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि **इंटरनेट** पर सभी **भाषाओं और लिपियों** का निर्बाध रूप से उपयोग किया जा सके।
- इसका मतलब है कि हर किसी के पास **ईमेल पते और वेबसाइट डोमेन** नाम हो सकते हैं जो उनकी **भाषा और पहचान** को दर्शाते हैं, और अधिक **समावेशी ऑनलाइन** अनुभव को बढ़ावा देते हैं।

137. खगोलविदों ने कॉस्मिक कैन्नीबालिस्म तारों की खोज की - टाइम्स ऑफ इंडिया

प्रासंगिकता: विज्ञान और प्रौद्योगिकी- विकास और रोजमर्रा की जिंदगी में उनके अनुप्रयोग और प्रभाव।

प्रीलिम्स टेकअवे
- ट्विन स्टार

समाचार:
- **पृथ्वी** और उ**सके साथी ग्रह** वाले **सौर मंडल** ने अपने **4.5 अरब वर्षों** के दौरान **उल्लेखनीय स्थिरता** दिखाई है

स्टार्स गॉन वाइल्ड: डिवोरिंग प्लैनेट्स इन देयर प्राइम
- समान समझे जाने वाले **जुड़वां तारों** का अध्ययन करने वाले **वैज्ञानिकों को असंतुलित रासायनिक संरचना** के साथ एक आश्चर्यजनक संख्या मिली।
- इससे पता चलता है कि सितारों में से एक ने **ग्रहों या ग्रह निर्माण खंडों** को निगल लिया होगा!
- आम तौर पर, जुड़वां तारे एक ही रासायनिक फिंगरप्रिंट साझा करते हैं क्योंकि वे एक ही ब्रह्मांडीय धूल के बादल से बनते हैं।
- लेकिन जांच की गई **91 जोड़ियों** में से लगभग **8%** में, एक तारे में **लोहे, निकल** और **टाइटेनियम** जैसे तत्वों का **उच्च स्तर** दिखा, जो एक **भस्म चट्टानी दुनिया** का संकेत देता है।
- ये फ़ास्टिंग सितारे आश्चर्यजनक रूप से यंग और हेल्थी थे, हमारे भविष्य के लाल विशाल सूर्य की तरह अपने जीवन के अंत के करीब नहीं थे।
- इस "**कॉस्मिक कैन्नीबालिस्म**" के पीछे कल्प्रिट किसी बड़े ग्रह या गुज़रते तारे से गुरुत्वाकर्षण का झटका हो सकता है, जो एक असहाय ग्रह को उसके हंगर तारे के रास्ते में डाल देता है।

- इस खोज से पता चलता है कि **ग्रह प्रणालियाँ** पहले की तुलना में अधिक अव्यवस्थित हैं और **ग्रह संभावित** रूप से नष्ट हो सकते हैं या पूरे निगल जा सकते हैं।
- अपेक्षा से अधिक **होमलेस ग्रहों** के होने से इन **कॉस्मिक रिफ्यूजी** की तलाश खगोल विज्ञान में एक नई सीमा बन सकती है!

138. केरल ने केंद्र की स्मार्ट मीटर योजना को खारिज किया - इंडियन एक्सप्रेस

प्रीलिम्स टेकअवे
- स्मार्ट मीटर राष्ट्रीय कार्यक्रम
- बिजली ग्रिड

प्रासंगिकता: बुनियादी ढांचा: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़कें, हवाई अड्डे, रेलवे आदि।

समाचार:
- **स्मार्ट बिजली मीटर** के **रोलआउट** के लिए एक **वैकल्पिक मॉडल** की ओर **केरल** का कदम, प्रभावी रूप से केंद्र की **3 लाख करोड़ रुपये** की **स्मार्ट मीटर परियोजना** को खत्म कर रहा है
- यह **केंद्र सरकार** की उस योजना के कार्यों में एक विस्तार के रूप में आता है जिसका **लक्ष्य मार्च 2025** तक सभी घरों में **250 मिलियन पारंपरिक मीटरों** को स्मार्ट मीटर से बदलना है।

स्मार्ट मीटर: भारत के लिए एक पावर अपग्रेड
- **एक मीटर** जो न केवल आपके **बिजली** के उपयोग को ट्रैक करता है बल्कि **वोल्टेज के स्तर** पर भी नजर रखता है और **बिजली कंपनी** को अपडेट भेजता है।
- **भारत सरकार पारंपरिक मीटरों** को इन **उच्च तकनीक** वाले उपकरणों से बदलने की एक बड़ी पहल पर जोर दे रही है।
- इस **"स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम" (SMNP)** का लक्ष्य पूरे देश में **250 मिलियन स्मार्ट मीटर** स्थापित करना है।

लाभ
- उपभोक्ताओं के लिए, **स्मार्ट मीटर** उनके बिजली उपयोग में **एक विंडो** प्रदान करते हैं, जिससे वे खपत को **ट्रैक** कर सकते हैं और अपनी आदतों को समायोजित करके संभावित रूप से पैसे बचा सकते हैं।
- बिजली कंपनियों के लिए, **स्मार्ट मीटर गेम-चेंजर** हैं।
- ये **बिलिंग सटीकता** में सुधार कर सकते हैं, **मीटर रीडिंग लागत** को कम कर सकते हैं और यहां तक कि **समग्र बिजली मांग** को प्रबंधित करने में भी मदद कर सकते हैं।
- साथ ही, ये **मीटर एक केंद्रीय प्रणाली** से जुड़ते हैं, जिससे घाटे को कम करने और **बिजली कंपनियों** के **राजस्व** को बढ़ाने में मदद मिलती है।
- कुल मिलाकर, **स्मार्ट मीटर रोलआउट भारत** में **अधिक कुशल और विश्वसनीय बिजली** क्षेत्र की दिशा में एक कदम है।

139. ICCC: अनुकूलित समाधानों के लिए एकीकृत फार्म डेटा डैशबोर्ड -इंडियन एक्सप्रेस

प्रीलिम्स टेकअवे
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
- कृषि ICCC

प्रासंगिकता: देश के विभिन्न हिस्सों में प्रमुख फसल-फसल पैटर्न, - विभिन्न प्रकार की सिंचाई और सिंचाई प्रणाली, कृषि उपज का भंडारण, परिवहन और विपणन और मुद्दे और संबंधित बाधाएं; किसानों की सहायता में ई-प्रौद्योगिकी।

समाचार:
- इस महीने की शुरुआत में, **कृषि मंत्री** ने **नई दिल्ली** के कृषि भवन में स्थापित **कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र (ICCC)** का उद्घाटन किया।
- अधिकारियों ने **ICCC** को **कृषि पद्धतियों** की **उन्नति** के लिए **प्रौद्योगिकी** का लाभ उठाने में एक "महत्वपूर्ण स्थिति " बताया है।

कृषि ICCC
- यह एक **डिजिटल** हब है जो **किसानों को सशक्त** बनाने के लिए **उन्नत तकनीक** का उपयोग करता है।
- यह **कृषि** के लिए एक **केंद्रीय तंत्रिका तंत्र** की तरह काम करता है, जो **मौसम स्टेशनों, भूमि रिकॉर्ड** और पिछली **फसल के आंकड़ों** जैसे विभिन्न स्रोतों से ढेर सारी जानकारी एक साथ लाता है।
- **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस** का उपयोग करते हुए, **कृषि ICCC किसानों** को उनकी **स्थानीय भाषा** में व्यक्तिगत सलाह प्रदान करने के लिए इस विशाल विवरण का विश्लेषण करती है।

- एक **विशाल डैशबोर्ड** की कल्पना करें जो **फसल की पैदावार, वर्षा पैटर्न** और यहां तक कि संभावित सूखे के बारे में **वास्तविक समय** की जानकारी प्रदर्शित करता हो।
- यह बिल्कुल वही है जो **कृषि ICCC** प्रदान करता है, जिससे **किसानों** को **कृषि परिदृश्य** का **व्यापक दृष्टिकोण** मिलता है।
- इस सारी जानकारी को एक छत के नीचे लाकर, कृषि ICCC का लक्ष्य बेहतर निर्णय लेने और अंततः कृषि परिणामों में सुधार करके खेती में क्रांति लाना है।

140. भारत में 2015 से क्षय रोग (TB) के नए मामलों में 16% की गिरावट -द हिंदू

प्रासंगिकता: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे
- क्षय रोग
- राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम

समाचार:
- **तपेदिक** का शीघ्र पता लगाने और **उपचार शुरू** करने को **सुनिश्चित करने** के **भारत के प्रयासों** के साथ-साथ **सामुदायिक भागीदारी** के कई प्रयासों के परिणामस्वरूप **वर्ष 2015** के बाद से घटनाओं में **16%** की गिरावट आई है (प्रत्येक वर्ष नए **क्षय रोग (TB)** मामले सामने आते हैं) और **मृत्यु दर** में **18%** की कमी आई है।

मुख्य बिंदु
- **भारत** में घटना दर में गिरावट आई है और **मृत्यु दर वर्ष 2015** में **28 प्रति लाख जनसंख्या** से घटकर **वर्ष 2022** में **23 प्रति लाख जनसंख्या** हो गई है।
  - **केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय** द्वारा जारी **भारत क्षय रोग (TB) रिपोर्ट 2024** के अनुसार, देश ने इस बीमारी को खत्म करने के लिए **वर्ष 2025** का लक्ष्य रखा है।
- इसके अतिरिक्त, **2023** में अधिसूचित सभी **क्षय रोग (TB) मामलों** में से, लगभग **32% सूचनाएं निजी स्वास्थ्य** देखभाल क्षेत्र से आईं, जो पिछले वर्ष से **17%** की वृद्धि है।
- रिपोर्ट में जारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले **नौ वर्षों** में **वार्षिक आधार** पर **क्षय रोग (TB) मामलों** की समग्र अधिसूचना में **50%** से अधिक का सुधार हुआ है।
  - **उत्तर प्रदेश** में अधिसूचनाओं में सबसे अधिक उछाल (पिछले वर्ष की तुलना में **21%**) देखा गया।
- **राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP)** ने **राष्ट्रीय रणनीतिक योजना 2017-25** द्वारा निर्देशित **, क्षय रोग (TB) उन्मूलन** में तेजी लाने की दिशा में एक यात्रा शुरू की है।
- **रिपोर्ट** में कहा गया है, "**NTEP** ने **मुफ्त नैदानिक सेवाएं** प्रदान करना जारी रखा और **लगभग 1.89 करोड़ बलगम स्मीयर** परीक्षण किए गए है।"

141. स्काईरूट ने विक्रम 1 अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के चरण-2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया- द हिन्दू

प्रासंगिकता: आईटी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-प्रौद्योगिकी, जैव-प्रौद्योगिकी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित मुद्दों के क्षेत्र में जागरूकता।

प्रीलिम्स टेकअवे
- विक्रम-1 प्रक्षेपण यान
- इसरो

समाचार:
- अग्रणी अंतरिक्ष-तकनीकी कंपनी **स्काईरूट एयरोस्पेस** ने **आंध्र प्रदेश** के **श्रीहरिकोटा** में **सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (SDSC)** में **भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन** के **प्रणोदन परीक्षण** स्थल पर अपने **विक्रम -1 लॉन्च वाहन** के **चरण -2** का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।

मुख्य बिंदु
- लॉन्च वाहनों में कई चरण होते हैं।
- **चरण-2,** जिसे **कलाम-250** कहा जाता है, प्रक्षेपण यान की चढ़ाई के दौरान महत्वपूर्ण है क्योंकि यह **रॉकेट को पृथ्वी** के **वायुमंडल** के माध्यम से और **अंतरिक्ष** के निर्वात में ले जाएगा।
- **विक्रम-1** का प्रक्षेपण **भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र** के लिए एक ऐतिहासिक घटना होगी क्योंकि यह देश का पहला **निजी कक्षीय रॉकेट** प्रक्षेपण होगा।
- एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह **नवंबर 2022** में **स्काईरूट** द्वारा भारत के पहले निजी **रॉकेट विक्रम-S** के **उपकक्षीय प्रक्षेपण** का अनुसरण करता है।

- परीक्षण, जो **85 सेकंड** तक चला, ने **186 किलोन्यूटन (kN)** का चरम समुद्र-स्तर का जोर दर्ज किया, जो उड़ान में लगभग **235kN** के पूरी तरह से विस्तारित **वैक्यूम थ्रस्ट** में तब्दील हो जाएगा।
- **कलाम-250** एक **उच्च शक्ति** वाला **कार्बन मिश्रित रॉकेट मोटर** है, जो ठोस ईंधन और उ**च्च प्रदर्शन** वाले **एथिलीन-प्रोपलीन-डायन टेरपोलिमर (EPDM) थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम (TPS)** का उपयोग करता है।
- **स्टेज-2** में वाहन के **थ्रस्ट वेक्टर** नियंत्रण के लिए **उच्च परिशुद्धता इलेक्ट्रो-मैकेनिकल एक्चुएटर्स** के साथ एक **कार्बन एब्लेटिव फ्लेक्स नोजल** होता है, जो **रॉकेट को वांछित प्रक्षेपवक्र** प्राप्त करने में मदद करता है।
- **कलाम-250** में ठोस प्रणोदक को **सोलर इंडस्ट्रीज** द्वारा उनकी **नागपुर सुविधा** में संसाधित किया गया था।

142. विदेश में साइबर फ्रॉड केंद्रों से 250 नागरिकों को बचाया: विदेश मंत्रालय- द हिंदू

प्रासंगिकता: आईटी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-प्रौद्योगिकी, जैव-प्रौद्योगिकी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित मुद्दों के क्षेत्र में जागरूकता।

प्रीलिम्स टेकअवे
- फ़िशिंग
- मैलवेयर

समाचार:
- **केंद्र सरकार** कंबोडियाई अधिकारियों के साथ "**निकटता से सहयोग**" कर रही है और कंबोडिया से लगभग **250 भारतीयों** को बचाया है
- **विदेश मंत्रालय** ने कहा कि उन्हें **साइबर फ्रॉड और फर्जी ऑनलाइन भर्ती घोटालों** का लालच दिया गया था

साइबर फ्रॉड
- साइबर फ्रॉड आपराधिक गतिविधियां हैं जो **इंटरनेट पर या डिजिटल उपकरणों** का उपयोग करके लोगों, व्यवसायों या यहां तक कि सरकारों को पैसा कमाने के लिए धोखा देने के लिए की जाती हैं।
- इन अपराधों का उद्देश्य व्यवसाय, लोगों और सरकार की संवेदनशील जानकारी हासिल करना है।

साइबर फ्रॉड के तरीके
- **हैकिंग** : गुप्त जानकारी प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश करना।
- **फ़िशिंग:** लोगों की निजी जानकारी चुराने के लिए उन्हें फर्जी ईमेल, संदेशों या वेबसाइटों से धोखा देना।
- **मैलवेयर:** जानकारी चुराने या नियंत्रण लेने के लिए सॉफ़्टवेयर की स्थापना करता हूँ।
- **पहचान की चोरी** : फ्रॉड करने के लिए किसी की व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग करना।
- **सोशल इंजीनियरिंग:** लोगों से जानकारी प्राप्त करने के लिए उनका विश्वास हासिल करके उन्हें धोखा देना।

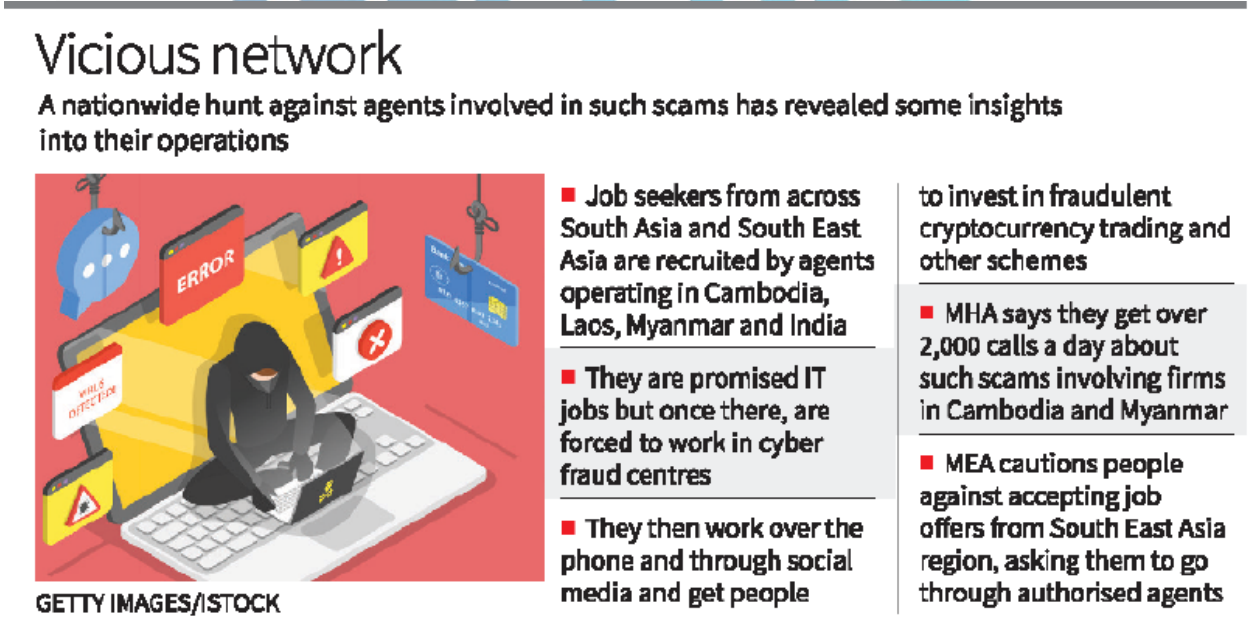

एडिटोरियल, जिस्ट, एक्सप्लेनेर

143. मॉरीशस, मालदीव और भारत के आपसी राजनैतिक सम्बन्ध - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: भारत और उसके पड़ोसी-संबंध।
प्रसंग:

- **मालदीव** और **मॉरीशस** में हाल के विकास **भारत के रणनीतिक हितों** को **भारतीय महासागर** में विशेष रूप से चीन की वार्ता में बढ़ती हुई उपस्थिति के प्रति सावधानी को पुनर्बलित करते हैं।

मालदीव मामला

- चीन समर्थक माने जाने वाले मालदीव के राष्ट्रपति ने नवंबर 2023 में सत्ता में आने के बाद भारत से मालदीव से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने का अनुरोध किया था।
- भारतीय "तकनीकी कर्मियों" की पहली टीम देश में तैनात तीन विमानन प्लेटफार्मों में से एक का कार्यभार संभालने के लिए मालदीव पहुंची।
- वे भारतीय सैन्य कर्मियों की जगह लेंगे जिनके पहले बैच को 10 मार्च तक द्वीप छोड़ना आवश्यक है।
- यह भारत और मालदीव के बीच 10 मई तक भारतीय सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने के समझौते के अनुरूप है।

मॉरीशस मामला

- मार्च 2015 में भारतीय प्रधान मंत्री की मॉरीशस यात्रा के बाद, भारत ने अगालेगा द्वीप पर "समुद्र और वायु परिवहन सुविधाओं में सुधार" के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- हाल ही में, भारत और मॉरीशस ने संयुक्त रूप से अगालेगा द्वीप पर एक हवाई पट्टी और जेटी का उद्घाटन किया, जिससे क्षेत्र में कनेक्टिविटी और सुरक्षा बढ़ेगी।
  - अगालेगा एक दो-द्वीप मॉरीशस निर्भरता है जो पोर्ट लुइस के उत्तर में 1,100 किमी और माले से 2,500 किमी दक्षिण-पश्चिम में है।
- उद्घाटन मॉरीशस को उसके विकास लक्ष्यों को पूरा करने और समुद्री सुरक्षा बढ़ाने में समर्थन देने की भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
- इससे मॉरीशस के विशाल 2.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर विशेष आर्थिक क्षेत्र की अधिक प्रभावी निगरानी हो सकेगी।
- इसके अलावा, यह मॉरीशस को समुद्री डकैती, आतंकवाद, नशीले पदार्थों और मानव तस्करी और अवैध और अनियमित मछली पकड़ने से बेहतर ढंग से निपटने में सक्षम बनाएगा।

हिंद महासागर में चीन की मौजूदगी

- हिंद महासागर में चीन की बढ़ती उपस्थिति भारत के रणनीतिक हितों, विशेषकर समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए चुनौतियां पैदा करती है।
  - चीन एकमात्र ऐसा देश है जिसका हिंद महासागर के छह द्वीपों अर्थात श्रीलंका, मालदीव, मॉरीशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस में से प्रत्येक में एक दूतावास है।
  - संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, भारत या फ्रांस जैसे किसी भी पारंपरिक खिलाड़ी के सभी छह देशों में दूतावास नहीं हैं।
- हिंद महासागर के द्वीप देशों के साथ चीन की राजनयिक, आर्थिक और सैन्य गतिविधियां क्षेत्र में उसके दीर्घकालिक इरादों के बारे में चिंताएं बढ़ाती हैं।
- विश्लेषकों ने आगे विस्तार की आशा व्यक्त की है, जिसके जवाब में भारत को अपनी साझेदारी और रणनीतिक पहल को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।

भारत की प्रतिक्रिया

- भारत चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए हिंद महासागर के द्वीप देशों के साथ सहयोग करने के रणनीतिक महत्व को पहचानता है।
- इसलिए, राजनयिक प्रयास हमारे रणनीतिक हितों और सुरक्षा सहयोग को आगे बढ़ाते हुए द्वीप देशों में घरेलू राजनीति के प्रबंधन पर केंद्रित हैं।
- मालदीव और मॉरीशस के साथ भारत का जुड़ाव हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक विकास को बनाए रखने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

144. प्लास्टिक से हिमालयी राज्यों कों खतरा - द हिंदू

प्रासंगिकता: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन।
प्रसंग:

- भारतीय हिमालय की **प्राचीन सुंदरता प्लास्टिक प्रदूषण, शहरीकरण में वृद्धि,** नई **औद्योगिक गतिविधियों** और बढ़ती पर्यटक आमद के कारण खतरे में है।
- यह **प्लास्टिक प्लेग क्षेत्र** के नाजुक **पारिस्थितिकी तंत्र** और लाखों **डाउनस्ट्रीम** के लिए महत्वपूर्ण **मीठे पानी** के स्रोतों के लिए खतरा है।

प्लास्टिक वेब:

- प्लास्टिक कचरा हर जगह है, पहाड़ों के शिखर से लेकर समुद्र की गहराई तक, यह हमारे अंदर तक पहुंच जाता है। अनुचित निपटान मिट्टी और पानी को प्रदूषित करता है, जिससे क्षेत्र की अद्वितीय जैव विविधता और निचले इलाकों में समुदायों को बनाए रखने वाले मीठे पानी के स्रोत खतरे में पड़ जाते हैं।
- पर्यटक अपनी छाप छोड़ रहे हैं।हिमालय की बढ़ती लोकप्रियता की कीमत चुकानी पड़ रही है, लोकप्रिय स्थल प्लास्टिक कचरे में डूब रहे हैं, जिसका खामियाजा रामसर स्थलों जैसे नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को भुगतना पड़ रहा है।

विनियमन:

- **पैची सॉल्यूशन:** : जबकि SWM और PWM नियम जैसे कानून मौजूद हैं, वे अक्सर पर्वतीय क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करने में विफल रहते हैं। प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध जैसी राज्य-स्तरीय पहल सराहनीय हैं लेकिन प्रवर्तन और बुनियादी ढांचे के निर्माण में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- **अपशिष्ट प्रबंधन अंतर** : नियमों के बावजूद, अपशिष्ट पृथक्करण और उचित निपटान अपर्याप्त है। अतिप्रवाहित लैंडफिल प्रदूषण में और योगदान करते हैं, जिससे संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र खतरे में पड़ जाता है।

समाधान ढूँढना: इस संकट से निपटने के लिए, हमें चाहिए:

- **निवेश और सशक्तिकरण** : क्षेत्र के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का आवंटन करें, बुनियादी ढांचे का निर्माण करें और कचरे को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए स्थानीय सरकारों को सशक्त बनाएं।
- **शिक्षा और भागीदारी** : सतत शिक्षा अभियानों और अपशिष्ट पृथक्करण पहल के माध्यम से जनता को शामिल करें।
- **पूलिंग संसाधन:** अपशिष्ट प्रबंधन बुनियादी ढांचे और संचालन को मजबूत करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन, अनुदान और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी निधि जैसी मौजूदा पहलों को मिलाएं।

निष्कर्ष

- साथ मिलकर काम करके, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि राजसी हिमालय प्राचीन सुंदरता का प्रतीक बना रहे, न कि प्लास्टिक प्रदूषण का।

145. भारत के परमाणु कार्यक्रम की स्थिति- द हिंदू

प्रासंगिकता: विज्ञान और प्रौद्योगिकी- विकास और रोजमर्रा की जिंदगी में उनके अनुप्रयोग और प्रभाव।
प्रसंग:

- **प्रधानमंत्री** ने **तमिलनाडु** के **कलपक्कम** में **मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन** में स्वदेशी **प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR)** की **कोर-लोडिंग** प्रक्रिया की शुरुआत देखी।

मुख्य बिंदु	प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR) का महत्व:
• भारत ने परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए ईंधन लोड करना शुरू किया **भारत का त्रि-चरणीय परमाणु कार्यक्रम:** • इसका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास हासिल करना है। • **चरण 1:** प्राकृतिक यूरेनियम द्वारा ईंधन वाले दबावयुक्त भारी जल रिएक्टरों (PHWR) का उपयोग करता है। • **चरण 2 (** वर्तमान): फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों (FBRs) के लिए प्लूटोनियम बनाने के लिए चरण 1 से खर्च किए गए ईंधन को पुन: संसाधित करता है। • **चरण 3** (भविष्य): उन्नत भारी जल रिएक्टरों (AHWRs) का उपयोग करता है जो थोरियम-प्लूटोनियम ईंधन जलाते हैं और विखंडनीय यूरेनियम-233 उत्पन्न करते हैं।	• यह भारत के परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण में प्रवेश का प्रतीक है। • भारत को वाणिज्यिक FBR संचालित करने वाला दूसरा देश (रूस के बाद) बना दिया गया है। • यह भारत की उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकी और शांतिपूर्ण अनुप्रयोगों के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। • FBR जटिल हैं और कई देशों ने तकनीकी चुनौतियों के कारण उन्हें छोड़ दिया है। • PFBR भविष्य के ईंधन के प्रजनन के लिए शुरुआत में थोरियम-यूरेनियम कंबल में परिवर्तित होने वाले मिश्रित ऑक्साइड (MOX) ईंधन का उपयोग करता है। • यह परियोजना भारत के थोरियम-आधारित परमाणु ईंधन चक्र के दीर्घकालिक लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण है।

146. खनिज तत्वों से सम्बंधित मामला - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: दुनिया भर में प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण (दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप सहित); विश्व के विभिन्न हिस्सों (भारत सहित) में प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों की स्थिति के लिए जिम्मेदार कारक।

समाचार:

- **क्रिटिकल मिनरल्स** के **विषय** पर **सरकार** द्वारा **पिछले वर्ष दो महत्वपूर्ण** कदम उठाये गये हैं।
- सबसे पहले **जुलाई 2023** में **30 महत्वपूर्ण खनिजों** (दुर्लभ पृथ्वी के अलावा, जो आवर्त सारणी में स्पष्ट रूप से पहचाने जाते हैं) की एक सूची की पहचान करना था।
- दूसरा, **नवंबर 2023** में मौजूदा **खनन कानूनों** में **संशोधन** करना था ताकि **20 महत्वपूर्ण ब्लॉकों** की **नीलामी** में **निजी क्षेत्र** की **भागीदारी** की **अनुमति** मिल सके।

महत्वपूर्ण खनिज:	चुनौतियाँ और चिंताएँ:
• **पहचान** : भारत ने स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा और उर्वरक सहित विभिन्न उद्योगों के लिए आवश्यक 30 महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान की है। • **महत्व** : ये खनिज स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों और राष्ट्रीय विकास को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों और नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती मांग इन संसाधनों की बड़े पैमाने पर आवश्यकता पैदा करती है। • **वैश्विक मांग** : जलवायु परिवर्तन शमन प्रयासों के कारण महत्वपूर्ण खनिजों की वैश्विक मांग आसमान छूने की उम्मीद है, जिससे भारत के लिए रणनीतिक योजना और संसाधन सुरक्षा महत्वपूर्ण हो जाएगी।	• **एकाग्रता** : महत्वपूर्ण खनिज भंडार कुछ देशों, मुख्य रूप से चीन, में भारी मात्रा में केंद्रित हैं, जो असमान वितरण और प्रसंस्करण क्षमताओं के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में कमजोरियां पैदा कर रहे हैं। • **चीन का प्रभुत्व:** महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ पृथ्वी के शोधन में चीन का प्रभुत्व अपने एकाधिकार के माध्यम से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और तकनीकी प्रगति को प्रभावित करने की क्षमता के बारे में चिंता पैदा करता है। • **निर्भरता जोखिम** : भारत के महत्वाकांक्षी स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य विशेष रूप से बैटरी निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा बुनियादी ढांचे के लिए महत्वपूर्ण खनिजों पर बहुत अधिक निर्भर हैं। • अन्य देशों के साथ समझौतों के माध्यम से संसाधनों को सुरक्षित करने के प्रयासों के बावजूद, भारत आयात पर बहुत अधिक निर्भर है, जिससे घरेलू उद्योगों और तकनीकी प्रगति के लिए चुनौतियाँ पैदा हो रही हैं। **भारत की प्रतिक्रिया:** • **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग** : अमेरिका के नेतृत्व वाली खनिज सुरक्षा साझेदारी जैसी पहल में भारत की भागीदारी • इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिज भंडार और प्रसंस्करण विशेषज्ञता रखने वाले देशों के साथ सहयोग करके निर्भरता जोखिमों को कम करके आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना है।

दीर्घकालिक समाधान:

- **सामरिक योजना**: महत्वपूर्ण खनिजों और प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी तक पहुंच की कमी भारत की डीकार्बोनाइजेशन यात्रा में बाधा बन सकती है।
- इन चुनौतियों से पार पाने के लिए दीर्घकालिक रणनीतिक योजना और संसाधन विविधीकरण आवश्यक है।

147. भारत की न्याय व्यवस्था में महिलाओं की वर्तमान स्थिति - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: महिलाओं और महिला संगठनों की भूमिका, जनसंख्या और संबंधित मुद्दे, गरीबी और विकास संबंधी मुद्दे, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके समाधान।

प्रसंग:

- नवीनतम **इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (IJR)** बताती है कि **न्याय वितरण प्रणाली पुलिस, न्यायपालिका, जेल, कानूनी सहायता** और **मानवाधिकार आयोग** बनाने वाली प्रत्येक **उपप्रणाली** में **लैंगिक अंतर व्यापक** बना हुआ है।

मुख्य बिंदु

- एक नई रिपोर्ट, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (IJR), भारत की न्याय प्रणाली में महिलाओं की चिंताजनक कमी का खुलासा करती है।
- यह महिला भागीदारी बढ़ाने के लिए कोटा के बावजूद है।
- रिपोर्ट पुलिस, अदालतों, जेलों और मानवाधिकार आयोगों सहित न्याय प्रणाली के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण लैंगिक अंतर को दर्शाती है।
- जबकि कोटा ने कुछ महिलाओं को सिस्टम में प्रवेश करने में मदद की है, वे ज्यादातर निचले स्तर के पदों पर केंद्रित हैं।

स्पष्ट आँकड़े

- डेटा स्पष्ट है कि संपूर्ण न्याय प्रणाली में केवल लगभग 3 लाख (300,000) महिलाएँ काम करती हैं।
- यहां तक कि न्यायपालिका में भी, जैसे-जैसे आप रैंक ऊपर बढ़ते हैं, संख्या घटती जाती है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में केवल 13% महिलाएँ हैं, और सर्वोच्च न्यायालय में केवल तीन महिला न्यायाधीश हैं। भारत में कभी भी कोई महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं रही है।
- रिपोर्ट में लैंगिक विविधता की कमी के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की भी आलोचना की गई है।
- NHRC में कभी भी कोई महिला आयुक्त नहीं रही है, और केवल छह राज्य मानवाधिकार आयोगों में महिला सदस्य या सचिव हैं।

नेतृत्व की भूमिका में महिलाओं की कमी:

- नेतृत्व की भूमिकाओं में महिलाओं की कमी इन संस्थानों के भीतर लैंगिक समानता के प्रति व्यापक उदासीनता का संकेत देती है।
- रिपोर्ट जिम्मेदारी से ध्यान हटाने और असंतुलन को दूर करने के लिए सक्रिय कदम उठाने में विफल रहने के लिए निर्णय निर्माताओं की आलोचना करती है।
- रिपोर्ट का तर्क है कि अधिक विविध न्याय प्रणाली से सभी को लाभ होगा।
- शोध से पता चलता है कि अधिक विविधता वाले कार्यस्थल अधिक प्रभावी होते हैं।
- महिलाओं को शामिल करने से नए दृष्टिकोण और अनुभव आएंगे, जिससे जटिल मुद्दों की अधिक अच्छी समझ विकसित होगी।
- एक अधिक समावेशी न्याय प्रणाली को जनता द्वारा अधिक वैध और भरोसेमंद के रूप में भी देखा जाएगा। लोग ऐसी प्रणाली पर भरोसा करने की अधिक संभावना रखते हैं जो उस समाज को प्रतिबिंबित करती है जिसकी वह सेवा करती है।

निष्कर्ष

- रिपोर्ट कार्रवाई के आह्वान के साथ समाप्त होती है।
- न्याय संस्थानों को उन चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहने की जरूरत है जो महिलाओं को व्यवस्था में पूरी तरह से भाग लेने से रोकती हैं।
- इसके लिए महिलाओं की उन्नति में आने वाली बाधाओं की पहचान करने और उन्हें दूर करने के लिए मौजूदा संरचनाओं और प्रथाओं की गहन समीक्षा की आवश्यकता है।

148. भारत द्वारा अपनी श्रम शक्ति का न्यूनतम उपयोग- द हिंदू

प्रासंगिकता: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधन जुटाने, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे।

प्रसंग:

- अधिकांश **भारतीय पूंजी या भूमि** के स्वामित्व के विपरीत अपनी **संपूर्ण आय श्रम** के माध्यम से अर्जित करते हैं।
- इसके अलावा, लगभग **90% कामकाजी भारतीय आबादी अनौपचारिक रोजगार के** माध्यम से अपनी आजीविका कमाती है, जिसमें **बहुत कम** या **कोई नौकरी सुरक्षा** नहीं, कोई **रोजगार लाभ** नहीं, कोई **सामाजिक सुरक्षा** नहीं और **कम कमाई** होती है।

सुधारों का गहन अध्ययन

- पहली नज़र में ऐसा लगेगा कि हाल के दिनों में चीज़ों में सुधार हुआ है जिसके लिए हमारे पास आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) का वार्षिक डेटा है।
  - वर्ष 2017-18 की शुरुआत, जिसने पहले के आवधिक राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (रोज़गार-बेरोजगारी) की जगह ले ली।
- कुल मिलाकर, श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) वर्ष 2021-22 में लगातार बढ़कर 58.35% हो गई है, जो वर्ष 2017-18 में 52.35% से शुरू हुई, एक प्रवृत्ति जो बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा संचालित की जा रही है।
- इसके अलावा, कुल बेरोजगारी दर भी वर्ष 2017-18 में 6.2% से घटकर वर्ष 2021-22 में 4.2% हो गई है।
- युवाओं के लिए, बेरोजगारी दर संख्या अधिक है (वर्ष 2017-18 में 12% से वर्ष 2021-22 में 8.5%) लेकिन वही गिरावट की प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है।
- LFPR और बेरोजगारी दर दोनों के लिए, वर्ष 2022-23 के लिए उपलब्ध नवीनतम आंकड़े समान प्रक्षेपवक्र प्रदर्शित करते हैं।

भारत में नौकरियों का संकट, व्यापक आर्थिक कारण

- जब हम नियोजित की विभिन्न श्रेणियों, अर्थात् नियमित वेतन/वेतनभोगी कार्य, आकस्मिक कार्य और स्व-रोजगार और उनके रुझानों को देखते हैं, तो हम देख सकते हैं कि LFPR में सुधार और बेरोजगारी दर में गिरावट काफी हद तक स्व-रोजगार से प्रेरित है।
- यदि हम यह पहचानने के लिए कि कौन सी उपश्रेणी स्व-रोज़गार में समग्र वृद्धि की व्याख्या करती है, उन्हें अलग से देखें तो एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति सामने आती है।
- जबकि स्व-रोजगार करने वालों का अंश जो नियोक्ता हैं, वर्ष 2017-18 में 3.78% से एक प्रतिशत से भी कम अंक बढ़कर वर्ष 2021-22 में 4.57% हो गया है।
- स्व-रोज़गार में अधिकांश वृद्धि अवैतनिक पारिवारिक श्रमिकों की वृद्धि से हुई है, जो इस अवधि में 26% से बढ़कर 31.4% हो गई है।
- यद्यपि अध्ययन की अवधि के दौरान, नियोजित पूल के भीतर, प्रत्येक रोजगार प्रकार में श्रमिकों की पूर्ण संख्या बढ़ रही है
  - परिवार द्वारा संचालित किराना स्टोर में सहायक जैसे अवैतनिक पारिवारिक श्रम के अनुपात में सबसे तेज वृद्धि देखी गई है।

नौकरी बाजार में महिलाओं की संख्या अधिक होने का निर्धारक

- वेतनभोगी और स्व-रोज़गार दोनों की औसत दैनिक कमाई इस अवधि के दौरान स्थिर रही, वास्तविक रूप से कोई वृद्धि नहीं हुई।
- हालाँकि, आकस्मिक काम करने वालों में वर्ष 2017-18 में प्रति दिन ₹162 से बढ़कर वर्ष 2021-22 में प्रति दिन ₹196 हो गई, जो लगभग 20% की वृद्धि है।
- यह वह श्रेणी है जो नियोजित लोगों की कुल औसत कमाई में मध्यम वृद्धि के लिए जिम्मेदार है।
- हालांकि यह एक सकारात्मक विकास है, हमें इसे 30-दिवसीय कार्य माह के संदर्भ में भी रखना चाहिए, आकस्मिक श्रमिक 2010 की कीमतों पर ₹6,000 प्रति माह कमा रहे थे (या, 2021 की कीमतों में ₹11,520)।
- यह ग्रामीण क्षेत्रों में ₹4,080 प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में ₹5,000 प्रति माह (2011-12 की कीमतों में गरीबी रेखा) की गरीबी रेखा से बमुश्किल ऊपर है।
- हमारे निष्कर्षों को सारांशित करने के लिए, जबकि वर्ष 2017-18 के बाद से LFPR में वृद्धि और बेरोजगारी दर में गिरावट एक सकारात्मक संकेत प्रतीत होती है,

जनसांख्यिकीय लाभांश का चरण

- कुल मिलाकर, स्वयं-खाता श्रमिक, कैज़ुअल श्रमिक और अवैतनिक पारिवारिक श्रमिक नियोजित लोगों में से तीन-चौथाई से अधिक हैं।
- हमारी कामकाजी आबादी का तीन चौथाई से अधिक हिस्सा ऐसे काम में लगा हुआ है जो आमतौर पर कम उत्पादकता वाला है।
- इसे संदर्भ में रखने के लिए, भारत जनसांख्यिकीय लाभांश की अवधि में है, जिसके 20 वर्षों से कम समय में चरम पर पहुंचने और लगभग 30 से 35 वर्षों में समाप्त होने की उम्मीद है।
- श्रम उत्पादकता हासिल करने के इस सुनहरे दौर में, अर्थव्यवस्था कम गुणवत्ता वाले कार्यों में बहुमत को संलग्न करके अपनी श्रम पूंजी का इष्टतम ढंग से उपयोग करना जारी रखती है।

149. भारत में गरीबी से सम्बंधित मामला - द प्रिंट

प्रासंगिकता: महिलाओं और महिला संगठनों की भूमिका, जनसंख्या और संबंधित मुद्दे, गरीबी और विकास संबंधी मुद्दे, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके समाधान।

समाचार:

- हालाँकि वर्तमान सरकार के दावों के संबंध में कई विवाद हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या भारत ने जितनी तेजी से विकास किया है, वैसा ही हुआ है, लेकिन युद्ध के कोहरे में सबसे ज्यादा संदर्भों में गरीबी के आंकड़ों के विषय में बहस हो रही है।

बढ़ती भ्रांति

- एक समय, भारत एक सांख्यिकीय प्रणाली बनाने वाला अग्रणी विकासशील देश था जो जीवन स्तर की निगरानी करता था और व्यापक रूप से स्वीकृत गरीबी रेखा स्थापित करने वाला पहला देश भी था।
- यह अवधारणा इतनी प्रभावशाली थी कि यह वर्ष 1970 के दशक के अंत में विकसित विश्व बैंक की प्रारंभिक अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा के लिए संदर्भ बिंदु और प्राथमिक आधार बन गई।
- लेकिन पिछले दशकों में भ्रम बढ़ गया क्योंकि भारत के लिए गरीबी रेखा को पहले उपयुक्त माना जाता था, लेकिन 'कैलोरी बहाव' जैसी घटनाओं के कारण इसका प्रभाव खत्म हो गया।
  - जिसमें लोग कम कैलोरी का उपभोग करते हैं लेकिन नए रूपों में और सांख्यिकीय पद्धतियों में बदलाव के कारण, जिससे तुलनीयता के बारे में अंतहीन बहस छिड़ गई।

सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता वाली समिति

- समिति ने माना कि शहरी क्षेत्रों के लिए एक उपयुक्त गरीबी रेखा (बदले में पूरे भारत के लिए गरीबी रेखा को तय करने के लिए उपयोग की जाती है)
  - वह ऐसा होगा जो पूर्ववर्ती गरीबी रेखा द्वारा उत्पन्न शहरी गरीबी अनुमानों के समान ही उत्पन्न होगा।
- विघटन का समाधान कोई नया तरीका नहीं था, बल्कि पुराने पर पैच के बाद पैच लगाना था।
- दुर्भाग्य से, स्कोरिंग अंकों पर प्रीमियम के कारण अवधारणाओं और विधियों के सावधानीपूर्वक पुनर्विचार पर आधारित इस तरह के दृष्टिकोण का अभाव रहा है।

नीति आयोग का राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक

- यह सरकार की सेवा-वितरण उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है, बिना यह बताए कि आय बढ़ रही है या नहीं
- सरकार को लोकसभा चुनाव के ठीक समय पर जीत का दावा करने की अनुमति देने के लिए शॉर्टकट और एक्सट्रपलेशन का सहारा लेकर भ्रम की स्थिति को और बढ़ा दिया है।
- यदि यह पर्याप्त नहीं था, तो सरकार ने हाल ही में घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) वर्ष 2022-23 की एक 'फैक्टशीट' जारी की, जो यह भी घोषित करती है कि गरीबी में तेजी से गिरावट आई है।
  - लेकिन अध्ययन नए तरीकों पर निर्भर करता है जिनकी पर्याप्त व्याख्या नहीं की गई है और विशेषज्ञों ने निर्णय सुरक्षित रखा है।

150. पश्चिमी घाट में एक जनजाति को जीवन रेखा की आवश्यकता - द हिंदू

प्रासंगिकता: केंद्र और राज्यों द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का प्रदर्शन; इन कमजोर वर्गों की सुरक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थाएं और निकाय।

प्रसंग:

- **मकुटा गांव** की कहानी **भारत** में **स्वदेशी समुदायों** के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालती है।
- जबकि फानी **येरावा जनजाति** ने **वन अधिकार अधिनियम** के तहत **पैतृक भूमि** अधिकारों को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है, उनके जीवन का तरीका नाटकीय रूप से बदल रहा है।

आजीविका में बदलाव:

- **भूमि अधिकार प्रदान किए गए** : जनजाति ने वन भूमि पर अपने ऐतिहासिक दावे की कानूनी मान्यता प्राप्त की।
- **वनों पर निर्भरता कम हुई** : बाजार परिवर्तन और बिचौलियों द्वारा शोषण ने आय के लिए वन संसाधनों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है।
- **दिहाड़ी मजदूरी बढ़ रही है** : कई व्यक्ति अब दैनिक मजदूरी वाली नौकरियों की तलाश में हैं, लघु वन उत्पादों को इकट्ठा करने की पारंपरिक प्रथाओं की तुलना में बेहतर वेतन के कारण अक्सर पड़ोसी राज्यों में पलायन कर रहे हैं।

उभरते सामाजिक मुद्दे:

- **शराब की लत** : समुदाय के भीतर शराब के दुरुपयोग में चिंताजनक वृद्धि समग्र कल्याण को प्रभावित कर रही है और बच्चों की शिक्षा में बाधा डाल रही है।
- **सीमित समर्थन:** इन महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों में अक्सर शासी निकायों से पर्याप्त जागरूकता और समर्थन का अभाव होता है।

वन अधिकार अधिनियम, 2006

- यह अधिनियम वनों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों (FDST) और अन्य पारंपरिक वनवासियों (OTFD) को वन अधिकारों और वन भूमि पर कब्जे को मान्यता देता है और उन्हें अधिकार देता है, जो पीढ़ियों से ऐसे जंगलों में रह रहे हैं।
- वन अधिकारों का दावा किसी भी सदस्य या समुदाय द्वारा किया जा सकता है, जो 13 दिसंबर, 2005 से पहले कम से कम तीन पीढ़ियों (75 वर्ष) का है।
  - मुख्य रूप से वास्तविक आजीविका आवश्यकताओं के लिए वन भूमि में निवास करते हैं।
- यह FDST और OTFD की आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए वनों की संरक्षण व्यवस्था को मजबूत करता है।
- ग्राम सभा प्रकृति निर्धारण की प्रक्रिया शुरू करने का प्राधिकारी है
  - और व्यक्तिगत वन अधिकार (IFR) या सामुदायिक वन अधिकार (CFR) या दोनों की सीमा जो FDST और OTFD को दी जा सकती है।

कार्यवाई के लिए बुलावा:

- स्थानीय **नेताओं और कार्यकर्ताओं** ने **सरकार** से इन उभरती **सामाजिक चुनौतियों** का समाधान करने के लिए कदम बढ़ाने और लक्षित हस्तक्षेप प्रदान करने का आग्रह किया है। यह सीधे तौर पर इन हाशिए पर रहने वाले **समुदायों की जीवन स्थितियों** में **सुधार और कल्याण** में योगदान देगा।

151. रेडियोधर्मी अपशिष्ट कैसे उत्पन्न होता है - द हिंदू

प्रासंगिकता: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन

प्रसंग:

- भारत के परमाणु कार्यक्रम ने इसके प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कोर को लोड करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है ।
- यह प्रगति ऊर्जा स्वतंत्रता के लिए **प्रचुर थोरियम भंडार** का उपयोग करने के उनके लक्ष्य के अनुरूप है।
- हालाँकि, **उत्पादित रेडियोधर्मी अपशिष्ट** का प्रबंधन एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है।

मुख्य बिंदु	रेडियोधर्मी अपशिष्ट संबंधी चिंताएँ:
• **रेडियोधर्मी अपशिष्ट उत्पादन** : जब रिएक्टर में ईंधन न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है, तो यह रेडियोधर्मी तत्वों का निर्माण करता है। • यह अपशिष्ट, जिसे प्रयुक्त ईंधन कहा जाता है, अत्यधिक रेडियोधर्मी है और दशकों तक पानी के नीचे भंडारण की आवश्यकता होती है। • बाद में, इसे आगे के भंडारण के लिए सुरक्षित कास्क्स (पीपों) में स्थानांतरित कर दिया जाता है। • **वैश्विक चुनौती**: स्थापित परमाणु कार्यक्रम वाले देशों को पर्याप्त अपशिष्ट संचय का सामना करना पड़ता है। • अमेरिका, कनाडा और रूस उदाहरण के तौर पर काम करते हैं।	• **स्वास्थ्य संबंधी खतरे** : यह अपशिष्ट रेडियोधर्मी रहता है और सहस्राब्दियों तक मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा बना रहता है। • **पर्यावरणीय प्रभाव** : फुकुशिमा और चेरनोबिल जैसी दुर्घटनाएँ पर्यावरण में रेडियोधर्मी सामग्री के जारी होने के गंभीर परिणामों को दर्शाती हैं। • **वित्तीय बोझ** : सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेडियोधर्मी अपशिष्ट की हैंडलिंग, परिवहन, भंडारण और निपटान को नियंत्रित करने वाले सख्त नियम इन सुविधाओं को बनाए रखने में महत्वपूर्ण लागत और जनशक्ति की आवश्यकता होती है।

152. भारत की अनुसंधान एवं विकास निधि से सम्बंधित मामला - द हिंदू

प्रासंगिकता: विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियाँ; प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण और नई प्रौद्योगिकी का विकास।

प्रसंग:

- देश के भीतर **अनुसंधान** और **नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र** को मजबूत करने के लिए **वर्ष 2024-25** के अंतरिम बजट में **₹1 लाख करोड़** के कोष की घोषणा की गई है।

मुख्य बिंदु

- आर्थिक विकास, तकनीकी प्रगति और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने में अनुसंधान और नवाचार के महत्व को कम करके आंका नहीं जा सकता है।
- इसमें पेटेंट अनुदान, प्रदान की गई पीएचडी और प्रकाशन आउटपुट के संदर्भ में उल्लेखनीय आउटपुट के साथ-साथ सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में भारत के तुलनात्मक रूप से कम R&D व्यय की जांच करना शामिल है।
- इन पहलों के वास्तविक निहितार्थों को समझने के लिए इस आउटपुट की गुणवत्ता का विश्लेषण करना भी उतना ही जरूरी है।
- भारत के अनुसंधान एवं विकास में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है, अनुसंधान और विकास (GERD) पर सकल व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि 2010-11 में ₹6,01,968 मिलियन से बढ़कर 2020-21 में ₹12,73,810 मिलियन हो गई है।
- हालाँकि, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान और विकास निवेश 0.64% है
- भारत चीन (2.4%), जर्मनी (3.1%), दक्षिण कोरिया (4.8%) और संयुक्त राज्य अमेरिका (3.5%) जैसी प्रमुख विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं से पीछे है।

अनुसंधान आउटपुट, नवाचार

- सालाना, भारत प्रभावशाली 40,813 पीएचडी उत्पन्न करता है और संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है।
- इसके अतिरिक्त, भारत का अनुसंधान उत्पादन पर्याप्त बना हुआ है और वर्ष 2022 में 3,00,000 से अधिक प्रकाशनों के साथ विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है।
  - देश के मजबूत अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र और विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला गया।
- भारत ने पेटेंट अनुदान में भी सराहनीय प्रदर्शन किया है और वर्ष 2022 में 30,490 पेटेंट के साथ विश्व स्तर पर छठा स्थान हासिल किया है।
- भारत में, GERD मुख्य रूप से सरकारी क्षेत्र द्वारा संचालित है, जिसमें निजी क्षेत्र के उद्योग का योगदान वर्ष 2020-21 के दौरान केवल 36.4% है।
- आर्थिक विकास और तकनीकी उन्नति पर विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के सकारात्मक प्रभाव को अधिकतम करने के लिए सरकार, व्यावसायिक उद्यमों और HEI के बीच सहयोग आवश्यक है।

अनुसंधान एवं विकास में निवेश

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अनुसंधान एवं विकास आंकड़ों (वर्ष 2022-23) के अनुसार,वर्ष 2020-21 में अनुसंधान एवं विकास में भारत का कुल निवेश 17.2 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया।
- इस राशि के भीतर, 54% ($9.4 बिलियन) सरकारी क्षेत्र को आवंटित किया जाता है और मुख्य रूप से चार प्रमुख वैज्ञानिक एजेंसियों द्वारा उपयोग किया जाता है
  - रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (30.7%), अंतरिक्ष विभाग (18.4%), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (12.4%), और परमाणु ऊर्जा विभाग (11.4%)।
- सुव्यवस्थित निर्णय लेने और रणनीतिक संरेखण में भारत की ताकत को बनाए रखते हुए अन्य विकसित देशों में अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र से सीखना अपने अनुसंधान एवं विकास परिदृश्य को अनुकूलित करने के लिए एक शक्तिशाली शक्ति हो सकता है।
- भारत को ऐसी नीतियां लागू करनी चाहिए जो निजी कंपनियों को अनुसंधान एवं विकास में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करें।

पहल का प्रभाव

- नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी (NDTSP) जैसी पहल तकनीकी प्रगति और नवाचार के प्रति एक मजबूत प्रतिबद्धता का संकेत देती है।
- अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) अधिनियम का हालिया अधिनियमन, विकास की आधारशिला के रूप में अनुसंधान और नवाचार को उत्प्रेरित करने के लिए सरकार के समर्पण को रेखांकित करता है।
- इस अधिनियम का उद्देश्य HEI के भीतर एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति का पोषण करते हुए भारत के निरंतर अनुसंधान एवं विकास निवेश अंतर को पाटना है।

निष्कर्ष

- NDTSP और ANRF अधिनियम के साथ संयुक्त अंतरिम बजट, विशेष रूप से उभरते उद्योगों में निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाले अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने की भारत की प्रतिबद्धता के बारे में सकारात्मक संकेत भेजता है।

153. CAA और न्यायिक कार्यवाही की स्थिति -द हिंदू

प्रासंगिकता: शासन के महत्वपूर्ण पहलू, पारदर्शिता और जवाबदेही, ई-गवर्नेंस अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएँ, सीमाएँ और क्षमता; नागरिक चार्टर, पारदर्शिता और जवाबदेही और संस्थागत और अन्य उपाय।

प्रसंग:

- संसद द्वारा **नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA)**, 2019 पारित करने के **चार साल** बाद, **गृह मंत्रालय** (MHA) ने कानून को लागू करने के लिए नियमों को अधिसूचित किया।
- **CAA** को **सुप्रीम कोर्ट** में भी चुनौती दी जा रही है , कई याचिकाकर्ताओं ने नियमों के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग करते हुए नई याचिकाएं दायर की हैं।
- यह **पाकिस्तान, अफगानिस्तान** और **बांग्लादेश** से **छह गैर-मुस्लिम समुदायों** हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई और जैन के **गैर-दस्तावेज आप्रवासियों** के लिए तेजी से नागरिकता प्रदान करता है।

CAA के निहितार्थ क्या हैं?

- दिसंबर 2019 में, संसद ने नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 अधिनियम) में एक संशोधन पारित किया, जिसमें धारा 2(1)(B) में एक नया प्रावधान शामिल किया गया, जो "अवैध प्रवासियों" को परिभाषित करता है।
- तदनुसार, 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश करने वाले अनिर्दिष्ट अप्रवासी,
  - जिन्हें केंद्र सरकार ने पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920, या विदेशी अधिनियम, 1946 के तहत छूट दी है
  - वर्ष 1955 अधिनियम के तहत नागरिकता के लिए पात्र होंगे।
- हालाँकि, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ आदिवासी क्षेत्रों को कानून के दायरे से छूट दी गई थी।
- इन संरक्षित क्षेत्रों तक पहुँचने के लिए, संबंधित राज्य सरकारों से इनर लाइन परमिट (ILP) की आवश्यकता होती है।
- 28 मई, 2021 को केंद्र सरकार ने 1955 अधिनियम की धारा 16 के तहत एक आदेश जारी किया
  - उच्च प्रवासी आबादी वाले पांच राज्यों में जिला कलेक्टरों को वर्ष 2019 संशोधन में पहचाने गए समूहों को नागरिकता प्रदान करने की शक्ति प्रदान करना।
- CAA को वर्ष 1985 के असम समझौते को खत्म करने के कदम के रूप में भी करार दिया गया है, जो किसी भी ऐसे व्यक्ति को विदेशी मानता है जो 24 मार्च, 1971 के बाद अपने वंश को साबित नहीं कर सकता है और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है।

धारा 6A को चुनौती का क्या महत्व है?

- CAA के खिलाफ कार्यवाही 1955 अधिनियम की धारा 6A को चुनौती के परिणाम पर भी निर्भर है
  - जिसे 15 अगस्त, 1985 को हस्ताक्षरित "असम समझौते" नामक समझौता ज्ञापन के आगे पेश किया गया था।
- धारा 6A यह निर्धारित करती है कि असम में प्रवेश के लिए कट-ऑफ तिथि 24 मार्च, 1971 स्थापित करके कौन विदेशी है।
  - जो लोग 1 जनवरी, 1966 को या उसके बाद, लेकिन 25 मार्च, 1971 से पहले राज्य में आए, उन्हें "विदेशी" घोषित किया जाना था।
  - भारतीय नागरिकों के सभी अधिकार और दायित्व होंगे, सिवाय इसके कि वे 10 वर्षों तक मतदान नहीं कर सकेंगे।
- यदि 24 मार्च 1971 को राज्य में प्रवेश के लिए वैध कट-ऑफ तिथि के रूप में बरकरार रखा जाता है, तो CAA को असम समझौते का उल्लंघन माना जा सकता है क्योंकि यह एक अलग समयरेखा स्थापित करता है।

154. चुनावों में जेनेरिक AI का प्रभाव - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियाँ; प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण और नई प्रौद्योगिकी का विकास।

प्रसंग:

- **चुनावों** पर **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)** के प्रभाव ने वर्ष 2018 **कैम्ब्रिज एनालिटिका** घोटाले के बाद व्यापक ध्यान आकर्षित किया, जिसने **फेसबुक** जैसे **प्लेटफार्मों से उपयोगकर्ता डेटा** का शोषण करके **चुनावी गतिशीलता** को प्रभावित करने में **सोशल मीडिया** की भूमिका को रेखांकित किया।

मुख्य बिंदु

- AI तीन मुख्य रास्ते प्रस्तुत करता है जिसके माध्यम से यह चुनावी संदर्भों में गलत सूचना के प्रसार को बढ़ा सकता है।
- सबसे पहले, इसमें बड़े पैमाने पर झूठी जानकारी की पहुंच बढ़ाने की क्षमता है।
- दूसरे, अति-यथार्थवादी डीप फेक के निर्माण के माध्यम से, AI-जनित सामग्री मतदाताओं की राय को प्रभावित कर सकती है, इससे पहले कि इसे प्रभावी ढंग से खारिज किया जा सके।
- तीसरे, AI पारंपरिक बॉट्स और स्वचालित खातों की प्रभावशीलता को पार करते हुए, अभूतपूर्व सटीकता के साथ व्यक्तिगत मतदाताओं के लिए सटीक सूक्ष्म लक्ष्यीकरण, प्रचार-प्रसार को सक्षम बनाता है।
- फेसबुक और ट्विटर जैसे प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफार्मों द्वारा तथ्य-जांच और चुनाव अखंडता प्रयासों में कटौती से ये जोखिम बढ़ गए हैं।
- हालांकि यूट्यूब, टिकटॉक और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म AI-जनरेटेड चुनाव-संबंधित विज्ञापनों की लेबलिंग अनिवार्य करते हैं, लेकिन यह उपाय फुलप्रूफ नहीं हो सकता है।
- पूर्वानुमान बताते हैं कि AI 2024 तक लगभग दैनिक आधार पर सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर हानिकारक सामग्री का तेजी से प्रसार करेगा।
  - संभावित रूप से 50 से अधिक देशों में चुनावों को प्रभावित करना और सरकारों की वैधता को कम करना, जिससे सामाजिक अस्थिरता पैदा होगी।

भारत के नियामक कदम

- इन जोखिमों को पहचानते हुए, भारत ने AI द्वारा प्रचारित गलत सूचना को रोकने के लिए नियामक कदम उठाए हैं।
- सरकार ने हानिकारक गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए डिजिटल प्लेटफार्मों से तकनीकी और प्रक्रियात्मक उपाय लागू करने का आह्वान किया है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) का इरादा चुनावों के बाद डीपफेक और दुष्प्रचार से निपटने के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित करने का है।
- हाल ही में, MeitY ने Google और OpenAI जैसी प्रमुख तकनीकी कंपनियों को एक सलाह जारी की, जिसमें उनसे यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया कि उनकी सेवाएँ भारतीय कानूनों का अनुपालन करें और चुनावी अखंडता से समझौता न करें।
- हालाँकि, इस कदम को जेनेरिक AI क्षेत्र में कुछ स्टार्टअप्स की आलोचना का सामना करना पड़ा, उन्हें डर था कि अत्यधिक विनियमन से नवाचार बाधित हो सकता है।
- यह घटना AI-संचालित गलत सूचना से निपटने और AI क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के बीच नियामकों को नाजुक संतुलन को रेखांकित करती है ।

155. नेपाल की राजनीतिक व्यवस्था से संबधित मामला - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते जिनमें भारत शामिल है और/या भारत के हितों को प्रभावित करते हैं।

समाचार:

- **नेपाल** के **प्रधान मंत्री** ने पिछले सप्ताह संसद के **275 सदस्यीय निचले सदन** में **विश्वास मत** जीता, जिसमें उपस्थित **268 सांसदों** में से **157 का** समर्थन हासिल किया।

नेपाल की शक्ति का परिभ्रमण द्वार: एक राजनीतिक रस्साकशी

- नेपाल की सरकार म्यूजिकल चेयर का खेल बन गई है, जिसमें शीर्ष पर लगातार बदलाव होता रहता है।
- वर्ष 2008 में गणतंत्र बनने के बाद से, देश ने आश्चर्यजनक रूप से 13 सरकारें देखी हैं, जिनका नेतृत्व अक्सर एक ही प्रमुख प्रतिभागी प्रचंड, देउबा और ओली करते हैं।

नेपाल में अस्थिरता का प्रभाव

- लगातार हो रहे इस राजनीतिक मंथन ने नेपाल की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है.
- कई युवा नेपालियों को घर पर अवसरों की कमी के कारण विदेश में काम खोजने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

भारत का रुख

- भारत, नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार, इन घटनाक्रमों पर चिंता और सावधानी के साथ नजर रख रहा है।
- जहां प्रचंड के साथ उनके अच्छे संबंध हैं, वहीं उनके नए साथी ओली का भारत के साथ तनावपूर्ण इतिहास रहा है।
- प्रधानमंत्री के रूप में ओली के पिछले कार्यों से दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए थे।

दो दिग्गजों के बीच नेपाल

- भारत और चीन के बीच नेपाल का स्थान एक जटिल भू-राजनीतिक स्थिति पैदा करता है। नेपाली नेताओं ने भारत के साथ अपने संबंधों में चीन को लाभ के रूप में इस्तेमाल किया है।
- बदले में, चीन संभावित रूप से भारत के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए नेपाल में निवेश और सहायता बढ़ा रहा है।

भारत के लिए आगे की राह

- नई दिल्ली को एक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
- उन्हें नेपाली लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए, उन्हें अलग-थलग करने से बचना चाहिए और प्रभुत्व नहीं, बल्कि समानता पर आधारित एक मजबूत साझेदारी की दिशा में काम करना चाहिए।

156. IPCC रिपोर्ट में समानता की समस्या - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन।

समाचार:

- संयुक्त राष्ट्र की जलवायु रिपोर्ट उत्सर्जन और बोझ में लगातार असमानता दर्शाती है

संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिदृश्यों का विश्लेषण करने वाले एक नए अध्ययन से एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति का पता चलता है:

- 500 से अधिक भविष्य के मार्गों पर विचार करने के बावजूद, विकसित और विकासशील देशों के बीच आय, ऊर्जा उपयोग और उत्सर्जन असमानताएं 2050 तक बढ़ने का अनुमान है।

इक्विटी(समानता क्यों मायने रखती है	IPCC रिपोर्ट में असमानताएँ
• जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा "साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों" के सिद्धांत को मान्यता देता है। • इसका मतलब यह है कि धनी राष्ट्र, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से उत्सर्जन में अधिक योगदान दिया है, उन्हें जलवायु कार्रवाई के बोझ का बड़ा हिस्सा लेना चाहिए। • इस सिद्धांत की अनदेखी करते हुए केवल तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता जोखिमों पर ध्यान केंद्रित करना। • आदर्श रूप से, विकसित क्षेत्र "शुद्ध नकारात्मक" उत्सर्जन को शीघ्रता से प्राप्त कर लेंगे, जिससे विकासशील देशों के लिए शेष कार्बन बजट को स्थायी रूप से बढ़ने के लिए मुक्त कर दिया जाएगा। • हालाँकि, वर्तमान परिदृश्य इसे प्रतिबिंबित नहीं करते हैं।	अध्ययन ने IPCC की नवीनतम रिपोर्ट (AR6) के परिदृश्यों की जांच की और पाया: • वर्ष 2050 तक, उप-सहारा अफ्रीका, दक्षिण एशिया, पश्चिम एशिया और शेष एशिया (दुनिया की 60% आबादी का प्रतिनिधित्व) में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद वैश्विक औसत से कम होने का अनुमान है। • वस्तुओं और सेवाओं की खपत, ऊर्जा के उपयोग और जीवाश्म ईंधन की खपत में समान असमानताएं मौजूद हैं, ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ की तुलना में अधिक खपत करता है। • परिदृश्य विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में भूमि आधारित कार्बन सिंक और कार्बन कैप्चर प्रौद्योगिकियों (CCS) पर अधिक निर्भरता का अनुमान लगाते हैं।

निष्कर्ष

- ये निष्कर्ष अधिक न्यायसंगत जलवायु परिदृश्यों की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं।
- विकासशील देशों पर उत्सर्जन कम करने और विकसित देशों द्वारा पैदा की गई मेस को साफ करने का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए।

157. इंडो-पैसिफिक रणनीति- द हिंदू

प्रासंगिकता: भारत के हितों, भारतीय प्रवासियों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव।

प्रसंग:

- जबकि **जनवरी 2021** से **भारत सरकार** का ध्यान **क्वाड** को मजबूत करने के निरंतर प्रयास के साथ **इंडो-पैसिफिक** पर केंद्रित था
- **अक्टूबर 2023** से **नीति** का ध्यान वापस **हिंद महासागर** पर **केंद्रित** हो गया है।
- बेशक, इंडो-पैसिफिक रणनीति **प्रशांत और हिंद महासागर** दोनों को कवर करती है, लेकिन जब खतरा गहराता है, तो दूर के तटों की तुलना में तत्काल पड़ोस अधिक मायने रखता है।

नीति परिवर्तन	अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, फ्रांस और जर्मनी कहां खड़े हैं

• ऐसा लगता है कि मालदीव भारत के साथ टकराव की राह पर बढ़ रहा है।
• नई दिल्ली के धैर्य और कूटनीतिक चातुर्य के बावजूद, माले ने चीन के प्रति अपना आलिंगन गहरा करना जारी रखा है।
• इसके विपरीत, श्रीलंका ने अपने बंदरगाहों पर चीनी सहित विदेशी अनुसंधान जहाजों पर एक साल की रोक लगाकर भारत की सुरक्षा चिंताओं के प्रति अधिक संवेदनशीलता दिखाई।
• पिछले महीने, भारत की SAGAR नीति ने एक मूल्यवान लाभांश उत्पन्न किया
  ○ भारत और मॉरीशस के प्रधानमंत्रियों ने अगालेगा द्वीप समूह में एक नई हवाई पट्टी और एक जेटी का उद्घाटन किया
  ○ अपने विशाल विस्तारित आर्थिक क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए मॉरीशस की क्षमता को बढ़ावा देना।
• द्वीप राष्ट्रों से अटा पड़ा पश्चिमी हिंद महासागर और अरब सागर से स्वेज़ तक फैला उत्तरी हिंद महासागर दोनों फिर से सक्रिय भूगोल बन गए हैं।
• जिबूती, क्याउकफ्यू, ग्वादर और हंबनटोटा में नौसैनिक अड्डों की बीजिंग की खोज के पीछे एक स्पष्ट पैटर्न उभर रहा है।
• उन्होंने रेखांकित किया कि भारत और अमेरिका हिंद-प्रशांत क्षेत्र में प्रमुख हितधारक हैं, सहयोग से उन्हें चीन के साथ रणनीतिक प्रतिस्पर्धा से निपटने में मदद मिलती है।
• "उभरते" खतरों से निपटने में पानी के भीतर डोमेन जागरूकता में सहयोग को एक प्रमुख लक्ष्य के रूप में पहचाना गया है।
	• जबकि वे दक्षिण चीन सागर में बीजिंग के अवैध दावों के बारे में चिंतित हैं, उन्हें यह देखना होगा कि हिंद महासागर में भी इसी तरह की मुखरता और शत्रुतापूर्ण इरादे पैदा हो रहे हैं।
	• लेकिन जब चीन के व्यवहार और उसे चलाने वाली दीर्घकालिक प्रेरणाओं की व्याख्या करने की बात आती है तो वे 'अध्ययनित अस्पष्टता' प्रदर्शित करते हैं।
	• यूरोपीय देशों की चीन से भौगोलिक दूरी उन्हें सुरक्षा का एहसास दिलाती है।
	भारत के अन्य विकल्प
	• सबसे पहले, भारत को अपने रणनीतिक साझेदारों को स्पष्ट संदेश देने की जरूरत है कि वह अपनी इंडो-पैसिफिक जिम्मेदारियों के प्रति सचेत है
	  ○ यह हिंद महासागर क्षेत्र को प्राथमिकता देता है।
	• दूसरा, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) और कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव (CSC) के एक महत्वपूर्ण ऑडिट की आवश्यकता है।
	• जबकि IORA ख़राब प्रदर्शन कर रहा है और प्रभावी होने के लिए बहुत अनाकार हो गया है, CSC को एक प्रमुख सदस्य को खोने का खतरा है
	  ○ मालदीव, अगर चीन के साथ द्वीप राष्ट्र की साझेदारी गहरी होती है।
	• नई दिल्ली के लिए समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने और ब्लू इकोनॉमी की क्षमता को अनुकूलित करने के उद्देश्य से एक नए तंत्र के निर्माण को प्रोत्साहित करने का समय आ गया है।
	• इस समूह में पड़ोस के चार देश (भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार) और चार द्वीप राज्य (मॉरीशस, सेशेल्स, कोमोरोस और मेडागास्कर) शामिल हो सकते हैं।
	• अगर मालदीव समझदारी भरी नीति अपनाए तो नौवीं सीट मालदीव के लिए रखी जा सकती है।
	• इस समूह का नाम 'हिन्द महासागर सहयोग संगठन' रखा जा सकता है।
	• चूंकि भारत का लक्ष्य तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का है, इसलिए उसे अपनी नौसेना को तीसरी या चौथी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने के लिए नए बजटीय संसाधन खोजने चाहिए।

158. भारत का सौर अपशिष्ट वर्ष 2030 तक 600 किलोटन तक पहुंचने की संभावना: CEEW अध्ययन - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन।

प्रसंग:

- प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार, **भारत ने वित्तीय वर्ष** (वित्त वर्ष) **वर्ष 2022-2023** में लगभग **100 किलोटन (kt) सौर अपशिष्ट** उत्पन्न किया।
- अध्ययन में कहा गया है कि देश में उत्पादित सौर अपशिष्ट की मात्रा **वर्ष 2030** तक **600 किलो टन** तक पहुंचने की उम्मीद है।

मुख्य बिंदु

- विश्लेषण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) और ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (CEEW), एक जलवायु थिंक टैंक द्वारा किया गया था।
- मार्च 2023 तक भारत की वर्तमान सौर क्षमता 66.7 गीगावॉट है
  - पिछले 10 वर्षों में इसमें 23 गुना वृद्धि हुई है और वर्ष 2030 तक स्थापित सौर क्षमता 292 गीगावॉट तक पहुंचने की उम्मीद है।

सौर अपशिष्ट क्या है?

- अध्ययन के अनुसार, सौर अपशिष्ट का तात्पर्य सौर मॉड्यूल के निर्माण के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट और क्षेत्र (परियोजना जीवनकाल) से निकलने वाले अपशिष्ट से है।

अध्ययन के निष्कर्ष क्या हैं?

- वर्ष 2030 तक, भारत की वर्तमान स्थापित सौर क्षमता वर्तमान से तीन गुना अधिक 340 kt उत्पन्न करेगी।
- इस अपशिष्ट का लगभग 67 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश सहित पांच राज्यों द्वारा उत्पादित होने की उम्मीद है।
- चूंकि फेंके गए मॉड्यूल में सिलिकॉन, तांबा, टेल्यूरियम और कैडमियम जैसे खनिज होते हैं जिन्हें महत्वपूर्ण खनिजों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
  - भारत सरकार द्वारा देश के आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अध्ययन में उन पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया।

सौर अपशिष्ट से कैसे निपटें?

- इसने नीति निर्माताओं से स्थापित सौर क्षमता का एक व्यापक डेटाबेस बनाए रखने का आग्रह किया, जो अगले वर्षों में सौर अपशिष्ट का अनुमान लगाने में मदद करेगा।
- रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नीति निर्माताओं को रिसाइक्लर्स को प्रोत्साहित करना चाहिए और बढ़ते सौर अपशिष्ट को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए हितधारकों पर दबाव डालना चाहिए।
- भारत को सोलर रीसाइक्लिंग के लिए बाजार बनाने पर ध्यान देने की जरूरत है।
- सामान्य समझ यह है कि सौर अपशिष्ट तभी होता है जब मॉड्यूल अपने जीवन के अंत तक पहुंचते हैं, जो लगभग 25 वर्ष है।
- हालाँकि, रिपोर्ट बताती है कि ऐसे अन्य तरीके भी हैं जिनसे सौर अपशिष्ट उत्पन्न होता है।
- पारंपरिक पुनर्चक्रण में चांदी और सिलिकॉन जैसी अधिक मूल्यवान सामग्री को इस विधि के माध्यम से पुनर्प्राप्त नहीं किया जा सकता है।
- उच्च-मूल्य पुनर्चक्रण के रूप में यह विधि रासायनिक प्रक्रियाओं की सहायता से चांदी और सिलिकॉन को भी पुनर्प्राप्त कर सकती है।

159. वैश्विक जल संकट से सम्बंधित मामला - द हिंदू

प्रासंगिकता: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन।

समाचार:

- संयुक्त राष्ट्र **विश्व जल विकास** रिपोर्ट हाल ही में **यूनेस्को** द्वारा प्रकाशित की गई
- रिपोर्ट हमें याद दिलाती है कि भारत सहित "**दुनिया के मीठे पानी** के **संसाधनों** का एक बड़ा हिस्सा सीमा पार जल में है"।

मुख्य बिंदु

- वर्ष 2024 की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र में, हाल के वर्षों में जल प्रदूषण की मात्रा विशेष रूप से मेघना, ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु में काफी खराब हो गई है।
- विश्व संसाधन संस्थान के अनुसार, 17 देश जल तनाव के 'अत्यंत उच्च' स्तर का सामना कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप लोगों के बीच संघर्ष, अशांति और शांति का खतरा है।
- भारत भी इन समस्याओं से अछूता नहीं है। भारत में पानी की उपलब्धता पहले से ही इतनी कम है कि इसे पानी की श्रेणी में रखा जा सकता है
- भारत के लगभग हर राज्य और मुख्य शहरों में भूजल स्तर में कमी आ रही है।
- बेंगलूरु इसका प्रमुख उदाहरण है
  - लेकिन जलग्रहण उपचार उपायों की कमी या अनुपयुक्तता के कारण खराब डिजाइन और जल निकायों का खराब रखरखाव होता है
  - अधिकांश जलाशयों/जलस्रोतों/आर्द्रभूमियों में सिल्टेड जमा हो गई है, जिसके परिणामस्वरूप भंडारण क्षमता और कम प्रभावकारिता कम हो गई है।
- उचित सतही एवं भूजल प्रबंधन का अभाव है।
- भारत में वर्षा आधारित क्षेत्र, जिसमें 48% से अधिक भूमि शामिल है, सकल कृषि उत्पाद का लगभग 45% उत्पादन करता है।

समाधान

- यह सामान्य रूप से विभिन्न संसाधन संरक्षण उपायों और वर्षा जल संचयन (इन-सीटू और एक्स-सीटू) को अपनाने से ही संभव हो सकता है।
  - विशेष रूप से छत पर वर्षा जल संचयन सुनिश्चित करना।
- वर्षा जल संचयन (RWH) पुनर्भरण को बढ़ाकर और सिंचाई में सहायता करके पानी की कमी और सूखे के खिलाफ सख्त सक्षम बनाता है।

जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सरकारी योजनाएं

- 'प्रति बूंद अधिक फसल
- 'गांव का पानी गांव में
- 'खेत का पानी खेत में
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के तहत 'हर मेध प्रति पेड'
- जल विभाजन प्रबंधन
- मिशन अमृत सरोवर
- जल शक्ति अभियान कार्यक्रम।
- लेकिन तालाबों/जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए एक प्रोटोकॉल की आवश्यकता है (यह अभी उपलब्ध नहीं है)।
- इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए प्रत्येक जलाशय की स्थिति, उसकी जल उपलब्धता, पानी की गुणवत्ता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की स्थिति का अध्ययन करने की बहुत आवश्यकता है। प्रत्येक जल निकाय के जलग्रहण भंडारण कमांडर क्षेत्र पर ध्यान देकर प्रत्येक गांव में अधिक जल निकाय बनाने और उनके पुनरुद्धार की भी आवश्यकता है।

अतिरिक्त कदम

- सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों के साथ जल संसाधनों को एकीकृत करने और एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन वाले IOT आधारित स्वचालन जैसी कुशल सिंचाई तकनीकों को सुनिश्चित करना
- घरेलू उद्देश्यों के लिए पानी के उपयोग को कम करने के लिए जल मीटर लगाना
- कोई मुफ़्त बिजली नहीं, लाइन विभागों का अभिसरण और लिंकेज होना; सामुदायिक जागरूकता और लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना, जल संरक्षण के बारे में जागरूकता अभियान; भूजल उपयोग तटस्थता सुनिश्चित करना;

160. ब्लैक कार्बन उत्सर्जन पर अंकुश लगाने की आवश्यकता -द हिंदू

प्रासंगिकता: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन।

समाचार:

- **नवंबर 2021** में **ग्लासगो** में **COP26** जलवायु वार्ता में, **भारत** ने **वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन** हासिल करने का वादा किया, जिससे खुद को **कार्बन तटस्थता** की दौड़ में अग्रणी के रूप में स्थापित किया जा सके।
- **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय** के अनुसार, भारत ने **वर्ष 2023** तक **180 गीगावॉट** से अधिक की **नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता** स्थापित की थी और **वर्ष 2030** तक **500 गीगावॉट** के अपने लक्ष्य को पूरा करने की उम्मीद है।
- जबकि **कार्बन डाइऑक्साइड शमन रणनीतियों** से दीर्घावधि में लाभ मिलेगा, उन्हें **अल्पकालिक राहत** प्रदान करने वाले प्रयासों के साथ-साथ चलने की आवश्यकता है।

<table>
<tr>
<td>
ब्लैक कार्बन प्रासंगिक क्यों है?
• ब्लैक कार्बन वह काला, कालिखयुक्त पदार्थ है जो बायोमास और जीवाश्म ईंधन के पूरी तरह से दहन नहीं होने पर अन्य प्रदूषकों के साथ उत्सर्जित होता है।
• यह ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है और गंभीर जोखिम पैदा करता है।
• अध्ययनों में ब्लैक कार्बन के संपर्क और हृदय रोग, जन्म संबंधी जटिलताओं और समय से पहले मृत्यु के उच्च जोखिम के बीच सीधा संबंध पाया गया है।
• वर्ष 2016 के एक अध्ययन के अनुसार, आवासीय क्षेत्र भारत के कुल ब्लैक कार्बन उत्सर्जन में 47% योगदान देता है।
• उद्योगों का योगदान 22%, डीजल वाहनों का 17%, खुले में जलने वाले वाहनों का 12% और अन्य स्रोतों का 2% है।
• पिछले दशक में उद्योग और परिवहन क्षेत्रों में डीकार्बोनाइजेशन प्रयासों से ब्लैक कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है, लेकिन आवासीय क्षेत्र एक चुनौती बना हुआ है।
क्या PMUY से मदद मिली?
• मई 2016 में, भारत सरकार ने कहा कि प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को मुफ्त तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) कनेक्शन प्रदान करेगी।
• प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण और गरीब परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन उपलब्ध कराना और पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन पर उनकी निर्भरता को कम करना था।
• PMUY ने LPG कनेक्शन के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित किया है, जिसमें मुफ्त गैस स्टोव, LPG सिलेंडर के लिए जमा राशि और एक वितरण नेटवर्क शामिल है।
• इस प्रकार, यह कार्यक्रम ब्लैक कार्बन उत्सर्जन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम है, क्योंकि यह पारंपरिक ईंधन खपत के लिए एक स्वच्छ विकल्प प्रदान करता है।
• हालाँकि, RTI डेटा के अनुसार, 2022-2023 में, सभी PMUY लाभार्थियों में से 25% (2.69 करोड़) लोगों ने या तो शून्य LPG रिफिल या केवल एक LPG रिफिल का लाभ उठाया, जिसका अर्थ है कि वे अभी भी खाना पकाने के लिए पूरी तरह से पारंपरिक बायोमास पर निर्भर हैं।
</td>
<td>
सरकार की भूमिका क्या है?
• इन क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने की कुंजी मुख्य रूप से स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन तक पहुंच सुनिश्चित करने में निहित है।
• जबकि भविष्य में नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने का वादा किया गया है, ग्रामीण समुदायों के लिए तत्काल लाभ LPG के उपयोग से आने की उम्मीद है।
• PMUY की सफलता में एक और बड़ी बाधा LPG वितरण नेटवर्क में अंतिम-मील कनेक्टिविटी की कमी है, जिसके परिणामस्वरूप दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्र ज्यादातर बायोमास पर निर्भर हैं।
• इस समस्या का एक संभावित समाधान बायोमास को कंपोस्ट करके कोल-बेड मीथेन (CBM) गैस का स्थानीय उत्पादन है।
• CBM कम ब्लैक-कार्बन उत्सर्जन और निवेश के साथ एक अधिक स्वच्छ ईंधन है।
• पंचायतें ग्राम स्तर पर स्थानीय स्तर पर CBM गैस का उत्पादन करने की पहल कर सकती हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन मिल सके।
</td>
</tr>
</table>

निष्कर्ष

- चूँकि भारत **दीर्घकालिक डीकार्बोनाइजेशन** की दिशा में **वैश्विक मंच** पर अपनी **जिम्मेदारियों को निभा** रहा है, इसलिए कार्रवाई करने की तत्काल आवश्यकता है।
- हाल के अनुमानों से संकेत मिलता है कि **आवासीय उत्सर्जन** को कम करने से घर के अंदर **वायु प्रदूषण** के संपर्क में आने से **प्रति वर्ष 6.1 लाख** से अधिक मौतों को रोका जा सकेगा।

161. चीन और ताइवान के बीच भू राजनैतिक संबंध - द हिन्दू

प्रासंगिकता: भारत के हितों, भारतीय प्रवासियों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव।

प्रसंग:

- **राष्ट्रीय हितों** के विस्तार के साथ, **भारत** के पास दूर के खतरों के खिलाफ कार्रवाई करने की मजबूत मजबूरियां हैं। **भारत ताइवान** सहित **एशिया** के **सुदूर** किनारों पर विवादों में अपने हितों को उलझा हुआ पाता है।

मुख्य बिंदु

- चीन ताइवान पर अपना दावा करता है, और जरूरत पड़ने पर बलपूर्वक द्वीप पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है, जबकि अमेरिका ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि वह शायद ताइवान की रक्षा के लिए लड़ेगा।
- भारत के ताइवान को लेकर संघर्ष करने की अत्यधिक संभावना नहीं है।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसा कोई संघर्ष कभी न हो, इसमें महत्वपूर्ण आर्थिक और सुरक्षा हित और मूल्यवान नीति लीवर हैं।

यथास्थिति बनाए रखने

- नई दिल्ली के पास ऐसा करने के तीन मुख्य कारण हैं। सबसे पहले, यथास्थिति में इसकी हिस्सेदारी है, ताइवान एक स्वशासित क्षेत्र है जो स्वतंत्रता की घोषणा नहीं करता है।
- भारत और ताइवान ने वर्ष 2001 के बाद से व्यापार को सात गुना बढ़ाया है और एक संभावित मुक्त व्यापार समझौते की तलाश कर रहे हैं।
- दूसरा, ताइवान के खिलाफ कोई भी चीनी आक्रामकता भारत के लिए बेहद महंगी होगी।
- ब्लूमबर्ग के एक हालिया अध्ययन का अनुमान है कि संघर्ष की लागत वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 10% से अधिक होगी।
- ताइवान पर संघर्ष एक ऐसी चीज़ है जिसे भारत बर्दाश्त नहीं कर सकता, खासकर जब वह राष्ट्रीय विकास के लिए स्थिरता और विकास चाहता है

भारत क्या कर सकता है

- बीजिंग निस्संदेह कम खर्चीले और विघटनकारी गैर-सैन्य तरीकों को अपनाना पसंद करेगा, जब तक वे व्यवहार्य बने रहेंगे।
- इसमें शामिल जोखिमों को देखते हुए, यह तभी सैन्य अभियान का सहारा लेगा जब यह संतुष्ट हो जाए कि इसने जीत के लिए पर्याप्त शर्तें निर्धारित कर दी हैं।
- इसलिए ताइवान जलडमरूमध्य में सैन्य संतुलन सबसे महत्वपूर्ण निवारक होगा, लेकिन भारत जैसे गैर-जुझारू राज्य बीजिंग को यह विश्वास दिलाकर कि उसने पर्याप्त रूप से शर्तें निर्धारित नहीं की हैं, रोकथाम को बढ़ावा दे सकता है।
- भारत के पास छह प्रकार के नीति विकल्प उपलब्ध हैं:
  - अंतर्राष्ट्रीय कानून तर्क
  - आक्रामकता के विरोध में आख्यान तैयार करना
  - समन्वित राजनयिक संदेशवाहक
  - आर्थिक जोखिम कम करना
  - ताइवानी लोगों का समर्थन करने के लिए सक्रिय सूचना संचालन
  - हिंद महासागर में अमेरिकी सेना को सैन्य सहायता।
- चीन-ताइवान विवाद पर उनके प्रभाव की परवाह किए बिना, ये विकल्प भारत की भव्य रणनीतिक स्थिति को भी आगे बढ़ा सकते हैं।
- इसलिए, ऐसी नीतियां ताइवान या अमेरिका के लिए अनुकूल नहीं हैं; वे भारतीय स्वार्थ का कार्य होंगी।

निष्कर्ष

- राजनीतिक संदर्भ के आधार पर वे **चीनी प्रतिशोध** को आमंत्रित कर सकते हैं लेकिन कोई भी नीति लागत मुक्त नहीं है, और **भारत** ने हाल ही में आवश्यकता पड़ने पर **चीनी अपमान** का सामना करने के लिए कड़ी इच्छा दिखाई है।
- **भारत** के बढ़ते हित और महत्वाकांक्षाएं विभिन्न **नीति सेटिंग्स** की आवश्यकता का सुझाव देती हैं, और ऐसी **नीतियों** की लागत कुछ न करने की लागत से कम हो जाएगी।

162. विश्व व्यापार संगठन (WTO) का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन -द हिंदू

प्रासंगिकता: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधन जुटाने, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे।

समाचार:

- **अबू धाबी** में **विश्व व्यापार संगठन (WTO)** के **13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC13)** में महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक विकास के लिए **निवेश सुविधा (IFD)** पर समझौते को न अपनाना था।

मुख्य बिंदु

- भारत जैसे देशों के विरोध के बावजूद, WTO में IFD समझौते के लिए बातचीत वर्ष 2017 में 70 देशों द्वारा बहुपक्षीय आधार पर शुरू की गई थी।
- यह संयुक्त वक्तव्य पहल नामक एक प्रक्रिया के माध्यम से किया गया था।
- इस समझौते का उद्देश्य निवेश प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रावधान बनाना है।
- अबू धाबी में, ये 120 देश WTO समझौते के अनुबंध 4 के भीतर IFD समझौते को बहुपक्षीय समझौते (PA) के रूप में शामिल करना चाहते थे।
- ये PA उन WTO सदस्य देशों को बाध्य करते हैं जो उन्हें स्वीकार करते हैं और शेष सदस्यों पर अधिकार नहीं बनाते हैं या दायित्व नहीं थोपते हैं।

भारत की चिंताएं

- IFD समझौते में, अन्य बातों के अलावा, राज्यों को नियामक पारदर्शिता बढ़ाने और विदेशी निवेश प्रवाह को बढ़ाने के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता होगी।
- महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समझौते में बाजार पहुंच, निवेश सुरक्षा और निवेशक-राज्य विवाद निपटान (ISDS) पर प्रावधान शामिल नहीं हैं।
- ISDS, जो विदेशी निवेशकों को निवेश स्वीकार करने वाले राज्य के खिलाफ संधि दावे लाने की अनुमति देता है, हाल के वर्षों में एक विवादास्पद मुद्दा रहा है।

निवेश व्यापार नहीं है

- इस पर कि क्या निवेश WTO का हिस्सा हो सकता है, भारत का मुख्य तर्क यह है कि निवेश अपने आप में व्यापार नहीं है।
- आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के अनुसार, लगभग 70% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के माध्यम से होता है
  - जो व्यापार और निवेश की विशेषता है, इस प्रकार दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध साबित होता है।
- इसलिए, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि कई आधुनिक मुक्त व्यापार समझौते, जैसे कि क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP) और ट्रांस-पैसिफ़िक साझेदारी के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में सुविधा और सुरक्षा दोनों को कवर करने वाले विस्तृत निवेश प्रावधान शामिल हैं।
- दिलचस्प बात यह है कि यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ भारत के नवनिर्मित व्यापार समझौते में निवेश के प्रावधान भी शामिल हैं
  - हालाँकि यह सुविधा और प्रचार उपायों तक ही सीमित है।
- भारत ने तर्क दिया कि वर्ष 2004 में, WTO की जनरल काउंसिल ने फैसला किया कि व्यापार और निवेश के बीच संबंधों पर बातचीत तथाकथित 'सिंगापुर मुद्दों' में से एक है
  - क्योंकि इसे वर्ष 1996 के WTO सिंगापुर मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में पेश किया गया था
  - जो 2001 में शुरू हुई दोहा दौर की वार्ता के हिस्से के रूप में नहीं होगी।

निष्कर्ष

- WTO का एक अनिवार्य कार्य **अंतरराष्ट्रीय व्यापार** की बढ़ती जटिल प्रकृति को नियंत्रित करने के लिए मौजूदा नियमों को अद्यतन करना और नए नियम बनाना है।
- हालाँकि, सर्वसम्मति पर पहुंचने में भारी कठिनाइयों के कारण **WTO** की निर्णय लेने की प्रक्रिया गतिरोध बनी हुई है।
- इस दृष्टिकोण से, **IFD** समझौते जैसे PA WTO के गतिरोध वाले विधायी कार्य को फिर से मजबूत करने के लिए आवश्यक हैं।
- भारत, जो जल्द ही **तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था** होगी, को **PA** के प्रति अपने रक्षात्मक दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करना चाहिए, जैसा कि **WTO** में प्रस्तावित **IFD** समझौते में है।

163. भारत में इंटरनेट स्वतंत्रता से सम्बन्धित मामला - द हिंदू

प्रासंगिकता: विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप और उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

प्रसंग:

- लगातार **पांच वर्षों** से, **भारत इंटरनेट प्रतिबंध** लगाने वाले देशों की **वैश्विक सूची** में शीर्ष पर है, **वर्ष 2016** और **वर्ष 2022** के बीच दुनिया में दर्ज किए गए सभी **ब्लैकआउट** में से **लगभग 60% भारत** में हुए हैं।
- पिछले दशक में राज्य द्वारा लगाए गए **शटडाउन** ने **राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था** के लिए ख़तरे का हवाला दिया है।

इंटरनेट शटडाउन

- सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर (SFLC) द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार, भारत सरकार ने 1 जनवरी 2014 से 31 दिसंबर 2023 के बीच कुल 780 शटडाउन लगाए।
- वर्ष 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और 2020 में फार्म बिल पेश करने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान शटडाउन फ्लारेड हो गया।
- वर्ष 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था को हुए कुल नुकसान में भारत में इंटरनेट व्यवधानों का योगदान 70% से अधिक था।
- भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम के अनुसार, भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केवल "सार्वजनिक आपातकाल" या "सार्वजनिक सुरक्षा" के हित में इंटरनेट शटडाउन लगा सकते हैं।
- हालाँकि, कानून यह परिभाषित नहीं करता है कि आपातकालीन या सुरक्षा मुद्दा क्या है।

अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ मामला

- अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ के ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि इंटरनेट शटडाउन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
  - और अनिश्चित काल तक चलने वाला शटडाउन असंवैधानिक है।
- इसके अलावा, अदालतों ने सरकारों से शटडाउन आदेशों को सार्वजनिक करने के लिए कहा है, विशेषज्ञों ने नोट किया है कि इस प्रावधान का पालन बहुत ही खराब तरीके से किया गया है।

प्रतिबंध का कारण

- SFLC डेटा के अनुसार, वर्ष 2015 और वर्ष 2022 के बीच 55,000 से अधिक वेबसाइटें ब्लॉक की गईं है।
- सेंसर की गई सामग्री का सबसे बड़ा हिस्सा आईटी अधिनियम की धारा 69A के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया गया था।
- गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत प्रतिबंधित संगठनों के लिंक के कारण URL ब्लॉक कर दिए गए थे।
- वेबसाइटों को ब्लॉक करने का आम तौर पर उद्धृत कारण साइबर अपराध का बढ़ता खतरा है।

भारत और वैश्विक रुझान

- फ्रीडम हाउस की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक इंटरनेट स्वतंत्रता में लगातार 13वें वर्ष गिरावट आई है और 29 देशों में ऑनलाइन मानवाधिकारों के लिए माहौल खराब हो गया है।
- पिछले तीन वर्षों में भारत की रैंकिंग इसी बेंचमार्क के आसपास रही है।
- यह वर्ष 2016 और वर्ष 2017 से गिरावट है, जब भारत ने 2023 में 59 अंक से 50 अंक प्राप्त किए थे।

164. केरल सरकार अपने विधेयकों पर राष्ट्रपति की मंजूरी रोकने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची-इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली - सरकार के मंत्रालय और विभाग; दबाव समूह और औपचारिक/अनौपचारिक संघ और राज्य व्यवस्था में उनकी भूमिका।

समाचार:

- **केरल सरकार** द्वारा पिछले हफ्ते **सुप्रीम कोर्ट** में याचिका दायर की गई और कहा कि **राष्ट्रपति** ने राज्य द्वारा पारित **चार विधेयकों** पर बिना कोई कारण बताए मंजूरी रोक दी है।

- **राज्यपाल** ने **सात विधेयकों** को **राष्ट्रपति** के पास भेजने से पहले **दो साल** तक उनकी सहमति रोक रखी थी।
- **केरल** ने शीर्ष अदालत से आग्रह किया कि **राज्य** के **विधेयकों** को **राष्ट्रपति** के पास भेजे जाने को **"असंवैधानिक और सद्भावना की कमी"** घोषित किया जाए।

राज्यपाल की भूमिका • **भारतीय संविधान राज्यपाल** को राज्य की कानून बनाने की प्रक्रिया में एक भूमिका देता है, लेकिन इससे मतभेद पैदा हो सकता है। **राज्यपाल के विकल्प:** • **विधेयक को मंजूरी:** यह सबसे आम परिदृश्य है। • **सहमति रोकना:** राज्यपाल विधेयक को कानून बनने से अस्थायी रूप से रोक सकते हैं। वे विधायिका से इस पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकते हैं। • **राष्ट्रपति को भेजें:** कुछ मामलों में, राज्यपाल विधेयक को समीक्षा के लिए राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। **विवाद: बहुत अधिक समय लगना** • संविधान यह निर्दिष्ट नहीं करता है कि राज्यपाल को किसी विधेयक पर कितने समय तक निर्णय लेना है। • कुछ राज्यपाल लंबे समय तक विधेयकों को रोके रखते हैं, जिससे कानून निर्माता निराश होते हैं।	**स्टेट्स फाइटिंग बैक** • कई **राज्य सरकारें** यह तर्क देते हुए अदालत में गई हैं कि **राज्यपाल निर्णयों** में देरी करके अपने **अधिकारों का उल्लंघन** कर रहे हैं। **राष्ट्रपति की भूमिका:** • **राष्ट्रपति** की भूमिका **राज्यपाल** की तुलना में अधिक सीमित है। • **राष्ट्रपति समीक्षा** के लिए भेजे गए विधेयकों को या तो मंजूरी दे सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं, लेकिन **राज्यपालों** के विपरीत, **राष्ट्रपति** को किसी विधेयक को अस्वीकार करने का कारण बताना होगा।

मुद्दा अभी भी बना हुआ है:

- हालाँकि **न्यायालय** का निर्णय **राज्यपाल** की ज़िम्मेदारी को स्पष्ट करता है, लेकिन यह निर्णय लेने के लिए कोई विशिष्ट **समय-सीमा** नहीं देता है।
- इसका मतलब है कि संघर्ष की संभावना बनी रहती है। **सुप्रीम कोर्ट** में **केरल सरकार** की हालिया याचिका इस चल रही बहस पर प्रकाश डालती है।

165. सतत निर्माण सामग्री पारंपरिक निर्माण सामग्री के पर्यावरण के अनुकूल - द हिंदू

प्रासंगिकता: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधन जुटाने, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे।

प्रसंग:

- **भारत** में **निर्माण कार्यों** में अभूतपूर्व तेजी देखी जा रही है, जिसमें **सालाना 3,00,000** से अधिक आवास **इकाइयां** बनाई जा रही हैं।
- यह **वृद्धि आर्थिक अवसर** और बेहतर **जीवन स्तर** लाती है लेकिन महत्वपूर्ण **पर्यावरणीय चुनौतियाँ** भी पैदा करती है।
- **भवन निर्माण क्षेत्र**, एक **प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता**, भारत के **बिजली उपयोग** का **33%** से अधिक हिस्सा है, जो **पर्यावरणीय गिरावट** और **जलवायु परिवर्तन** में योगदान देता है।
- **इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान** में **वर्ष 2017** और **वर्ष 2037** के बीच **कूलिंग** मांग में **आठ गुना वृद्धि** का अनुमान लगाया गया है, जिसमें सक्रिय **कूलिंग** मांग को कम करते हुए **थर्मल** आराम की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

इको-निवास संहिता:

- यह ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) द्वारा विकसित एक आवासीय ऊर्जा संरक्षण भवन कोड है।
- कोड गर्मी के लाभ और हानि को सीमित करने और पर्याप्त प्राकृतिक वेंटिलेशन और दिन की रोशनी की क्षमता सुनिश्चित करने के लिए मानक निर्धारित करता है।

इसे दो भागों में लॉन्च किया गया था

- ENS 2018 (भाग 1) ऊर्जा-कुशल आवासीय भवनों के निर्माण के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करता है।
- ब्यूरो द्वारा ENS 2021 के रूप में लॉन्च किया गया ENS भाग 2 बिल्डिंग के कोड अनुपालन और इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम पर केंद्रित है।
- यह अन्य पहलुओं को भी संबोधित करता है, जैसे भवन संचालन के लिए इलेक्ट्रो-मैकेनिकल उपकरण में ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, दीवार सामग्री और संरचनात्मक प्रणालियों की सन्निहित ऊर्जा।

आवासीय लिफाफा संप्रेषण मूल्य

- यह एक इमारत के आवरण के माध्यम से गर्मी हस्तांतरण को मापने वाला एक मीट्रिक है।
- कम आरईटीवी मूल्यों से इनडोर वातावरण ठंडा हो जाता है और ऊर्जा का उपयोग कम हो जाता है।
- इष्टतम दक्षता, बेहतर रहने वाले आराम और कम उपयोगिता व्यय के लिए, 15W/m2 या उससे कम का RETV बनाए रखने की अनुशंसा की जाती है।

आगे की राह

- **एकीकृत डिजाइन** में गहराई से उतरने और **रणनीतियों** को अनुकूलित करने के लिए **स्थिरता विशेषज्ञों** के साथ **अंतःविषय** सहयोग एक **सतत निर्मित वातावरण** की क्षमता को अनलॉक कर सकता है।
- **सतत निर्माण** की ओर **यात्रा चुनौतीपूर्ण** है लेकिन **हरित भविष्य** के लिए आवश्यक है।
- **निर्माण डिजाइन** और **गतिविधियों** की फिर से कल्पना करके, अभिनव **दीवार सामग्री** का निर्माण करके, और **स्थिरता** की **संस्कृति** को बढ़ावा देकर, हम **लचीली** और **ऊर्जा-कुशल संरचनाएं** बना सकते हैं जो **पर्यावरणीय लक्ष्यों** के साथ संरेखित होती हैं और जनता के जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार करती हैं।

166. अंतरराष्ट्रीय परिवहन गलियारों के लिए भारत के प्रयास - द प्रिंट

प्रासंगिकता: विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का भारत के हितों, प्रवासी भारतीयों पर प्रभाव।

प्रसंग

- **पूर्व** से **पश्चिम** तक, **भारत** आज प्रमुख **अंतरराष्ट्रीय परिवहन गलियारों** का नेतृत्व कर रहा है जो अंततः **अटलांटिक** को **एशिया** के माध्यम से **प्रशांत महासागर** से जोड़ देगा।

मुख्य बिंदु

- प्रधानमंत्री इन गलियारों के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं
  - अरब प्रायद्वीप के माध्यम से भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) पहल
  - पश्चिम में अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) से दक्षिण पूर्व एशिया में त्रिपक्षीय राजमार्ग तक
  - पूर्व में चेन्नई-व्लादिवोस्तोक मार्ग।
- जबकि IMEC का लक्ष्य भारत को रेल और समुद्री संपर्क के माध्यम से अरब प्रायद्वीप के माध्यम से यूरोप से जोड़ना है
- दो दशक पहले INSTC की अवधारणा 7,200 किलोमीटर तक फैली हुई है, जिसमें जहाज, रेल और सड़क मार्ग शामिल हैं जो भारत को ईरान और मध्य एशिया से रूस तक जोड़ते हैं।
- चेन्नई-व्लादिवोस्तोक गलियारा रूस के सुदूर पूर्व के साथ भारत की कनेक्टिविटी का वादा करता है।
- INSTC का शुरू में इरादा ईरान के माध्यम से भारत से रूस तक माल भेजने का था। माल का पहला सेट ज़ुलाई 2022 में ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह के माध्यम से स्थानांतरित किया गया था।
- INSTC को ईरान और रूस जैसे स्वीकृत देशों के लिए एक व्यवहार्य समाधान के रूप में देखा गया है।
- विदेश मंत्री ने IMEC और एक अन्य क्षेत्रीय कनेक्टिविटी परियोजना को भारत-म्यांमार-थाईलैंड (IMT) त्रिपक्षीय राजमार्ग से जोड़ना शुरू कर दिया है।

आर्थिक गलियारों के लिए वैश्विक दबाव बढ़ रहा है

- त्रिपक्षीय राजमार्ग वर्ष 2001 से दक्षिण एशिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (SASEC) कार्यक्रम का एक हिस्सा रहा है।
- यह कार्यक्रम सीमा पार कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने और देशों के बीच तेजी से व्यापार कनेक्शन की सुविधा के लिए बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका को एक साथ लाता है।

वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिए साझेदारी (PGII)

- G7 ने 2021 में इस बुनियादी ढांचे की कमी को पहचाना जब उसने बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड (B3W) की घोषणा की गई है।
- B3W का लक्ष्य विकासशील दुनिया में 40 ट्रिलियन डॉलर के बुनियादी ढांचे के अंतर को पाटना और BRI का विकल्प पेश करना है।
- वर्ष 2023 में जापान के हिरोशिमा में G7 नेताओं के शिखर सम्मेलन के मौके पर इन प्रयासों को अंततः ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट (PGII) के लिए साझेदारी का नाम दिया गया।
- IMEC भारत के पश्चिमी तट से संयुक्त अरब अमीरात तक माल भेजेगा और रेल के माध्यम से सऊदी अरब और फिर संभवतः जॉर्डन के माध्यम से इज़राइल तक यात्रा करेगा।
  - मूल समझौता ज्ञापन पर न तो इज़राइल और न ही जॉर्डन ने हस्ताक्षर किए।

वैश्विक गठबंधनों की झलक

- BRI के एक भाग के रूप में, 2017 में, चीन ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए पहले बेल्ट एंड रोड फोरम (BRI फोरम) की मेजबानी की है।
- इस कार्यक्रम में 130 से अधिक देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधिमंडलों के साथ-साथ 29 राष्ट्राध्यक्षों और सरकारों ने भाग लिया।
- भारत ने फोरम में भाग लेने से इनकार कर दिया और यहां तक कि इस पहल में शामिल होने से भी इनकार कर दिया।
- वर्ष 2023 में आयोजित तीसरे फोरम में अंतरराष्ट्रीय मान्यता की कमी के बावजूद तालिबान की उपस्थिति देखी गई, जो वर्ष 2021 से अफगानिस्तान में सत्ता में रहे संगठन के साथ बीजिंग के बढ़ते संबंधों को रेखांकित करता है।
- सितंबर 2023 में IMEC की घोषणा के ठीक बाद तुर्की ने अपना स्वयं का "इराक डेवलपमेंट रोड" प्रस्तावित किया।
- इस परियोजना के तहत माल को इराक के अंतिम छोर पर ग्रैंड फॉ बंदरगाह पर स्थानांतरित किया जाएगा और फिर यूरोप पहुंचने से पहले जमीन के रास्ते तुर्की ले जाया जाएगा।

GEO IAS
It's about quality

फैक्ट फटाफट

1. वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम(VSHORADS)

- हाल ही में, DRDO ने वेरी शॉर्ट-रेंज एयर डिफेंस सिस्टम (VSHORADS) मिसाइल के दो उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किए।
- VSHORADS एक चौथी पीढ़ी का मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम (MANPAD) है जिसे विशेष रूप से कम दूरी पर कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- ये कम दूरी की, हल्की और पोर्टेबल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं जिन्हें व्यक्तियों या छोटे समूहों द्वारा दागा जा सकता है।
- इसे DRDO के अनुसंधान केंद्र इमारत (RCI), हैदराबाद द्वारा अन्य DRDO प्रयोगशालाओं और भारतीय उद्योग भागीदारों के सहयोग से स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है।
- प्रमुख विशेषताऐं
  - इसे जमीनी बलों और महत्वपूर्ण संपत्तियों को हवाई खतरों से बचाने के लिए कम दूरी की वायु रक्षा क्षमताएं प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
  - इसमें कई नवीन तकनीकों को शामिल किया गया है, जिसमें एक डुअल-बैंड IIR सीकर, एक लघु प्रतिक्रिया नियंत्रण प्रणाली और एकीकृत एवियोनिक्स शामिल हैं।
  - यह डुअल-थ्रस्ट सॉलिड मोटर द्वारा संचालित होता है।
  - मिसाइल और इसका लांचर पोर्टेबल हैं, जो कठिन इलाके में उनकी त्वरित तैनाती को सक्षम बनाता है।

2. बायोट्रिग

- एक हालिया अध्ययन में दावा किया गया है कि पायरोलिसिस प्रणाली पर आधारित एक नई अपशिष्ट प्रबंधन तकनीक BioTRIG ग्रामीण भारतीयों की मदद कर सकती है।
- यह कचरे को ऑक्सीजन मुक्त कक्ष के अंदर सील करके काम करता है और इसे 400 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म करने से इस प्रक्रिया में उपयोगी रसायन उत्पन्न होते हैं।
- शोधकर्ताओं ने पायरोलिसिस के तीन उत्पादों अर्थात जैव-तेल, सिनगैस और बायोचार उर्वरक की रूपरेखा तैयार की, जो ग्रामीण भारतीयों को स्वस्थ और हरित जीवन जीने में मदद कर सकते हैं।
- महत्व
  - सिनगैस और बायो-ऑयल भविष्य के चक्रों में पायरोलिसिस प्रणाली को गर्मी और बिजली प्रदान करते हैं और अतिरिक्त बिजली का उपयोग स्थानीय घरों और व्यवसायों को बिजली देने के लिए किया जाता है।
  - पर्यावरण के अनुकूल बायो-ऑयल का उपयोग घरों में पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन के विकल्प के रूप में किया जाता है, और बायोचार का उपयोग कार्बन भंडारण, मिट्टी की गुणवत्ता और उर्वरता बढ़ाने के लिए किया जाता है।
  - यह समुदायों से प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष लगभग 350 किलोग्राम CO2-eq तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकता है।
  - यह ग्रामीण भारतीयों को घर के अंदर वायु प्रदूषण को कम करने, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करने और स्वच्छ बिजली पैदा करने में मदद कर सकता है।

3. जूस जैकिंग

- हाल ही में RBI ने जूस जैकिंग को लेकर मोबाइल फोन यूजर्स के लिए एक चेतावनी संदेश जारी किया है।
- "जूस जैकिंग" शब्द पहली बार वर्ष 2011 में खोजी पत्रकार ब्रायन क्रेब्स द्वारा गढ़ा गया था।
- यह साइबर हमले का एक रूप है जहां डेटा चोरी करने या उससे जुड़े उपकरणों पर मैलवेयर इंस्टॉल करने के लिए सार्वजनिक USB चार्जिंग पोर्ट से छेड़छाड़ की जाती है।
- इस हमले का उपयोग हैकर्स द्वारा लक्षित डिवाइस पर संग्रहीत उपयोगकर्ताओं के पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड की जानकारी, पते और अन्य संवेदनशील डेटा को चुराने के लिए किया जाता है।

4. जीन थेरेपी

- हाल ही में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि भारत ने 'हीमोफीलिया A' के लिए जीन थेरेपी का पहला मानव नैदानिक परीक्षण किया है।
- जीन थेरेपी एक ऐसी तकनीक है जो बीमारी का इलाज या इलाज करने के लिए किसी व्यक्ति के जीन को संशोधित करती है।
- जीन थेरेपी कई तंत्रों द्वारा काम कर सकती है जैसे
  - रोग पैदा करने वाले जीन को जीन की स्वस्थ प्रतिलिपि से बदलना
  - रोग पैदा करने वाले जीन को निष्क्रिय करना जो ठीक से काम नहीं कर रहा है
  - किसी बीमारी के इलाज में मदद के लिए शरीर में एक नया या संशोधित जीन प्रविष्ट करना
- कैंसर, आनुवांशिक बीमारियों और संक्रामक रोगों सहित बीमारियों के इलाज के लिए जीन थेरेपी उत्पादों का अध्ययन किया जा रहा है।

5. रोएन ओलमी

- हाल ही में, गोवा में शोधकर्ताओं ने तटीय राज्य में व्यापक रूप से स्वादिष्ट व्यंजन के रूप में खाई जाने वाली जंगली मशरूम प्रजाति से सोने के नैनोकणों का संश्लेषण किया।
- रोएन ओलमी टर्मिटोमाइसेस प्रजाति का एक मशरूम है जो दीमक की पहाड़ियों पर उगता है।
  - इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है ये केवल दीमकों के सहयोग से ही बढ़ते हैं।
- यह एक खाने योग्य जंगली मशरूम है जो गोवा वासियों के बीच लोकप्रिय है और मानसून के दौरान खाया जाता है।
- यह पश्चिमी घाट के लिए स्थानिक है, जहां घने जंगल और उच्च आर्द्रता एक आदर्श प्रजनन भूमि प्रदान करते हैं।
- यह जंगल और घास के मैदानों के पारिस्थितिक तंत्र में एक शक्तिशाली बायोडिग्रेडिंग कवक के रूप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो जमीन पर 50% मृत पौधों की सामग्री को समृद्ध मिट्टी में परिवर्तित करता है।
- इसके अतिरिक्त, टर्मिटो-माइसेज़ को पूरे एशिया और अफ्रीका में विभिन्न स्वदेशी समुदायों में उनके जातीय-औषधीय महत्व के लिए मान्यता दी गई है।

6. GRAPES-3 एक्सपेरिमेंट

- GRAPES-3 को एयर शावर डिटेक्टरों की एक श्रृंखला और एक बड़े क्षेत्र म्यूऑन डिटेक्टर के साथ ब्रह्मांडीय किरणों का अध्ययन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- भारत के ऊटी में स्थित, यह टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च द्वारा संचालित है।
- इसका उद्देश्य विभिन्न खगोल भौतिकी सेटिंग्स में ब्रह्मांडीय किरणों के त्वरण की जांच करना है।
- उद्देश्य: अध्ययन करना
  - आकाशगंगा और उससे आगे >1014 eV ब्रह्मांडीय किरणों की उत्पत्ति, त्वरण और प्रसार।
  - ब्रह्मांडीय किरणों के ऊर्जा स्पेक्ट्रम में "घुटने" का अस्तित्व।
  - ब्रह्मांड में उच्चतम ऊर्जा (~1020 eV) कॉस्मिक किरणों का उत्पादन और/या त्वरण।
  - न्यूट्रॉन सितारों और अन्य कॉम्पैक्ट वस्तुओं से मल्टी-टीईवी γ-किरणों का खगोल विज्ञान।
- GRAPES-3 प्रयोग ने हाल ही में लगभग 166 टेरा-इलेक्ट्रॉन-वोल्ट (TeV) ऊर्जा पर कॉस्मिक-रे प्रोटॉन स्पेक्ट्रम में एक नई सुविधा की खोज की, जबकि स्पेक्ट्रम को 50 TeV से लेकर 1 पेटा-इलेक्ट्रॉन-वोल्ट (PeV) से थोड़ा अधिक तक मापा गया।

7. ओबिलिस्क

- ओबिलिस्क मानव शरीर में मौजूद वायरस जैसी संस्थाओं का एक नया खोजा गया वर्ग है।
- इसमें विविध RNA का एक वर्ग शामिल है जो मानव और वैश्विक माइक्रोबायोम में उपनिवेशित हो गया है और किसी का ध्यान नहीं गया है।
- RNA की उनकी मुड़ी हुई लंबाई से बनी अत्यधिक सममित, रॉड जैसी संरचनाओं के नाम पर, ओबिलिस्क के आनुवंशिक अनुक्रम आकार में केवल 1,000 वर्ण (न्यूक्लियोटाइड) के आसपास हैं।

- आनुवंशिक सामग्री के इन रहस्यमय टुकड़ों में कोई पता लगाने योग्य अनुक्रम या यहां तक कि किसी अन्य जैविक एजेंटों के लिए ज्ञात संरचनात्मक समानताएं भी नहीं हैं।
- वे अन्य आनुवंशिक अणुओं की तुलना में भी काफी बड़े होते हैं जो पौधों से लेकर बैक्टीरिया तक कोशिकाओं के अंदर सह-अस्तित्व में रहते हैं, जिन्हें प्लास्मिड कहा जाता है, जो आमतौर पर DNA से बने होते हैं।
- ओबिलिस्क जीवों के अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे वायरस और वाइरोइड के बीच कहीं स्थित होते हैं।
- हालाँकि अन्य ओबिलिस्क के मेजबान अज्ञात हैं, ऐसी संभावना है कि उनमें से कुछ बैक्टीरिया में पाए जा सकते हैं।
- हमारे शरीर के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के ओबिलिस्क मौजूद दिखाई देते हैं।

8. जम्मू-कश्मीर में ओबीसी आरक्षण

- केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण प्रदान करने के लिए लोकसभा में एक नया विधेयक पेश किया है।
- इस कानून का उद्देश्य मौजूदा कानूनों को संवैधानिक प्रावधानों के साथ संरेखित करना है।
- यह भारत की आजादी के बाद पहली बार पंचायतों और नगर पालिकाओं में ओबीसी के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा।
- प्रस्तावित जम्मू और कश्मीर स्थानीय निकाय कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 प्रासंगिक अधिनियमों में संशोधन करके उन्हें संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप लाने का प्रयास करता है।
- यह विधेयक स्थानीय शासन में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण से संबंधित प्रावधानों को प्रभावित करेगा।
- वर्तमान में, जम्मू-कश्मीर में इन स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है।
- विधेयक का उद्देश्य कानून पारित होने के बाद आरक्षित सीटों की संख्या निर्धारित करने के लिए एक आयोग को सशक्त बनाकर इस अंतर को संबोधित करना है।

9. व्योमित्र

- भारत वर्ष 2025 में अपने मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान की तैयारी कर रहा है।
- देश पहले महत्वपूर्ण प्रणालियों का परीक्षण करने के लिए व्योममित्र नामक एक ह्यूमनॉइड रोबोट को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बना रहा है।
- व्योममित्र, जिसका वजन 40 किलोग्राम है और इसरो द्वारा विकसित किया गया है।
- यह अंतरिक्ष यान की कक्षा के भीतर मानवीय कार्यों का अनुकरण करेगा।
- यह नियंत्रण पैनल संचालित करने, मापदंडों की निगरानी करने, जीवन समर्थन संचालन करने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके बातचीत में संलग्न होने के लिए सुसज्जित है।
- व्योममित्र का लक्ष्य चालक दल की उड़ानों से पहले गगनयान मॉड्यूल की रहने योग्य स्थिति और सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
- उनकी तैनाती भविष्य के गगनयान मिशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

10. हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल लक्ष्य "ABHYAS (अभ्यास)"

- हाल ही में, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने हाई-स्पीड एक्सपेंडेबल हवाई लक्ष्य 'अभ्यास' के चार उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किए।
- अभ्यास एक हाई-स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट (HEAT) है।
- इसे DRDO के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान (ADE) द्वारा डिजाइन किया गया है।
- यह हथियार प्रणालियों के अभ्यास के लिए एक यथार्थवादी खतरे का परिदृश्य प्रस्तुत करता है।
- यह सशस्त्र बलों में शामिल किए जाने वाले उपकरणों के सत्यापन के लिए आदर्श मंच है (केवल वे उपकरण जिन्हें हवाई हमले की आवश्यकता होती है)।
- इसे ADE द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित ऑटोपायलट की मदद से स्वायत्त उड़ान के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- इसमें हथियार अभ्यास के लिए आवश्यक एक रडार क्रॉस-सेक्शन और एक दृश्य और अवरक्त वृद्धि प्रणाली है।
- लक्ष्य ड्रोन में एक लैपटॉप-आधारित ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम होता है जिसके साथ विमान को एकीकृत किया जा सकता है और उड़ान पूर्व जांच, उड़ान के दौरान डेटा रिकॉर्डिंग, उड़ान के बाद रीप्ले और उड़ान के बाद विश्लेषण किया जा सकता है।

11. इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट (ICIMOD)

- हाल ही में, ICIMOD के विशेषज्ञों ने हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र को विनाश के कगार पर एक जीवमंडल घोषित किया और प्रकृति के नुकसान को रोकने के लिए साहसिक कार्रवाई और तत्काल वित्त का आह्वान किया।
- ICIMOD, 1983 में स्थापित, हिंदू कुश हिमालय (HKH) के लोगों की ओर से काम करने वाला एक अंतर-सरकारी ज्ञान और शिक्षण केंद्र है।
- मिशन: ज्ञान का निर्माण और साझा करना जो क्षेत्रीय नीति और कार्रवाई को संचालित करता है और निवेश को आकर्षित करता है जो एचकेएच के विविध देशों और समुदायों को हरित, अधिक समावेशी और जलवायु-लचीला विकास में बदलने में सक्षम बनाता है।
- सदस्य देश: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान।
- मुख्यालय: काठमांडू, नेपाल
- कार्य
  - यह महत्वपूर्ण पर्वतीय समस्याओं के नवीन समाधान खोजने के लिए सूचना और ज्ञान सृजन और साझाकरण के माध्यम से क्षेत्र की सेवा करता है।
  - यह विज्ञान को नीतियों और ज़मीनी प्रथाओं से जोड़ता है।
  - यह एक क्षेत्रीय मंच प्रदान करता है जहां विशेषज्ञ, योजनाकार, नीति निर्माता और व्यवसायी सतत पर्वतीय विकास की उपलब्धि के लिए विचारों और दृष्टिकोणों का आदान-प्रदान कर सकते हैं।

12. एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन

- यह भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास "डेज़र्ट साइक्लोन 2024" का उद्घाटन संस्करण है।
- यह 2 जनवरी से 15 जनवरी तक राजस्थान में आयोजित किया जाएगा।
- इस अभ्यास का उद्देश्य शहरी परिचालन में सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखने और साझा करके अंतरसंचालनीयता को बढ़ाना है।
- यह अभ्यास रणनीतिक साझेदारी में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हो रहा है।

13. राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड

- NJDG ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में बनाए गए न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामले के विवरण का एक डेटाबेस है।
- इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा कंप्यूटर सेल रजिस्ट्री के समन्वय से विकसित किया गया है।
- डेटा को कनेक्टेड जिला और तालुका अदालतों द्वारा लगभग वास्तविक समय के आधार पर अपडेट किया जाता है।
- राष्ट्रीय डेटा शेयरिंग और एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी (NDSAP) के अनुरूप, NJDG केंद्र और राज्य सरकारों को एक ओपन एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (API) प्रदान करता है।
- इसके माध्यम से कोई भी मामले से संबंधित जानकारी, संस्था, लंबित मामलों और मामलों के निपटान, मामले के प्रकार, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वर्ष-वार विवरण जैसे आंकड़ों तक पहुंच सकता है।

14. सवेरा प्रोग्राम

- हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने गुड़गांव में मेदांता फाउंडेशन और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से सवेरा कार्यक्रम का उद्घाटन किया।
- स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने और रोकथाम करने के उद्देश्य से, इस पहल में दृष्टिबाधित व्यक्तियों का उपयोग उनकी बढ़ी हुई स्पर्श संवेदनशीलता के कारण स्क्रीनिंग के लिए किया जाता है।
  - शहरी क्षेत्रों में महिलाओं में स्तन कैंसर को एक प्रचलित कैंसर प्रकार के रूप में उजागर किया गया है।
  - भारत में प्रतिदिन लगभग 90,000 महिलाएं स्तन कैंसर से अपनी जान गंवाती हैं।
- दृष्टिबाधित व्यक्ति आधे सेंटीमीटर में भी स्तन कैंसर के घावों का पता लगा सकते हैं, जबकि एक सामान्य डॉक्टर एक सेंटीमीटर में ही स्तन कैंसर के घावों का पता लगा सकता है।
- अपने प्रारंभिक चरण में, कार्यक्रम सेक्टर 10 के सिविल अस्पताल, सेक्टर 31 के पॉलीक्लिनिक और वज़ीराबाद के PHC में लॉन्च किया जाएगा।

15. PSiFI सिस्टम

- हाल ही में, वैज्ञानिकों ने एक अग्रणी तकनीक का अनावरण किया, जिसका नाम पर्सनलाइज्ड स्किन-इंटीग्रेटेड फेशियल इंटरफ़ेस (PSiFI) है, जो वास्तविक समय में मानवीय भावनाओं को पहचानने में सक्षम है।
- यह तकनीक "घर्षण चार्जिंग" की घटना पर आधारित है, जहां घर्षण पर वस्तुएं सकारात्मक और नकारात्मक चार्ज में अलग हो जाती हैं।
- सिस्टम में अपनी तरह का पहला द्विदिश ट्राइबोइलेक्ट्रिक स्ट्रेन और कंपन सेंसर है जो मौखिक और गैर-मौखिक अभिव्यक्ति डेटा के एक साथ संवेदन और एकीकरण को सक्षम बनाता है।
- एक परिष्कृत डेटा प्रोसेसिंग सर्किट के साथ मिलकर, सिस्टम निर्बाध वायरलेस डेटा ट्रांसफर की सुविधा देता है, जिससे भावनाओं की तत्काल पहचान संभव हो जाती है।
- मशीन लर्निंग एल्गोरिदम द्वारा सशक्त, यह मानवीय भावनाओं को पहचानने में उल्लेखनीय दक्षता प्रदर्शित करता है, यहां तक कि उन परिदृश्यों में भी जहां व्यक्ति मुखौटे पहनते हैं।
- PSiFI प्रणाली स्व-संचालित, सुस्पष्ट, विस्तार योग्य और पारदर्शी है।

16. अलास्कापोक्स

- हाल ही में, अलास्का का एक बुजुर्ग व्यक्ति अलास्कापॉक्स से मरने वाला पहला व्यक्ति बन गया।
- अलास्कापॉक्स एक ऑर्थोपॉक्स वायरस है जिसे पहली बार वर्ष 2015 में अलास्का, संयुक्त राज्य अमेरिका में खोजा गया था।
- यह एक डबल-स्ट्रैंडेड DNA वायरस है जो चेचक, मंकीपॉक्स और काउपॉक्स के समान जीनस ऑर्थोपॉक्सवायरस से संबंधित है।
  - ऑर्थोपॉक्सवायरस ज़ूनोटिक वायरस हैं जो मनुष्यों सहित विभिन्न स्तनधारियों को संक्रमित कर सकते हैं।
- वर्तमान साक्ष्य इंगित करते हैं कि अलास्कापॉक्स वायरस मुख्य रूप से छोटे स्तनधारियों में होता है।
  - वायरस की सबसे अधिक पहचान रेड-बैक्ड वोल्स और शूज़ में की गई है।
- लक्षण: एक या अधिक त्वचा पर घाव (धक्कों या फुंसी), सूजे हुए लिम्फ नोड्स और जोड़ों और/या मांसपेशियों में दर्द, प्रतिरक्षाविहीन लोगों में अधिक गंभीर बीमारी का खतरा बढ़ सकता है।
- संचरण: जबकि अलास्कापॉक्स का मानव-से-मानव संचरण अभी तक नहीं दे।

17. बोचासनवासी अक्षर पुरूषोत्तम स्वामीनारायण संस्था (BAPS)

- प्रधानमंत्री अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर, बोचासनवासी अक्षर पुरूषोत्तम स्वामीनारायण संस्था BAPSमंदिर का उद्घाटन किया।
- BAPS एक सामाजिक-आध्यात्मिक हिंदू आस्था है जो भगवान स्वामीनारायण (1781-1830 CE) द्वारा प्रचारित वैदिक शिक्षाओं पर आधारित है।
- यह संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के साथ परामर्शदात्री स्थिति वाला एक गैर सरकारी संगठन है।

- इसकी औपचारिक स्थापना 1907 ई. में ब्रह्मस्वरूप शास्त्रीजी महाराज द्वारा की गई थी।
- BAPS अनुयायियों की पाँच आजीवन प्रतिज्ञाएँ: शराब नहीं, व्यसन नहीं, व्यभिचार नहीं, मांस नहीं, शरीर और मन की अशुद्धता नहीं।

18. स्वाति पोर्टल

- हाल ही में, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने "महिलाओं के लिए विज्ञान-एक प्रौद्योगिकी और नवाचार (SWATI)" पोर्टल लॉन्च किया।
- उद्देश्य: STEMM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा) में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक ऑनलाइन पोर्टल बनाना।
- स्वाति पोर्टल का डेटाबेस लैंगिक-अंतर की चुनौतियों का समाधान करने के लिए नीति-निर्माण में काम आएगा।
- इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च (NIPGR), नई दिल्ली द्वारा विकसित, होस्ट और रखरखाव किया जाता है।

19. गोल्ड नैनोकण

- सोने के नैनोकण (AuNPs) 1 से 100 nm के व्यास वाले छोटे सोने के कण होते हैं।
- एक बार पानी में घुल जाने के बाद, AuNP को कोलाइडल सोना भी कहा जाता है।
- इन्हें 'स्वर्ण भस्म' भी कहा जाता है।
- गोलाकार AuNP में आकार और आकृति-संबंधित ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक गुण, बड़े सतह-से-आयतन अनुपात, उत्कृष्ट जैव-अनुकूलता और कम विषाक्तता जैसे उपयोगी गुण होते हैं।
- AuNP के महत्वपूर्ण भौतिक गुणों में सतह प्लास्मोन अनुनाद (SPR) और प्रतिदीप्ति को बुझाने की क्षमता शामिल है।
- गोलाकार AuNPs जलीय घोल में रंगों की एक श्रृंखला (जैसे, भूरा, नारंगी, लाल और बैंगनी) प्रदर्शित करते हैं क्योंकि कोर का आकार 1 से 100 nm तक बढ़ जाता है।

20. गोल्डन लैंगर्स

- इसे उनके फर के रंग से सबसे आसानी से पहचाना जा सकता है, जिसके आधार पर उनका नाम रखा गया है।
- यह देखा गया है कि उनका फर मौसम के अनुसार रंग बदलता है।
- शिशुओं का रंग भी वयस्कों से भिन्न होता है क्योंकि वे लगभग शुद्ध सफेद होते हैं।
- यह असम, भारत और पड़ोसी भूटान तक सीमित है जहां वे साल भर रहते हैं।
- ये जिस क्षेत्र में निवास करते हैं वह चार भौगोलिक स्थलों भूटान (उत्तर), मानस नदी (पूर्व), संकोश नदी (पश्चिम) और ब्रह्मपुत्र नदी (दक्षिण) की तलहटी से घिरा हुआ क्षेत्र तक ही सीमित है।

21. मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टार्गेटेबल री-एंट्री व्हीकल (MIRV) तकनीक

- MIRV एक ही मिसाइल से सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित कई लक्ष्यों को निशाना बना सकता है।
- अब तक, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के पास MIRV से सुसज्जित मिसाइलें हैं।
- जहां पाकिस्तान ऐसी मिसाइल प्रणाली विकसित कर रहा है, वहीं इजरायल के पास भी यह मिसाइल होने या इसे विकसित करने का संदेह है।
- इन मिसाइलों को जमीन से या समुद्र से (या पनडुब्बी से) लॉन्च किया जा सकता है।

22. कृषि और ग्रामीण सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और बीमा (सारथी) पोर्टल

- हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री ने 'सारथी' प्लेटफॉर्म का अनावरण किया।
- उद्देश्य: भारत में किसानों और ग्रामीण आबादी के लिए विशेष रूप से तैयार PMFBY सहित बीमा उत्पादों की एक पूरी श्रृंखला प्रदान करना।
- यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) भारत के सहयोग से शुरू किया गया व्यापक डिजिटल बीमा मंच है।
- यह पोर्टल बीमा उत्पादों को देखने, खरीदने और उनका लाभ उठाने के लिए एकल-खिड़की मंच होगा।

- प्लेटफ़ॉर्म में डिजिटल भुगतान विकल्प और सुव्यवस्थित प्रीमियम संग्रह, सहज दावा आरंभ, ट्रैकिंग और समाधान के अलावा हितधारकों के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस हैं।

23. बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (BOT) मॉडल

- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) निजी डेवलपर्स के लिए बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (BOT) मॉडल के तहत निर्माण और संचालन के लिए उच्च यातायात घनत्व वाले गलियारों की एक सूची लेकर आया है।
- BOT एक प्रकार का समझौता है जिसका उपयोग अक्सर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में किया जाता है, विशेष रूप से सार्वजनिक सुविधाओं या उपयोगिताओं के निर्माण और संचालन में।
- यह एक पारंपरिक सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल है जिसमें एक निजी इकाई को एक निश्चित अवधि के लिए एक विशिष्ट परियोजना या सुविधा को डिजाइन, वित्त, निर्माण, संचालन और रखरखाव करने के अधिकार और जिम्मेदारियां दी जाती हैं।
- निजी संस्था अनुबंध अवधि के दौरान परियोजना से जुड़े वित्तीय और परिचालन जोखिमों को भी वहन करती है।
- अनुबंध अवधि के अंत में, सुविधा का स्वामित्व और नियंत्रण वापस सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण को स्थानांतरित कर दिया जाता है, जो मूल मालिक हो सकता है।
- स्थानांतरण अक्सर पूर्व निर्धारित मूल्यांकन या मुआवजा तंत्र के साथ होता है।
- निजी कंपनी को रियायत अवधि के दौरान राजस्व प्राप्त होता है, जबकि सरकार को अग्रिम निवेश के बिना बुनियादी ढांचे के विकास से लाभ होता है।
- BOT विशेष रूप से ग्रीनफील्ड परियोजनाओं (बिना पूर्व कार्य के नई परियोजनाएं) और बड़े पैमाने पर, पूंजी-गहन परियोजनाओं के लिए उपयुक्त है।

24. जिरकोन मिसाइल

- कीव में एक लक्ष्य को भेदने की कोशिश में, रूसी सेना ने हाल ही में 3M22 जिरकोन मिसाइल लॉन्च की।
- 3M22 जिरकॉन, या SS-N-33, रूस में विकसित एक स्क्रैमजेट-संचालित पैंतरेबाज़ी एंटी-शिप हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है।
- कथित तौर पर यह मिसाइल 9 मैक तक की गति और 1000 किमी की दूरी तक उड़ान भरने में सक्षम है।
- यह दो चरणों वाली मिसाइल है जो पहले चरण में ठोस ईंधन और दूसरे चरण में स्क्रैमजेट मोटर का उपयोग करती है।
- मिसाइल में ठंडे सुपरसोनिक दहन रैमजेट इंजन का उपयोग किया जाता है, जो मिसाइल की आगे की गति के कारण सुपरसोनिक गति से बहने वाली हवा को संपीड़ित करके दहन की सुविधा प्रदान करता है।
- मार्गदर्शन प्रणाली: सक्रिय और निष्क्रिय रडार साधक।
- उड़ान के दौरान, मिसाइल पूरी तरह से एक प्लाज्मा बादल से ढकी होती है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी की किसी भी किरण को अवशोषित कर लेती है और मिसाइल को रडार के लिए अदृश्य बना देती है।

25. CAA, 2019

- इसने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता के लिए पात्र बनाने के लिए वर्ष 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया।
- अवैध प्रवासी कौन हैं?: एक अवैध आप्रवासी वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश करता है या अनुमत समय से अधिक समय तक रहता है, संभावित रूप से अभियोजन, निर्वासन या कारावास का सामना करना पड़ सकता है।
- इन समुदायों के जो लोग 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में आए थे, उन्हें अवैध अप्रवासी नहीं माना जाएगा, जिससे प्राकृतिककरण का रास्ता मिल जाएगा।
- हालाँकि, इसमें मुस्लिम समुदाय को छूट दी गई है।

26. व्यायाम-सदा तनसीक

- हाल ही में, भारत और सऊदी अरब की सेनाएं राजस्थान के महाजन में सदा तनसीक नाम से अपना पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित कर रही हैं।
- उद्देश्य: संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के तहत अर्ध रेगिस्तानी इलाके में संयुक्त अभियानों के लिए दोनों पक्षों के सैनिकों को प्रशिक्षित करना।
- यह दोनों पक्षों को उप-पारंपरिक डोमेन में संचालन करने की रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाओं में अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने में सक्षम बनाएगा।
- इससे दोनों पक्षों के सैनिकों के बीच अंतरसंचालनीयता, सौहार्द्र और सौहार्द विकसित करने में मदद मिलेगी।
- इसमें मोबाइल वाहन चेक पोस्ट की स्थापना, घेरा और तलाशी अभियान, हाउस इंटरवेंशन ड्रिल, रिफ्लेक्स शूटिंग, स्लिथरिंग और स्नाइपर फायरिंग शामिल होगी।

27. नॉनअल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस (NASH)

- यह लीवर की सूजन और लीवर में वसा के निर्माण के कारण होने वाली क्षति है। यह गैर-अल्कोहल फैटी लीवर रोग नामक स्थितियों के समूह का हिस्सा है।
- NASH खराब हो सकता है और लीवर पर घाव का कारण बन सकता है, जिससे सिरोसिस हो सकता है। लेकिन बीमारी हमेशा बदतर नहीं होती।
- यह लिवर की उस तरह की बीमारी के समान है जो लंबे समय तक भारी शराब पीने से होती है लेकिन NASH उन लोगों में होता है जो शराब नहीं पीते हैं।

28. बायोट्रिग

- एक हालिया अध्ययन में दावा किया गया है कि पायरोलिसिस प्रणाली पर आधारित एक नई अपशिष्ट प्रबंधन तकनीक बायोटीआरआईजी ग्रामीण भारतीयों की मदद कर सकती है।
- यह अपशिष्ट को ऑक्सीजन मुक्त कक्ष के अंदर सील करके और इसे 400 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म करके काम करता है; इस प्रक्रिया में उपयोगी रसायन उत्पन्न होते हैं।
- शोधकर्ताओं ने पायरोलिसिस के तीन उत्पादों अर्थात जैव-तेल, सिनगैस और बायोचार उर्वरक की रूपरेखा तैयार की, जो ग्रामीण भारतीयों को स्वस्थ और हरित जीवन जीने में मदद कर सकते हैं।
- महत्व
  - सिनगैस और बायो-ऑयल भविष्य के चक्रों में पायरोलिसिस प्रणाली को गर्मी और बिजली प्रदान करते हैं और अतिरिक्त बिजली का उपयोग स्थानीय घरों और व्यवसायों को बिजली देने के लिए किया जाता है।
  - पर्यावरण के अनुकूल जैव-तेल का उपयोग घरों में पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन के विकल्प के रूप में किया जाता है, और बायोचार का उपयोग कार्बन भंडारण, मिट्टी की गुणवत्ता और उर्वरता बढ़ाने के लिए किया जाता है।
  - यह समुदायों से प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष लगभग 350 किलोग्राम CO2-eq तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकता है।
  - यह ग्रामीण भारतीयों को घर के अंदर वायु प्रदूषण को कम करने, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करने और स्वच्छ बिजली पैदा करने में मदद कर सकता है।

29. स्टेट ऑफ द ज्यूडिशियरी रिपोर्ट

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग द्वारा 'स्टेट ऑफ द ज्यूडिशियरी' शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी।
- मुख्य निष्कर्ष
  - भारत में लगभग पाँचवें (19.7%) जिला अदालत परिसरों में महिलाओं के लिए अलग शौचालय नहीं हैं।
  - मौजूदा महिला शौचालयों में अक्सर टूटे दरवाजे और अनियमित पानी की आपूर्ति होती है, जिससे उपयोगकर्ताओं की स्वच्छता और गरिमा से समझौता होता है।

- कुछ अदालत परिसरों में पुरुष और महिला न्यायाधीशों के लिए साझा शौचालय हैं।
- जिला अदालत परिसरों में केवल 6.7% महिला शौचालय सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनों से सुसज्जित हैं।
- अधिकांश जिला अदालतों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से नामित शौचालयों का अभाव है।
- कुछ मामलों में न्यायाधीश शौचालयों की सफ़ाई सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से सफ़ाईकर्मियों और सफ़ाईकर्मियों को नियुक्त करते हैं।

30. एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन

- यह भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास "डेजर्ट साइक्लोन 2024" का उद्घाटन संस्करण है।
- यह राजस्थान में 2 जनवरी से 15 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा.
- इस अभ्यास का उद्देश्य शहरी परिचालन में सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखने और साझा करके अंतरसंचालनीयता को बढ़ाना है।
- यह अभ्यास रणनीतिक साझेदारी में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हो रहा है।

31. राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड

- NJDG ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में बनाए गए न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामले के विवरण का एक डेटाबेस है।
- इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा कंप्यूटर सेल रजिस्ट्री के समन्वय से विकसित किया गया है।
- डेटा को कनेक्टेड जिला और तालुका अदालतों द्वारा लगभग वास्तविक समय के आधार पर अपडेट किया जाता है।
- राष्ट्रीय डेटा शेयरिंग और एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी (NDSAP) के अनुरूप, NJDG केंद्र और राज्य सरकारों को एक ओपन एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (API) प्रदान करता है।
- इसके माध्यम से कोई भी मामले से संबंधित जानकारी, संस्था, लंबित मामलों और मामलों के निपटान, मामले के प्रकार, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वर्ष-वार विवरण जैसे आंकड़ों तक पहुंच सकता है।

32. पुन: प्रयोज्य लैंडिंग वाहन (RLV) LEX 02

- यह लैंडिंग प्रयोग एयरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में आयोजित श्रृंखला का दूसरा है।
- पिछले वर्ष RLV-LEX-01 मिशन पूरा होने के बाद RLV-LEX-02 का प्रदर्शन किया गया
  - हेलीकॉप्टर से निकलने पर नाममात्र की प्रारंभिक स्थितियों से पुन: प्रयोज्य लॉन्च वाहन (RLV) की स्वायत्त लैंडिंग क्षमता।

33. मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया

- ये अधिकतर प्रोकैरियोटिक जीव हैं जो स्वयं को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अनुरूप व्यवस्थित करते हैं।
- ऐसा माना जाता था कि ये जीव उन स्थानों तक पहुंचने के लिए चुंबकीय क्षेत्र का अनुसरण करते थे जहां इष्टतम ऑक्सीजन सांद्रता होती थी।
- इन जीवाणुओं में छोटी-छोटी थैलियों में "लौह से भरपूर नवीन संरचित कण" थे जो अनिवार्य रूप से एक कम्पास के रूप में काम करते थे।
- ये मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया लौह-समृद्ध खनिज मैग्नेटाइट या ग्रेगाइट से बने छोटे क्रिस्टल बनाते हैं।

34. मेमे कॉइन्स

- ये क्रिप्टोकरेंसी की एक अनूठी श्रेणी हैं, जिन्होंने डिजिटल मुद्रा क्षेत्र में महत्वपूर्ण लोकप्रियता हासिल की है।
- ये इंटरनेट पर मेमे कल्चर के विकास में अपनी उत्पत्ति का पता लगाते हैं।
- इन्हें 'मेमेटिक टोकन' या 'सामुदायिक सिक्के' के रूप में भी जाना जाता है, मेमे कॉइन्स इंटरनेट कल्चर पर स्टिर या ह्यूमोरोस ट्रीब्यूट के रूप में बनाई गई डिजिटल मुद्राएं हैं।
- वे अक्सर नाम, लोगो और ब्रांडिंग प्रदर्शित करते हैं जो लोकप्रिय मीम्स, जोक्स या इंटरनेट घटनाओं का संदर्भ देते हैं।

35. अफानसी निकितिन सीमाउंट

- अफानसी निकितिन सीमाउंट मध्य भारतीय बेसिन की एक संरचनात्मक विशेषता है, जो भारत के तट से लगभग 3,000 किमी दूर स्थित है।
- इसमें एक मुख्य पठार शामिल है, जो आसपास के समुद्र तल (4800 मीटर) से 1200 मीटर ऊपर है। यह कोबाल्ट, निकल, मैंगनीज और तांबे के भंडार से समृद्ध है।

36. खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024

- यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) और यूके स्थित गैर-लाभकारी संगठन WRAP (अपशिष्ट और संसाधन कार्रवाई कार्यक्रम) द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया एक अध्ययन है।
- यह खुदरा और उपभोक्ता (घरेलू और खाद्य सेवा) स्तर पर बर्बाद होने वाले भोजन और अखाद्य भागों की वैश्विक और राष्ट्रीय पीढ़ी को ट्रैक करता है।
- रिपोर्ट "खाद्य अपशिष्ट" को "मानव खाद्य आपूर्ति श्रृंखला से हटाए गए भोजन और संबंधित अखाद्य भागों" के रूप में परिभाषित करती है।
- ''खाद्य हानि'' को "सभी फसल और पशुधन मानव-खाद्य वस्तु मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कटाई के बाद/वध उत्पादन/आपूर्ति श्रृंखला से खुदरा स्तर तक और उसे छोड़कर पूरी तरह से बाहर निकल जाती है"।
- इसमें कहा गया है कि वर्ष 2022 में, 1.05 बिलियन टन खाद्य अपशिष्ट उत्पन्न हुआ (अखाद्य भागों सहित), जो प्रति व्यक्ति 132 किलोग्राम था और उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कुल भोजन का लगभग पांचवां हिस्सा था।
- कई निम्न और मध्यम आय वाले देशों में वर्ष 2030 तक भोजन की बर्बादी को आधा करने के सतत विकास लक्ष्य 12.3 को पूरा करने के लिए प्रगति पर नज़र रखने के लिए पर्याप्त प्रणालियों का अभाव बना हुआ है।

37. कोंडा रेड्डी जनजाति

- कोंडा रेड्डीज़ एक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है जो गोदावरी नदी के किनारे और आंध्र प्रदेश के गोदावरी और खम्मम जिलों के पहाड़ी वन क्षेत्रों में निवास करता है।
- उनकी मातृभाषा तेलुगु है, जिसका उच्चारण अद्वितीय है।
- वैवाहिक संबंधों को विनियमित करने के लिए कोंडा रेड्डी जनजाति को बहिर्विवाही वर्गों में विभाजित किया गया है।
- अन्य तेलुगु भाषी लोगों की तरह, उनके उपनाम अलग-अलग नामों से पहले लगाए जाते हैं।
- आम तौर पर, प्रत्येक सेट बहिर्विवाही होता है, लेकिन कुछ सेट को भाई सेट माना जाता है और भाई सेट (सजातीय संबंध) के साथ विवाह गठबंधन निषिद्ध है।

GEO IAS

It's about quality

ABOUT US

GEO IAS is the best institute for civil services in India for providing top quality teaching and materials, offering you most optimum path for your success in Civil Services exam. Our aim is to provide quality training with an affordable fee structure. Our uniquely designed course make us the best institute for UPSC to crack the exam in one go. We have a dedicated team of experienced and young teachers and counsellors who make sure that every student who joins the institute, must get customized way of preparation which matches with student's learning style.
The only institute of UPSC in India which has 3 AI enabled Mobile apps. We believe in Smart way of teaching and learning. The classes are available in offline as well as in online mode. We take the help of animation so that you may visualize the lectures. Unlimited tests for prelims and mains with solution in both form (Hard copy and soft copy). We have the set of 15 lac mcqs on each topic. We provide daily news analysis, Highlighted news paper and links of important Sansad TV shows. The institute has best success rate with more than 230 students have cleared the exam. HIGHEST RATED INSTITUTE as per GOOGLE, SULEKHA and JUST DIAL and the magazine on civil services

+91-9477560001 /002/005

BRANCH: Delhi Kolkata, Raipur, Patna | HEAD OFFICE: 641, Ramlal Kapoor Marg, Mukherjee Nagar, Delhi, 110009

info@geoias.com

www.geoias.com